IAS BABA

TOPPER'S RECOMMENDED
BEST CHOICE

One Stop Destination For UPSC/IAS Preparation

Baba's Monthly

CURRENT AFFAIRS MAGAZINE

Women's Reservation Bill 2023.

End of Old Multilateralism – and the Beginning of a New Order.

India – Canada Relations.

20th ASEAN-India Summit.

First Global Symposium on Farmers Rights.

Stem Cell Therapy .

हिंदी

ONLINE & OFFLINE
LIVE

IAS BABA

PRELIMS EXCLUSIVE PROGRAMME (PEP) 2024

Most Comprehensive Prelims CLASSROOM Program

GARIMA LOHIA
RANK 2
UPSC CSE 2022
PEP STUDENT

400+ Hours of Prelims Focused Classes

- 1:1 Personal Mentorship
- Solve 5000+ MCQ's for PRELIMS 2024
- Prelims Exclusive Handouts
- 125+ Daily Tests & Full Length Tests
- PYQ Classes & CSAT Classes by Prelims Experts
- Current Affairs - Classes, Handouts & Tests

ADMISSIONS OPEN

Starts December 15th

www.iasbaba.com | support@iasbaba.com | 91691 91888

विषय-सूची

PRELIMS.....4

राजव्यवस्था और शासन

- केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA)
- अनुच्छेद 371 D
- ई-कोर्ट मिशन मोड प्रोजेक्ट
- राष्ट्रीय उच्च शिक्षा योग्यता ढांचा (NHEQF)
- राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (NMC)

अंतरराष्ट्रीय संबंध

- 20वां आसियान-भारत शिखर सम्मेलन
- अफ्रीका जलवायु शिखर सम्मेलन 2023
- आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (OECD)
- G20 नई दिल्ली घोषणा
- एशिया प्रशांत क्षेत्र के राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों का सम्मेलन
- भारत-कनाडा संबंध
- G4 देश
- फाइव आइज़ एलायंस
- भारत और फ़िनलैंड

भूगोल

- धूमकेतु निशिमुरा
- उत्तरी समुद्री मार्ग
- भोज वेटलैंड
- हीराकुंड बांध
- काओबल गली-मुश्कोह घाटी
- इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023

अर्थव्यवस्था

- ऑपरेट ट्रांसफर (बीओटी) मॉडल बनाएं
- सेंट्रल बैंक डिजिटल मुद्रा (CBDC)
- भारतीय मानक ब्यूरो (BIS)
- किसानों के अधिकारों पर पहली वैश्विक संगोष्ठी
- विश्व व्यापार संगठन (WTO)
- ओआईएमएल (इंटरनेशनल ऑर्गनाइजेशन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी) प्रमाणपत्र
- विश्व व्यापार रिपोर्ट 2023
- वित्तीय समावेशन के लिए जी20 वैश्विक भागीदारी (जीपीएफआई) बैठक
- E-NAM 2.0
- JPM GBI-EM ग्लोबल डायवर्सिफाइड इंडेक्स
- वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में उछाल
- ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023
- रत्न एवं आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद (GJEPC)

पर्यावरण और पारिस्थितिकी

- रेड सैंड बोआ
- हूलोंगापार गिब्बन अभयारण्य
- वायु गुणवत्ता जीवन सूचकांक (AQLI)
- बीएस 6 स्टेज II इलेक्ट्रिफाइड फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल
- फुजियानवेनेटर प्रोडिगियोसस
- सेगुर हाथी गलियारा
- आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए सेंडाई फ्रेमवर्क
- वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व
- कोले वेटलैंड्स
- कैमूर वन्यजीव अभयारण्य
- वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM)
- पिंक बॉलवर्म

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

- दोध्रुवी विकार
- स्पैमोफ्लैज
- LIGO-भारत परियोजना
- निपाह वायरस (NiV)
- प्रोबायोटिक्स
- इंजीनियर्स डे
- TTPs (रणनीति, तकनीक और प्रक्रियाएं)-आधारित साइबर अपराध जांच ढांचा
- पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम (PCOS)
- मिशन साइकी (Psyche)
- सिट्रान
- कैलिप्सो मिशन

इतिहास, कला एवं संस्कृति

- विश्व संस्कृत दिवस 2023
- पुलिकली (पुलिक्कली)
- संत नारायण गुरु
- केरल के नृत्य रूप
- कोणार्क चक्र

- फणीगिरी कलाकृतियाँ
- मेगालिथिक डोलमेन साइट
- शांति निकेतन
- होयसल मंदिर
- आदि शंकराचार्य की मूर्ति
- मेवाड़ शैली की चित्रकारी
- हाइफा का युद्ध

सरकारी पहल, योजनाएँ और नीतियाँ

- पोषण (समग्र पोषण के लिए प्रधान मंत्री की व्यापक योजना) योजना
- मेरा बिल मेरा अधिकार योजना
- पर्सनलाइज्ड एडेप्टिव लर्निंग (PAL)
- ग्रामोद्योग विकास योजना
- हेरिटेज 2.0 कार्यक्रम अपनाना
- मालवीय मिशन - शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम
- बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली
- स्किल इंडिया डिजिटल ऐप
- NeVA परियोजना
- श्रेयस योजना
- किसान ऋण पोर्टल
- जीसीईएस वेब पोर्टल और मोबाइल एप्लिकेशन
- प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई)

विविध

- रेमन मैग्सेसे पुरस्कार
- पुरुष हॉकी 5एस एशिया कप 2023
- MQ-9B ड्रोन
- ट्राइफेड (भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास महासंघ)
- बोरलॉग पुरस्कार
- काउंटर टेररिज्म फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज (FTX) 2023
- दादा साहब फाल्के लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार
- एमएस स्वामीनाथन
- विश्व विश्वविद्यालय रैंकिंग 2024

MAINS

PAPER 1

- जाति-आधारित पृथक निर्वाचन क्षेत्रों पर गांधी-अंबेडकर बहस
- भारत में बढ़ती मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं
- बहुविवाह विरोधी कानून

PAPER II

- महिला आरक्षण विधेयक 2023
- एक राष्ट्र एक चुनाव' प्रणाली (ONOE)
- बिहार सरकार का जाति आधारित सर्वे
- धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए शैक्षिक योजनाएँ
- पुराने बहुपक्षवाद का अंत - और एक नई व्यवस्था की शुरुआत
- भारत-अमेरिका संबंध
- भारत-सऊदी अरब संबंध
- भारत-ब्राजील संबंध
- भारत-कनाडा संबंध
- पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन (ईएएस) और इसका महत्व

PAPER III

- जेंडर रिस्पॉन्सिव बजटिंग
- स्टेम सेल थेरेपी
- राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (NMCG)
- क्वांटम कंप्यूटिंग में वैश्विक पहल: अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की भूमिका

PRACTICE QUESTIONS .....

ANSWER

PRELIMS

राजव्यवस्था और शासन

केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA)

संदर्भ: केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) ने हाल ही में मैसर्स आईक्यूआरए आईएएस संस्थान (IQRA IAS Institute) के खिलाफ उनकी वेबसाइट से भ्रामक प्रशंसापत्र और भ्रामक दावे को तत्काल प्रभाव से बंद करने का आदेश जारी किया है।

पृष्ठभूमि: -

- यह मुद्दा सीसीपीए के संज्ञान में 2018 में बनी आईक्यूआरए आईएएस संस्थान की वेबसाइट के माध्यम से आया। वेबसाइट में 2015 और 2017 में हुई यूपीएससी सीएसई के शीर्ष रैंक धारकों के प्रशंसापत्र के माध्यम से जानबूझकर और गलत तरीके से दावा किया गया कि वे उनके छात्र रहे हैं, जो तथ्यात्मक रूप से धोखा है।
- इसलिए सीसीपीए ने स्वत: संज्ञान लिया और पाया कि उपरोक्त दावे झूठे हैं। सीसीपीए ने पाया कि संस्थान ने खुद को इस तरह दिखाया कि वो सर्वश्रेष्ठ यूपीएससी ऑनलाइन प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज़ 2020 प्रदान करने वाला ऐसा कोचिंग संस्थान है जिसके पास पूरे भारत में सर्वश्रेष्ठ टीचर हैं। इस प्रकार इसे पुणे में एक साल के भीतर यूपीएससी की टॉप कोचिंग संस्थान बन गया था।
- तदनुसार, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के उल्लंघन के मद्देनजर IQRA IAS संस्थान को नोटिस जारी किया गया।

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019:-

- उपभोक्ता की परिभाषा: उपभोक्ता को ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया जाता है जो प्रतिफल के बदले कोई वस्तु खरीदता है या सेवा प्राप्त करता है।
- बहिष्करण: इसमें वह व्यक्ति शामिल नहीं होता है जो पुनर्विक्रय के लिए कोई वस्तु या व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए कोई वस्तु या सेवा प्राप्त करता है।
- यह इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों, टेलीशॉपिंग, मल्टी-लेवल मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से ऑफ़लाइन और ऑनलाइन सहित सभी तरीकों से लेनदेन को कवर करता है।
- भ्रामक विज्ञापन की परिभाषा: यह अधिनियम किसी भी उत्पाद या सेवा के संबंध में "भ्रामक विज्ञापन" को "एक विज्ञापन" के रूप में परिभाषित करता है, जो:-
    - ऐसे उत्पाद या सेवा का गलत वर्णन करता है; या
    - ऐसे उत्पाद या सेवा की प्रकृति, पदार्थ, मात्रा या गुणवत्ता के बारे में
    - उपभोक्ताओं को झूठी गारंटी देता है या गुमराह करने की संभावना रहती है।
    - एक स्पष्ट या निहित प्रतिनिधित्व बताता है, जो कि निर्माता या विक्रेता या सेवा प्रदाता द्वारा किया जाता है, तो एक अनुचित व्यापार व्यवहार का गठन होगा; या• जानबूझकर महत्वपूर्ण जानकारी छुपाता है।

उपभोक्ताओं के अधिकार:-

- अधिनियम में छह उपभोक्ता अधिकारों को परिभाषित किया गया है, जिनमें शामिल हैं:-
    - सुरक्षा का अधिकार, सूचित होने का अधिकार, चुनने का अधिकार, सुनवाई का अधिकार, निवारण पाने का अधिकार और उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार।

केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) के बारे में:-

- स्थापना: वर्ष 2020 में
- मंत्रालय: उपभोक्ता मामलों का मंत्रालय
- मुख्यालय: दिल्ली
- उद्देश्य: अनुचित व्यापार प्रथाओं और जनता एवं उपभोक्ताओं के हितों के लिए हानिकारक झूठे और भ्रामक विज्ञापनों पर नकेल कस कर उपभोक्ता के अधिकारों की रक्षा करना।
- केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 की धारा 10(1) के तहत गठित एक प्राधिकरण है।

संघटन: -

- प्रमुख: मुख्य आयुक्त
- सदस्य: इसमें दो अन्य आयुक्त सदस्य के रूप में शामिल होते है।

- इनमें से एक वस्तुओं से संबंधित मामलों को देखता है जबकि दूसरा सेवाओं से संबंधित मामलों को देखता है।

- जांच विंग: सीसीपीए में एक जांच विंग होती है, जिसका नेतृत्व एक महानिदेशक करता है।
- जिला कलेक्टर: उनके पास भी उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन, अनुचित व्यापार प्रथाओं और झूठे या भ्रामक विज्ञापनों की शिकायतों की जांच करने की शक्ति होगी।

शक्तियां एवं कार्य:-

- उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन या अनुचित व्यापार प्रथाओं से संबंधित मामलों में स्वत: संज्ञान, या प्राप्त शिकायत पर, या केंद्र सरकार के निर्देश पर पूछताछ या जांच करना।
- उन वस्तुओं को वापस लेना या उन सेवाओं को वापस लेना जो "खतरनाक, संकटपूर्ण, या असुरक्षित" होती हैं।
- ऐसी वस्तुओं या सेवाओं के खरीदारों को वापस मंगाई गई वस्तुओं या सेवाओं की कीमतें वापस करने का आदेश पारित करना।
- झूठे और भ्रामक विज्ञापनों के निर्माता या समर्थनकर्ता पर दो साल तक की कैद के साथ 10 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाना।
  - एक ही निर्माता या समर्थनकर्ता द्वारा किए गए प्रत्येक बाद के अपराध के लिए जुर्माना 50 लाख रुपये तक जा सकता है, जिसमें पांच साल तक की कैद हो सकती है।
- झूठे या भ्रामक विज्ञापन के समर्थनकर्ता को भविष्य में किसी भी उत्पाद या सेवा का समर्थन करने से प्रतिबंधित करना।
- जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग और राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के समक्ष उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन या अनुचित व्यापार प्रथाओं की शिकायत दर्ज करना।

अवश्य पढ़ें: नया उपभोक्ता अधिकार कानून

SOURCE: PIB

अनुच्छेद 371 D

संदर्भ: आंध्र प्रदेश के छात्र शैक्षणिक संस्थानों में 'स्थानीय कोटा' खोने की संभावना देख रहे हैं क्योंकि मई 2024 में 10 वर्ष की अवधि के बाद आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम की वैधता समाप्त होने पर अनुच्छेद 371 डी उनके बचाव में नहीं आ सकता है।

पृष्ठभूमि: -

- शिक्षण समुदाय और छात्र समुदाय को निकट भविष्य में शैक्षणिक संस्थानों में 'स्थानीय कोटा' खोने की संभावना का डर है।
- उनका डर इस तथ्य से उपजा है कि आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, जो मई 2014 में लागू हुआ, केवल 10 वर्षों के लिए वैध है।
- इसका मतलब यह है कि आंध्र प्रदेश के विभाजन से पहले बनाए गए नियम और कानून मई 2024 के बाद लागू नहीं होंगे।

अनुच्छेद 371 D के बारे में:-

- भारतीय संविधान का अनुच्छेद 371 भारतीय संघ के 11 राज्यों के लिए विशेष प्रावधानों से संबंधित है।
- यह भारत के संविधान के भाग XXI, अनुच्छेद 371 का एक हिस्सा है।

लाभार्थी राज्य:-

- यह अनुच्छेद अनुच्छेद 371-A से लेकर अनुच्छेद 371-J तक है।
- यह महाराष्ट्र, गुजरात, नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा और कर्नाटक राज्यों के लिए विशेष प्रावधान देता है।
- कुछ राज्यों को विशेष प्रावधान देने वाले अनुच्छेद 371 के पीछे मुख्य उद्देश्य हैं:-
  - इन राज्यों के पिछड़े क्षेत्रों की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करना।
  - इन क्षेत्रों के आर्थिक और सांस्कृतिक हितों की सुरक्षा करना।
  - स्थानीय चुनौतियों का मुकाबला और इन क्षेत्रों में प्रथागत कानूनों की रक्षा करना।
- अनुच्छेद 371D, आंध्र प्रदेश राज्य के लिए विशेष प्रावधान देता है।
- इसे 1974 में 32वें संशोधन अधिनियम, 1973 द्वारा संविधान में जोड़ा गया था।
- इसमें कहा गया है कि: राष्ट्रपति को "राज्य के विभिन्न हिस्सों के लोगों के लिए सार्वजनिक रोजगार और शिक्षा" में "समान अवसर और सुविधाएं" सुनिश्चित करनी चाहिए। वह राज्य सरकार से "राज्य की सिविल सेवा में किसी भी वर्ग या वर्गों के पदों, या राज्य के अंतर्गत सिविल पदों के किसी भी वर्ग या वर्गों को राज्य के विभिन्न हिस्सों के लिए अलग-अलग स्थानीय संवर्गों में व्यवस्थित करने की मांग कर सकता है"। उसके पास शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के संबंध में समान शक्तियां हैं।

लाभ : -

- यह राज्य के लोगों के लिए समान अवसर और सुविधाएं प्रदान करता है।
- यह रोजगार और शिक्षा के मामलों में उनके अधिकारों की रक्षा करता है। (निवास-आधारित नौकरी कोटा)
- राज्य सरकार आवश्यकतानुसार स्थानीय कैडर में सिविल पदों या पदों पर सीधी भर्ती आयोजित कर सकती है।

अवश्य पढ़ें: असममित संघवाद

SOURCE: THE HINDU

ई-कोर्ट मिशन मोड प्रोजेक्ट

संदर्भ: सरकार ने हाल ही में राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना के हिस्से के रूप में ई-कोर्ट मिशन मोड प्रोजेक्ट चरण -3 को मंजूरी दी है।

पृष्ठभूमि:-

- यह राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना का एक हिस्सा है।
- यह चार वर्षों तक सात हजार 210 करोड़ रुपये के वित्तीय परिव्यय के साथ चलेगा।

ई-कोर्ट मिशन मोड परियोजना के बारे में:-

- लॉन्च: वर्ष 2007 में
- मंत्रालय: कानून एवं न्याय मंत्रालय
- ई-कोर्ट परियोजना भारत सरकार के न्याय विभाग द्वारा शुरू की गई एक मिशन-मोड परियोजना है।
- उद्देश्य: देश में जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के सार्वभौमिक कम्प्यूटरीकरण और न्याय प्रणाली की सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (ICT) सक्षमता को बढ़ाकर वादियों, वकीलों और न्यायपालिका को निर्दिष्ट सेवाएं प्रदान करना।
- कार्यान्वयन: ई-कोर्ट परियोजना को भारत की ई-समिति सुप्रीम कोर्ट और न्याय विभाग के सहयोग से कार्यान्वित किया जा रहा है।
- इस परियोजना का उद्देश्य आवश्यक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर एप्लिकेशन प्रदान करना है ताकि अदालतें ई-सेवाएं प्रदान कर सकें और न्यायपालिका अदालतों के कामकाज की निगरानी और प्रबंधन करने में सक्षम हो सके।
- यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है।
- सुप्रीम कोर्ट की ई-समिति "भारतीय न्यायपालिका के सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) के कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय नीति और कार्य योजना-2005" के तहत संकल्पित ई-कोर्ट परियोजना के कार्यान्वयन की देखरेख कर रही है।
- ई समिति के अध्यक्ष भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश डॉ. न्यायमूर्ति धनंजय वाई चंद्रचूड़ हैं।

चरण:-

- चरण I: इसे वर्ष 2011-2015 के दौरान लागू किया गया था।
- चरण II: इसे वर्ष 2015 में शुरू किया गया था जिसके तहत विभिन्न ज़िला और अधीनस्थ न्यायालयों को कंप्यूटरीकृत किया गया है।
- चरण III के लिए ड्राफ्ट विज़न दस्तावेज़ का लक्ष्य है: (ईकोर्ट परियोजना का चरण III)
    - अदालती प्रक्रियाओं का डिजिटलीकरण।
    - न्यायपालिका के इलेक्ट्रॉनिक बुनियादी ढांचे को उन्नत करना।
    - वकीलों और (Litigants) तक पहुंच सक्षम करना।
    - इंटरऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम (ICJS) के माध्यम से राज्य की विभिन्न शाखाओं के बीच सूचनाओं का निर्बाध आदान-प्रदान।
    - इन शाखाओं में न्यायपालिका, पुलिस और जेल प्रणालियाँ शामिल हैं।

लाभ :-

- तेज़ न्याय वितरण। (न्यायालय अभिलेखों का डिजिटलीकरण)
- भारतीय अदालतों में लगभग 3.27 करोड़ लंबित मामलों का निपटारा।
- सामान्य वादियों के लिए अधिक देरी और कठिनाइयों को कम करना।
- न्यायपालिका में लोगों का विश्वास पैदा करना।

चुनौतियाँ:-

- तकनीकी चुनौतियाँ: जटिल प्रक्रिया जिसमें मौजूदा प्रौद्योगिकी और बुनियादी ढांचे को उन्नत करना शामिल है।
- साइबर सुरक्षा जोखिम
- समानता संबंधी चिंताएँ: अदालतों का डिजिटलीकरण हाशिए पर रहने वाले समुदायों, विशेषकर जिनके पास प्रौद्योगिकी तक पहुंच नहीं है, के लिए न्याय तक पहुंच में मौजूदा असमानताओं को बढ़ा सकता है।
- अभिलेखों का संरक्षण: अभिलेखों का डिजिटलीकरण ऐतिहासिक अभिलेखों के संरक्षण के लिए चुनौतियाँ पैदा करता है।

अवश्य पढ़ें: न्यायपालिका और एआई

SOURCE: AIR

राष्ट्रीय उच्च शिक्षा योग्यता ढांचा (NHEQF)

संदर्भ: विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (University Grants Commission -UGC) ने हाल ही में राष्ट्रीय उच्च शैक्षिक योग्यता ढांचे (NHEQF) को अंतिम रूप दिया है, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा प्रस्तावित एक नियामक सुधार है।

इसके बारे में:

- **डेवलपमेंट:** श्रम और रोजगार मंत्रालय ने राष्ट्रीय व्यावसायिक योग्यता फ्रेमवर्क (National Vocational Qualifications Framework (NVQF) विकसित किया और शिक्षा मंत्रालय ने व्यावसायिक शिक्षा योग्यता फ्रेमवर्क (NVEQF) विकसित किया।
- NHEQF ने मापदंडों को 5 से 10 के स्तर में विभाजित किया है।
  - स्तर 1 से 4 तक स्कूली शिक्षा को कवर किया गया है।
  - NHEQF स्तर 5 अध्ययन के स्नातक कार्यक्रम के पहले वर्ष (पहले दो सेमेस्टर) के लिए उपयुक्त सीखने के परिणामों का प्रतिनिधित्व करता है;
  - जबकि स्तर 10 अध्ययन के डॉक्टरेट-स्तरीय कार्यक्रम के लिए उपयुक्त सीखने के परिणामों का प्रतिनिधित्व करता है।
- NHEQF के अनुसार, छात्रों को अध्ययन का एक कार्यक्रम पूरा करने के बाद इच्छित स्नातक प्रोफ़ाइल/विशेषताओं को अपने पास रखना और प्रदर्शित करना होगा।
- यह विभिन्न स्तरों पर चार-वर्षीय स्नातक कार्यक्रम, स्नातकोत्तर डिग्री और डॉक्टरेट डिग्री को पूरा करने के लिए आवश्यक क्रेडिट की मात्रा भी स्थापित करता है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के बारे में:

- स्थापित: 28 दिसंबर, 1953
- यह यूजीसी अधिनियम, 1956 के अनुसार एक वैधानिक संगठन है।
- मंत्रालय: शिक्षा मंत्रालय
- यूजीसी के अधिदेश में शामिल हैं:
  - विश्वविद्यालय शिक्षा को बढ़ावा देना और समन्वय करना।
  - विश्वविद्यालयों में शिक्षण, परीक्षा और शोध के मानकों को निर्धारित करना और बनाए रखना।
  - शिक्षा के न्यूनतम मानकों पर नियम बनाना।
  - कॉलेजिएट और विश्वविद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में विकास की निगरानी करना; विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों आदि को अनुदान वितरित करना।

Source: The Hindu

राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (NMC)

संदर्भ: भारत के राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) को 10 वर्षों के कार्यकाल के लिए प्रतिष्ठित वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेडिकल एजुकेशन (World Federation for Medical Education-WFME) मान्यता दर्जा से सम्मानित किया गया है।

परिचय:

- राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम, 2019 के तहत वैधानिक निकाय है।
- मुख्यालय: नई दिल्ली
- इसने भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956 के तहत गठित मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया (एमसीआई) का स्थान लिया है।
- मंत्रालय: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

- **कार्य:**
  - NMC चिकित्सा शिक्षा और चिकित्सा पेशेवरों को नियंत्रित करता है।
  - आयोग चिकित्सा योग्यताओं को मान्यता देता है, मेडिकल स्कूलों को मान्यता देता है, मेडिकल प्रैक्टिशनरों को पंजीकरण प्रदान करता है, चिकित्सा पद्धति की निगरानी करता है और भारत में चिकित्सा बुनियादी ढांचे का आकलन करता है।
- सदस्य: इसमें अध्यक्ष (केवल चिकित्सा पेशेवर), 10 पदेन सदस्य और 22 अंशकालिक सदस्यों सहित 33 सदस्य होते हैं।
- NMC के अंतर्गत चार स्वायत्त बोर्ड:
  - अंडर-ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन बोर्ड (स्नातक (यूजी) पाठ्यक्रमों के लिए मानदंड निर्धारित करता है),
  - स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा बोर्ड (स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए मानदंड निर्धारित करता है),
  - मेडिकल मूल्यांकन और रेटिंग बोर्ड (मेडिकल शिक्षा संस्थानों का निरीक्षण और मूल्यांकन करता है), और
  - नैतिकता और चिकित्सा पंजीकरण बोर्ड (डॉक्टरों के पेशेवर आचरण को नियंत्रित और उन्हें पंजीकृत करता है)।

वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेडिकल एजुकेशन (WFME) के बारे में:

- स्थापना : वर्ष 1972 में
- मुख्यालय: फ़र्नी-वोल्टेयर, फ्रांस
- लक्ष्य: यह मेडिकल डॉक्टरों की शिक्षा और प्रशिक्षण से संबंधित एक वैश्विक संगठन है।
- उद्देश्य: यह वह संगठन है जो विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के समक्ष आधिकारिक तौर पर और विश्व स्तर पर चिकित्सा शिक्षकों और चिकित्सा शिक्षण संस्थानों का प्रतिनिधित्व करता है।
- WFME का मान्यता कार्यक्रम यह सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कि चिकित्सा संस्थान शिक्षा और प्रशिक्षण के उच्चतम अंतरराष्ट्रीय मानकों को पूरा करते हैं और बनाए रखते हैं।

Source: AIR

अंतरराष्ट्रीय संबंध

20वां आसियान-भारत शिखर सम्मेलन

संदर्भ: प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी आसियान-भारत शिखर सम्मेलन और पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए इंडोनेशिया की दो दिवसीय यात्रा पर जाएंगे।

20वें आसियान-भारत शिखर सम्मेलन के बारे में:-

- मेज़बान: इंडोनेशिया
- स्थान: जकार्ता, इंडोनेशिया
- महत्व: पिछले वर्ष भारत-आसियान संबंधों के व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक पहुंचने के बाद यह पहला शिखर सम्मेलन होगा। (भारत-आसियान संबंध)
- यह भारत-आसियान संबंधों की प्रगति की समीक्षा करेगा और सहयोग की भविष्य की दिशा तय करेगा।

पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन के बारे में:-

- स्थापना: वर्ष 2005 में (पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन)
- पहला शिखर सम्मेलन: कुआलालंपुर, मलेशिया
- दिनांक: 14 दिसंबर 2005
- 18वाँ शिखर सम्मेलन: जकार्ता, इंडोनेशिया
- यह भारत-प्रशांत क्षेत्र के सामने आने वाली प्रमुख राजनीतिक, सुरक्षा और आर्थिक चुनौतियों पर रणनीतिक बातचीत और सहयोग के लिए 18 क्षेत्रीय नेताओं का एक प्लेटफॉर्म है।
- करीबी क्षेत्रीय सहयोग को आगे बढ़ाने में इस मंच की महत्वपूर्ण भूमिका है।
- 18वां पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन आसियान देशों के नेताओं और भारत सहित इसके आठ संवाद भागीदारों को क्षेत्रीय और वैश्विक महत्व के मुद्दों पर विचारों का आदान-प्रदान करने का अवसर प्रदान करेगा।

अवश्य पढ़ें: भारत-आसियान सम्मेलन

SOURCE: AIR

अफ्रीका जलवायु शिखर सम्मेलन 2023

संदर्भ: हाल ही में अफ्रीका जलवायु शिखर सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किया गया।

पृष्ठभूमि:-

- कम कार्बन पदचिह्न होने के बावजूद, अफ्रीका जलवायु परिवर्तन के मानव प्रभाव को असमान रूप से सहन करता है।
- इस प्रकार, क्षेत्रीय और वैश्विक कार्रवाई की तत्काल आवश्यकता पर प्रकाश डालते हुए, राष्ट्रपति विलियम रुटो ने 4 सितंबर, 2023 को नैरोबी, केन्या में अफ्रीका जलवायु शिखर सम्मेलन, 2023 (ACW23) का उद्घाटन करते हुए हमें याद दिलाया।

अफ्रीका जलवायु शिखर सम्मेलन 2023 के बारे में:-

- दिनांक: 4 से 6 सितंबर 2023
- स्थान: नैरोबी, केन्या। (अफ्रीका)
- शिखर सम्मेलन का उद्देश्य विश्व स्तर पर और विशेष रूप से अफ्रीका में जलवायु परिवर्तन और उससे जुड़ी लागतों के बढ़ते जोखिम को संबोधित करना है।
- अफ्रीका जलवायु शिखर सम्मेलन में, नेताओं को महत्वाकांक्षी प्रतिज्ञाएँ और प्रतिबद्धताएँ करने के लिए बुलाया जाएगा।
- इन कार्यों का मार्गदर्शन करने के लिए एक व्यापक "प्रतिज्ञा और प्रतिबद्धता ढांचा" विकसित किया जाएगा।
- शिखर सम्मेलन के नतीजे अफ्रीकी महाद्वीप के लिए आम सहमति पर पहुंचने और दुबई (संयुक्त अरब अमीरात) में आयोजित होने वाले जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के आगामी 28वें कॉन्फ्रेंस ऑफ़ पार्टीज़ (COP28) के लिए कार्रवाई जुटाने के लिए महत्वपूर्ण हैं।

थीम और फोकस क्षेत्र:-

- जलवायु कार्रवाई वित्तपोषण।
- अफ्रीका के लिए हरित विकास एजेंडा।
- जलवायु कार्रवाई और आर्थिक विकास।
- वैश्विक पूंजी अनुकूलन।

MUST READ:27th COP of UNFCCC

SOURCE: DOWN TO EARTH

आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (OECD)

संदर्भ: आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (ओईसीडी) के महासचिव माथियास कॉर्मन हाल ही में G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए नई दिल्ली पहुंचे।

पृष्ठभूमि:-

- यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष चार्ल्स मिशेल भी G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने पहुंचे।

आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (ओईसीडी) के बारे में:-

- स्थापना: वर्ष 1960 में
- मुख्यालय: पेरिस, फ्रांस
- उद्देश्य: ऐसी नीतियों को आकार देना जो सभी के लिए समृद्धि, समानता, अवसर और कल्याण को बढ़ावा देती है।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि:-

- OECD का अग्रदूत यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन (OEEC) था।
- OEEC का गठन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप के पुनर्निर्माण के लिए मार्शल योजना के तहत अमेरिकी और कनाडाई सहायता को प्रशासित करने के लिए किया गया था।
- OEEC को OECD में बदलने वाले कन्वेंशन पर 1960 में पेरिस में हस्ताक्षर किए गए और 1961 में लागू हुआ।

OECD के सदस्य:-

- इसमें वर्तमान में 38 सदस्य देश हैं और प्रत्येक सदस्य देश का प्रतिनिधित्व उनके राजदूतों के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल द्वारा किया जाता है।
- 38 सदस्य देशों में ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, कनाडा, चिली, कोलंबिया, कोस्टा रिका, चेक गणराज्य, डेनमार्क, एस्टोनिया, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, हंगरी, आइसलैंड, आयरलैंड, इज़राइल, इटली, जापान, दक्षिण कोरिया, लातविया, लिथुआनिया, लक्ज़मबर्ग, मैक्सिको, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, पोलैंड, पुर्तगाल, स्लोवाक गणराज्य, स्लोवेनिया, स्पेन, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल हैं।
- भारत ओईसीडी के साथ कामकाजी संबंधों वाला एक गैर-सदस्यीय अर्थव्यवस्था है।

OECD के कार्य:-

- यह दुनिया भर में आर्थिक विकास के दृष्टिकोण पर आर्थिक रिपोर्ट, सांख्यिकीय डेटाबेस, विश्लेषण और पूर्वानुमान प्रकाशित करने के लिए जिम्मेदार है। (OECD/G20 समावेशी फ्रेमवर्क टैक्स डील)
- यह समूह आर्थिक विकास पर सामाजिक मुद्दों के प्रभाव का विश्लेषण करता है और सिफारिशें करता है।
- यह दुनिया भर में रिश्वतखोरी और अन्य प्रकार के वित्तीय अपराधों को खत्म करने का प्रयास करता है।
- इसका उद्देश्य दुनिया भर में रिश्वतखोरी और अन्य वित्तीय अपराधों को खत्म करना है।
- यह उन राष्ट्रों की "ब्लैक लिस्ट" भी रखता है जिन्हें असहयोगी टैक्स हेवेन माना जाता है।

रिपोर्ट:-

- ओईसीडी आर्थिक आउटलुक
- ओईसीडी संचार आउटलुक
- ओईसीडी इंटरनेट इकोनॉमी आउटलुक

MUST READ: Digital taxation & OECD: On a weak pillar

SOURCE: AIR

G20 नई दिल्ली घोषणा

संदर्भ: ग्रुप ऑफ़ ट्वेंटी (G20) ने हाल ही में नई दिल्ली G20 लीडर्स घोषणा पत्र को अपनाया।

पृष्ठभूमि:-

- नई दिल्ली लीडर्स घोषणा पत्र को 9 सितंबर, 2023 को अपनाया गया था।
- जलवायु परिवर्तन सहित पर्यावरणीय संकटों और चुनौतियों से निपटने के लिए देश अपने कार्यों में तेजी लाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

नई दिल्ली जी20 लीडर्स घोषणा के बारे में:-

- नई दिल्ली लीडर्स की घोषणा को कई मुद्दों पर सर्वसम्मति से अपनाया गया।
- इनमें सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी), जलवायु वित्त, ऊर्जा परिवर्तन, प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र का उपयोग और बहाल करना, महासागर आधारित अर्थव्यवस्था का दोहन और संरक्षण, प्लास्टिक प्रदूषण, आपदा जोखिम को कम करना और लचीला बुनियादी ढांचे का निर्माण शामिल है। (एसडीजी भारत)
- सतत भविष्य के लिए हरित विकास संधि के तहत घोषणा में, देशों ने "जलवायु परिवर्तन सहित पर्यावरणीय संकटों और चुनौतियों का समाधान करने के लिए कार्यों में तत्काल तेजी लाने" की प्रतिबद्धता जताई है।
- **पेरिस समझौता:** इस घोषणा का एक उद्देश्य "पेरिस समझौते और उसके तापमान लक्ष्य के पूर्ण और प्रभावी कार्यान्वयन को मजबूत करके जलवायु परिवर्तन से निपटना है।
- यह समानता और सामान्य लेकिन विभेदित जिम्मेदारियों और संबंधित क्षमताओं (CBDR) के सिद्धांत को दर्शाता है।
- CBDR के सिद्धांतों को शामिल करना दिलचस्प है क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे कुछ विकसित जी20 देश इसके उपयोग के खिलाफ रहे हैं।
- G20 सदस्यों ने जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल (आईपीसीसी) की छठी मूल्यांकन संश्लेषण रिपोर्ट के निष्कर्षों का भी हवाला दिया।
- इसमें कहा गया है कि वैश्विक ग्रीनहाउस गैस (जीएचजी) उत्सर्जन 2020 के बीच और वैश्विक मॉडल वाले मार्गों में 2025 से पहले चरम पर पहुंचने का अनुमान है, जो बिना किसी या सीमित ओवरशूट के वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करता है। और उनमें जो तापमान को 2°C तक सीमित करते हैं और तत्काल कार्रवाई करते हैं। (जलवायु परिवर्तन को कम करना)
- G20 सदस्यों ने जलवायु परिवर्तन और संक्रमण मार्गों से उत्पन्न व्यापक आर्थिक जोखिमों पर भी प्रकाश डाला।
- G20 देशों ने भारत की अध्यक्षता में आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह के संस्थागतकरण पर भी ध्यान किया, जिसने आपदा जोखिम न्यूनीकरण की दिशा में प्रयासों को उत्प्रेरित किया।
- दस्तावेज़ राष्ट्रीय और स्थानीय क्षमताओं, नवीन वित्तपोषण उपकरणों, निजी क्षेत्र के निवेश और ज्ञान साझाकरण को मजबूत करने के माध्यम से शुरुआती चेतावनी और शीघ्र कार्रवाई पर प्रगति में तेजी लाने की भी चर्चा करता है।
- सदस्यों ने "इस तरह के सहयोग और साझाकरण को आगे बढ़ाने" में संयुक्त राष्ट्र की पहल जैसे डीआरआर के लिए वैश्विक मंच और आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे के लिए गठबंधन का समर्थन किया।

अवश्य पढ़ें: भारत और G20 प्रेसीडेंसी

SOURCE: DOWN TO EARTH

एशिया प्रशांत क्षेत्र के राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों का सम्मेलन

संदर्भ: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में नई दिल्ली में एशिया प्रशांत क्षेत्र के राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों के सम्मेलन का उद्घाटन किया।

परिचय:-

- **मेजबानी:** राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी), भारत
- **दिनांक:** 20 - 21, सितंबर, 2023
- **स्थान:** विज्ञान भवन, नई दिल्ली
- यह दो दिवसीय सम्मेलन मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा की 75वीं वर्षगांठ और राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों और पेरिस सिद्धांतों के 30 साल पूरे होने की खुशी मनाएगा।

- पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन पर एक उप-विषय भी आयोजित किया गया।
- इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग व्यवसाय और मानवाधिकार पर एक सेमिनार का आयोजन करेगा।
- इस आयोजन का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि व्यवसाय अपने संचालन में मानवाधिकारों और पर्यावरणीय स्थिरता को प्राथमिकता दें।
- यह एशिया प्रशांत के राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों (एनएचआरआई) का द्विवार्षिक सम्मेलन है।
- इससे पहले 2002 और 2014 में एशिया पैसिफिक फोरम की ऐसी AGM और कॉन्फ्रेंस भारत में आयोजित की गई थी।

एशिया प्रशांत फोरम के बारे में:-

- **स्थापित:** वर्ष 1996 में
- एशिया प्रशांत फोरम की स्थापना एशिया प्रशांत क्षेत्र में स्वतंत्र एनएचआरआई की स्थापना को बढ़ावा देने और मानवाधिकारों को यथासंभव प्रभावी ढंग से बढ़ावा देने और उनकी रक्षा एवं उनके काम में सहायता करने के लिए की गई थी।
- **उद्देश्य:** एशिया प्रशांत क्षेत्र में स्वतंत्र एनएचआरआई की स्थापना को बढ़ावा देना और हमारे सदस्यों को अपना काम यथासंभव प्रभावी ढंग से करने में सहायता करना।

सदस्यता:-

- पांच संस्थापक सदस्यों से, एपीएफ सदस्यता का विस्तार 26 एनएचआरआई तक हो गया है।
- एनएचआरसी, भारत एनएचआरआई के एशिया प्रशांत फोरम के संस्थापक सदस्यों में से एक है।
- राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों के गठबंधन के रूप में, यह अपने दृष्टिकोण को वास्तविकता बनाने में मदद करने के लिए एक साथ कार्य करता है और विशेषज्ञता साझा करता है।
- यह सरकारों, नागरिक समाज संगठनों, क्षेत्रीय मानवाधिकार निकायों और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ मिलकर काम करता है।
- इसका उद्देश्य मजबूत साझेदारी बनाना और हमारे सदस्यों के प्रभाव को मजबूत करना है क्योंकि वे निष्पक्ष, समावेशी और लचीले समुदायों के निर्माण के लिए काम करते हैं।
- इसका नेटवर्क अब 4,000 से अधिक समर्पित मानवाधिकार रक्षकों का समर्थन करता है जो सबसे कमजोर लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए ग्राउंड लेवल पर अथक प्रयास करते हैं।
- महत्व: इसने एक मजबूत और एकजुट मंच बनाया है जो हमारे क्षेत्र में कुछ सबसे गंभीर मानवाधिकार चुनौतियों का समाधान करने के लिए एशिया प्रशांत के सभी कोनों से राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों (एनएचआरआई) को एक साथ लाता है।

अवश्य पढ़ें: मानवाधिकार आयोगों को और सशक्त बनाना

SOURCE: AIR

भारत-कनाडा संबंध

संदर्भ: हाल ही में खालिस्तान समर्थक नेता और एक कनाडाई नागरिक हरदीप सिंह निज्जर की हत्या ने भारत-कनाडा संबंधों में राजनयिक चुनौतियों का कारण बना दिया है।

मुद्दे की पृष्ठभूमि:-

- खालिस्तान टाइगर फोर्स के प्रमुख हरदीप सिंह निज्जर को हाल ही के दिनों में कनाडा के सरे में गुरुद्वारा साहिब परिसर में गोली मार कर हत्या कर दी गई। हरदीप सिंह निज्जर को भारत सरकार ने 'वांछित आतंकवादी' घोषित किया था।
- कनाडा के प्रधान मंत्री जस्टिन ट्रूडो ने हाल ही में भारत सरकार के एजेंटों और खालिस्तान समर्थक नेता और कनाडाई नागरिक हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बीच "संभावित संबंध" के एक्सप्लोसिव (खतरनाक) आरोप लगाए।
    - हरदीप सिंह निज्जर का नाम 2018 में कनाडा के प्रधान मंत्री जस्टिन ट्रूडो की भारत यात्रा के दौरान पंजाब के तत्कालीन सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह द्वारा सौंपी गई वांछित सूची में शामिल किया गया था।
- 1980 के दशक से लेकर ट्रूडो के कार्यकाल के आखिरी आठ वर्षों तक, खालिस्तान मुद्दे ने हमेशा द्विपक्षीय संबंधों को प्रभावित किया है।
- लेकिन इस बार, ओटावा ने कार्रवाई तेज कर दी है और नई दिल्ली द्विपक्षीय संबंधों की जटिलता और वैश्विक मंच पर प्रतिष्ठा की कीमत को ध्यान में रखते हुए स्थिति पर नजर रख रही है।

भारत-कनाडा संबंधों के बारे में:-

- भारत और कनाडा के बीच साझा लोकतांत्रिक मूल्यों, बहु-सांस्कृतिक, बहु-जातीय और बहु-धार्मिक प्रकृति पर आधारित दीर्घकालिक

द्विपक्षीय संबंध हैं।

- वर्ष 1947: भारत ने 1947 में कनाडा के साथ राजनयिक संबंध स्थापित किये।
- वर्ष 1951: भारत के लिए कनाडा का सहायता कार्यक्रम 1951 में शुरू हुआ और कोलंबो योजना के तहत इसमें काफी वृद्धि हुई।
    - कनाडा ने भारत को खाद्य सहायता, परियोजना वित्तपोषण और तकनीकी सहायता प्रदान की।
- वर्ष 1974: भारत के स्माइलिंग बुद्धा परमाणु परीक्षण के कारण भारत-कनाडा संबंधों में गिरावट आई।
- वर्ष 1976: कनाडाई सरकार ने 1976 में भारत और पाकिस्तान दोनों के साथ द्विपक्षीय परमाणु सहयोग को इस दावे के बाद तोड़ दिया कि भारत के पहले परमाणु उपकरण के निर्माण के लिए उपयोग की जाने वाली विखंडन योग्य सामग्री कनाडा द्वारा आपूर्ति किए गए CIRUS परमाणु अनुसंधान रिएक्टर से प्राप्त की गई थी।
- वर्ष 1985: एयर इंडिया फ्लाइट 182 पर सिख अलगाववादियों द्वारा बमबारी के परिणामस्वरूप कनाडा और भारत ने आतंकवाद विरोधी द्विपक्षीय वार्ता जारी रखी।
- वर्ष 2015: अप्रैल 2015 में भारत के प्रधान मंत्री की कनाडा यात्रा ने द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ा दिया।
- हाल के वर्षों में, दोनों देश आपसी महत्व के कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं।

महत्व:-

- कनाडा दुनिया के सबसे बड़े भारतीय प्रवासियों में से एक की मेजबानी करता है, जिसमें भारतीय मूल के लोगों की संख्या 16 लाख है।
- यह कनाडा की कुल आबादी का 3 प्रतिशत से अधिक और 700,000 एनआरआई का हिस्सा है।
- मंत्रिस्तरीय स्तर पर, कनाडा और भारत विदेश नीति, व्यापार और निवेश, वित्त और ऊर्जा पर मंत्रिस्तरीय संवादों के आधार पर एक रणनीतिक साझेदारी का आनंद लेते हैं।
- आधिकारिक स्तर पर, नियमित कार्य समूह होते हैं जो आतंकवाद-निरोध, सुरक्षा, कृषि, शिक्षा, विज्ञान, प्रौद्योगिकी आदि पर ध्यान केंद्रित करते हैं।

व्यापारिक संबंध

- वर्ष 2021 में, भारत कनाडा का 14वां सबसे बड़ा निर्यात बाजार और कुल मिलाकर 13वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार था।
- वर्ष 2022 के आंकड़ों के अनुसार, कनाडा में पढ़ने वाले 2.3 लाख विदेशी छात्रों में भारत शीर्ष स्रोत बन गया है।
- भारत एक प्रमुख भागीदार है क्योंकि कनाडा क्षेत्र के लिए एक नई, व्यापक रणनीति के तहत इंडो-पैसिफिक में अपने आर्थिक संबंधों को मजबूत कर रहा है।

भारत-कनाडा संबंधों में चुनौतियाँ:-

- सिख उग्रवाद और कनाडा में सिख अलगाववादी समूहों की उपस्थिति।
- खालिस्तान आंदोलन के पुनरुद्धार को लेकर चिंता।
- कनाडा की राजनीति पर सिख प्रवासी का प्रभाव
- व्यापार के लिए बाधाएँ: भारत के जटिल श्रम कानून; बाज़ार संरक्षणवाद; नौकरशाही नियम।

सहयोग के क्षेत्र:-

- राजनीतिक रूप से, भारत और कनाडा संसदीय संरचना और प्रक्रियाओं में समानताएं साझा करते हैं।
- व्यावसायिक: भारत और कनाडा के बीच द्विपक्षीय व्यापार 2020 में 6.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक रहा। व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते (सीईपीए) के लिए बातचीत चल रही है।
- परमाणु सहयोग: परमाणु सहयोग समझौते (एनसीए) पर 2010 में नागरिक परमाणु सहयोग, परमाणु सहयोग की बहाली पर संयुक्त समिति द्वारा हस्ताक्षर किए गए।
- सुरक्षा और रक्षा सहयोग: अंतरराष्ट्रीय मंचों पर, आपसी जहाज यात्राएं, 2018 में आतंकवाद का मुकाबला करने पर भारत और कनाडा के बीच सहयोग की रूपरेखा आदि शामिल है।
- लोगों से लोगों के बीच संबंध
- सांस्कृतिक आदान-प्रदान
- कोविड-19 महामारी के दौरान सहयोग। (कोविड-19 की दूसरी लहर)

अवश्य पढ़ें: भारत और G20 प्रेसीडेंसी

SOURCE: THE INDIAN EXPRESS

G4 देश

संदर्भ: हाल ही में G4 देशों ने दोहराया है कि निकाय को अधिक प्रतिनिधिक, वैध, प्रभावी और कुशल बनाने के लिए स्थायी और गैर-स्थायी दोनों श्रेणियों में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का विस्तार आवश्यक है।

परिचय :

- G4 ब्राज़ील, जर्मनी, भारत और जापान का एक समूह है जो UNSC का स्थायी सदस्य बनने के इच्छुक हैं।
- ये UNSC की स्थायी सदस्यता के लिए एक-दूसरे की बोली का समर्थन कर रहे हैं।
- G4 राष्ट्र पारंपरिक रूप से वार्षिक उच्च स्तरीय संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र के मौके पर मिलते हैं।

G4 का विपक्ष: कॉफ़ी क्लब

- यूनाइटिंग फॉर कंसेंसस (यूएफसी), या कॉफी क्लब, 1990 के दशक में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सीटों के संभावित विस्तार के विरोध में उभरा।
- UNSC में स्थायी सीटों की संख्या बढ़ाने के प्रस्ताव को अस्वीकार करने के लिए इटली ने पाकिस्तान, मैक्सिको और मिस्र के साथ मिलकर 1995 में कॉफ़ी क्लब की स्थापना की।

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के बारे में:

- **स्थापित:** वर्ष 1945 में संयुक्त राष्ट्र चार्टर द्वारा
- **मुख्यालय:** न्यूयॉर्क शहर, यूएसए
- **सदस्य:** 15 सदस्य
- वीटो शक्ति वाले स्थायी सदस्य (P5 सदस्य): संयुक्त राज्य अमेरिका, रूसी संघ, फ्रांस, चीन और यूनाइटेड किंगडम।
- अस्थायी सदस्य: सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य दो वर्ष की अवधि के लिए चुने जाते हैं।
- 10 गैर-स्थायी सीटें क्षेत्रीय आधार पर निम्नानुसार वितरित की जाती हैं:
  - अफ्रीकी और एशियाई राज्यों के लिए पाँच।
  - पूर्वी यूरोपीय राज्यों के लिए (A)
  - लैटिन अमेरिकी और कैरेबियाई राज्यों के लिए दो;
  - पश्चिमी यूरोपीय और अन्य राज्यों के लिए दो

Source: AIR

फाइव आइज़ एलायंस

संदर्भ: हाल ही में कनाडा में अमेरिकी राजदूत ने दावा किया है कि "फाइव आईज साझेदारों के बीच साझा खुफिया जानकारी" ने कनाडा के प्रधान मंत्री को खालिस्तान अलगाववादी की हत्या में भारतीय एजेंटों की संभावित संलिप्तता के बारे में सूचित किया था।

परिचय :

- **स्थापित:** द्वितीय विश्व युद्ध के बाद
- **सदस्य देश:** ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका।
- "फाइव आइज़" शब्द आम सुरक्षा खतरों और चुनौतियों से निपटने के लिए सिग्नल इंटेलिजेंस (SIGINT) इकट्ठा और साझा करने के पांच देशों के सामूहिक प्रयासों को संदर्भित करता है।
- उद्देश्य:
  - **इंटेलिजेंस शेयरिंग:** गठबंधन के सदस्य वैश्विक सुरक्षा खतरों के बारे में अपनी सामूहिक समझ को बढ़ाने के लिए सिग्नल इंटेलिजेंस को साझा करने के लिए सहयोग करते हैं, जिसमें इंटरसेप्टेड संचार और इलेक्ट्रॉनिक डेटा शामिल हैं।
  - **आतंकवाद विरोधी और राष्ट्रीय सुरक्षा:** फाइव आइज़ नेटवर्क महत्वपूर्ण खुफिया जानकारी का आदान-प्रदान करके और संयुक्त अभियानों में सहयोग करके आतंकवाद का मुकाबला करने और अन्य राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं को संबोधित करने पर ध्यान केंद्रित करता है।
  - **साइबर सुरक्षा और खतरे:** साइबर खतरों के बढ़ते महत्व को देखते हुए, गठबंधन प्रतिकूल देशों और गैर-राज्य अभिनेताओं

की साइबर गतिविधियों की निगरानी और समाधान करने के लिए मिलकर काम करता है।

- **सूचना और प्रौद्योगिकी साझा करना:** फाइव आइज़ साझेदार खुफिया जानकारी एकत्र करने, विश्लेषण और क्रिप्टोग्राफी के क्षेत्र में विशेषज्ञता और तकनीकी प्रगति साझा करते हैं।

Source: Indian Express

भारत और फ़िनलैंड

संदर्भ: भारत और फ़िनलैंड ने हाल ही में गतिशील क्षेत्र के लिए मानव संसाधन के विकास सहित दूरसंचार के कई क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच सहयोग पर सहमति व्यक्त की है।

भारत और फिनलैंड के बारे में:-

- फिनलैंड और भारत के बीच पारंपरिक रूप से मधुर और मैत्रीपूर्ण संबंध रहे हैं।
- हाल के वर्षों में, दोनों पक्षों द्वारा अनुसंधान, नवाचार और निवेश में सहयोग से द्विपक्षीय संबंधों में विविधता आई है।
- वर्ष 2019 में दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों के 70 साल पूरे हो गए।

आर्थिक सहयोग:-

- फिनलैंड भारत को अपने उत्पादों के लिए एक बाजार और अपने उच्च-प्रौद्योगिकी उद्योगों के लिए एक अनुकूल निवेश गंतव्य के रूप में देखता है।
- भारत फिनलैंड को यूरोपीय संघ के एक महत्वपूर्ण सदस्य और आधुनिक प्रौद्योगिकी के भंडार के रूप में देखता है।

एस एंड टी सहयोग:-

- नवाचार नीतियों के विकास, सूचना और वैज्ञानिकों के आदान-प्रदान और अनुसंधान एवं विकास सहयोग के लिए फरवरी 2008 में एस एंड टी में सहयोग के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे।
- भारत और फिनलैंड दोनों अंटार्कटिक संधि के सलाहकार सदस्य हैं और अंटार्कटिका में उनके सक्रिय स्टेशन हैं।
- फिनलैंड 2023 में और भारत 2024 में अंटार्कटिक संधि परामर्श बैठक (एटीसीएम) की मेजबानी करेगा।
- भारत मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department-IMD) और फिनिश मौसम विज्ञान संस्थान (Finnish Meteorological Institute-FMI) 2014 से वायुमंडलीय पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग कर रहे हैं।

सांस्कृतिक संबंध:-

- भारतीय संस्कृति और योग फिनलैंड में बहुत लोकप्रिय हैं।
- भारतीय नृत्य और संगीत को बढ़ावा देने वाले भारतीय संघों और अन्य सांस्कृतिक संगठनों द्वारा नियमित रूप से सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।

पर्यावरण संबंध:-

- क्षमता निर्माण सहित वायु गुणवत्ता में फिनिश मौसम विज्ञान संस्थान (एफएमआई), भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) और ऊर्जा एवं संसाधन संस्थान (टीईआरआई) के बीच 2004 से सफल साझेदारी हुई है।

शिक्षा में सहयोग:-

- फिनलैंड शिक्षा के क्षेत्र में कई मापदंडों पर लगातार स्कोर करने वाला वैश्विक नेता है।
- प्रारंभिक बाल्यावस्था और K-12 शिक्षा में सर्वोत्तम प्रथाओं के आदान-प्रदान के लिए निजी कंपनियों के बीच गठजोड़ किया गया है।

- उच्च शिक्षा क्षेत्र में सहयोग के लिए 2020-2025 की अवधि के लिए 10 फिनिश विश्वविद्यालयों और 23 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (आईआईटी) के एक संघ के बीच एक समझौता ज्ञापन है।

अवश्य पढ़ें: भारत में विदेशी विश्वविद्यालय

SOURCE: AIR

भूगोल

धूमकेतु निशिमुरा

संदर्भ: हाल की रिपोर्टों से पता चलता है कि धूमकेतु निशिमुरा सितंबर में दिखाई दे सकता है।

धूमकेतु निशिमुरा के बारे में:-

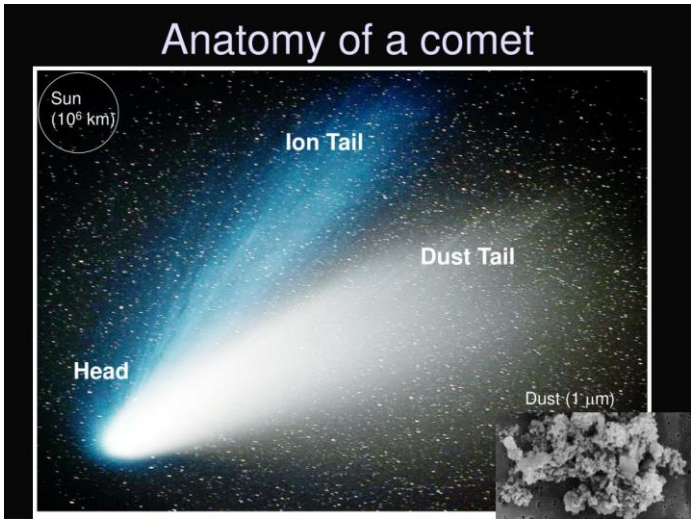

- खोजा गया: 11 अगस्त, 2023।
- खोजकर्ता: हिदेओ निशिमुरा। (बर्नार्डिनेली-बर्नस्टीन धूमकेतु)
- इसे एक मानक डिजिटल कैमरे के साथ 30 सेकंड के एक्सपोज़र के दौरान खोजा गया था।
- धूमकेतु निशिमुरा की छवि जून लेक, कैलिफ़ोर्निया, संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई थी।
    - धूमकेतु: धूमकेतु जमी हुई गैसों, धूल और चट्टानों से बने आकाशीय पिंड हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं।
    - ये प्रारंभिक सौर मंडल से उत्पन्न होते हैं और जब ये सूर्य के नजदीक आते हैं तो गैस और धूल के निकलने के कारण इनकी पूंछ विकसित हो जाती है।
    - ये पूँछें उन्हें पृथ्वी से दृश्यमान बनाती हैं।
- इसे ग्रीन कोमा और पतली पूंछ के साथ चित्रित किया गया था।
- इसके 1.8 की तीव्रता तक चमकने की उम्मीद है।
- इसका हमसे निकटतम आगमन 12 सितंबर को होगा और इसका पेरिहेलियन 17/18 सितंबर को होगा।
- धूमकेतु वर्तमान में सिंह राशि में स्थित है।
    - सिंह तारामंडल: रात के आकाश में एक प्रमुख तारामंडल, जिसे सिंह के आकार द्वारा दर्शाया गया है।
    - यह राशि चक्र नक्षत्रों में से एक है और इसमें विभिन्न तारे और खगोलीय पिंड शामिल हैं।
    - तारामंडल सूर्योदय से लगभग 90 मिनट पहले पूर्व-उत्तरपूर्वी क्षितिज की ओर दिखाई देता है।
- जैसे-जैसे धूमकेतु सूर्य के करीब आ रहा है, विजिटर भी क्षितिज के करीब आ रहा है, इस प्रकार इस सप्ताह के बाद इसका निरीक्षण करना और अधिक कठिन हो गया है।
- अपनी खोज के बाद से, C/2023 P1 निशिमुरा की चमक बढ़ गई है और आंतरिक सौर मंडल में इसका मार्ग निर्धारित हो गया है।
- जैसे-जैसे धूमकेतु सूर्य की ओर गोता लगाएगा, यह निश्चित रूप से तीव्र होता जाएगा और संभवतः सितंबर की शुरुआत में खुली आंखों वाली वस्तु बन जाएगा।
- धूमकेतु सूर्य के निकट भी कोणीय रूप से होगा, इसलिए इसे केवल सूर्यास्त या सूर्योदय के निकट ही देखना संभव होगा।

अवश्य पढ़ें: एक्सोप्लैनेट

SOURCE: THE INDIAN EXPRESS

उत्तरी समुद्री मार्ग

संदर्भ: भारत और रूस हाल के दिनों में उत्तरी समुद्री मार्ग और पूर्वी समुद्री गलियारे के इस्तेमाल की खोज कर रहे हैं।

पृष्ठभूमि:-

- भारत और रूस ने उत्तरी समुद्री मार्ग (एनएसआर) जैसे नए परिवहन गलियारों की खोज की संभावना पर चर्चा की।
- दोनों पक्ष इस बात पर भी सहमत हुए कि भारतीय नाविकों को व्लादिवोस्तोक में रूसी समुद्री प्रशिक्षण संस्थान में ध्रुवीय और आर्कटिक जल पर प्रशिक्षित किया जाएगा, जो सिमुलेटर से सुसज्जित है।
- भारत बढ़ी हुई कनेक्टिविटी और व्यापार की क्षमता को पहचानते हुए एनएसआर के विकास के संबंध में साझेदारी पर सहयोग करने का इच्छुक है।

उत्तरी समुद्री मार्ग के बारे में:-

- आर्कटिक महासागर के पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्र उत्तरी समुद्री मार्ग (एनएसआर) के माध्यम से जुड़े हुए हैं, जिन्हें कभी-कभी पूर्वोत्तर मार्ग (एनईपी) के रूप में भी जाना जाता है।
- यह यूरोप और एशिया-प्रशांत क्षेत्र को जोड़ने वाला सबसे छोटा शिपिंग मार्ग है।
- यूरोप और एशिया के बीच का मार्ग केवल 13,000 किमी लंबा है, जबकि स्वेज नहर मार्ग 21,000 किमी लंबा है, जो यात्रा की अवधि को एक महीने से घटाकर दो सप्ताह से भी कम कर देता है।
- यह आर्कटिक महासागर के चार समुद्रों से होकर गुजरता है।
- यह मार्ग बैरेंट्स और कारा समुद्र (कारा जलडमरूमध्य) के बीच की सीमा से शुरू होता है और बेरिंग जलडमरूमध्य (प्रोविडेनिया खाड़ी) पर समाप्त होता है।

लाभ :-

- स्वेज या पनामा के माध्यम से मौजूदा शिपिंग लेन की तुलना में एनएसआर 50% तक की संभावित दूरी बचत प्रदान करता है।
- इस क्षेत्र में तेल और गैस के मौजूदा वैश्विक भंडार का 40 प्रतिशत से अधिक हिस्सा हो सकता है।
- कोयला, जस्ता और चांदी के भी महत्वपूर्ण भंडार हो सकते हैं।

एनएसआर विकास में भारत के लाभ:-

- बढ़ता कार्गो यातायात: 2018-2022 के दौरान एनएसआर कार्गो यातायात में लगभग 73% की वृद्धि हुई।
- रणनीतिक पारगमन मार्ग: भारत की भौगोलिक स्थिति और समुद्री परिवहन पर निर्भरता एनएसआर को एक महत्वपूर्ण पारगमन मार्ग बनाती है। भारत-रूस संबंध
- भू-राजनीति: भारत एनएसआर पर चीन और रूस के संभावित सामूहिक प्रभाव का पूरक बनना चाहेगा। (भारत-रूस सैन्य गठबंधन)

अवश्य पढ़ें: रूस-यूक्रेन युद्ध

SOURCE: THE HINDU

भोज वेटलैंड

संदर्भ: नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार को भोज वेटलैंड में क्रूज जहाजों के साथ-साथ अन्य मोटर-चालित नौकाओं के संचालन को रोकने का आदेश दिया।

भोज वेटलैंड के बारे में:-

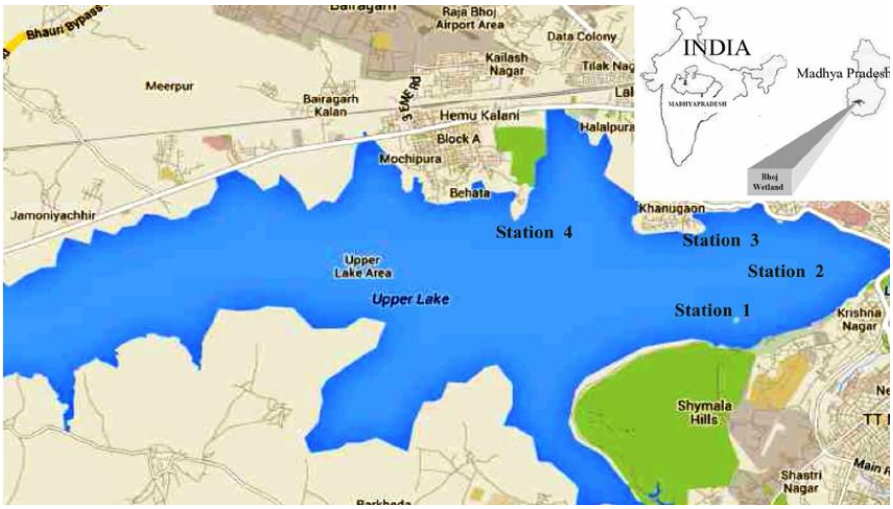

IMAGE SOURCE: ResearchGate

- स्थान: भोपाल, मध्य प्रदेश।
- भोज वेटलैंड में दो सन्निहित मानव निर्मित जलाशय शामिल हैं।
- ऊपरी और निचली झीलें भोपाल शहर में स्थित हैं।
- **ऐतिहासिक पृष्ठभूमि:-**
  - भोज वेटलैंड की कल्पना सबसे पहले दूरदर्शी राजा परमार राजा भोज ने 1005-1055 ई. में की थी।
  - उन्होंने कोलांस पर मिट्टी का बांध बनाकर झील का निर्माण किया।
  - निचली झील का निर्माण बहुत बाद में 1794 में नवाब हयात मोहम्मद खान के मंत्री छोटे खान द्वारा किया गया था।
- भदभदा डैम 1965 में भोजताल के दक्षिण-पूर्व कोने पर बनाया गया था।
- इसे 2002 में रामसर साइट के रूप में नामित किया गया था।

भोज वेटलैंड को खतरा:-

- भोज वेटलैंड को हर तरफ शहरीकरण और मानव बस्तियों से विभिन्न खतरों का सामना करना पड़ रहा है।

अवश्य पढ़ें : आर्द्रभूमि पर रामसर कन्वेंशन का COP14

SOURCE: THE HINDU

हीराकुंड बांध

संदर्भ: ओडिशा सरकार ने हाल ही में हीराकुंड बांध के निर्माण से विस्थापित लोगों के पुनर्वास की योजना की घोषणा की।

पृष्ठभूमि:-

- सात दशक लंबे भूमि विस्थापन मुद्दे के समाधान में झारसुगुड़ा जिले के 19 गांवों के 1,749 परिवारों को 3,231 एकड़ भूमि पर अधिकार दिया जाएगा।

हीराकुंड बांध के बारे में:-

- **उद्घाटन:** वर्ष 1957 में
- **स्थान:** संबलपुर, ओडिशा से 15 किलोमीटर दूर।
- **नदी:** महानदी
- **प्रकार:** यह मिट्टी, कंक्रीट और चिनाई की एक मिश्रित संरचना है। (केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी))
- **स्थापित क्षमता:** 287.8 मेगावाट
- **बांध की ऊंचाई:** 80.96 मीटर

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि:-

- 1937 की भारी बाढ़ के बाद, एर. एम. विश्वेश्वरैया ने महानदी डेल्टा में बाढ़ की समस्या से निपटने के लिए महानदी बेसिन में भंडारण जलाशयों की विस्तृत जांच का प्रस्ताव दिया।
- बहुउद्देश्यीय हीराकुंड बांध परियोजना ओडिशा के तत्कालीन राज्यपाल डॉ. अजोध्या नाथ खोसला की योजना का पहला चरण है।
- बुर्ला पावर हाउस की यूनिट III की कमीशनिंग 1956 में पूरी हुई।
- पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1948 में आधारशिला रखी।
- इस परियोजना का औपचारिक उद्घाटन 13 जनवरी 1957 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था।

उद्देश्य:-

- सिंचाई करना।
- विद्युत उत्पादन करना ।
- बाढ़ नियंत्रण। (राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण)

मुख्य विशेषताएं:-

- हीराकुंड बांध परियोजना बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई और बिजली उत्पादन के लिए एक बहुउद्देशीय योजना है।
- यह भारत की सबसे पुरानी जल विद्युत परियोजनाओं में से एक है।
- यह आजादी के बाद देश की पहली प्रमुख बहुउद्देश्यीय नदी घाटी परियोजना थी।
- यह भारत का सबसे लंबा बांध है।

- डेब्रीगढ़ वन्यजीव अभयारण्य हीराकुंड बांध के पास स्थित है।
    - यह पूर्व और उत्तर में विशाल हीराकुंड जलाशय से घिरा है।

अवश्य पढ़ें: सुन्नी बांध जल विद्युत परियोजना

SOURCE: THE HINDU

काओबल गली-मुश्कोह घाटी

संदर्भ: कारगिल युद्ध का युद्धक्षेत्र काओबल गली-मुश्कोह घाटी को हाल ही में पर्यटकों के लिए खोल दिया गया।

पृष्ठभूमि:-

- वर्ष 1999 में तोपखाने की गोलियों से गूंजने वाली मुश्कोह घाटी इस साल पर्यटन मानचित्र पर है।
- भारत और पाकिस्तान के बीच 43 महीने तक चले युद्धविराम समझौते के कारण यह संभव हो सका।

इसके बारे में:-

- स्थान: कारगिल के द्रास सेक्टर, जम्मू और कश्मीर में।
- यह भारत और पाकिस्तान के बीच 1999 के कारगिल युद्ध के दौरान एक युद्धक्षेत्र था। (कारगिल विजय दिवस)
- इस क्षेत्र में उत्तरी कश्मीर में गुरेज़ घाटी शामिल है, जो पहले पाकिस्तान की ओर से गोलाबारी के कारण नागरिकों के लिए दुर्गम थी, लेकिन अब कारगिल के द्रास सेक्टर में मुश्कोह घाटी से जुड़ती है।

गुरेज़ घाटी:-

- गुरेज़ में 4,167 मीटर की ऊंचाई पर काओबल गली सबसे ऊंचा दर्रा है।
- यह गुरेज़ को मुश्कोह घाटी से जोड़ता है।
- नदी: किशनगंगा नदी इस घाटी से होकर बहती है।
- गुरेज़ घाटी नियंत्रण रेखा (एलओसी) के नजदीक है।
- निवासी: बुर्जिल दर्रे के बहुत करीब स्थित होने के कारण, जो एस्टोर की ओर जाता है, निवासी जातीय डार्ड/शिन हैं।
    - वे शिना भाषा बोलते हैं और उनकी पोशाक और संस्कृति की शैली पाकिस्तानी प्रशासित गिलगित-बाल्टिस्तान में उनके रिश्तेदारों के समान ही है।
    - लगभग 38,000 निवासियों वाली गुरेज़ घाटी इस वर्ष अब तक 50,000 पर्यटकों की मेजबानी करके एक रिकॉर्ड स्थापित कर रही है।
- जीव: आइबेक्स, कस्तूरी मृग, और मर्मोट्स, हिमालयी भूरा भालू, और हिम तेंदुआ।
    - ज़ुम्बा याक (अन्य याक से छोटा) गुरेज घाटी के बुदुआब गांव में पाया जाता है।

मुश्कोह घाटी:-

- स्थान: द्रास (लद्दाख)। (ऑपरेशन सद्भावना)
- इसे जंगली ट्यूलिप की घाटी के नाम से भी जाना जाता है।
- मुश्कोह के घास के मैदानों में जंगली ट्यूलिप के फूल उगते हैं।
- यह घाटी लुप्तप्राय हिमालयी यू (Himalayan yew) का भी घर है।

अवश्य पढ़ें: जम्मू और कश्मीर नेट प्रतिबंधों के लिए न्यायिक उपाय

SOURCE: THE HINDU

इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023

संदर्भ: इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023 हाल ही में जारी की गई।

परिचय :-

- रिलीज़: 27 सितंबर 2023
- द्वारा जारी: अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान और संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष।

रिपोर्ट की मुख्य बातें:-

- हाल के वर्षों में भारत में बुजुर्गों का प्रतिशत तेजी से बढ़ रहा है और यह प्रवृत्ति आने वाले दशकों में भी जारी रहने की संभावना है,
- 2050 तक भारत की कुल आबादी में बुजुर्गों की भागीदारी 20 फीसदी से ज्यादा तक पहुंच सकती है।

- 0-14 वर्ष के बच्चों की संख्या के अनुपात में बुजुर्गों की संख्या भी अधिक होगी।
- 15-59 वर्ष की आयु वर्ग में कामकाजी लोगों की संख्या घटेगी।
- साथ ही, महिलाएं पुरुषों की तुलना में अधिक समय तक जीवित रहेंगी, जिसके कारण अधिक उम्र की महिलाओं की संख्या अधिक उम्र के पुरुषों की तुलना में ज्यादा होगी।
- इनमें बड़ी संख्या ग्रामीण महिलाओं की होगी।
- इसमें कहा गया है कि 1961 के बाद से भारत की बुजुर्ग आबादी में दशकीय वृद्धि मध्यम से उच्च थी।
- यह गति 2001 तक धीमी थी लेकिन आने वाले दशकों में इसके बढ़ने की उम्मीद है।
- रिपोर्ट में कहा गया है कि वैश्विक जनसंख्या बढ़ रही है, भले ही लोग लंबे समय तक जीवित रह रहे हैं। (विश्व जनसंख्या संभावनाएँ)
- रिपोर्ट के मुताबिक, भारत में 60 साल का पुरुष 18.3 साल और जीवित रह सकता है, जबकि महिलाएं 19 साल जीवित रह सकती हैं।
- केरल और हिमाचल प्रदेश में महिलाओं की उम्र पुरुषों से 4 साल अधिक हो सकती है।
- रिपोर्ट में चिंता व्यक्त की गई है कि चूंकि भारत में महिलाओं की जीवन प्रत्याशा पुरुषों की तुलना में अधिक होगी, इसलिए विधवा महिलाओं की संख्या काफी होगी। (जनसंख्या चिंता)

अवश्य पढ़ें: जनसांख्यिकीय लाभांश

SOURCE: DOWN TO EARTH

अर्थव्यवस्था

ऑपरेट ट्रांसफर (बीओटी) मॉडल बनाएं

संदर्भ: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में छोटी राजमार्ग परियोजनाओं के माध्यम से बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर (बीओटी) मॉडल को पुनः प्रवर्तन करने का सुझाव दिया है।

परिचय :-

- बिल्ड-ऑपरेट-ट्रांसफर (बीओटी) अनुबंध एक मॉडल है जिसका उपयोग बड़ी परियोजनाओं, विशेष रूप से सार्वजनिक-निजी भागीदारी के माध्यम से विकसित बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को वित्तपोषित करने के लिए किया जाता है।
- वे आम तौर पर बड़े पैमाने पर, ग्रीनफील्ड बुनियादी ढांचा परियोजनाएं हैं जिन्हें आमतौर पर पूरी तरह से सरकार द्वारा वित्तपोषित, निर्मित और संचालित किया जाएगा।
- बिल्ड-ऑपरेट-ट्रांसफर (बीओटी) अनुबंध के तहत, एक इकाई-आमतौर पर एक सरकार-एक निजी कंपनी को लाभ कमाने की उम्मीद में 20 से 30 साल की अवधि के लिए एक परियोजना के वित्तपोषण, निर्माण और संचालन के लिए रियायत देती है।
- उस अवधि के बाद, परियोजना उस सार्वजनिक इकाई को वापस कर दी जाती है जिसने मूल रूप से रियायत दी थी।

भारत में आमतौर पर उपयोग किए जाने वाले अन्य PPP निवेश मॉडल:-

निर्माण, संचालन, कम से कम, स्थानांतरण (बोल्ट):-

- इस दृष्टिकोण में, सरकार एक निजी संस्था को एक सुविधा बनाने (और संभवतः इसे डिजाइन भी करने), सुविधा का मालिक बनने और सार्वजनिक क्षेत्र को सुविधा पट्टे पर देने के लिए रियायत देती है।
- पट्टा अवधि के अंत में सुविधा का स्वामित्व सरकार को हस्तांतरित करना होगा।

हाइब्रिड वार्षिकी मॉडल (HAM):-

- केंद्र सरकार परियोजना लागत का 40% वहन करती है।
- शेष राशि की व्यवस्था डेवलपर द्वारा की जाती है।

इंजीनियरिंग, खरीद और निर्माण मॉडल (ईपीसी)

- ईपीसी मॉडल साझेदारी के लिए सरकार को परियोजना की कुल फंडिंग की आवश्यकता होती है।
- निजी क्षेत्र का भागीदार इंजीनियरिंग और निर्माण आवश्यकताओं को प्रदान करता है।

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के बारे में:-

- स्थापना: वर्ष 1988 में
- मंत्रालय: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
- यह केंद्र सरकार की एक स्वायत्त एजेंसी है, जो भारत में 70,000 किमी से अधिक राष्ट्रीय राजमार्गों के नेटवर्क के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है।
- यह एक वैधानिक निकाय है।

- इसकी स्थापना भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 के माध्यम से की गई थी।
- वर्ष 1995: इसे औपचारिक रूप से एक स्वायत्त निकाय बनाया गया।
- यह राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास, प्रबंधन, संचालन और रखरखाव के लिए जिम्मेदार है।

अवश्य पढ़ें: डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट के लिए फोरम

SOURCE: FINANCIAL EXPRESS

सेंट्रल बैंक डिजिटल मुद्रा (CBDC)

संदर्भ: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) हाल के दिनों में केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा (CBDC) को लोकप्रिय बनाने के लिए नई सुविधाएँ पेश करने के लिए ऋणदाताओं के साथ काम कर रहा है।

परिचय:-

- सीबीडीसी एक आभासी रूप में अपने केंद्रीय बैंक के माध्यम से सरकार द्वारा स्थापित/समर्थित फिएट मनी या धन है।
- यह केंद्रीय बैंक द्वारा डिजिटल रूप में जारी की गई एक कानूनी निविदा है।
- यह ब्लॉकचेन की शक्ति को वितरित लेजर तकनीक (डीएलटी) के लॉजिस्टिक्स के साथ जोड़ता है, जहां डेटा को केंद्रीकृत भंडारण की आवश्यकता के बिना कई स्थानों पर सिंक्रनाइज़ किया जा सकता है।

मुख्य विशेषताएं:-

- सीबीडीसी एक उच्च सुरक्षा वाला डिजिटल उपकरण है।
- यह भुगतान का एक साधन, खाते की एक इकाई और मूल्य का भंडार है।
- कागजी मुद्रा की तरह, जालसाजी को रोकने के लिए प्रत्येक इकाई को विशिष्ट रूप से पहचाना जा सकता है।
- यह भौतिक मुद्रा की तरह ही केंद्रीय बैंक का दायित्व है।
- यह एक डिजिटल वाहक उपकरण है जिसे सभी प्रकार की डिजिटल भुगतान प्रणालियों और सेवाओं द्वारा संग्रहीत, स्थानांतरित और प्रसारित किया जा सकता है।

लाभ :-

- सीबीडीसी एक तेज़ प्रणाली है।
- वित्तीय समावेशन
- मौद्रिक नीति सुविधा में सुधार
- यह सीमा पार लेनदेन के लिए एक क्षेत्रीय मुद्रा बन सकती है।

अवश्य पढ़ें: रुपया

SOURCE: THE INDIAN EXPRESS

भारतीय मानक ब्यूरो (BIS)

संदर्भ: भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) हाल ही में जागरूकता पैदा करने और भारतीय मानकों के अनुपालन को बढ़ावा देने के लिए 2.4 लाख ग्राम पंचायतों तक पहुंचा।

पृष्ठभूमि:-

- इस पहल का उद्देश्य ग्रामीण स्तर पर लागू सरकारी कार्यक्रमों और योजनाओं की समग्र गुणवत्ता और सुरक्षा को बढ़ाना है।

भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) के बारे में:-

- स्थापना: वर्ष 1986 में
- मंत्रालय: उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय।
- मुख्यालय: नई दिल्ली
- भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) की स्थापना बीआईएस अधिनियम, 1986 के तहत वस्तुओं के मानकीकरण, मार्किंग और गुणवत्ता प्रमाणन की गतिविधियों के सामंजस्यपूर्ण विकास और उससे जुड़े या उसके आकस्मिक मामलों के लिए की गई थी।
- उद्देश्य: वस्तुओं के मानकीकरण, मार्किंग और गुणवत्ता प्रमाणन की गतिविधियों का सामंजस्यपूर्ण विकास और उससे जुड़े या उसके प्रासंगिक मामलों के लिए।
- बीआईएस भारत का राष्ट्रीय मानक निकाय है।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि:-

- यह पहले भारतीय मानक संस्थान (आईएसआई) था, जिसे 1946 में उद्योग और आपूर्ति विभाग के संकल्प के तहत स्थापित किया गया था।
- आईएसआई को 1860 के सोसायटी पंजीकरण अधिनियम के तहत पंजीकृत किया गया था।
- एक नया भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 जिसे 22 मार्च 2016 को अधिसूचित किया गया था, 12 अक्टूबर 2017 से लागू किया गया है।
- यह वस्तुओं, लेखों, प्रक्रियाओं, प्रणालियों और सेवाओं के मानकीकरण और प्रमाणन के संबंध में बीआईएस की गतिविधियों को सुदृढ़ करता है।

संघटन:-

- अध्यक्ष, पदेन: माननीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री, भारत सरकार।
- उपाध्यक्ष, पदेन: माननीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री, भारत सरकार।

कार्य:-

बीआईएस नीचे दी गई विभिन्न गतिविधियों में शामिल है:-

- मानक निर्माण
- उत्पाद प्रमाणन योजना
- अनिवार्य पंजीकरण योजना
- विदेशी विनिर्माता प्रमाणन योजना
- हॉल मार्किंग योजना
- प्रयोगशाला सेवाएँ
- प्रयोगशाला मान्यता योजना
- भारतीय मानकों की बिक्री
- उपभोक्ता मामले की गतिविधियाँ
- प्रचार गतिविधियां
- प्रशिक्षण सेवाएँ, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर
- जानकारी सेवाएँ

अवश्य पढ़ें: भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) और हॉलमार्क

SOURCE: AIR

किसानों के अधिकारों पर पहली वैश्विक संगोष्ठी

संदर्भ: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में नई दिल्ली में किसानों के अधिकारों पर पहली वैश्विक संगोष्ठी का उद्घाटन किया।

इसके बारे में:-

- स्थान: आईसीएआर कन्वेंशन सेंटर, राष्ट्रीय कृषि विज्ञान केंद्र, नई दिल्ली।
- दिनांक: 12 से 15 सितंबर, 2023।
- **ऐतिहासिक पृष्ठभूमि:** पहला GFSR आयोजित करने का प्रस्ताव भारत सरकार द्वारा सितंबर 2022 में भारत में आयोजित खाद्य और कृषि के लिए पादप आनुवंशिक संसाधनों पर अंतर्राष्ट्रीय संधि (अंतर्राष्ट्रीय संधि) के शासी निकाय (जीबी9) के नौवें सत्र में रखा गया था, जिस पर FAO द्वारा सहमति व्यक्त की गई।
- द्वारा आयोजित: खाद्य और कृषि संगठन (एफएओ), रोम के खाद्य और कृषि के लिए पादप आनुवंशिक संसाधनों पर अंतर्राष्ट्रीय संधि (अंतर्राष्ट्रीय संधि) का सचिवालय।
- मेजबानी: कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, पौधों की विविधता और किसानों के अधिकार संरक्षण (पीपीवीएफआर) प्राधिकरण, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर), आईसीएआर-भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (आईएआरआई) , और आईसीएआर-नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज (एनबीपीजीआर) के सहयोग से।
- उद्देश्य: किसानों के अधिकारों और वैश्विक खाद्य सुरक्षा और कृषि में उनकी आवश्यक भूमिका से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों को संबोधित

करना।

- दुनिया भर के 59 देशों से प्रख्यात वैज्ञानिक और संसाधन व्यक्ति भाग लेंगे।
- वे इस बात पर विचार-विमर्श करेंगे कि स्थानीय और स्वदेशी समुदायों और दुनिया के सभी क्षेत्रों के किसानों ने पादप आनुवंशिक संसाधनों (पीजीआर) के संरक्षण और विकास में जो भारी योगदान दिया है, उसे कैसे पहचाना और पुरस्कृत किया जाए।

प्रमुख एजेंडा:-

- किसानों के अधिकारों पर ध्यान: संगोष्ठी अपने केंद्रीय विषय के रूप में किसानों के अधिकारों पर ज़ोर देती है।
- भविष्य के काम के लिए प्रस्ताव: प्रतिभागी भविष्य के काम के लिए प्रस्ताव तैयार करने के उद्देश्य से चर्चा और विचार-विमर्श में संलग्न होते हैं।
- ज्ञान और जागरूकता: संगोष्ठी का एक अनिवार्य परिणाम इसके प्रतिभागियों के बीच किसानों के अधिकारों के बारे में ज्ञान और जागरूकता को बढ़ावा देना है। (भारत में किरायेदार किसान)
- सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करना: संगोष्ठी हितधारकों के लिए किसानों के अधिकारों से संबंधित सर्वोत्तम प्रथाओं, अनुभवों और सीखे गए सबक को साझा करने के लिए एक मूल्यवान मंच के रूप में कार्य करती है। (जैविक खेती)
- किसानों के अधिकारों और मानव अधिकारों का अंतर्संबंध: यह स्वीकार करना कि किसानों के अधिकार मानव अधिकारों के लिए अंतर्निहित हैं, कृषि और खेती के व्यापक संदर्भ में उनके महत्व को रेखांकित करता है।

MUST READ:Doubling the Farmers' Income

SOURCE: AIR

विश्व व्यापार संगठन (WTO)

संदर्भ: हाल ही में, अमेरिका और भारत के बीच विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) विवादों को पारस्परिक रूप से सहमत समाधान के माध्यम से हल किया गया था।

पृष्ठभूमि:-

- जून 2023 में पारस्परिक रूप से सहमत समाधानों के माध्यम से अमेरिका और भारत के बीच विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के छह लंबित विवादों को हल करने के निर्णय के साथ, भारत ने अधिसूचना संख्या 53/2023 (कस्टम) के तहत सेब, अखरोट और बादाम सहित आठ अमेरिकी मूल के उत्पादों पर अतिरिक्त शुल्क वापस ले लिया है।
- सेब और अखरोट पर प्रत्येक पर 20% और बादाम पर 20 रुपये प्रति किलोग्राम का अतिरिक्त शुल्क 2019 में अमेरिका के उत्पादों पर मोस्ट फेवर्ड नेशन (एमएफएन) शुल्क के ऊपर लगाया गया था, जो कि अमेरिका के कुछ स्टील और एल्युमीनियम उत्पादों पर टैरिफ बढ़ाने के राज्य संरक्षणवादी उपाय के प्रतिशोध के रूप में लगाया गया था।
- भारत द्वारा अमेरिकी मूल के उत्पादों पर लगाए गए ये अतिरिक्त शुल्क वापस ले लिए गए हैं क्योंकि अमेरिका अपवर्जन प्रक्रिया के तहत स्टील और एल्युमीनियम उत्पादों को बाजार पहुंच प्रदान करने पर सहमत हुआ है।
- सेब, अखरोट और बादाम पर मोस्ट फेवर्ड नेशन (एमएफएन) शुल्क में कोई कटौती नहीं की गई है, जो अभी भी अमेरिकी मूल के उत्पादों सहित सभी आयातित उत्पादों पर क्रमशः 50%, 100% और 100 रुपये प्रति किलोग्राम पर लागू होता है।
- यह उपाय कम गुणवत्ता वाले सेबों की डंपिंग और भारतीय बाजार में किसी भी हिंसक मूल्य निर्धारण से रक्षा करेगा।

WTO के बारे में:-

- स्थापना: वर्ष 1995 में
- मुख्यालय: जिनेवा, स्विट्जरलैंड
- सदस्य: 164 सदस्य
- भारत WTO का सदस्य है। (डब्ल्यूटीओ में चीन की विकासशील स्थिति)
- WTO व्यापार नियमों की वैश्विक प्रणाली संचालित करता है।
- यह विकासशील देशों को उनकी व्यापार क्षमता बनाने में मदद करता है।
- यह अपने सदस्यों को व्यापार समझौतों पर बातचीत करने और एक-दूसरे के साथ आने वाली व्यापार समस्याओं को हल करने के लिए एक मंच भी प्रदान करता है।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि:-

- इसकी स्थापना मराकेश समझौते के बाद की गई थी जिसे 15 अप्रैल 1994 को अनुमोदित किया गया था।
- टैरिफ और व्यापार पर सामान्य समझौते को मराकेश समझौते द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था।
- GATT केवल नियमों और बहुपक्षीय समझौतों का एक समूह था और इसमें संस्थागत संरचना का अभाव था।
- GATT 1947 को समाप्त कर दिया गया और WTO ने GATT 1994 के रूप में इसके प्रावधानों को संरक्षित किया और माल में व्यापार को नियंत्रित करना जारी रखा।
- यह राष्ट्रों के बीच व्यापार के नियमों से निपटने वाला एकमात्र वैश्विक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है।

विश्व व्यापार संगठन के कार्य:-

- अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए नियम स्थापित करना और लागू करना
- व्यापार नियमों पर चर्चा करना
- डब्ल्यूटीओ समझौतों की देखरेख करना
- खुला व्यापार बनाए रखना
- विवादों का निपटारा करना
- अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्थानों के बीच सहयोग
- विकासशील देशों के व्यापारिक हितों की रक्षा करना

MUST READ:Pact

SOURCE: PIB

ओआईएमएल (इंटरनेशनल ऑर्गनाइजेशन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी) प्रमाणपत्र

संदर्भ: हाल ही में, भारत दुनिया का 13वां देश बन गया है जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत ओआईएमएल (इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी) प्रमाणपत्र जारी करता है।

ओआईएमएल (इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी) प्रमाणपत्रों के बारे में:-

- स्थापना: वर्ष 1955 में
- मुख्यालय: पेरिस
- ओआईएमएल (इंटरनेशनल ऑर्गनाइजेशन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी) कानूनी मेट्रोलॉजी के क्षेत्र में एक प्रसिद्ध अंतरराष्ट्रीय मानक-निर्धारण निकाय है।
- इसकी प्राथमिक भूमिका दुनिया भर में कानूनी मेट्रोलॉजी अधिकारियों और उद्योगों द्वारा उपयोग के लिए मॉडल नियमों, मानकों और संबंधित दस्तावेजों को विकसित करना है।
- ये मानक नैदानिक थर्मामीटर, अल्कोहल ब्रीथ विश्लेषक, रडार गति मापने वाले उपकरण, बंदरगाहों पर जहाज टैंक और पेट्रोल वितरण इकाइयों जैसे मापने वाले उपकरणों के प्रदर्शन से संबंधित राष्ट्रीय कानूनों और विनियमों को सुसंगत बनाने में महत्वपूर्ण हैं।
- भारत 1956 में ओआईएमएल का सदस्य बना।
- भारत ने मेट्रोलॉजी में अंतरराष्ट्रीय मानकों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता पर जोर देते हुए मीट्रिक सम्मेलन पर हस्ताक्षर किए।
- OIML-CS (सर्टिफिकेट सिस्टम) OIML प्रमाणपत्र जारी करने, पंजीकरण करने और उनके संबंधित OIML-प्रकार के मूल्यांकन/परीक्षण रिपोर्ट के साथ उपयोग करने के लिए एक विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त प्रणाली है।

लाभ:-

- भारतीय निर्माता अब अपने उत्पादों को अधिक आसानी से निर्यात कर सकते हैं।
- भारत द्वारा प्रदान की जाने वाली प्रमाणन सेवाएँ अंतर्राष्ट्रीय निर्माताओं को आकर्षित करेंगी।
- प्रमाणन सेवाओं की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए, भारत को कानूनी मेट्रोलॉजी क्षेत्र में रोजगार के अवसरों में वृद्धि देखने की उम्मीद है।

जरूर पढ़ें: लीगल मेट्रोलॉजी (पैकेज्ड कमोडिटीज) नियम संशोधन 2022

SOURCE: AIR

विश्व व्यापार रिपोर्ट 2023

संदर्भ: हालिया विश्व व्यापार रिपोर्ट 2023 के अनुसार यूक्रेन युद्ध की शुरुआत ने विश्व व्यापार को खंडित करना शुरू कर दिया है।

विश्व व्यापार रिपोर्ट 2023 के बारे में:-

- लॉन्च: 12 सितंबर 2023।
- द्वारा प्रकाशित: डब्ल्यूटीओ। (भारत ने चीनी पर डब्ल्यूटीओ के फैसले को चुनौती दी)
- यह शांति, सुरक्षा, गरीबी में कमी और स्थिरता सहित व्यापार दक्षता से परे नीतिगत लक्ष्यों पर जोर देता है।
- इसमें यह निष्कर्ष प्रस्तुत किया गया है कि कैसे पुन: वैश्वीकरण या बढ़ा हुआ अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और व्यापक एकीकरण सुरक्षा, समावेशिता और पर्यावरणीय स्थिरता का समर्थन कर सकता है।

मुख्य विचार:-

- रिपोर्ट वैश्वीकरण के इर्द-गिर्द आख्यान में बदलाव को संबोधित करती है।
- यह शांति, सुरक्षा, गरीबी में कमी और स्थिरता सहित व्यापार दक्षता से परे नीतिगत लक्ष्यों पर जोर देता है।
- पुन: वैश्वीकरण: रिपोर्ट "पुनः वैश्वीकरण" की वकालत करती है, जो अधिक अर्थव्यवस्थाओं, लोगों और मुद्दों के लिए व्यापार एकीकरण का विस्तार करती है।

व्यापार का पुनर्विन्यास

o इसमें कहा गया है कि व्यापार का पुनर्अभिविन्यास व्यापार धीरे-धीरे भू-राजनीतिक रेखाओं के अनुरूप हो रहा है।
o इसमें कहा गया है कि काल्पनिक भू-राजनीतिक "ब्लॉक" के भीतर व्यापार प्रवाह उनके बीच की तुलना में तेजी से बढ़ रहा है, जो मित्रता की ओर बदलाव का संकेत देता है।

भूराजनीतिक बदलाव

- इसमें कहा गया है कि भूराजनीतिक तनाव, यूक्रेन संघर्ष और चीन के उदय ने वैश्विक व्यापार गतिशीलता को प्रभावित किया है।
- इसमें कहा गया है कि COVID-19 महामारी ने लचीली आपूर्ति श्रृंखलाओं के महत्व पर प्रकाश डाला।
  o इसमें कहा गया है कि चुनौतियों के बावजूद, चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया। (डब्ल्यूटीओ में चीन की विकासशील स्थिति)
- समावेशन: यह बताता है कि समावेशन व्यापार एकीकरण ने लाखों लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है।
- स्थिरता: इसमें कहा गया है कि स्थिरता व्यापार हरित प्रौद्योगिकियों तक पहुंच प्रदान करके स्थिरता में योगदान कर सकता है।

अवश्य पढ़ें: 12वां डब्ल्यूटीओ मंत्रिस्तरीय सम्मेलन

SOURCE: BUISINESS LINE

वित्तीय समावेशन के लिए जी20 वैश्विक भागीदारी (जीपीएफआई) बैठक

संदर्भ: वित्तीय समावेशन के लिए चौथी G20 वैश्विक साझेदारी (GPFI) बैठक हाल ही में संपन्न हुई।

पृष्ठभूमि:-

- तीन दिवसीय बैठक में जी20 जीपीएफआई प्रतिनिधियों ने एमएसएमई के लिए सक्रिय विकास, डिजिटल वित्तीय साक्षरता और उपभोक्ता संरक्षण के माध्यम से उपभोक्ताओं को सशक्त बनाने के साथ-साथ जीपीएफआई के प्रमुख प्राथमिकता वाले क्षेत्रों, अर्थात् डिजिटल वित्तीय समावेशन और एसएमई (लघु और मध्यम उद्यम) वित्त पर विचारोत्तेजक चर्चा में भाग लिया।

इसके बारे में:-

- स्थान: मुंबई, भारत
- दिनांक: 14-16 सितंबर, 2023 तक।
- बैठक में G20 सदस्य देशों, विशेष आमंत्रित देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के 50 से अधिक प्रतिनिधि एक साथ आये। (भारत और जी20 प्रेसीडेंसी)
- बैठक में डिजिटल वित्तीय समावेशन और एसएमई वित्त के क्षेत्रों में जी20 इंडिया प्रेसीडेंसी के तहत वित्तीय समावेशन एजेंडा के चल रहे काम पर चर्चा शामिल थी।
- एमएसएमई को सक्रिय करने के लिए डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे पर एक संगोष्ठी 14 सितंबर, 2023 को आयोजित की गई थी।

- संगोष्ठी में दो प्रमुख विषयों "डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे के माध्यम से उच्च आर्थिक विकास के लिए एमएसएमई को सक्रिय करना" और "क्रेडिट गारंटी और एसएमई पारिस्थितिकी तंत्र" पर वैश्विक विशेषज्ञों के बीच एक पैनल चर्चा हुई।
- जीपीएफआई सदस्यों ने डिजिटल वित्तीय समावेशन के लिए जी20 जीपीएफआई उच्च-स्तरीय सिद्धांतों के कार्यान्वयन, राष्ट्रीय प्रेषण योजनाओं के अद्यतन और एसएमई वित्तपोषण में आम बाधाओं को दूर करने के लिए एसएमई सर्वोत्तम प्रथाओं और अभिनव उपकरणों के संबंध में जीपीएफआई कार्य पर चर्चा की।
- जीपीएफआई बैठक के हिस्से के रूप में 16 सितंबर, 2023 को "डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे के माध्यम से वित्तीय समावेशन को आगे बढ़ाना: डिजिटल और वित्तीय साक्षरता और उपभोक्ता संरक्षण के माध्यम से उपभोक्ताओं को सशक्त बनाना" पर एक संगोष्ठी भी आयोजित की गई थी।
- चौथी जीपीएफआई डब्ल्यूजी बैठक में भाग लेने वाले प्रतिनिधियों ने मुंबई में कन्हेरी गुफाओं का भी दौरा किया।

महत्व:-

- नई दिल्ली नेताओं की घोषणा के माध्यम से, जी20 नेताओं ने "मजबूत, टिकाऊ, संतुलित और समावेशी विकास" और "सतत विकास के लिए 2030 एजेंडा के पूर्ण और प्रभावी कार्यान्वयन" में तेजी लाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई और रेखांकित किया कि एमएसएमई दोनों प्रतिबद्धताएं को पूरा करने में मुख्य होंगे।
- दो-पैनल चर्चाओं के माध्यम से, प्रतिष्ठित वैश्विक पैनलिस्टों ने क्रेडिट अंतर को पाटने, पारदर्शिता को बढ़ावा देने, सामर्थ्य बढ़ाने और नवाचारों और उत्पादकता लाभ को बढ़ाने के लिए डीपीआई (डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर) जैसे अभिनव उपायों के माध्यम से एमएसएमई के सामने आने वाली चुनौतियों को दूर करने के तरीकों पर विचार-विमर्श किया।
- जीपीएफआई पूर्ण बैठक में डिजिटल वित्तीय समावेशन के लिए जी20 जीपीएफआई उच्च-स्तरीय सिद्धांतों के कार्यान्वयन, राष्ट्रीय प्रेषण योजनाओं के अद्यतन और एसएमई वित्तपोषण में आम बाधाओं को दूर करने के लिए एसएमई सर्वोत्तम प्रथाओं और अभिनव उपकरणों के संबंध में जीपीएफआई कार्य पर चर्चा शामिल थी।
- चर्चाओं ने चल रहे तीन-वर्षीय वित्तीय समावेशन कार्य योजना FIAP 2020 के शेष कार्य को पूरा करने में योगदान दिया, जो अपने अंतिम वर्ष में है और GPFI द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है।
- जीपीएफआई सदस्य नई जी20 वित्तीय समावेशन कार्य योजना के तहत सार्वभौमिक वित्तीय समावेशन के दृष्टिकोण की दिशा में काम करना जारी रखने पर सहमत हुए। (वित्तीय समावेशन सूचकांक)
- चर्चा में इस बात पर चर्चा हुई कि उपभोक्ता संरक्षण और उपभोक्ता साक्षरता के लिए वित्तीय समावेशन को आगे बढ़ाने के लिए डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे का उपयोग कैसे किया जा सकता है। (वित्तीय समावेशन में माइक्रोफाइनेंस संस्थानों की भूमिका)

अवश्य पढ़ें:वित्तीय समावेशन में डिजिटल बैंकों की भूमिका

SOURCE: AIR

e-NAM 2.0

संदर्भ: हाल ही में e-NAM 2.0 और कृषि विपणन सुधार पर एक राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की गई।

पृष्ठभूमि:-

- e-NAM पर एपीएमसी की कुल संख्या 1389 तक ले जाने के लिए एकीकरण के लिए हाल ही में 28 नई मंडियों को मंजूरी दी गई।

इसके बारे में:-

- लॉन्च: वर्ष 2016 में
- कार्यान्वयन एजेंसी: लघु किसान कृषि व्यवसाय कंसोर्टियम (एसएफएसी)।
- मंत्रालय: कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय।
- उद्देश्य: भारत में कृषि वस्तुओं के लिए मौजूदा मंडियों को "एक राष्ट्र एक बाजार" में एकीकृत करना।

मुख्य विशेषताएं:-

- e-NAM 2.0 मौजूदा e-NAM का उन्नत संस्करण होगा।
- eNAM प्लेटफ़ॉर्म भारत में कृषि वस्तुओं के लिए एक ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफ़ॉर्म है।
- यह एक अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक व्यापार पोर्टल है जो सभी राज्यों में कृषि उपज बाजार समितियों (एपीएमसी) को जोड़ता है।

- यह किसानों, व्यापारियों और खरीदारों को वस्तुओं में ऑनलाइन व्यापार की सुविधा प्रदान करता है।
- यह संपर्क रहित दूरस्थ बोली-प्रक्रिया प्रदान करता है।
- यह मोबाइल आधारित किसी भी समय भुगतान की सुविधा प्रदान करता है जिसके लिए व्यापारियों को मंडियों या बैंकों में जाने की आवश्यकता नहीं है।

लाभ :-

- ई-एनएएम प्रौद्योगिकी हस्तक्षेपों के माध्यम से एपीएमसी मंडी संचालन में सक्षमता लाने में सक्षम है:-
  - o डिजिटल वेटब्रिज और वेइंग स्केल के माध्यम से वजन करने में सटीकता।
  - o उन्नत परख उपकरण के माध्यम से परख में सटीकता।
  - o कमोडिटी की कीमतों पर वास्तविक समय की ऑनलाइन जानकारी।
  - o अधिक खरीदारों/विक्रेताओं तक पहुंच और व्यापार में पारदर्शिता।
  - o अनेक ऑनलाइन भुगतान माध्यमों से भुगतान में पारदर्शिता।
  - o डिजिटलीकरण के माध्यम से समग्र मंडी संचालन में बेहतर दक्षता।

चुनौतियाँ:-

- इंटरनेट कनेक्टिविटी का अभाव
- किसान ऑनलाइन व्यापार के बजाय भौतिक व्यापार में अधिक सहज महसूस करते हैं क्योंकि उन्हें अपनी उपज के परिवहन में समस्याओं का सामना करना पड़ता है।
- कुल मंडियों का बहुत छोटा प्रतिशत ई-एनएएम प्लेटफॉर्म के माध्यम से जुड़ा हुआ है।

अवश्य पढ़ें: ई-मंडियों का ई-नाम प्लेटफॉर्म में एकीकरण

SOURCE: PIB

JPM GBI-EM ग्लोबल डायवर्सिफाइड इंडेक्स

संदर्भ: भारत को जून 2024 तक जेपीएम जीबीआई-ईएम ग्लोबल डायवर्सिफाइड इंडेक्स में शामिल किया जाएगा।

पृष्ठभूमि:-

- जेपी मॉर्गन चेज़ एंड कंपनी ने घोषणा की है कि वह 28 जून 2024 से अपने उभरते बाजारों के बॉन्ड इंडेक्स में भारत सरकार के बॉन्ड को शामिल करेगी।
- विश्लेषक के अनुमान के अनुसार, इस कदम से संभावित रूप से देश में लगभग 25 बिलियन डॉलर आकर्षित हो सकते हैं।
- इसका अंतिम वेटेज संभवतः 10% की सीमा तक पहुंच जाएगा, जिसे प्रति माह 1% की दर से बढ़ाया जाएगा।
- इसका समावेशन 31 मार्च, 2025 तक 10 महीनों में चरणबद्ध किया जाएगा।

इस कदम के निहितार्थ:-

- वर्तमान में, विदेशी निवेशकों के पास भारतीय ऋण का दो प्रतिशत हिस्सा है, यह संख्या अगले समावेशन के बाद दोगुनी से अधिक हो सकती है।
- एक बार शामिल होने के बाद भारतीय बांडों के सूचकांक में दस प्रतिशत भागीदारी होने की उम्मीद है।
- समावेशन के परिणामस्वरूप सूचकांक ट्रैकिंग प्रबंधक भारत को धन आवंटित करेंगे, जो कि दसियों अरब डॉलर में होने की उम्मीद है।
- यह भारत में विदेशी प्रवाह को बढ़ावा देने वाला एक कारक हो सकता है और विदेशी निवेशकों के भारतीय निश्चित आय बाजार में अधिक सक्रिय होने की संभावना है।
- विशेषज्ञों का मानना है कि इस कदम से सरकार के लिए उधार लेने की लागत में कमी आने की संभावना है।
- यह भारतीय रुपये और बांड बाजारों को समर्थन देगा और देश की क्रेडिट रेटिंग में सुधार करेगा।

इसके बारे में:-

- सरकारी बॉन्ड इंडेक्स-उभरते बाजार (जीबीआई-ईएम) वैश्विक वित्तीय बाजार में व्यापक रूप से ट्रैक किया जाने वाला सूचकांक है।
- इसमें उभरते बाजार वाले देशों द्वारा जारी किए गए सरकारी बांड शामिल हैं। (एनआरआई के लिए सरकारी बांड)
- ये देश अपने आर्थिक विकास, साख और अपने बांड बाजारों के आकार के मामले में काफी भिन्न होते हैं।

- उभरते बाजार ऋण क्षेत्र में निवेश निर्णय और पोर्टफोलियो आवंटन अक्सर इस सूचकांक द्वारा निर्देशित होते हैं।
- सूचकांक का रखरखाव जेपी मॉर्गन सहित प्रमुख वित्तीय संस्थानों द्वारा किया जाता है।
- जेपी मॉर्गन ईएसजी ईएमबीआई ग्लोबल डायवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट ग्रेड इंडेक्स (जेईएसजी ईएमबीआई आईजी) सॉवरेन और अर्ध-सॉवरेन संस्थाओं द्वारा जारी किए गए तरल, अमेरिकी डॉलर के उभरते बाजार के निश्चित और फ्लोटिंग-रेट ऋण उपकरणों को ट्रैक करता है।
- सूचकांक ईएसजी मानदंड और ग्रीन बांड मुद्दों पर उच्च रैंक वाले जारीकर्ताओं की ओर झुकाव और कम वेटेज वाले जारीकर्ताओं और कम रैंक वाले जारीकर्ताओं को हटाने के लिए ईएसजी स्कोरिंग और स्क्रीनिंग पद्धति लागू करता है।
- JESG EMBI IG स्थापित फ्लैगशिप जे.पी. मॉर्गन ईएमबीआई पर आधारित है।
- ग्लोबल डायवर्सिफाइड इंडेक्स उन उपकरणों को ट्रैक करता है जिन्हें निवेश ग्रेड (आईजी) के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
- GBI-EM सूचकांक स्थिर नहीं है, यह समय-समय पर अद्यतन होता रहता है।
- ये अद्यतन सुनिश्चित करते हैं कि सूचकांक प्रासंगिक और अद्यतन बना रहे।

महत्व:-

- यह अंतर्राष्ट्रीय पूंजी प्रवाह को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
- यह वैश्विक निवेशकों के लिए इन बांडों के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए एक बेंचमार्क के रूप में कार्य करता है।

लाभ:-

- वैश्विक पूंजी तक पहुंच
- अंतर्राष्ट्रीय पूंजी बाजार को बढ़ावा
- निवेशकों का विश्वास बढ़ना। (बांड आय)
- फंडिंग स्रोतों का विविधीकरण।

चुनौतियाँ:-

- अन्य देशों से बहिर्प्रवाह।
- मुद्रा जोखिम प्रबंधन।
- कराधान नीतियां।

अवश्य पढ़ें: हरित बांड

SOURCE: THE INDIAN EXPRESS

वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में उछाल

संदर्भ: हाल ही में वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में 80 डॉलर प्रति बैरल से ऊपर की बढ़ोतरी ने भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतों को अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंचाने में योगदान दिया है।

पृष्ठभूमि:-

- 22 अप्रैल 2022 को 16 डॉलर प्रति बैरल के निचले स्तर पर पहुंचने के बाद से ब्रेंट कच्चे तेल की कीमत लगातार बढ़ रही है।
- वर्ष (2023) की शुरुआत के बाद से, यह लगभग 58% बढ़कर लगभग $51.8 प्रति बैरल से सितंबर में लगभग $81 हो गया है।
- 20 अगस्त 2023 को 65 डॉलर प्रति बैरल से पिछले छह हफ्तों में वृद्धि तेज रही है।
- विश्लेषकों के अनुसार, कीमतें 86 डॉलर प्रति बैरल के अपने मध्यवर्ती शीर्ष स्तर के करीब हैं, जिसके आसपास कुछ नरमी की उम्मीद है, भले ही व्यापक रुझान अभी भी बढ़ रहा है। (तेल की कीमत में वृद्धि)

मूल्य वृद्धि के कारण:-

- विश्व अर्थव्यवस्था के कोविड-19 महामारी से उबरने के साथ ही वैश्विक मांग में सुधार के कारण 2021 में कच्चे तेल की कीमतें तेजी से बढ़ी हैं।
- OPEC+ समूह द्वारा बनाए गए आपूर्ति प्रतिबंधों ने अंतरराष्ट्रीय तेल की कीमतों को ऊंचा रखा है।
- इन तेल उत्पादक अर्थव्यवस्थाओं ने धीमी उत्पादन वृद्धि का संकेत दिया है, जिसके कारण गैस की कीमतों में भी वृद्धि हुई है।
- यूरोप और एशिया में गैस की कमी ने बिजली उत्पादन के लिए तेल की मांग को और बढ़ा दिया है।

भारत पर प्रभाव:-

- कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि ने भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतों को अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंचाने में योगदान दिया है।
- भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतें इन ईंधनों की अंतरराष्ट्रीय कीमतों के 15-दिवसीय रोलिंग औसत पर आंकी गई हैं।
- केंद्र और राज्य सरकारों के उच्च करों ने खुदरा कीमतों को कहीं अधिक ऊंचा करने में योगदान दिया है।
- विश्लेषकों का कहना है कि तेल की बढ़ती कीमतें अर्थव्यवस्था में बढ़ती मांग को दर्शाती हैं, और इक्विटी अक्सर अपेक्षित मुद्रास्फीति से अधिक प्रदान करती है जिससे तेल की वृद्धि हो सकती है।
- तेल के अनुरूप, कोयला सहित अन्य वस्तुओं की कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं।

प्रभाव स्टॉक और बांड:-

- बीएसई बेसिक मटेरियल इंडेक्स 3 अप्रैल, 2020 को 1,761 के निचले स्तर से तीन गुना से अधिक बढ़कर हाल ही में 5,725 पर पहुंच गया है।
- यह सामान्य दृष्टिकोण को दर्शाता है कि आगे चलकर आर्थिक सुधार मजबूत होगा।
- बांड के लिए: तेल की बढ़ती कीमतों के प्रत्यक्ष प्रभाव की तुलना में केंद्रीय बैंक की नीतियां कहीं अधिक बड़ी भूमिका निभाएंगी।
- इक्विटी निवेशकों के लिए: वे अपस्ट्रीम तेल कंपनियों में अपना निवेश बढ़ा सकते हैं, जिन्हें बढ़ती कीमतों से लाभ होता है।
- जिन क्षेत्रों में तेल एक प्रमुख लागत घटक है, वहां रिटर्न पर नकारात्मक प्रतिक्रिया की उम्मीद की जा सकती है।

मुद्रा और अर्थव्यवस्था पर प्रभाव:-

- कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें रुपये पर दबाव डालती हैं, क्योंकि तेल का एक प्रमुख आयातक होने के कारण भारत को उतनी ही मात्रा में कच्चा तेल खरीदने के लिए अधिक डॉलर की आवश्यकता होती है।
- कच्चे तेल की कीमतों में उछाल से भारत का खर्च बढ़ता है और राजकोषीय घाटे पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

अवश्य पढ़ें: तेल की बढ़ती कीमतें और मुद्रास्फीतिजनित मंदी

SOURCE: **THE ECONOMIC TIMES**

ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023

संदर्भ: ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 हाल ही में जारी किया गया।

पृष्ठभूमि:-

- ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में भारत ने 40वीं रैंक बरकरार रखी है।

ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 रैंकिंग के बारे में:-

- प्रकाशन: वार्षिक
- द्वारा प्रकाशित: विश्व बौद्धिक संपदा संगठन
  o WIPO संयुक्त राष्ट्र की एक स्व-वित्तपोषित एजेंसी है, जिसके 193 सदस्य देश हैं।
- संस्करण: 16वाँ संस्करण
- ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स किसी अर्थव्यवस्था के इनोवेशन इकोसिस्टम प्रदर्शन को मापने के लिए एक प्रमुख संदर्भ है।
- यह समय के साथ नवाचार में प्रगति का आकलन करने के लिए नीति निर्माताओं, व्यापारिक नेताओं और अन्य हितधारकों द्वारा उपयोग किया जाने वाला एक मूल्यवान बेंचमार्किंग टूल भी है।
- ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स (जीआईआई) का 2023 संस्करण अनिश्चितता से भरे आर्थिक माहौल की पृष्ठभूमि के खिलाफ वैश्विक नवाचार रुझानों का रूप पकड़ता है।
- ग्लोबल इनोवेशन ट्रैकर 2023 नवाचार निवेश में प्रमुख रुझानों को पकड़ता है और तकनीकी प्रगति और अपनाने की गति के साथ-साथ परिणामी सामाजिक आर्थिक प्रभाव को मापता है।
- सूचकांक 132 अर्थव्यवस्थाओं के बीच दुनिया की इस वर्ष की सबसे नवीन अर्थव्यवस्थाओं की रैंकिंग का खुलासा करता है।

मुख्य विचार:-

- वर्ष 2023 में सबसे नवीन अर्थव्यवस्थाएँ:-
  o लगातार 13वें वर्ष, स्विट्जरलैंड 2023 में सबसे नवीन अर्थव्यवस्था है, इसके बाद स्वीडन, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम

और सिंगापुर हैं।

- वर्ष 2023 में दुनिया के शीर्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी नवाचार क्लस्टर हैं: -
  o टोक्यो-योकोहामा, इसके बाद शेन्ज़ेन-हांगकांग-गुआंगज़ौ, सियोल, बीजिंग और शंघाई-सूज़ौ।
  o चीन के पास अब संयुक्त राज्य अमेरिका को पछाड़कर दुनिया में सबसे अधिक संख्या में क्लस्टर हैं।

भारत का प्रदर्शन:-

- भारत ने 132 अर्थव्यवस्थाओं में से 40वां स्थान बरकरार रखा।
- पिछले कुछ वर्षों में, भारत जीआईआई में लगातार ऊपर चढ़ गया है, 2015 में 81वें स्थान से बढ़कर अपनी वर्तमान स्थिति पर पहुंच गया है।

अवश्य पढ़ें:पेटेंट पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देना

SOURCE: AIR

रत्न एवं आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद (GJEPC)

संदर्भ: हाल ही में रत्न एवं आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद (जीजेईपीसी) ने हीरा उद्योगों से 15 अक्टूबर से 15 दिसंबर तक कच्चे हीरे का आयात बंद करने की अपील की है।

पृष्ठभूमि:-

- अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पॉलिश किए गए प्राकृतिक हीरों और जड़ित आभूषणों की मांग में कमी के कारण यह निर्णय लिया गया है।
- एक बयान में, जीजेईपीसी ने कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन जैसी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं से लूज़ पॉलिश वाले हीरे और आभूषणों की मांग पिछली कई तिमाहियों से प्रभावित हुई है।

इसके बारे में:-

- स्थापना: वर्ष 1966 में
- मुख्यालय: मुंबई
- मंत्रालय: वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
- दृष्टिकोण: भारत को गुणवत्तापूर्ण रत्नों और आभूषणों के लिए पसंदीदा स्रोत बनाना। (भारत का रत्न एवं आभूषण क्षेत्र)
- रत्न एवं आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद शीर्ष निकाय है जिसका उद्देश्य रत्न एवं आभूषण उत्पादों और उद्योग को बढ़ावा देना है।
- इसे हीरा निर्माण और व्यापार में अग्रणी माना जाता है।
- यह भारत में रत्न और आभूषण उद्योग की देखरेख करने वाला एक केंद्रीय प्रशासनिक और वैधानिक निकाय है।
- इसके क्षेत्रीय कार्यालय नई दिल्ली, कोलकाता, जयपुर और सूरत में हैं।
- यह रत्न और आभूषण क्षेत्र में भारत की निर्यात-आधारित वृद्धि को संचालित करता है। (निर्यात-उन्मुख इकाइयाँ)

उद्देश्य:-

ब्रांड इंडिया को बढ़ावा देना:-

- भारत के सबसे बड़े और दूसरे सबसे बड़े व्यापार शो, IIJS प्रीमियर और IIJS सिग्नेचर का आयोजन करना।
- अंतर्राष्ट्रीय आभूषण शो में संयुक्त भागीदारी का आयोजन करना।

सरकार और व्यापार को जोड़ना:-

- उद्योग और भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, डीजीएफटी, वाणिज्य विभाग, वित्त विभाग के बीच व्यापार से संबंधित मुद्दों पर बेहतर बातचीत की सुविधा प्रदान करना।

हीरे की अखंडता को कायम रखना:-

- भारत सरकार द्वारा नियुक्त नोडल एजेंसी के रूप में देश में किम्बर्ली प्रोसेस सर्टिफिकेशन योजना का क्रियान्वयन करना।

ज्ञान का प्रसार :-

- छह शहरों - मुंबई, दिल्ली, सूरत, जयपुर, वाराणसी और उडुपी में विनिर्माण कौशल, तकनीकी और डिजाइन उत्कृष्टता प्रदान करने वाले प्रशिक्षण संस्थान चलाना।

नवाचार और बुनियादी ढांचा:-

- सामान्य सुविधा केंद्रों पर एमएसएमई को किफायती आधुनिक मशीनें और उपकरण उपलब्ध कराना।

- देश भर में आभूषण पार्क स्थापित करना।

स्वास्थ्य और अच्छाई:-

- स्वास्थ्य रत्न नामक समूह मेडिक्लेम योजना के माध्यम से परिषद की सदस्य कंपनियों के कर्मचारियों के लिए स्वास्थ्य बीमा प्रदान करना।

समाज को वापस भुगतान:-

- वर्ष 2014 में जीजेईपीसी द्वारा स्थापित, ज्वैलर्स फॉर होप ने वंचितों के समर्थन में असाधारण काम करने वाले एक या अधिक गैर सरकारी संगठनों/धर्मार्थ संस्थाओं को हर साल 1 करोड़ रुपये का दान दिया है।

अवश्य पढ़ें: नई विदेश व्यापार नीति

स्रोत: द इंडियन एक्सप्रेस

पर्यावरण और पारिस्थितिकी

रेड सैंड बोआ

संदर्भ: हालिया रिपोर्ट के अनुसार, भारत में 2016 से 2021 तक रेड सैंड बोआ की बरामदगी की 172 घटनाएं दर्ज की गईं।

रिपोर्ट की मुख्य बातें:-

- पूरे भारत में 18 राज्यों और 87 जिलों को कवर करने वाले एक केंद्र शासित प्रदेश में अवैध सैंड बोआ व्यापार की घटनाएं दर्ज की गईं; यह सबसे अधिक संख्या महाराष्ट्र (59) और उसके बाद उत्तर प्रदेश (33) में दर्ज की गई।
- अध्ययन प्रजातियों के अवैध व्यापार में सोशल मीडिया की भूमिका पर भी प्रकाश डालता है।
- रिपोर्ट में यह भी सुझाव दिया गया है कि स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण संगठनों को अवैध सरीसृप व्यापार और मांग की स्थिति को बेहतर ढंग से समझने के लिए रचनात्मक अनुसंधान करना चाहिए।

रेड सैंड बोआ के बारे में:-

- वैज्ञानिक नाम: एरिक्स जॉनी
- परिवार: बोइडे
- पर्यावास: शुष्क और अर्ध-शुष्क क्षेत्र।
- वितरण: भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश के कुछ हिस्सों में।
- रेड सैंड बोआ एक दुर्लभ गैर विषैला सांप है।
- यह एक गैर विषैले साँप की प्रजाति है।
- यह मुख्यतः रात्रिचर होता है।
    - रात्रिचर: यह रात के दौरान सबसे अधिक सक्रिय रहता है।
- यह मुख्य रूप से लाल-भूरे रंग का साँप है जो औसतन 75 सेमी. लंबा होता है।
- अधिकांश साँपों के विपरीत इसकी पूँछ लगभग इसके शरीर जितनी मोटी होती है जिससे यह "दो सिरों" वाला लगता है।

पारिस्थितिक महत्व:-

- अन्य साँप प्रजातियों की तरह, रेड सैंड बोआ भी शिकार और शिकारी के बीच एक स्वस्थ आबादी बनाए रखकर पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। (खबरों में प्रजाति: घड़ियाल)

अनुप्रयोग:-

- इसका उपयोग चिकित्सा, सौंदर्य प्रसाधन और यहां तक कि काले जादू में भी किया जाता है, जिससे वैश्विक बाजार में इसका अत्यधिक महत्व है। (वन्यजीव संरक्षण)

संरक्षण की स्थिति:-

- IUCN रेड लिस्ट: निकट संकटग्रस्त
- वन्यजीवों और वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन (CITES): परिशिष्ट II
- भारतीय वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972: अनुसूची IV।

अवश्य पढ़ें: भारतीय पशु कल्याण बोर्ड (AWBI)

SOURCE: THE HINDU

हूलोंगापार गिब्बन अभयारण्य

संदर्भ: हाल ही में, असम में हूलोंगापार गिब्बन अभयारण्य आसपास के वन क्षेत्रों से संपर्क खोने के बाद एक वन द्वीप में बदल गया।

परिचय :-

- स्थान: असम का जोरहाट जिला
- वर्ष 2004 में हूलोंगापार गिब्बन अभयारण्य का नाम बदल दिया गया।
- इसे पहले गिब्बन वन्यजीव अभयारण्य या हूलोंगापार रिजर्व फॉरेस्ट के नाम से जाना जाता था।

- यह सदाबहार वन का एक पृथक संरक्षित क्षेत्र है।

वनस्पति:-

- जंगल की ऊपरी हिस्सों पर हूलोंगा वृक्ष का प्रभुत्व है, जबकि नाहर मध्य भागों पर हावी है।
- निचली आवरण में सदाबहार झाड़ियाँ और जड़ी-बूटियाँ हैं।

जीव-जंतु:-

- अभयारण्य में समृद्ध जैव विविधता है और यह भारत के एकमात्र वानरों, पश्चिमी हूलॉक, साथ ही पूर्वोत्तर भारतीय राज्यों में पाए जाने वाले एकमात्र रात्रिचर प्राइमेट, बंगाल स्लो लोरिस का घर है।
- अन्य जानवर: स्टंप-टेल्ड मकाक, उत्तरी पिग-टेल्ड मकाक, पूर्वी असमिया मकाक, रीसस मकाक, कैप्ड लंगूर, आदि।

हूलॉक गिब्बन के बारे में:-

- हूलॉक गिब्बन भारत की एकमात्र वानर प्रजाति है।
- यह पूर्वी बांग्लादेश, पूर्वोत्तर भारत, म्यांमार और दक्षिण-पश्चिम चीन का मूल निवासी है।
- सभी वानरों की तरह, ये बहुत बुद्धिमान, विशिष्ट व्यक्तित्व और मजबूत पारिवारिक बंधन वाले होते हैं।
- इसे पश्चिमी हूलॉक गिब्बन और पूर्वी हूलॉक गिब्बन में वर्गीकृत किया गया है।

पश्चिमी हूलॉक गिब्बन:-

- ये पूर्वोत्तर के सभी राज्यों में ब्रह्मपुत्र नदी के दक्षिण और दिबांग नदी के पूर्व क्षेत्र के बीच सीमित हैं।
- संरक्षण की स्थिति:-
    - IUCN रेड लिस्ट: संकटग्रस्त

पूर्वी हूलॉक गिब्बन:-

- यह भारत में अरुणाचल प्रदेश और असम के विशिष्ट इलाकों में और भारत के बाहर दक्षिणी चीन तथा उत्तर-पूर्व म्याँमार में पाया जाता है।
- संरक्षण की स्थिति:-
    - IUCN लाल सूची: असुरक्षित

अवश्य पढ़ें: काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान

SOURCE: THE HINDU

वायु गुणवत्ता जीवन सूचकांक (AQLI)

संदर्भ: हाल ही में जारी वायु गुणवत्ता जीवन सूचकांक (AQLI) रिपोर्ट से पता चलता है कि वायु प्रदूषण दिल्ली के निवासियों के जीवन को लगभग 11.9 वर्ष कम कर रहा है।

रिपोर्ट की मुख्य बातें:-

- भारत में पार्टिकुलेट मैटर के उच्च स्तर से प्रभावित होने वाले लोगों की संख्या को देखते हुए, देश को दुनिया के सभी देशों की तुलना में वायु प्रदूषण से स्वास्थ्य पर सबसे अधिक बोझ का सामना करना पड़ रहा है।
- दक्षिण एशिया में 2013 से 2021 तक कण प्रदूषण 9.7 प्रतिशत बढ़ गया है।
- भारत में PM2.5 का स्तर 9.5 प्रतिशत बढ़ा।
    - पार्टिकुलेट मैटर (पीएम): हवा में पाए जाने वाले कण, जिनमें धूल, गंदगी, कालिख, धुआं और तरल बूंदें शामिल होती हैं यह लंबे समय तक हवा में बने रहते हैं।
- उपग्रहों से प्राप्त 2021 के PM2.5 डेटा के अनुसार, भारत में प्रदूषण 2020 में 56.2 µg/m3 से बढ़कर 2021 में 58.7 µg/m3 हो गया है।
    - यह WHO के दिशानिर्देश 5 µg/m3 से 10 गुना से भी अधिक है।
- वर्ष 2021 में दिल्ली का वार्षिक औसत PM2.5 स्तर 126.5 µg/m3 पाया गया, जो विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) दिशानिर्देश से 25 गुना से अधिक है। (दिल्ली और वायु प्रदूषण)
- रिपोर्ट में कहा गया है कि पार्टिकुलेट मैटर प्रदूषण भारत में जीवन प्रत्याशा को कम करने, हृदय रोगों को मात देने और बच्चे एवं मातृ कुपोषण के मामले में मानव स्वास्थ्य के लिए सबसे बड़ा खतरा है।
- यदि WHO के दिशानिर्देशों का पालन नहीं किया गया तो औसत भारतीय निवासी की जीवन प्रत्याशा 5.3 वर्ष कम हो जाएगी।

वायु गुणवत्ता जीवन सूचकांक (AQLI) के बारे में:-

- निर्माता: शिकागो विश्वविद्यालय में ऊर्जा नीति संस्थान (ईपीआईसी)
- प्रकाशित: वार्षिक
- वायु गुणवत्ता जीवन सूचकांक (AQLI), जीवन प्रत्याशा पर वायु प्रदूषण के प्रभाव का विवरण प्रदान करता है।

AQLI की विशेष विशेषताएं:-

- AQLI पर आधारित अनुसंधान आज दुनिया के कई हिस्सों में व्याप्त अत्यधिक सांद्रता वाले प्रदूषण डेटा पर आधारित है।
- AQLI के अंतर्निहित अनुसंधान की कारण प्रकृति इसे वायु प्रदूषण के प्रभाव को स्वास्थ्य पर प्रभाव डालने वाले अन्य कारकों से अलग करने की अनुमति देती है।
- AQLI औसत व्यक्ति के लिए जीवन प्रत्याशा के नुकसान का अनुमान बताता है।
- AQLI अत्यधिक स्थानीयकृत उपग्रह डेटा का उपयोग करता है, जिससे जीवन प्रत्याशा की रिपोर्ट करना संभव हो जाता है जो काउंटी या समान स्तर पर प्रभाव डालता है।

अवश्य पढ़ें: वायु प्रदूषण को कम करने के लिए भारत की कठिन लड़ाई

SOURCE: THE INDIAN EXPRESS

बीएस 6 स्टेज II इलेक्ट्रिफाइड फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल

संदर्भ: बीएस 6 स्टेज II 'विद्युतीकृत फ्लेक्स ईंधन वाहन' का विश्व का पहला प्रोटोटाइप हाल ही में लॉन्च किया गया था।

पृष्ठभूमि:-

- ये वाहन प्रौद्योगिकियाँ इथेनॉल द्वारा पेट्रोल के अधिक प्रतिस्थापन का अवसर प्रदान करेंगी क्योंकि यह 20% से अधिक इथेनॉल मिश्रण के किसी भी उच्च मिश्रण का उपयोग करने में सक्षम होती है।

परिचय :-

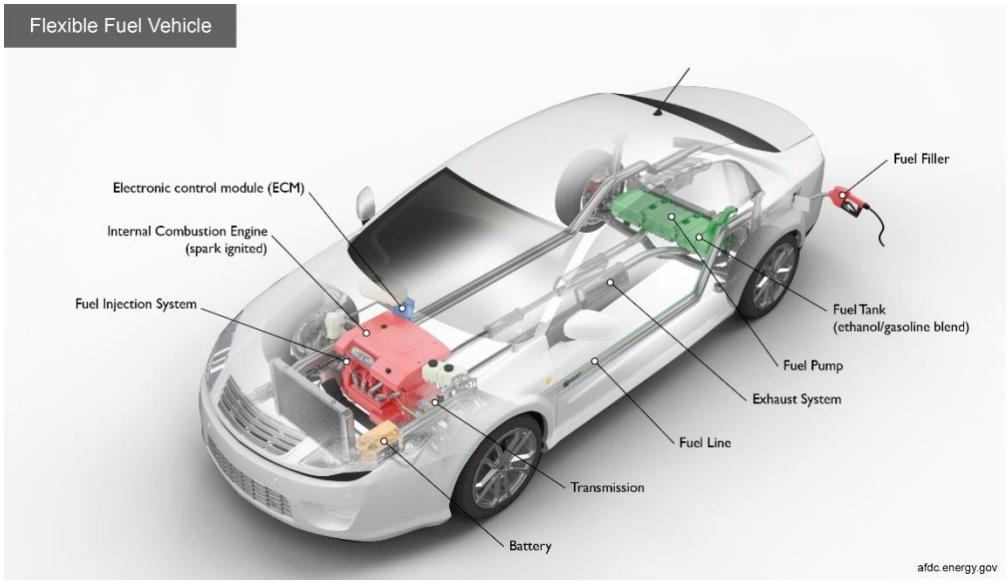

- फ्लेक्स-फ्यूल वाहन (एफएफवी) 100% पेट्रोल, 100% बायो-एथेनॉल या दोनों के संयोजन पर चलने में सक्षम हैं।
- ये वाहन ऐसे इंजनों से सुसज्जित हैं जो उपलब्ध ईंधन मिश्रण के आधार पर अपने ईंधन मिश्रण को समायोजित कर सकते हैं।
- विद्युतीकृत फ्लेक्स ईंधन वाहन एफएफवी का एक उन्नत संस्करण हैं।
- ये इथेनॉल-आधारित ईंधन और बिजली दोनों पर काम करने में सक्षम हैं। (हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहनों को शक्ति देने वाली तकनीक)
- ये बढ़ी हुई ईंधन दक्षता प्रदान करते हैं।
- ये पारंपरिक गैसोलीन-केवल वाहनों की तुलना में उत्सर्जन को कम करते हैं।
- एक विद्युतीकृत फ्लेक्स ईंधन वाहन में एक फ्लेक्सी ईंधन इंजन और एक इलेक्ट्रिक पावरट्रेन दोनों होते हैं।
- यह इसे उच्च इथेनॉल उपयोग और बहुत अधिक ईंधन दक्षता का दोहरा लाभ प्रदान करने की क्षमता देता है।
- एक मजबूत हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहन (एसएचईवी), 30-50% अधिक ईंधन दक्षता प्रदान कर सकता है क्योंकि यह इंजन बंद होने पर ईवी

मोड में 40-60% तक चल सकता है।

- विश्व का पहला बीएस-6 स्टेज-II, विद्युतीकृत फ्लेक्स ईंधन वाहन, टोयोटा किर्लोस्कर मोटर द्वारा विकसित किया गया है।
- इसमें फ्लेक्स-फ्यूल इंजन के साथ-साथ इलेक्ट्रिक पावरट्रेन दोनों हैं, जिससे बेहतर ईंधन दक्षता के साथ इथेनॉल का अधिक उपयोग होता है।

भारत स्टेज VI (बीएस VI) के बारे में:

- यह आंतरिक दहन और स्पार्क-इग्निशन इंजन उपकरण से उत्सर्जित वायु प्रदूषकों के स्तर को विनियमित करने के लिए स्थापित उत्सर्जन मानकों का एक सेट है।
- बीएस-VI में ईंधन की गुणवत्ता में वृद्धि की गई है, और अनुमेय सल्फर सामग्री (permissible Sulphur content) को 80% तक कम कर दिया गया है, यह 50 पार्ट्स प्रति मिलियन (पीपीएम) से अधिकतम 10 पीपीएम तक है।
- भारत ने दो चरणों में BS-VI उत्सर्जन (पहले के BS-IV से) मानदंडों का पालन करना अनिवार्य कर दिया है:-
- **चरण 1: 1 अप्रैल, 2020 से प्रभावी।**
- इसमें अनुमेय प्रदूषक सीमाओं में पर्याप्त कमी देखी गई, जिससे उत्सर्जन के लिए नए मानक स्थापित हुए।
- **चरण 2: 1 अप्रैल, 2023 को शुरू किया गया।**
- यह वास्तविक ड्राइविंग उत्सर्जन (आरडीई) परीक्षण पर केंद्रित है जो वास्तविक दुनिया की ड्राइविंग स्थितियों में वाहन द्वारा उत्सर्जित उत्सर्जन को मापता है।

अवश्य पढ़ें: फ्लेक्स फ्यूल टेक्नोलॉजी

SOURCE: AIR

फुजियानवेनेटर प्रोडिगियोसस

संदर्भ: एक विचित्र पक्षी जैसे डायनासोर फ़ुज़ियानवेनेटर प्रोडिगियोसस के साक्ष्य ने हाल ही में वैज्ञानिकों को मंत्रमुग्ध कर दिया।

पृष्ठभूमि:-

- वैज्ञानिकों ने फ़ुज़ियान प्रांत से फ़ुज़ियानवेनेटर नामक जुरासिक काल के डायनासोर के जीवाश्म का पता लगाने की जानकारी दी। (चीन में डायनासोर के पैरों के निशान)
- यह एक ऐसा प्राणी है जो पक्षियों की उत्पत्ति में एक महत्वपूर्ण विकासवादी चरण पर प्रकाश डालता है।

फ़ुज़ियानवेनेटर विलक्षण के बारे में:-

- वितरण: दक्षिणपूर्वी चीन। (भारत में असामान्य डायनासोर के अंडे)
- फ़ुज़ियानवेनेटर एवियलन्स नामक समूह का सदस्य है।
- इस समूह में सभी पक्षी और उनके निकटतम गैर-एवियन डायनासोर सगे-संबंधी शामिल हैं।
- अस्तित्व: अपनी मामूली शुरुआत के बावजूद, ये पक्षी 66 मिलियन वर्ष पहले क्षुद्रग्रह के हमले से बच गए, जिसने उनके गैर-एवियन डायनासोर साथियों को बर्बाद कर दिया था।
- आहार और जीवनशैली: खोजे गए फ़ुज़ियानवेनेटर जीवाश्म में जानवर की खोपड़ी और उसके पैरों के कुछ हिस्से नहीं मिले, जिससे उसके आहार और जीवनशैली की व्याख्या करना कठिन हो गया है।

शारीरिक विवरण: -

- यह तीतर के आकार का और पक्षी जैसा डायनासोर था।
- इसके पैर और भुजाएँ पंखों की तरह लम्बी थीं।
- इसकी हैरान करने वाली शारीरिक रचना से पता चलता है कि यह या तो तेज़ धावक था या आधुनिक पक्षी की तरह जीवन शैली जीता था।
- इसके निचले पैर की हड्डी - टिबिया - इसकी जांघ की हड्डी - फीमर से दोगुनी लंबी थी।
- इसकी एक लंबी हड्डी वाली पूंछ भी थी।
- अग्रपाद आमतौर पर पक्षी के पंख की तरह बना है, लेकिन उंगलियों पर तीन पंजे हैं, जो आधुनिक पक्षियों में अनुपस्थित हैं।
- यह निर्धारित नहीं किया जा सकता कि यह उड़ सकेगा या नहीं।

MUST READ:Dinosaur eggs

SOURCE: THE HINDU

सेगुर हाथी गलियारा

संदर्भ: सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त समिति ने हाल ही में सेगुर हाथी गलियारे के किनारे 12 निजी रिसॉर्ट्स को अवैध घोषित कर दिया।

पृष्ठभूमि:-

- समिति के फैसले ने इस बात पर प्रकाश डाला कि रिसॉर्ट्स ने गैरकानूनी संरचनाओं का निर्माण किया था जो हाथियों की प्राकृतिक आवाजाही में बाधा उत्पन्न करते थे।
- रिज़ॉर्ट मालिकों के दावे के बावजूद, जिन्होंने गलियारे को हाथी के निवास स्थान के रूप में नामित करने पर विवाद किया, समिति अंततः गलियारे की अखंडता को संरक्षित करने के पक्ष में रही।
- जबकि यह निर्णय गलियारे की सुरक्षा को सुरक्षित करता है, यह स्थानीय समुदायों के लिए आर्थिक निहितार्थ रखता है जो इन रिसॉर्ट्स द्वारा प्रदान किए गए रोजगार के अवसरों पर निर्भर हैं।

सेगुर हाथी गलियारे के बारे में:-

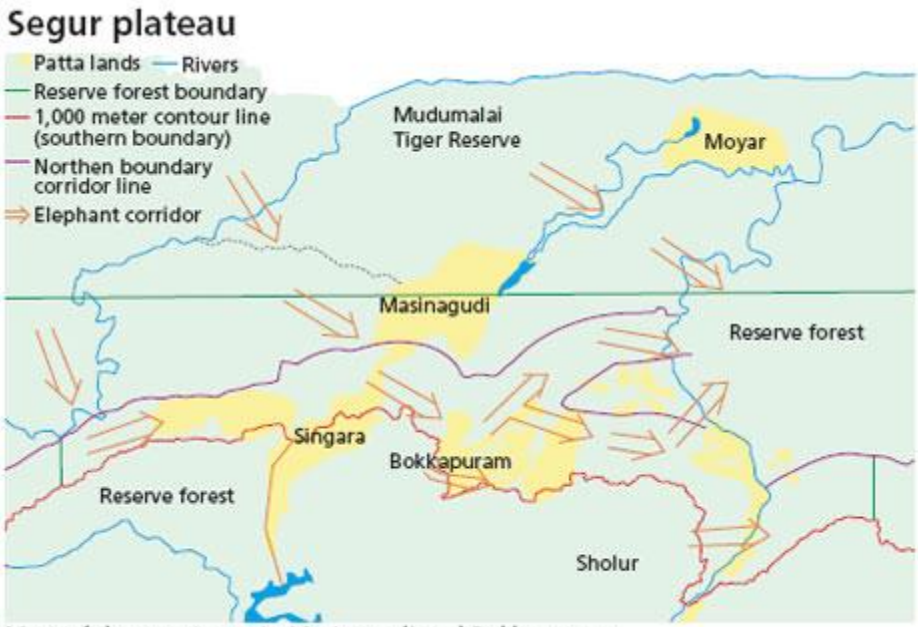

Most of the resorts are in Masinagudi and Bokkapuram

- सेगुर हाथी गलियारा नीलगिरि बायोस्फीयर रिजर्व के भीतर विभिन्न आवासों के बीच हाथियों और विभिन्न अन्य वन्यजीव प्रजातियों की आवाजाही के लिए एक महत्वपूर्ण मार्ग के रूप में कार्य करता है। (नीलगिरि बायोस्फीयर रिजर्व में लुप्तप्राय एशियाई हाथी)
- गलियारा पारिस्थितिक रूप से नाजुक सिगुर पठार (fragile Sigur plateau) में स्थित है।
- सिगुर पठार पश्चिमी और पूर्वी घाट को जोड़ता है।
- यह केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक से लगभग 6,300 एशियाई हाथियों की आसान आवाजाही की सुविधा प्रदान करता है।
- यह हाथियों की आबादी और उनकी आनुवंशिक विविधता को बनाए रखता है।
- हाथी भोजन और पानी की तलाश में पठार को पार करते हैं।
- इसके दक्षिण-पश्चिमी हिस्से में नीलगिरि पहाड़ियाँ हैं।
- मोयार नदी घाटी इसके उत्तरपूर्वी हिस्से पर है।
- यह पठार कम वर्षा वाली सीमांत भूमि है।
- इसकी मिट्टी खराब है और हाल के दिनों में जनसंख्या घनत्व भी कम है।
- सिगुर पठार में पाँच प्रमुख धाराएँ हैं: मोयार नदी, सिगुर नदी, अवराहल्ला नदी, केदारहल्ला नदी और गुंडातिहल्ला नदी।
    - ये सभी नदियाँ नीलगिरी पठार से निकलती हैं।

MUST READ:Project Re-Hab

SOURCE: THE HINDU

आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए सेंडाई फ्रेमवर्क

संदर्भ: नेताओं ने हाल ही में आयोजित शिखर सम्मेलन में आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए सेंडाई फ्रेमवर्क के पूर्ण कार्यान्वयन की सिफारिश की है।

पृष्ठभूमि:-

- दुनिया भर के नेता 18 सितंबर, 2023 को उच्च-स्तरीय सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) शिखर सम्मेलन के लिए एकत्र हुए और 2030 तक एसडीजी वितरित करने के अपने प्रयासों को तेज करने पर सहमत हुए।

आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए सेंडाई फ्रेमवर्क के बारे में:-

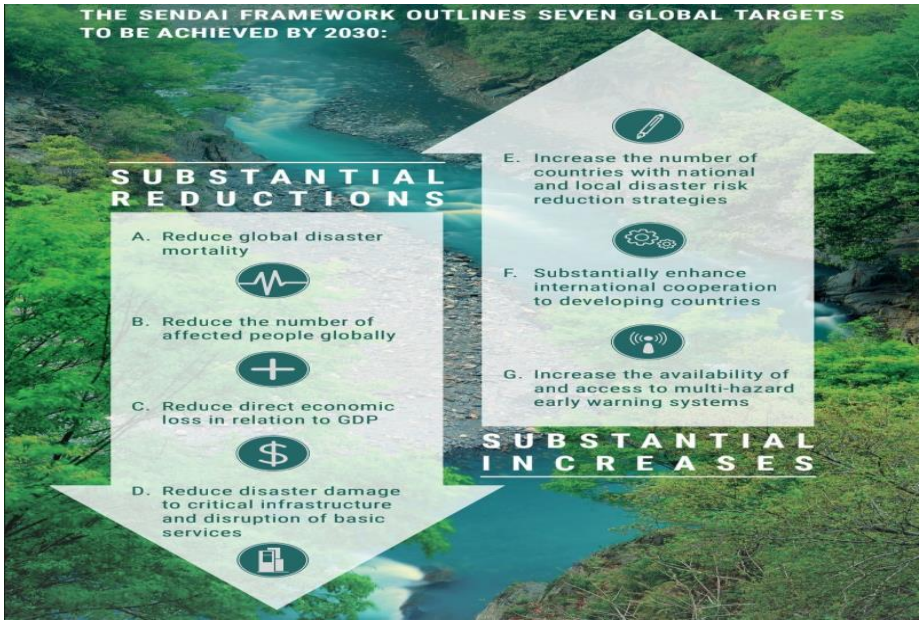

- अंगीकरण: वर्ष 2015 में
- समयावधि: वर्ष 2015-2030 तक
- इसे 18 मार्च 2015 को जापान के सेंदाई में तीसरे संयुक्त राष्ट्र विश्व सम्मेलन में अपनाया गया था।
- उद्देश्य: सभी स्तरों पर और साथ ही सभी क्षेत्रों के भीतर एवं सभी क्षेत्रों में विकास में आपदा जोखिम के बहु-खतरा प्रबंधन का मार्गदर्शन करना।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि:-

- यह संयुक्त राष्ट्र महासभा के अनुरोध पर आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए संयुक्त राष्ट्र कार्यालय द्वारा समर्थित, मार्च 2012 में शुरू किए गए हितधारक परामर्श और जुलाई 2014 से मार्च 2015 तक अंतर-सरकारी वार्ता का परिणाम है।
- यह ह्योगो फ्रेमवर्क फॉर एक्शन (एचएफए) 2005-2015 का उत्तराधिकारी उपकरण है: जसिमें आपदाओं के प्रति राष्ट्रों और समुदायों के लचीलेपन का निर्माण शामिल है।
- सेंदाई फ्रेमवर्क नए आपदा जोखिमों को रोकने और मौजूदा आपदा जोखिमों को कम करने के लिए कार्रवाई के लिए सात स्पष्ट लक्ष्यों और चार प्राथमिकताओं की रूपरेखा तैयार करता है।
- कार्रवाई के लिए चार प्राथमिकताओं में शामिल हैं:-
    - आपदा जोखिम को समझना: आपदा जोखिम प्रबंधन इसके सभी आयामों में आपदा जोखिम की समझ पर आधारित होना चाहिए।
    - आपदा जोखिम प्रबंधन के लिए आपदा जोखिम प्रशासन को मजबूत करना: राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर आपदा जोखिम प्रशासन।
    - लचीलेपन के लिए आपदा न्यूनीकरण में निवेश: आपदा जोखिम की रोकथाम और कटौती में सार्वजनिक और निजी निवेश।
    - प्रभावी प्रतिक्रिया के लिए आपदा तैयारियों को बढ़ाना, और पुनर्प्राप्ति, पुनर्वास और पुनर्निर्माण में "बेहतर निर्माण" करना: प्रतिक्रिया के लिए आपदा तैयारियों को मजबूत करना।
- इसका उद्देश्य व्यक्ति, व्यवसाय, समुदाय और देशों के जीवन, आजीविका और स्वास्थ्य और आर्थिक, भौतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और पर्यावरणीय संपत्तियों में आपदा जोखिम और नुकसान में पर्याप्त कमी लाना है।

- यह मानता है कि आपदा जोखिम को कम करने में राज्य की प्राथमिक भूमिका है।
- इसका मानना है कि जिम्मेदारी स्थानीय सरकार, निजी क्षेत्र और अन्य हितधारकों सहित अन्य हितधारकों के साथ साझा की जानी चाहिए। (आपदा प्रबंधन की पुनर्कल्पना)
- सेंडई फ्रेमवर्क जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौते सहित अन्य 2030 एजेंडा समझौतों के साथ मिलकर काम करता है।

महत्व:-

- आपदा जोखिम न्यूनीकरण 2015-2030 के लिए सेंडई फ्रेमवर्क 2015 के बाद के विकास एजेंडे का पहला प्रमुख समझौता था।
- यह सदस्य राज्यों के विकास लाभ को आपदा के जोखिम से बचाने के लिए ठोस कार्रवाई प्रदान करता है।

अवश्य पढ़ें: जोशीमठ संकट

SOURCE: DOWN TO EARTH

वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व

संदर्भ: हाल ही में, 'वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व' बड़ी बिल्लियों के लिए मध्य प्रदेश का 7वां संरक्षित आवास बन गया है।

परिचय :-

- स्थान: मध्य प्रदेश के दमोह और नरसिंहपुर जिले में।
- क्षेत्रफल: 2,339 वर्ग किलोमीटर
- नामकरण: इसका नाम गोंडी लोगों की रानी रानी दुर्गावती के नाम पर रखा गया है।
- नदियाँ: रिज़र्व के कुछ क्षेत्र नर्मदा और यमुना नदी घाटियों में स्थित हैं।
- संस्कृति: सिंगोरगढ़ किला रिजर्व के अंदर पाया जा सकता है।
- वनस्पति: शुष्क पर्णपाती।
- फ़्लोरा: प्रमुख पुष्प तत्वों में सागौन, साजा, धौरा, बेर, आंवला आदि शामिल हैं।

जीव-जंतु:-

- यह अभयारण्य विभिन्न प्रकार के स्तनधारियों, कुल 18 अलग-अलग प्रजातियों के लिए आवास प्रदान करता है।
- इनमें तेंदुआ, भेड़िया, मायावी सियार (elusive jackal), तेज़ भारतीय लोमड़ी, आकर्षक धारीदार लकड़बग्घा और मनमोहक सुस्त भालू जैसे उल्लेखनीय जीव शामिल हैं।
- इन मनोरम स्तनधारियों के अलावा, अभयारण्य पक्षियों, मछलियों, सरीसृपों और उभयचरों की कई प्रजातियों के लिए भी निवास स्थान के रूप में कार्य करता है।

महत्व: -

- यह मध्य प्रदेश का सातवां बाघ अभयारण्य है। (बाघ संरक्षण का महत्व)
- इसमें नौरादेही वन्यजीव अभयारण्य और दुर्गावती वन्यजीव अभयारण्य के भीतर के क्षेत्र शामिल होंगे।
- नए रिजर्व में बाघों की प्राकृतिक आवाजाही के लिए पन्ना टाइगर रिजर्व (पीटीआर) को दुर्गावती से जोड़ने वाला एक हरित गलियारा विकसित किया जाएगा।

अवश्य पढ़ें: मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में बौद्ध गुफाएं, मंदिर

SOURCE: THE HINDU

कोले वेटलैंड्स

संदर्भ: केरल की कोले आर्द्रभूमि विदेशी पौधों के खतरे का सामना कर रही है।

पृष्ठभूमि:-

- बड़े पैमाने पर फूल आने के कारण लोकप्रिय रूप से पिंक ब्लूम के नाम से मशहूर काबोम्बा फरकुटा, कोले आर्द्रभूमियों के लिए जलकुंभी और साल्विनिया मोलेस्टा के अलावा एक नया खतरा बन गया है।

परिचय:

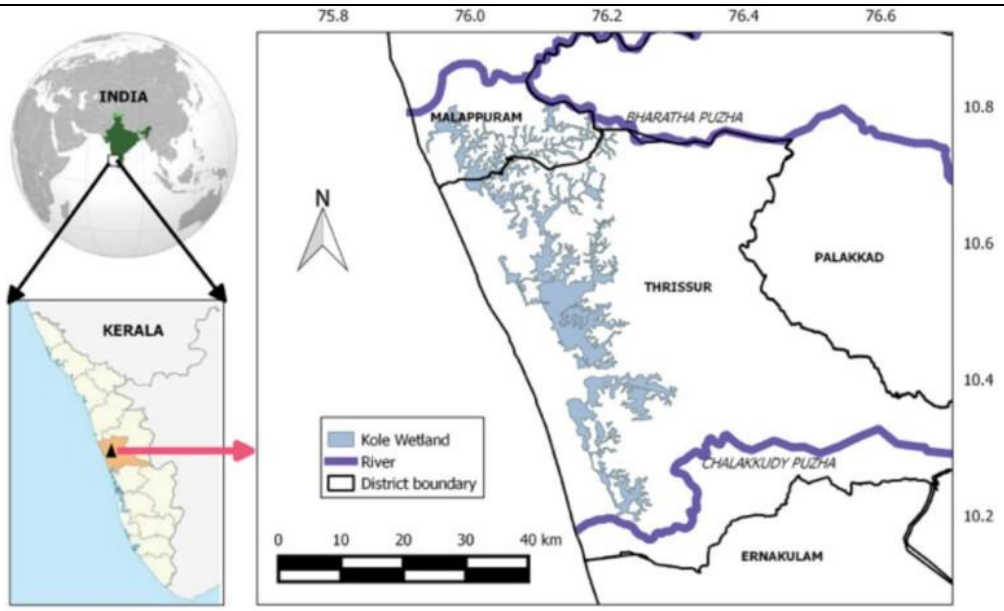

IMAGE SOURCE: fas.org.in

- स्थान: भारत के केरल में त्रिशूर और मलप्पुरम जिले।
- नदी: यह क्षेत्र दक्षिण में चलाकुडी नदी से लेकर उत्तर में भरतप्पुझा नदी और पोन्नानी तालुक तक फैला हुआ है।
- यह केरल की चावल की 40 प्रतिशत आवश्यकता को पूरा करता है।
- यह पोन्नानी शहर, त्रिशूर शहर, त्रिशूर जिले और मलप्पुरम जिले के लिए प्राकृतिक जल निकासी प्रणाली के रूप में कार्य करता है।
- यह केरल में सबसे बड़े, अत्यधिक उत्पादक और संकटग्रस्त आर्द्रभूमियों में से एक है।
- यह जलोढ़ मिट्टी के साथ उपजाऊ है जो मानसून में केचेरी और करुवन्नूर नदियों में जमा होती है।
- पक्षियों की संख्या के मामले में, त्रिशूर कोले वेटलैंड्स उड़ीसा में चिल्का झील और गुजरात में अमीपुर टैंक के बाद भारत में तीसरा सबसे बड़ा है। ('वेटलैंड्स ऑफ इंडिया' पोर्टल का शुभारंभ)
- यह प्रवासी पक्षियों के मध्य एशियाई फ्लाईवे में आता है।
- इसे बर्डलाइफ इंटरनेशनल द्वारा भारत के महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्रों में से एक के रूप में मान्यता दी गई है।
- यह एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण रामसर साइट है। (आर्द्रभूमि पर रामसर कन्वेंशन का COP14)
- यह अपनी उच्च जैव विविधता के लिए जाना जाता है।
- खतरा: इसे कैबोम्बा फुरकुटा नामक एक आक्रामक विदेशी पौधे की प्रजाति से एक नए खतरे का सामना करना पड़ रहा है, जिसे पिंक ब्लूम के नाम से भी जाना जाता है।

काबोम्बा फुरकुटा के बारे में:-

- काबोम्बा फुर्काटा वाटर शील्ड फैमली में जलीय पौधे की एक प्रजाति है।
- इसे सामान्य नाम रेड कैबोम्बा और फोर्क्ड फैनवॉर्ट से जाना जाता है।
- यह मध्य और दक्षिण अमेरिका का मूल निवासी है और उत्तर में क्यूबा और फ्लोरिडा के अंतिम छोर तक है।
- इसकी अधिकतम ऊंचाई 30 से 80 सेंटीमीटर के बीच होती है और चौड़ाई 8 सेंटीमीटर तक होती है।
- इसमें बैंगनी रंग के फूल लगते हैं।
- इसका उपयोग एक्वैरियम पौधे के रूप में किया जाता है।
- इसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलाना आमतौर पर आवश्यक होता है, क्योंकि इस पौधे को इष्टतम विकास के लिए उच्च प्रकाश और नियमित निषेचन की आवश्यकता होती है।
- भारत के केरल में इसे एक आक्रामक प्रजाति के रूप में रिपोर्ट किया गया है।
- इसका फैला हुआ तना प्रकाश को पानी की सतह में जाने नहीं देता है।

- यह जल निकायों का सूखा देता है, आर्थिक और पारिस्थितिक रूप से देशी जलीय पौधों और मीठे पानी की मछलियों के विकास में बाधा उत्पन्न करता है।
- इसके लिए भारी मात्रा में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, जिसके परिणामस्वरूप जैव विविधता और पानी की गुणवत्ता में गिरावट आती है।
- जबकि इसकी जीवंत गुलाबी उपस्थिति सुरम्य लग सकती है।
- यह क्षेत्र की जैव विविधता और कृषि उत्पादकता के लिए एक महत्वपूर्ण खतरा है।

अवश्य पढ़ें: आर्द्रभूमि संरक्षण

SOURCE: THE HINDU

कैमूर वन्यजीव अभयारण्य

संदर्भ: हाल की घोषणा के अनुसार, कैमूर वन्यजीव अभयारण्य बिहार में दूसरा बाघ अभयारण्य बन सकता है।

कैमूर वन्यजीव अभयारण्य के बारे में:-

- यह वर्ष 1979 में स्थापित किया गया।
- स्थान: भारत के बिहार का कैमूर जिला।
  - यह बिहार के दक्षिण-पश्चिमी भाग में, उत्तर प्रदेश और झारखंड की सीमाओं के करीब स्थित है।
- क्षेत्रफल: लगभग 1,504.96 वर्ग किलोमीटर
- पर्वत श्रृंखला: यह अभयारण्य कैमूर पहाड़ियों में एक व्यापक क्षेत्र को कवर करता है, जो विंध्य रेंज का हिस्सा हैं।
- कैमूर वन्यजीव अभयारण्य राज्य में एक महत्वपूर्ण वन्यजीव अभ्यारण्य है और क्षेत्र की जैव विविधता के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
- क्षेत्र की अद्वितीय जैव विविधता और इसके नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा की आवश्यकता को मान्यता देते हुए इस अभयारण्य को आधिकारिक तौर पर एक संरक्षित क्षेत्र के रूप में नामित किया गया था।
- यह अभयारण्य अपनी विविध वनस्पतियों और जीवों के लिए जाना जाता है।
- यह पौधों, जानवरों और पक्षियों की विभिन्न प्रजातियों के लिए प्राकृतिक आवास प्रदान करता है, जो क्षेत्र में पारिस्थितिक संतुलन में योगदान देता है।
- **वनस्पति:** पर्णपाती और उष्णकटिबंधीय शुष्क चौड़ी पत्ती वाले जंगलों का मिश्रण, जिसमें कई पौधों की प्रजातियां शामिल हैं जो इस क्षेत्र की मूल निवासी हैं।
- **फ़्लोरा:** साल अभयारण्य में पाई जाने वाली प्रमुख वृक्ष प्रजातियों में से एक है।
- अन्य वनस्पतियों में साजा, महुआ, सागौन बांस आदि शामिल हैं।
- **जीव-जंतु:** बंगाल टाइगर, भारतीय तेंदुए, भारतीय सूअर, भारतीय पैंगोलिन, स्लॉथ भालू, सांभर हिरण आदि।
- **पक्षी:** मोर, ग्रे पार्ट्रिज, बटेर, मालाबार पाइड हॉर्नबिल, स्वैलो, पैराडाइज़ फ्लाईकैचर, किंगफिशर, बुलबुल आदि।
  - सर्दियों के दौरान, यह अभयारण्य मध्य एशिया से कई पक्षी प्रजातियों के प्रवास का गवाह भी बनता है, जिनमें लेसर व्हाइट-फ्रंटेड गूज, फेरुगिनस डक, बेयर पोचार्ड डक, लेसर एडजुटेंट, ग्रेटर एडजुटेंट आदि शामिल हैं।

अवश्य पढ़ें: भारतीय वन्यजीव संस्थान (WII)

SOURCE: DOWN TO EARTH

वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM)

संदर्भ: हाल ही में, पंजाब ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) को पराली जलाने की समस्या से निपटने के लिए राज्य कार्य योजना और जिला-वार कार्य योजनाएँ प्रस्तुत कीं।

पृष्ठभूमि:-

- कार्य योजनाएं 2022 की तुलना में इस वर्ष धान की पराली जलाने की घटनाओं में 50% से अधिक की समग्र कमी लाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

परिचय :-

- स्थापना: वर्ष 2020 में

- यह एक स्थायी निकाय है। (वायु प्रदूषण)
- राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए आयोग की स्थापना की गई है।
- इसका उद्देश्य वायु गुणवत्ता सूचकांक और उससे जुड़े या उसके आनुषंगिक मामलों से जुड़ी समस्याओं का बेहतर समन्वय, अनुसंधान, पहचान और समाधान करना है।
- यह अंतर्निहित उपचारात्मक दृष्टिकोण के साथ दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और यूपी में वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए विविध प्रयासों के समन्वय और निगरानी के लिए एक वैधानिक तंत्र है।
- CAQM वायु प्रदूषण शमन के मामलों में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के साथ-साथ राज्य सरकारों सहित सभी मौजूदा निकायों को हटा देगा।
- महत्व: CAQM की स्थापना में वायु प्रदूषण की समस्या का समाधान करने की क्षमता है लेकिन एक संस्था अपने आप में कोई समाधान नहीं है।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि:-

- वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) की स्थापना अक्टूबर 2020 में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन अध्यादेश के तहत की गई थी।
- इस दौरान संसद का सत्र नहीं चल रहा था और ऐसे कानून की तत्काल आवश्यकता महसूस की गई।
- अध्यादेश 12 मार्च 2021 को समाप्त हो गया।
- परिणामस्वरूप, इसके लिए एक नया विधेयक प्रख्यापित किया गया। इसे दोनों सदनों और राष्ट्रपति की सहमति मिल गई, जिसके बाद 12 अगस्त 2021 को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन अधिनियम, 2021 पारित किया गया।
- CAQM का गठन 22 साल पुराने पर्यावरण प्रदूषण (रोकथाम और नियंत्रण) प्राधिकरण (EPCA) को भंग करने के बाद किया गया था।
- उद्देश्य:राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन करना।

आयोग के कार्य एवं शक्तियाँ:-

- आयोग NCR और उसके आसपास राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम, राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम और राष्ट्रीय परिवेश वायु गुणवत्ता मानकों को लागू करने के लिए तंत्र और साधन प्रदान करेगा।
- इसे वायु गुणवत्ता के पैरामीटर निर्धारित करने का काम सौंपा गया है।
- इस आयोग को उन गतिविधियों पर रोक लगाने का अधिकार है जिनसे एनसीआर में वायु प्रदूषण होने या बढ़ने की संभावना रहती है।
- आयोग स्वप्रेरणा से या व्यक्तियों और संगठनों की शिकायतों के आधार पर मामले उठा सकता है।
- यह केंद्र को एक वार्षिक रिपोर्ट सौंपेगा जिसे संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखा जाएगा।
- आयोग के प्रत्येक विनियमन और आदेश को संसद के समक्ष रखा जाएगा।
- आयोग विशेष रूप से पराली जलाने, औद्योगिक उत्सर्जन, सड़क की डस्ट, वाहन प्रदूषण, निर्माण गतिविधियों, बायोमास जलाने और वायु प्रदूषण के अन्य प्रमुख स्रोतों जैसे वायु प्रदूषण पैदा करने वाले कारकों को रोकने के लिए राज्यों द्वारा उठाए गए उपायों की निगरानी करेगा।

CAQM की संरचना:-

- अध्यक्ष: इसका एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होगा।
  - यह वह होगा "जो भारत सरकार का सचिव है या रहा है या किसी राज्य सरकार का मुख्य सचिव है"।
  - अध्यक्ष तीन वर्ष तक या 70 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक इस पद पर रहेगा।
- **राज्य प्रतिनिधि:** आयोग में पांच पदेन सदस्य भी होंगे जो या तो मुख्य सचिव हों, या दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश राज्यों में पर्यावरण संरक्षण से संबंधित विभाग के प्रभारी सचिव रहे हों।
- **विशेषज्ञ:** "वायु प्रदूषण से संबंधित मामलों में विशिष्ट वैज्ञानिक ज्ञान और अनुभव" वाले तीन पूर्णकालिक स्वतंत्र तकनीकी सदस्य; साथ ही सीपीसीबी से एक-एक तकनीकी सदस्य और इसरो द्वारा पदेन मनोनीत सदस्य होंगे।
- **सिविल सोसायटी:** वायु प्रदूषण से निपटने में अनुभव वाले गैर सरकारी संगठनों के तीन प्रतिनिधि होंगे।
- **अन्य:** इसमें नीति आयोग और कई मंत्रालयों के सदस्य होंगे।

अवश्य पढ़ें: राष्ट्रीय स्वच्छ वायु अभियान

SOURCE: PIB

पिंक बॉलवर्म

संदर्भ: पिंक बॉलवर्म के कारण होने वाला नुकसान राजस्थान से लेकर हरियाणा तक कपास के खेतों पर कहर बरपा रहा है।

पृष्ठभूमि: -

- पिंक बॉलवॉर्म (पीबीडब्ल्यू), एक अत्यधिक विनाशकारी कपास कीट, भारत के राजस्थान और हरियाणा राज्यों में संक्रमण के अभूतपूर्व स्तर तक पहुंच गया है, जिससे कपास की फसलें गंभीर रूप से प्रभावित हो रही हैं।

पिंक बॉलवर्म के बारे में:-

- पिंक बॉलवॉर्म कपास के सबसे विनाशकारी कीटों में से एक है।
- यह भारत का मूल निवासी है।
- यह मूल रूप से भारत में 1842 में रिपोर्ट किया गया था।
- यह अब दुनिया भर में कपास उगाने वाले क्षेत्रों में फैल गया है।
- वयस्क पिंक बॉलवर्म छोटे पतंगे होते हैं।
- इनके लार्वा सबसे हानिकारक चरण होते है, जिसे विशिष्ट गुलाबी बैंड द्वारा पहचाना जाता है।
- गुलाबी रंग का लार्वा आम तौर पर एक बीजकोष या बीज के अंदर, कूड़े में या भूमिगत कोकून में प्यूपा बनाता है।
- ये कपास के बीजों को खाते हैं, और रेशों को नुकसान पहुंचाते हैं।
- इससे फसल की पैदावार और गुणवत्ता में कमी आती है। (जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति)
- यह संक्रमण अन्य पौधों जैसे हिबिस्कस, ओक्रा और हॉलीहॉक को भी प्रभावित करता है।
- इस प्रकोप से कपास किसानों की आजीविका को खतरा है।
- यह तत्काल कीट प्रबंधन उपायों की मांग करता है। (एग्रीस्टैक प्रोजेक्ट)

अवश्य पढ़ें: GM फसलें और उनका विनियमन

SOURCE: THE INDIAN EXPRESS

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

दोध्रुवी विकार

संदर्भ: पाकिस्तानी एक्ट्रेस माहिरा खान ने हाल ही में खुलासा किया था कि वह बाइपोलर डिसऑर्डर से पीड़ित हैं।

परिचय :-

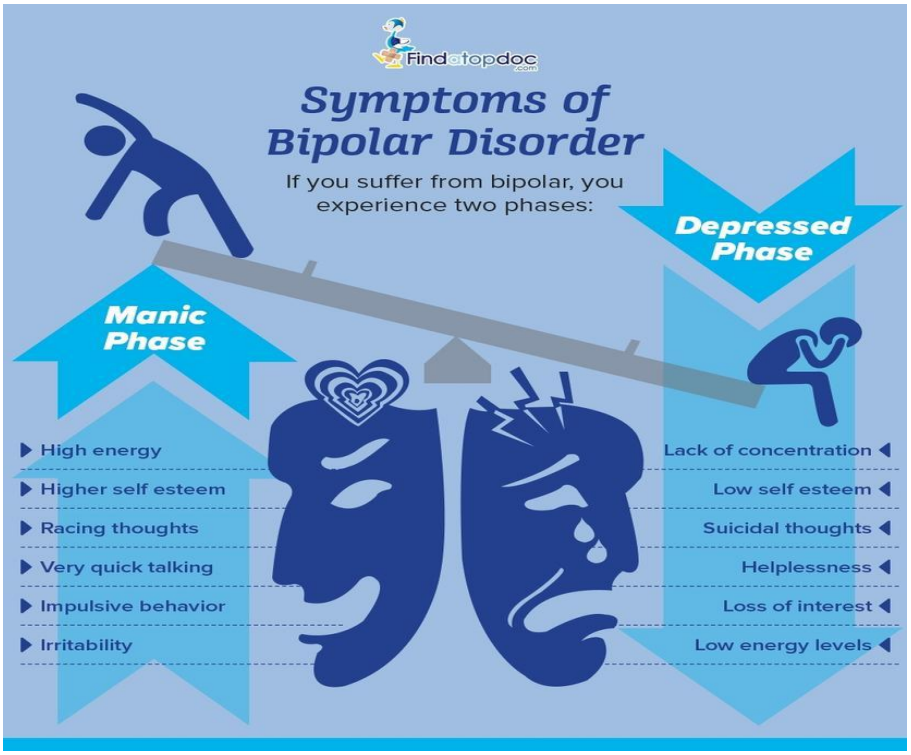

- यह एक मानसिक स्वास्थ्य स्थिति है जो गंभीर मूड स्विंग का कारण बनती है जिसमें भावनात्मक उतार-चढ़ाव (उन्माद या हाइपोमेनिया) और अवसाद शामिल हैं।
- स्थिति के लक्षण मूड और व्यवहार में अप्रत्याशित परिवर्तन का कारण बन सकते हैं, जिसके परिणामस्वरूप जीवन में महत्वपूर्ण संकट और कठिनाई हो सकती है। (मानसिक स्वास्थ्य)

द्विध्रुवी विकार के प्रकार:-

द्विध्रुवी और संबंधित विकार कई प्रकार के होते हैं।

द्विध्रुवी I:-

- कम से कम एक उन्मत्त चरण से पहले या बाद में एक प्रमुख अवसादग्रस्तता चरण होना। इसका परिणाम वास्तविकता से अलगाव या मनोविकृति भी हो सकता है।

द्विध्रुवी-II::-

- किसी को कम से कम एक प्रमुख अवसादग्रस्तता प्रकरण और कम से कम एक हाइपोमेनिक प्रकरण हुआ हो, लेकिन उसे कभी उन्मत्त प्रकरण न हुआ हो।

साइक्लोथिमिक विकार:

- बच्चों और किशोरों में कम से कम दो साल या एक वर्ष में हाइपोमेनिया के लक्षणों और अवसादग्रस्त लक्षणों की कई अवधियों का अनुभव हुआ है (हालांकि प्रमुख अवसाद से कम गंभीर)।

अन्य प्रकार:-

- इनमें कुछ दवाओं या शराब से या किसी चिकित्सीय स्थिति के कारण उत्पन्न द्विध्रुवी और संबंधित विकार शामिल हैं

द्विध्रुवी विकार के लक्षण:-

उन्माद के लक्षण ("उच्च"):-

- अत्यधिक खुशी, आशा और उत्साह

- खुशी होने से चिड़चिड़ा, क्रोधित और शत्रुतापूर्ण होने में अचानक परिवर्तन
- बेचैनी
- तेज़ आवाज और ख़राब एकाग्रता
- ऊर्जा में वृद्धि और नींद की कम आवश्यकता
- असामान्य रूप से उच्च सेक्स ड्राइव
- भव्य और अवास्तविक योजनाएँ बनाना
- ख़राब निर्णय शो करना
- अवसादग्रस्त अवधि के दौरान लक्षण ("लो "):-
- उदासी
- ऊर्जा की हानि
- निराशा या बेकार की भावनाएँ
- उन चीज़ों का आनंद न लेना जो उन्हें पहले पसंद थीं
- ध्यान केंद्रित करने में परेशानी होना
- भूलने की बीमारी
- धीरे-धीरे बात करना
- सेक्स ड्राइव का कम होना
- आनंद महसूस करने में असमर्थता
- बेकाबू रोना
- निर्णय लेने में परेशानी होना
- चिड़चिड़ापन

उपचार :-

- द्विध्रुवी विकार एक आजीवन स्थिति है, लेकिन उपचार योजना का पालन करके कोई भी व्यक्ति अपने मूड में बदलाव और अन्य लक्षणों को प्रबंधित कर सकता है।
- ज्यादातर मामलों में, द्विध्रुवी विकार का इलाज दवाओं और मनोवैज्ञानिक परामर्श (मनोचिकित्सा) से किया जाता है।

अवश्य पढ़ें: मानसिक स्वास्थ्य में कलंक और भेदभाव को चिन्हित करना

SOURCE: DOWN TO EARTH

स्पैमोफ्लैज

संदर्भ: मेटा ने हाल ही में दावा किया कि वह चीनी 'स्पैमोफ्लैज' ऑपरेशन से लड़ रहा है।

स्पैमोफ्लेज के बारे में:-

- यह एक ऑनलाइन चीनी स्पैम ऑपरेशन है। (साइबर हमले)
- यह चीन के बारे में सकारात्मक बातें और संयुक्त राज्य अमेरिका, पश्चिमी विदेश नीतियों और चीनी सरकार के आलोचकों के बारे में नकारात्मक टिप्पणी को बढ़ावा देता है।
- उत्पत्ति: चीन
- टारगेट: ताइवान, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, जापान और वैश्विक चीनी भाषी दर्शक।
- इसने यूरोप में मुख्यधारा के समाचार आउटलेट्स की वेबसाइटों की नकल की और यूक्रेन पर रूस के युद्ध के बारे में कहानियां पोस्ट कीं और फिर इसे ऑनलाइन विस्तार किया। (साइबर क्राइम)
- अभियान के खातों में राजनीतिक पोस्टों को आपस में जोड़ने की प्रवृत्ति होती है।
- यह फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, यूट्यूब और एक्स (पूर्व में ट्विटर) सहित 50 से अधिक प्लेटफार्मों और मंचों पर सक्रिय है।
- इस अभियान में शामिल कंपनियों को हाल ही में यूरोपीय संघ द्वारा मंजूरी दी गई थी।

अवश्य पढ़ें: वैश्विक साइबर सुरक्षा

SOURCE: TIMES OF INDIA

LIGO-भारत परियोजना

संदर्भ: हालिया रिपोर्टों के अनुसार, लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल-वेव ऑब्जर्वेटरी प्रोजेक्ट (एलआईजीओ)-भारत, चंद्रयान और आदित्य मिशन के बाद भारतीय वैज्ञानिकों का अगला फोकस है।

पृष्ठभूमि:-

- यह लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल-वेव ऑब्जर्वेटरी प्रोजेक्ट (एलआईजीओ) वेधशाला है।

परिचय:-

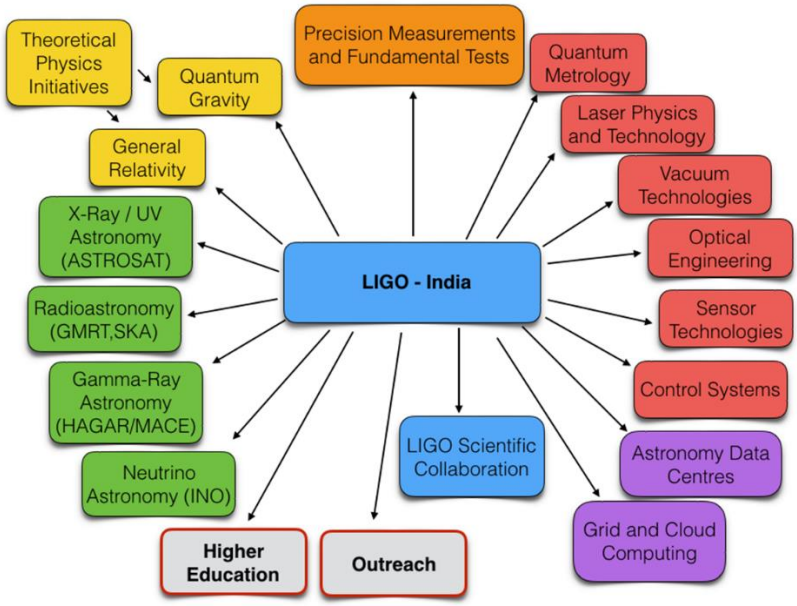

- स्थान: भारत के महाराष्ट्र का हिंगोली जिला
- दवारा निर्मित: परमाणु ऊर्जा विभाग और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने यू.एस. नेशनल साइंस फाउंडेशन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये।
- LIGO-इंडिया प्रोजेक्ट का लक्ष्य ब्रह्मांड से गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पता लगाना है।
    - गुरुत्वाकर्षण तरंगें: इन्हें सबसे पहले (1916) अल्बर्ट आइंस्टीन के सापेक्षता के सामान्य सिद्धांत में प्रतिपादित किया गया था।
    - ये तरंगें ब्लैक होल या न्यूट्रॉन सितारों जैसे विशाल आकाशीय पिंडों की गति से उत्पन्न होती हैं।
    - ये स्पेस टाइम तरंगें हैं जो बाहर की ओर फैलती हैं।
- आकाश में कहीं भी गुरुत्वाकर्षण तरंगों के स्रोत का पता लगाने के लिए चार तुलनीय डिटेक्टर दुनिया भर में एक साथ काम करेंगे।
- LIGO-इंडिया दुनिया में अपनी तरह का तीसरा होगा। (भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था)
- इसे अमेरिका में लुइसियाना (प्रथम) और वाशिंगटन (द्वितीय) में जुड़वां LIGO के सटीक विनिर्देशों के अनुसार बनाया गया है।
- चौथा डिटेक्टर जापान के कागरा में होगा।
    - LIGO: यह प्रयोगशालाओं का एक अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क जो गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पता लगाता है।
    - अमेरिका में LIGO ने पहली बार वर्ष 2015 में गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पता लगाया, जिसके कारण 2017 में भौतिकी में नोबेल पुरस्कार मिला।

महत्व:-

- यह भारत को एक प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिक प्रयोग में लाएगा।
- यह खगोल विज्ञान, खगोल भौतिकी और अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी में प्रगति लाएगा।

अवश्य पढ़ें: स्पेसटेक इनोवेशन नेटवर्क (स्पिन)

SOURCE: THE INDIAN EXPRESS

निपाह वायरस (NiV)

संदर्भ: हाल ही में केरल राज्य में निपाह वायरस (NiV) का प्रकोप हुआ है।

पृष्ठभूमि:-

- नवीनतम प्रकोप में दो लोगों की मौत हो गई है और दो अन्य को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिनमें से एक की हालत गंभीर है।
- राज्य सरकार ने उभरती स्थिति पर नजर रखने के लिए एक नियंत्रण कक्ष स्थापित किया है।
- राज्य में सबसे पहले NiV 2018 में कोझिकोड जिले में रिपोर्ट किया गया था।

परिचय:-

- निपाह वायरस (NiV) एक ज़ूनोटिक वायरस है।
  - ज़ूनोटिक वायरस: यह जानवरों से मनुष्यों में फैलता है।
- नेचुरल होस्ट: फ्रूट बट्स (टेरोपोडिडे परिवार)
- इन्क्यूबेशन पीरियड: 4 से 14 दिन।
  - ऊष्मायन अवधि: संक्रमण से लक्षणों की शुरुआत तक का अंतराल।
- मृत्यु दर: 40% से 75%
- निपाह वायरस को पहली बार 1999 में मलेशिया में सुअर पालकों के बीच फैलने के दौरान पहचाना गया था। (जीका वायरस रोग)
- इसे 2001 में बांग्लादेश में भी मान्यता दी गई थी, और तब से उस देश में लगभग वार्षिक प्रकोप हुआ है।
- पूर्वी भारत में भी समय-समय पर इस बीमारी की पहचान की गई है।
- प्राथमिकता वाली बीमारियों की WHO R&D ब्लूप्रिंट सूची की 2018 की वार्षिक समीक्षा से संकेत मिलता है कि निपाह वायरस के लिए त्वरित शोध और विकास की तत्काल आवश्यकता है।

ट्रांसमिशन:-

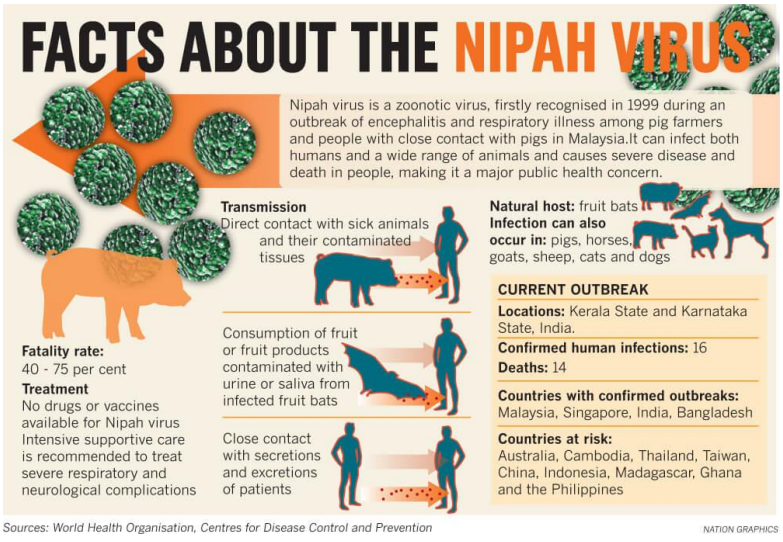

- निपाह वायरस जानवरों (जैसे चमगादड़ या सूअर), या दूषित खाद्य पदार्थों से मनुष्यों में फैलता है।
- संक्रमित रोगियों के परिवारों और देखभाल करने वालों के बीच निपाह वायरस के मानव-से-मानव संचरण की भी सूचना मिली है।

संकेत और लक्षण:-

- मानव संक्रमण स्पर्शोन्मुख संक्रमण से लेकर तीव्र श्वसन संक्रमण (हल्का, गंभीर) और घातक एन्सेफलाइटिस तक होता है।
- संक्रमित लोगों में शुरू में बुखार, सिरदर्द, मायलगिया (मांसपेशियों में दर्द), उल्टी और गले में खराश जैसे लक्षण विकसित होते हैं।
- इसके बाद चक्कर आना, सुस्ती, व्याकुलता और न्यूरोलॉजिकल संकेत हो सकते हैं जो तीव्र एन्सेफलाइटिस का संकेत देते हैं।
- कुछ लोगों को तीव्र श्वसन संकट सहित असामान्य निमोनिया और गंभीर श्वसन समस्याओं का भी अनुभव हो सकता है।
- गंभीर मामलों में एन्सेफलाइटिस और दौरे पड़ते हैं, जो 24 से 48 घंटों के भीतर कोमा में चले जाते हैं।

निदान:-

- निपाह वायरस संक्रमण का निदान रोग के तीव्र और स्वास्थ्य लाभ चरणों के दौरान क्लीनिकल हिस्ट्री से किया जा सकता है।
- उपयोग किए जाने वाले मुख्य परीक्षण हैं:-
    - शारीरिक तरल पदार्थों से वास्तविक समय पोलीमरेज़ श्रृंखला प्रतिक्रिया (आरटी-पीसीआर)।
    - एंजाइम-लिंक्ड इम्युनोसॉरबेंट परख (एलिसा) के माध्यम से एंटीबॉडी का पता लगाना।
    - पॉलीमरेज़ चेन रिएक्शन (पीसीआर) परख
    - सेल कल्चर द्वारा वायरस अलगाव।

इलाज:-

- वर्तमान में निपाह वायरस संक्रमण के लिए विशिष्ट कोई दवा या टीका नहीं है।
- WHO ने निपाह को WHO अनुसंधान और विकास ब्लूप्रिंट के लिए एक प्राथमिकता वाली बीमारी के रूप में पहचाना है।
- गंभीर श्वसन और तंत्रिका संबंधी जटिलताओं के इलाज के लिए गहन सहायक देखभाल की सिफारिश की जाती है।

रोकथाम:-

- चमगादड़ से मनुष्य में संचरण के जोखिम को कम करना: खजूर के रस और अन्य ताजे खाद्य उत्पादों तक चमगादड़ों की पहुंच कम करना।
- पशु-से-मानव में संचरण के जोखिम को कम करना: बीमार जानवरों या उनके ऊतकों को संभालते समय और वध करने और मारने की प्रक्रियाओं के दौरान दस्ताने और अन्य सुरक्षात्मक कपड़े पहनने चाहिए।
- मानव-से-मानव संचरण के जोखिम को कम करना: निपाह वायरस से संक्रमित लोगों के साथ असुरक्षित शारीरिक संपर्क से बचना चाहिए।

MUST READ:Zombie Virus

SOURCE: DOWN TO EARTH

प्रोबायोटिक्स

संदर्भ: हाल के अध्ययनों से कोलेस्ट्रॉल कम करने में प्रोबायोटिक्स की सकारात्मक भूमिका सामने आई है।

पृष्ठभूमि:-

- कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए प्रोबायोटिक्स का उपयोग रुचि का एक आगामी क्षेत्र है और शोध आशाजनक है।
- ऐसा माना जाता है कि प्रोबायोटिक्स कई तंत्रों के माध्यम से कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने में मदद करता हैं।
- इनमें कोलेस्ट्रॉल को कोशिकाओं में शामिल करने में मदद करना और मल के माध्यम से कोलेस्ट्रॉल को खत्म करने के लिए आंत के माइक्रोबायोम को समायोजित करना शामिल है।
- वर्ष 2018 के एक अध्ययन में, शोधकर्ताओं ने 32 अध्ययनों के परिणामों को एकत्रित किया और मेटा-विश्लेषण के रूप में जाने जाने वाले एक प्रकार के अध्ययन में उन सभी का एक साथ विश्लेषण किया।
- जिन लोगों ने प्रोबायोटिक्स लिया उनका कुल कोलेस्ट्रॉल स्तर 13 प्रतिशत कम हो गया।
- अन्य व्यवस्थित समीक्षाएँ इन निष्कर्षों का समर्थन करती हैं। (भारतीय वैज्ञानिकों ने अगली पीढ़ी का प्रोबायोटिक विकसित किया)

प्रोबायोटिक्स के बारे में:-

- प्रोबायोटिक्स जीवित लाभकारी बैक्टीरिया और/या यीस्ट का एक संयोजन हैं।
- प्रोबायोटिक सप्लीमेंट हमारे शरीर में अच्छे बैक्टीरिया जोड़ने का एक तरीका है।
- प्रोबायोटिक समुदाय रोगाणुओं नामक चीज़ों से बना होता है।
- हमारे शरीर पर और अंदर खरबों रोगाणु मौजूद हैं।
- ये रोगाणुओं का एक संयोजन है:
    - बैक्टीरिया
    - कवक (यीस्ट सहित)
    - वायरस
    - प्रोटोजोआ
- हर किसी का माइक्रोबायोम अद्वितीय होता है।
- किन्हीं दो लोगों में एक जैसी माइक्रोबियल कोशिकाएं नहीं होती हैं।

- जुड़वाँ बच्चे भी अलग-अलग होते हैं।

- प्रोबायोटिक बैक्टीरिया का सबसे आम प्रकार लैक्टोबैसिलस और बिफीडोबैक्टीरियम है।
- प्रोबायोटिक्स भी अच्छे यीस्टस से बने होते हैं।
  - प्रोबायोटिक्स में पाया जाने वाला सबसे आम प्रकार का यीस्ट सैक्रोमाइसेस बौलार्डी है।

कार्य तंत्र:-

- हमारे शरीर में लगातार अच्छे और बुरे दोनों तरह के बैक्टीरिया मौजूद रहते हैं। (iNCOVACC)
- जब हमें कोई संक्रमण होता है, तो अधिक खराब बैक्टीरिया होते हैं, जो आपके सिस्टम को असंतुलित कर देते हैं।
- यह आंतों में अच्छे बैक्टीरिया के बैलेंस को रीस्टोर करके काम करता है।

अवश्य पढ़ें: राष्ट्रीय जैविक संस्थान (एनआईबी)

SOURCE: DOWN TO EARTH

इंजीनियर्स डे

संदर्भ: हाल ही में इंजीनियर्स डे 2023 मनाया गया।

पृष्ठभूमि:-

- यह 15 सितंबर को मनाया गया।
- 15 सितंबर को श्रीलंका और तंजानिया में भी इंजीनियर दिवस मनाया जाता है।

परिचय :-

- यह दिन विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एम विश्वेश्वरैया द्वारा दिए गए योगदान को मान्यता देने के लिए मनाया जाता है।
- जन्म: वर्ष 1861
- एम विश्वेश्वरैया का जन्म कर्नाटक के बेंगलुरु के पास चिक्काबल्लापुर में एक तेलुगु परिवार में हुआ था।
- उन्हें आधुनिक मैसूर के जनक के रूप में जाना जाता था। उनका पूरा नाम मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया है।
- अपने गृहनगर में अपनी औपचारिक स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद, विश्वेश्वरैया मद्रास विश्वविद्यालय में बीए की पढ़ाई करने गए।
- हालाँकि, बाद में उन्होंने स्विच किया और पुणे में कॉलेज ऑफ साइंस से सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया।
- वह बाढ़ आपदा प्रबंधन और सिंचाई तकनीकों में निपुण थे।
- उन्हें सिंचाई तकनीक और बाढ़ नियंत्रण में उनके काम के लिए पहचाना गया।
- वह वर्ष 1912 से 1918 तक मैसूर के दीवान रहे।

योगदान:

- वह मैसूर में कृष्ण राजा सागर बांध के निर्माण के लिए जिम्मेदार मुख्य अभियंता थे।
- उन्होंने 1903 में स्वचालित जल फ्लडगेट का डिज़ाइन और पेटेंट कराया, जो पहली बार पुणे के खडकवासला जलाशय में स्थापित किए गए थे।
- वर्ष 1917 में, विश्वेश्वरैया ने बेंगलुरु में सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना की, जिसे बाद में उनके सम्मान में यूनिवर्सिटी विश्वेश्वरैया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग नाम दिया गया।
- उन्होंने बैंगलोर कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की।
- वह भारत में आर्थिक नियोजन के एक प्रसिद्ध अग्रदूत थे।

पुरस्कार:

- वर्ष 1955 में, भारत सरकार ने उन्हें उनकी कई औद्योगिक, आर्थिक और सामाजिक परियोजनाओं के लिए सर्वोच्च नागरिक सम्मान - भारत रत्न से सम्मानित किया।
- उन्हें किंग जॉर्ज पंचम द्वारा ब्रिटिश नाइटहुड से भी सम्मानित किया गया था, जिससे उन्हें "सर" की उपाधि मिली।

जरूर पढ़ें: सत्येंद्र नाथ बोस

SOURCE: THE INDIAN EXPRESS

TTPs (रणनीति, तकनीक और प्रक्रियाएं)-आधारित साइबर अपराध जांच ढांचा

संदर्भ: टीटीपी (रणनीति, तकनीक और प्रक्रिया) नामक एक नया साइबर अपराध जांच उपकरण-आधारित साइबर अपराध जांच ढांचा हाल ही में विकसित किया गया था।

पृष्ठभूमि:-

- एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि यह मामले को सुलझाने के लिए आवश्यक सबूतों की श्रृंखला की पहचान करने और अपराधियों को दोषी ठहराने के लिए सबूतों को मैप करने के लिए साइबर अपराधों को ट्रैक करने और वर्गीकृत करने में मदद कर सकता है।

परिचय :-

- द्वारा विकसित: विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) के सहयोग से आईआईटी कानपुर में आई-हब NTIHAC फाउंडेशन (c3ihub)।
- इसे नेशनल मिशन ऑन इंटरडिसिप्लिनरी साइबर-फिजिकल सिस्टम्स (एनएम-आईसीपीएस) के तहत विकसित किया गया है।
- यह अपराध निष्पादन जीवन चक्र में साइबर अपराधियों के संचालन के तरीकों को पकड़ने के लिए एक पद्धति और उपकरण है।
- इसे साहित्य अध्ययन, केस अध्ययन और रूपरेखा निर्माण की मदद से विकसित किया गया था।
- इसने फ्रेमवर्क में पहले से मौजूद अपराध को शामिल किया, इंटरैक्टिव फ्रेमवर्क नेविगेटर को विकसित किया और वास्तविक मामलों को फ्रेमवर्क पर मैप किया।
- प्रौद्योगिकी एक अनुमानित अपराध निष्पादन मार्ग बना सकती है और उपयोगकर्ता-व्युत्पन्न कीवर्ड के सेट के आधार पर अपराध पथ का सुझाव दे सकती है। (साइबर हमले)
- यह विभिन्न अपराधों में उपयोग किए जाने वाले तौर-तरीकों की तुलना भी कर सकता है, उपयोगकर्ता की भूमिकाएं प्रबंधित कर सकता है और अपराध पथों के लिए गतिविधि को ट्रैक कर सकता है।

महत्व:-

- यह किसी मामले को सुलझाने के लिए आवश्यक सबूतों की श्रृंखला की पहचान करता है और अपराधियों को दोषी ठहराने के लिए सबूतों को रूपरेखा पर मैप करता है।
- यह अत्यधिक प्रभावी हो सकता है क्योंकि यह जांच किए जाने वाले रूपों और तरीकों की संख्या को प्रतिबंधित करता है और मुख्य रूप से अपराधियों के टीटीपी पर निर्भर करता है।
    - इससे साइबर अपराधियों को सटीक और त्वरित सजा मिल सकेगी। (साइबर सुरक्षा)

टीटीपी ट्रायंगल के बारे में:-

- रणनीति: रणनीति उन तकनीकी उद्देश्यों ("क्यों") का वर्णन करती है जो एक हमलावर एक कार्रवाई कर रहा है।
- तकनीक: हमलावर द्वारा अपने हमले में शामिल होने के लिए उपयोग की जाने वाली विधियों का वर्णन कीजिए।
- प्रक्रियाएं: किसी हमले में उपयोग किए गए घटकों का विस्तृत विवरण, जिसमें हमलावरों द्वारा उपयोग किए गए उपकरण और अभ्यास शामिल हैं।

अवश्य पढ़ें: भारत का साइबर बुनियादी ढांचा

SOURCE: BUSINESSLINE

पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम (PCOS)

संदर्भ: हाल के अध्ययन शैक्षणिक तनाव और पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम (पीसीओएस) के बीच एक स्पष्ट संबंध स्थापित का रहे हैं।

पृष्ठभूमि:-

- सितंबर में पीसीओएस जागरूकता माह के बीच, एक चिंताजनक वास्तविकता सामने आती है कि शैक्षणिक दबाव अनजाने में युवा लड़कियों के बीच एक साइलेंट हेल्थ क्राइसिस में योगदान कर सकता है।

पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम (पीसीओएस) के बारे में:-

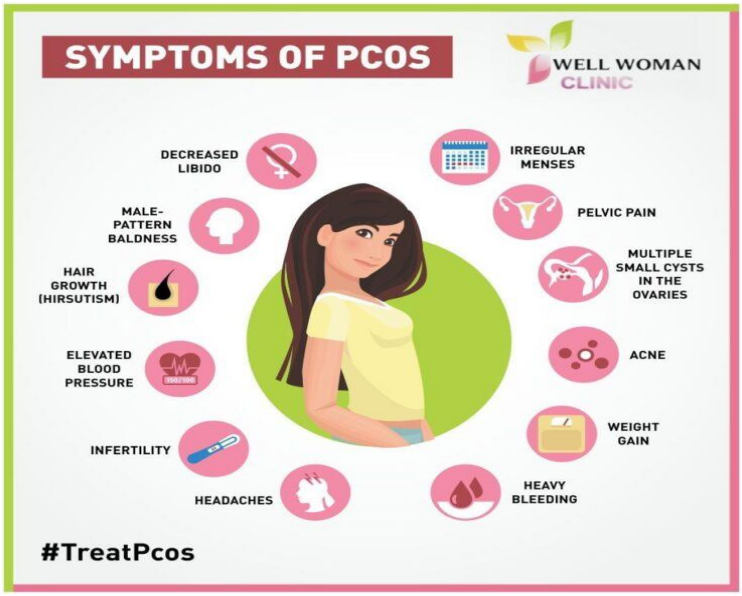

- पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम (पीसीओएस) एक हार्मोनल असंतुलन है जो तब होता है जब अंडाशय अतिरिक्त हार्मोन बनाते हैं।
    - अंडाशय: वह अंग जो अंडे पैदा करता है और रिलीज़ करता है।
- PCOS एक "सिंड्रोम" या लक्षणों का समूह है जो अंडाशय और ओव्यूलेशन को प्रभावित करता है।
- इसकी तीन मुख्य विशेषताएं हैं:
    - अंडाशय में सिस्ट
    - पुरुष हार्मोन का उच्च स्तर
    - अनियमित या छूटी हुई माहवारी
- PCOS महिलाओं को उनके बच्चे पैदा करने के वर्षों (15 से 44 वर्ष) के दौरान प्रभावित करता है।
- इस आयु वर्ग की 2.2 से 26.7 प्रतिशत महिलाओं को पीसीओएस है।
- PCOS सामान्य मासिक धर्म चक्र को बाधित करता है और गर्भवती होने को कठिन बना देता है।
- PCOS से पीड़ित 70 से 80 प्रतिशत महिलाओं में प्रजनन संबंधी समस्याएं होती हैं। (इन विट्रो फर्टिलाइजेशन (आईवीएफ) प्रक्रिया)

कारण:-

- PCOS किन कारणों से होता है इसका सटीक कारण अभी तक ज्ञात नहीं है।
- ऐसा माना जाता है कि पुरुष हार्मोन का उच्च स्तर अंडाशय को हार्मोन का उत्पादन करने और सामान्य रूप से अंडे बनाने से रोकता है।
- जीन, इंसुलिन प्रतिरोध और सूजन सभी को अतिरिक्त एण्ड्रोजन निर्माण से जोड़ा गया है।

PCOS के सामान्य लक्षण:-

- अनियमित माहवारी: ओव्यूलेशन की कमी हर महीने गर्भाशय की परत को गिरने से रोकती है।
- भारी रक्तस्राव: गर्भाशय की परत का निर्माण लंबे समय तक होता है, इसलिए आपको होने वाली माहवारी सामान्य से अधिक भारी हो सकती है।
- बालों का बढ़ना: इस स्थिति से पीड़ित 70 प्रतिशत से अधिक महिलाओं के चेहरे और पीठ, पेट और चेस्ट सहित शरीर पर बाल उग आते हैं।
- मुँहासे: पुरुष हार्मोन त्वचा को सामान्य से अधिक तैलीय बनाते हैं और चेहरे, चेस्ट और ऊपरी पीठ जैसे क्षेत्रों में मुँहासे पैदा करते हैं।
- भार बढ़ना: पीसीओएस से पीड़ित 80 प्रतिशत महिलाएं अधिक वजन वाली या मोटापे से ग्रस्त हैं।
- पुरुष पैटर्न गंजापन: सिर पर बाल पतले हो जाते हैं और झड़ सकते हैं।
- त्वचा का काला पड़ना: त्वचा के काले धब्बे शरीर की सिलवटों में बन सकते हैं जैसे गर्दन पर, कमर में और स्तनों के नीचे।
- सिरदर्द: कुछ महिलाओं में हार्मोन परिवर्तन के कारण सिरदर्द हो सकता है।

सामान्य चिकित्सा उपचार:-

- जन्म नियंत्रण गोलियाँ और अन्य दवाएं मासिक धर्म चक्र को विनियमित करने और बालों के विकास और मुँहासे जैसे पीसीओएस लक्षणों का इलाज करने में मदद कर सकती हैं।

जरूर पढ़ें: देश में बच्चों में एनीमिया पर नियंत्रण

SOURCE: THE HINDU

मिशन साइकी (Psyche)

संदर्भ: नेशनल एयरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन (NASA) जल्द ही एक साइकी मिशन लॉन्च करेगा।

परिचय :-

- लॉन्च तिथि: 5 अक्टूबर 2023
- प्रक्षेपण स्थल: नासा का कैनेडी स्पेस सेंटर, फ्लोरिडा, यूएसए।
- लॉन्चवाहन: स्पेसएक्स फाल्कन हेवी।
- साइकी, साइकी नामक धातु-समृद्ध क्षुद्रग्रह का अध्ययन करने के लिए नासा का एक मिशन है।

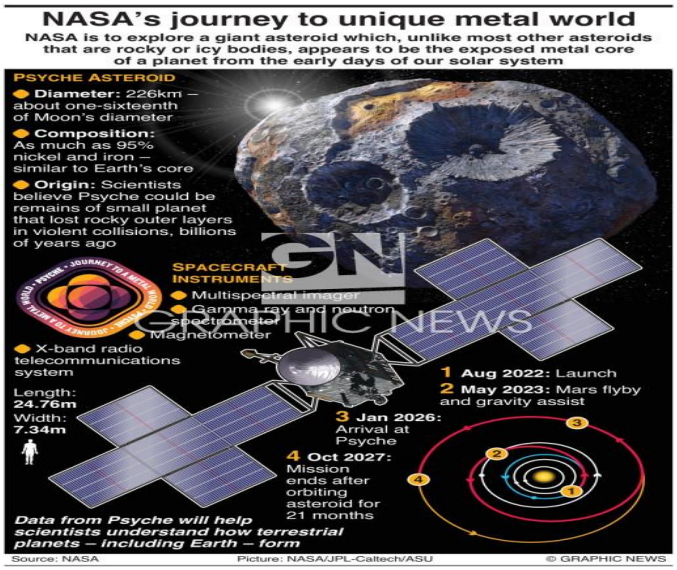

- क्षुद्रग्रह मानस मंगल और बृहस्पति के बीच मुख्य क्षुद्रग्रह बेल्ट में स्थित है।
- यह किसी क्षुद्रग्रह का अध्ययन करने वाला नासा का पहला मिशन है जिसमें चट्टान या बर्फ की तुलना में अधिक धातु है।
- क्षुद्रग्रह, जिसे साइकी भी कहा जाता है, की यात्रा लगभग छह वर्षों तक होगी।
- यह लगभग 3.6 अरब किलोमीटर की दूरी तय करेगा।
- साइकी अंतरिक्ष यान का आकार लगभग एक छोटी वैन के आकार का है।
- यह सौर विद्युत प्रणोदन द्वारा संचालित है।
- इसमें क्षुद्रग्रह साइकी का अध्ययन करने के लिए एक मैग्नेटोमीटर, एक गामा-रे और न्यूट्रॉन स्पेक्ट्रोमीटर और एक मल्टीस्पेक्ट्रल इमेजर है।
- जैसे ही अंतरिक्ष यान क्षुद्रग्रह को देखेगा, वह पृथ्वी पर तस्वीरें भेजना शुरू कर देगा।
- क्षुद्रग्रह मंगल और बृहस्पति के बीच सूर्य की परिक्रमा करता है। (नासा का इनसाइट मंगल मिशन)
- ऐसा माना जाता है कि यह ग्रहाणु का अवशेष कोर है, जो मुख्य रूप से लौह-निकल धातु से बना है।
- हालांकि क्षुद्रग्रह के खनन की कोई योजना नहीं है, कक्षा से इसका अध्ययन करने से पृथ्वी के कोर की संरचना में अमूल्य अंतर्दृष्टि मिल सकती है।
- अपने प्राथमिक मिशन के अलावा, साइकी अंतरिक्ष यान एक अग्रणी प्रौद्योगिकी प्रदर्शन की भी मेजबानी करेगा जिसे नासा के डीप स्पेस ऑप्टिकल कम्युनिकेशंस (डीएसओसी) प्रयोग के रूप में जाना जाता है। (निसार उपग्रह)
- यह प्रयोग अंतरिक्ष में विशाल दूरी तक डेटा प्रसारित करने के तरीके में क्रांतिकारी बदलाव ला सकता है, जिससे संभावित रूप से सौर मंडल की सबसे दूर तक पहुंच का पता लगाने की हमारी क्षमता में वृद्धि होगी।
- **महत्व:** यह मिशन प्रारंभिक सौर मंडल और स्थलीय ग्रहों के निर्माण की हमारी समझ में एक महत्वपूर्ण कदम का प्रतिनिधित्व करता है।

अवश्य पढ़ें: नासा का डार्ट मिशन

SOURCE: INDIA TODAY

सिट्रान

संदर्भ: भोपाल में भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (आईआईएसईआर) के शोधकर्ताओं ने हाल ही में एक सर्कुलर आरएनए वायरस, सिट्रान की पहचान की है।

पृष्ठभूमि:-

- यह विकास संभावित रूप से एचआईवी-1 से लड़ने के लिए नवीन दवाओं और उपचारों को जन्म दे सकता है।

सिट्रान के बारे में:-

- यह एक सर्कुलर आरएनए वायरस है।
- RNA सामान्य रूप से सीधी-श्रृंखला, मुक्त-अंत संरचनाएं हैं लेकिन ये वृत्ताकार RNA ('सर्कRNA') एक बंद-लूप बनाते हैं।
- सर्कैना जीन अभिव्यक्ति को विनियमित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और विभिन्न जैविक प्रक्रियाओं के लिए आवश्यक है।
- HIV-1 प्रतिकृति में इसकी भूमिका लंबे समय तक अस्पष्ट रही है।
- वृत्ताकार RNA को चिह्नित करना मुश्किल हो सकता है क्योंकि यह आमतौर पर कम प्रचुर मात्रा में होता है, जिससे मूल रूप में इसका पता लगाना और भी चुनौतीपूर्ण हो जाता है।
- वायरल संक्रमण के दौरान, वायरस से इतनी अधिक जानकारी मिलती है कि सर्कुलर RNA जैसे कम आम संक्रमणों को ढूंढना मुश्किल हो सकता है।

हालिया अध्ययन के निहितार्थों के बारे में:-

- शोधकर्ताओं ने HIV-1 वायरस से संक्रमित टी-कोशिकाओं (श्वेत रक्त कोशिकाओं) से circRNAs को सफलतापूर्वक पकड़ने के लिए 'circDR-Seq' नामक एक नया दृष्टिकोण विकसित किया और ciTRAN नामक एक विशिष्ट circRNA की पहचान की है। यह वायरस के गुणन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
- HIV-1 वायरल प्रोटीन आर (VpR) एक बहुक्रियाशील प्रोटीन है जो HIV-1 वायरल जीवन चक्र के कई चरणों में विशिष्ट भूमिका निभाता है और प्रतिरक्षा कोशिकाओं के एचआईवी-विरोधी कार्यों को प्रभावित करता है।
- आगे पाया गया कि HIV-1 संक्रमण VpR-निर्भर तरीके से सिट्रान अभिव्यक्ति को प्रेरित करता है और सिट्रान सेरीन/आर्जिनिन-समृद्ध स्प्लिसिंग फैक्टर 1 (SRSF1) के साथ इंटरैक्ट करता है, जो एक प्रोटीन है जो HIV-1 प्रतिलेखन को दबाने के लिए जाना जाता है।"

HIV-1 प्रतिकृति में सिट्रान की भूमिका का अनावरण:-

- एक हालिया अध्ययन में, IISER भोपाल के शोधकर्ताओं ने प्रत्यक्ष RNA नैनोपोर अनुक्रमण का उपयोग करते हुए, circDR-Seq नामक एक विशेष प्रोटोकॉल तैयार किया।
- इस अभिनव दृष्टिकोण के माध्यम से, वे HIV-1-संक्रमित टी कोशिकाओं (श्वेत रक्त कोशिकाओं) से circRNAs को कैप्चर करने में सक्षम थे और ciTRAN के अस्तित्व को इंगित किया, एक circRNA जो HIV-1 प्रतिलेखन पर प्रभाव डालता है।

नवीन औषधियों और उपचारों की संभावनाएँ

- यह समझना कि सिट्रान वायरस की प्रतिलेखन प्रक्रिया को कैसे नियंत्रित करता है, साथ ही HIV-1 के खिलाफ लड़ाई में गेम-चेंजर हो सकता है।
- यह नया ज्ञान इस लगातार बने रहने वाले वायरस से निपटने के लिए नवीन दवाओं और उपचारों के विकास के द्वार खोलता है।

MUST READ: mRNA Vaccine

SOURCE: DOWN TO EARTH

कैलिप्सो मिशन

संदर्भ: हाल ही में, NASA के CALIPSO मिशन ने 17 वर्षों के बाद पृथ्वी पर लेजर विस्फोट करना बंद कर दिया।

पृष्ठभूमि: -

- नासा ने हाल ही में घोषणा की कि उसके कैलिप्सो उपग्रह, जो LIDAR का उपयोग करके जलवायु, मौसम और वायु गुणवत्ता माप लेता है, ने अपना विज्ञान मिशन समाप्त कर दिया है।

कैलिप्सो मिशन के बारे में:-

- लॉन्च दिनांक: 28 अप्रैल, 2006

- लॉन्च स्थान: वैंडेनबर्ग एयर फ़ोर्स बेस, कैलिफ़ोर्निया, यूएसए।
- प्रक्षेपण यान: डेल्टा II रॉकेट। (लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान (एसएसएलवी))
- अंतरिक्ष यान: प्रोटियस
- ऑर्बिट के प्रकार: सूर्य-तुल्यकालिक
- कैलिप्सो एक संयुक्त अमेरिकी (नासा)/फ्रांसीसी (सेंटर नेशनल डी'एट्यूड्स स्पैटियल्स/सीएनईएस) मिशन है।
- निष्क्रिय इमेजरी के साथ संयुक्त अंतरिक्ष जनित लिडार के अवलोकन से पृथ्वी की जलवायु को विनियमित करने में एरोसोल और बादलों की भूमिका की बेहतर समझ पैदा होगी, विशेष रूप से, एरोसोल और बादल एक दूसरे के साथ कैसे इंटरैक्ट करते हैं।

मिशन का उद्देश्य:-

- कैलिप्सो का प्राथमिक उद्देश्य बादलों और एरोसोल (वायुमंडल में निलंबित छोटे ठोस और तरल कण) और पृथ्वी की जलवायु प्रणाली में उनकी भूमिकाओं के बारे में हमारी समझ को बढ़ाना है।
- कैलिप्सो का लक्ष्य प्रमुख वायुमंडलीय मापदंडों की निगरानी करके जलवायु परिवर्तन अनुसंधान के लिए मूल्यवान डेटा प्रदान करना है।
- मिशन वास्तविक समय वायुमंडलीय डेटा प्रदान करके बेहतर वायु गुणवत्ता आकलन और मौसम पूर्वानुमान में योगदान देता है।

उपकरण:-

- **लिडार प्रौद्योगिकी:** CALIPSO एक लिडार (प्रकाश का पता लगाने और रेंजिंग) उपकरण से सुसज्जित है, जिसे CALIOP (ऑर्थोगोनल पोलराइजेशन के साथ क्लाउड-एयरोसोल लिडार) के रूप में जाना जाता है।
- यह उच्च परिशुद्धता के साथ बादलों और एरोसोल की ऊंचाई और गुणों को मापने के लिए लेजर पल्स का उपयोग करता है।
- **निष्क्रिय सेंसर:** उपग्रह में इमेजिंग इन्फ्रारेड रेडियोमीटर (आईआईआर) सहित निष्क्रिय सेंसर भी शामिल हैं।
- वाइड फील्ड कैमरा (डब्ल्यूएफसी): बादलों और एरोसोल पर पूरक डेटा प्रदान करता है।

अवश्य पढ़ें: भारत-अमेरिका अंतरिक्ष सहयोग

SOURCE: THE INDIAN EXPRESS

इतिहास, कला एवं संस्कृति

विश्व संस्कृत दिवस 2023

संदर्भ: हाल ही में विश्व संस्कृत दिवस 2023 कोलंबो में मनाया गया।

विश्व संस्कृत दिवस 2023 के बारे में:-

- **स्थान:** कोलंबो
- मनाया गया: 31 अगस्त, 2023
- यह कार्यक्रम भारतीय उच्चायोग की सांस्कृतिक शाखा, स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक केंद्र (SVCC) द्वारा श्रीलंका के 12 विश्वविद्यालयों और संस्थानों के सहयोग से आयोजित किया गया था।
- यह आयोजन स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक केंद्र (SVCC) की रजत जयंती को चिह्नित करता है।
- इसमें कई प्रतिष्ठित श्रीलंकाई विश्वविद्यालयों के साथ एक सहयोगात्मक प्रयास दिखाया गया।

महत्व:-

- संस्कृत का यह उत्सव भारत और श्रीलंका के बीच गहरे सांस्कृतिक और भाषाई संबंधों को रेखांकित करता है।
- यह साझा विरासत के रूप में संस्कृत के महत्व पर जोर देता है।

विश्व संस्कृत दिवस:-

- यह श्रावण पूर्णिमा के दिन मनाया जाने वाला एक वार्षिक उत्सव है। (संस्कृत ग्राम कार्यक्रम: उत्तराखंड)
    - श्रावण पूर्णिमा: यह श्रावण माह के सबसे पवित्र दिनों में से एक माना जाता है और भगवान शिव को समर्पित है।
- ऐतिहासिक पृष्ठभूमि: शिक्षा मंत्रालय ने 1969 में श्रावण पूर्णिमा के अवसर पर विश्व संस्कृत दिवस घोषित किया था।
- भारत में विश्व संस्कृत दिवस के दिन पाणिनि को इस प्राचीन भाषा में उनके योगदान के लिए याद और सम्मानित किया जाता है।
    - पाणिनि: एक संस्कृत भाषाविद्, जिन्होंने अष्टाध्यायी नामक संस्कृत व्याकरण मार्गदर्शिका लिखी।

संस्कृत के बारे में:-

- संस्कृत सबसे पुरानी जीवित भाषाओं में से एक है। (संस्कृतीकरण क्या है)
- ऐसा कहा जाता है कि संस्कृत इंडो-जर्मनिक या इंडो-आर्यन भाषा परिवार से संबंधित है।
- यह लगभग 3,500 वर्ष पुरानी है।
- यह संस्कृत भाषा को दुनिया की सबसे पुरानी भाषा में से एक बनाता है।
- यह कई परंपराओं में एक पवित्र भाषा है।
- यह वेदों और योग शास्त्र जैसे अन्य प्रसिद्ध साहित्यिक कार्यों सहित प्राचीन ज्ञान का भंडार है।
- इसे हिंदी और सिंहली जैसी कई वर्तमान भाषाओं की जननी के रूप में भी जाना जाता है।

अवश्य पढ़ें: अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस

SOURCE: AIR

पुलिकली (पुलिक्कली)

संदर्भ: पुलिक्कली शो हाल ही में त्रिशूर शहर (केरल) में ओणम समारोह के दौरान प्रस्तुत किया गया था।

पुलिक्कली के बारे में:-

- स्थान: केरल
- स्थान: केरल के त्रिशूर जिले में स्वराज ग्राउंड
- परिचय: महाराजा राम वर्मा सक्थन थंपुरन (कोचीन के पूर्व शासक)
- नामकरण: मलयालम में पुली का मतलब तेंदुआ/बाघ और काली का मतलब खेल होता है।
- मुख्य विषय: बाघ का शिकार।
- इसे टाइगर डांस भी कहा जाता है।

- यह एक मनोरंजक सड़क लोक कला है।
- यह ओणम उत्सव के चौथे दिन किया जाता है।
- इसमें कलाकार अपने शरीर को पीले, लाल और काले रंग की धारियों से बाघ की तरह रंगते हैं और थाकिल, उडुक्कू और चेंडा जैसे पारंपरिक ताल वाद्ययंत्रों की लय पर नृत्य करते हैं।
- इसमें प्रतिभागी बाघ और शिकारी की भूमिका निभाते हैं।
    - ओणम: यह केरल राज्य का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है।
    - यह एक फसल उत्सव है।
    - यह मलयालम कैलेंडर (कोल्लावर्षम) के पहले महीने चिंगम महीने की शुरुआत में मनाया जाता है।

अवश्य पढ़ें: कथकली नृत्य

SOURCE: THE HINDU

संत नारायण गुरु

संदर्भ: हाल ही में संतनारायण गुरु की जयंती मनाई गई।

पृष्ठभूमि:-

- समाज सुधारक और संत नारायण गुरु की जयंती 31 अगस्त 2023 को यादगीर में मनाई गई।

परिचय :-

- नारायण गुरु भारत के एक संत एवं समाज सुधारक थे। (भक्ति आंदोलन)
- उन्हें केरल के सामाजिक ताने-बाने को बदलने का श्रेय दिया गया है।
- उन्होंने जाति व्यवस्था और सभी समुदायों के लोगों के बीच समानता के लिए लड़ाई लड़ी।
- वे उस युग के महान विचारक थे।
- उन्होंने दलित समुदाय के लोगों और उनके अधिकारों के लिए आवाज उठाई।
- उन्होंने समाज में गहरी जड़ें जमा चुके अंधविश्वास के खिलाफ लोगों का मार्गदर्शन किया।
- उन्होंने उन दलितों के लिए एक मंदिर बनवाया जिन्हें पूजा के लिए मंदिरों में प्रवेश से मना कर दिया गया था।
- उन्होंने मानवता की 'एकता' का उपदेश दिया, उन्होंने जाति और पंथ की सीमाओं को पार करते हुए मानवता की 'एकता' का उपदेश दिया।
- वर्ष 1888 में, उन्होंने यह दिखाने के प्रयास में कि भगवान की छवि का अभिषेक ब्राह्मणों का एकाधिकार नहीं था, केरल के अरविप्पुरम में शिव की एक मूर्ति स्थापित की।
    - यह लोकप्रिय रूप से अरविप्पुरम आंदोलन के नाम से जाना जाता है।
- उन्होंने कई महत्वपूर्ण साहित्यिक कृतियों में योगदान दिया, जिनमें सबसे प्रभावशाली है आत्मोपदेश सतकम जिसकी रचना उन्होंने 1897 में की थी।

अवश्य पढ़ें: संत कबीर

SOURCE: THE HINDU

केरल के नृत्य रूप

संदर्भ: हाल ही में आयोजित ओणम समारोह के दौरान केरल के विभिन्न नृत्य प्रस्तुत किए गए।

पृष्ठभूमि:-

- इस वर्ष, ओणम उत्सव 20 अगस्त 2023 को शुरू हुआ और थिरुवोणम 31 अगस्त को पड़ा क्योंकि 10 दिवसीय फसल उत्सव दक्षिण भारतीय राज्य केरल में मनाया गया था।
- यह मलयालम वर्ष की शुरुआत का प्रतीक है, जिसे कोल्ला वर्षम कहा जाता है, और पौराणिक राजा महाबली की वापसी को बड़े उत्साह और सांस्कृतिक उत्साह के साथ मनाया जाता है।

केरल के शास्त्रीय नृत्यों के बारे में:-

- केरल अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के लिए जाना जाता है। (कराकट्टम नृत्य)
- इसमें विभिन्न शास्त्रीय नृत्य रूप शामिल हैं, ओणम 2023 समारोह के दौरान किए गए इनमें से कुछ में शामिल हैं: -

कथकली:-

- इसकी उत्पत्ति 300 साल पहले केरल में हुई थी। (कथकली नृत्य)
- यह राज्य के सबसे प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य रूपों में से एक है।
- यह भारत के आठ शास्त्रीय नृत्यों में से एक है।
- यह नृत्य, संगीत, अभिनय, भक्ति, नाटक, वेशभूषा और मेकअप के तत्वों को मिलाकर एक अत्यधिक शैलीबद्ध और नाटकीय कला है।
- कथकली प्रदर्शन अतीत की महान कहानियों को फिर से बताता है, ज्यादातर भारतीय महाकाव्यों से, या हाथ और चेहरे के इशारों और अभिव्यक्तियों का उपयोग करके महाबली किंवदंती या त्योहार से जुड़ी अन्य पौराणिक कहानियों के एपिसोड को चित्रित करता है।

मोहिनीअट्टम:-

- यह एक सुंदर और गीतात्मक नृत्य शैली है।
- यह हिंदू भगवान विष्णु के जादुई मोहिनी अवतार के सम्मान में किया जाता है।
- यह भारत के आठ शास्त्रीय नृत्यों में से एक है।
- यह विशेष रूप से महिलाओं द्वारा किया जाता है।
- इसकी विशेषता सौम्य, प्रवाहपूर्ण चाल और अभिव्यंजक कहानी है, जो ओणम त्योहार के दौरान राजा महाबली से संबंधित कहानियों का वर्णन करती है।

कूडियाट्टम:-

- इसे यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता प्राप्त है।
- यह दुनिया के सबसे पुराने शास्त्रीय रंगमंच रूपों में से एक है।
- इसमें पारंपरिक वेशभूषा और श्रृंगार के साथ विस्तृत और अनुष्ठानिक प्रदर्शन शामिल हैं।
- इसमें हिंदू महाकाव्यों और पुराणों की कहानियों को दर्शाया गया है जिनका कभी-कभी ओणम के दौरान मंचन किया जाता है।

तिरुवतिराकली:-

- यह एक पारंपरिक समूह नृत्य है।
- इसमें महिलाओं द्वारा सुंदर गोलाकार मूवमेंट और संगीत की लय पर अपने हाथों की ताली बजाना शामिल है।
- यह समूह नृत्य प्रायः महिलाओं द्वारा किया जाता है।
- इसे नारीत्व का उत्सव माना जाता है।
- यह अधिकतर शाम को चन्द्रमा की रोशनी में किया जाता है।

चक्यार कुथु:-

- यह एक पारंपरिक एकल प्रदर्शन है।
- इसमें कलाकार ओणम पर हास्यप्रद और नाटकीय ढंग से रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्यों के प्रसंगों का वर्णन करते हैं।
- यह अपने आप में कोई नृत्य शैली नहीं है।
- यह केरल की प्रदर्शन कला परंपरा का एक अभिन्न अंग है।

ओट्टमथुलाल:-

- यह नृत्य शैली प्रसिद्ध मलयालम कवि कुंचन नांबियार द्वारा बनाई गई थी।
- इसमें एक एकल कलाकार व्यंग्यपूर्ण और विनोदी शैली में नृत्य और गीत के साथ कहानियाँ सुनाता है।
- यह प्रदर्शन मृदंगम (बैरल के आकार का ड्रम) के साथ होता है।

अवश्य पढ़ें: राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव 2022

SOURCE: HIDUSTAN TIMES

कोणार्क चक्र

संदर्भ: भारत ने हाल ही में आयोजित G 20 शिखर सम्मेलन में कोणार्क सूर्य मंदिर के कोणार्क चक्र का प्रदर्शन किया।

पृष्ठभूमि:-

- जैसे ही विश्व नेता G20 शिखर सम्मेलन के लिए दिल्ली के भारत मंडपम में पहुंचने लगे, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने बिल्डिंग के दूसरे स्तर

पर आगमन क्षेत्र में उनमें से प्रत्येक का व्यक्तिगत रूप से स्वागत किया।

- पीएम मोदी ने पारंपरिक फोटो-ऑप के लिए उनसे हाथ मिलाया, जिसकी पृष्ठभूमि में ओडिशा के कोणार्क व्हील को चित्रित करने वाली एक दीवार थी।

कोणार्क व्हील के बारे में:-

- स्थित: स्थित: कोणार्क सूर्य मंदिर, पुरी, ओडिशा।
- कोणार्क व्हील, जिसे कोणार्क चक्र के नाम से भी जाना जाता है।
- यह कोणार्क मंदिर से जुड़ा एक प्रतिष्ठित प्रतीक है।
- यह चक्र सूर्य देव के रथ का प्रतीक है।

कोणार्क चक्र के महत्व के संबंध में विभिन्न सिद्धांत मौजूद हैं:-

- एक व्याख्या के अनुसार, सात घोड़े सप्ताह के दिनों का प्रतिनिधित्व करते हैं, 12 जोड़ी पहिये वर्ष के 12 महीनों का प्रतिनिधित्व करते हैं, और 24 पहिये दिन के 24 घंटों का प्रतिनिधित्व करते हैं, 8 प्रमुख तीलियाँ एक दिन के तीन घंटे की अवधि (प्रहर) को दर्शाती हैं।
- एक अन्य व्याख्या से पता चलता है कि पहिये "जीवन के पहिये" के समान सृजन, संरक्षण और प्राप्ति के चक्र का प्रतीक हैं।
- कुछ लोगों का मानना है कि 12 जोड़ी पहिये 12 राशियों का प्रतिनिधित्व करते हैं।
- अन्य लोग बौद्ध प्रतीकवाद में कोणार्क चक्र और धर्मचक्र, कर्म चक्र के बीच समानताएं दर्शाते हैं। (धर्मचक्र दिवस पर बौद्ध दर्शन)

नक्काशी और सजावट:-

- कोणार्क मंदिर के 24 पहिए, हालांकि आकार और वास्तुकला में समान हैं, लेकिन हर तरफ अद्वितीय नक्काशी है।
- मोटी तीलियों को उनके केंद्र पर गोलाकार पदकों से सजाया गया है।
- पहियों की धुरियाँ सतह से लगभग एक फुट ऊपर उभरी हुई हैं, उनके सिरों पर भी सजावट की गई है।
- पहियों के रिम्स पर विभिन्न पक्षियों और जानवरों के चित्रण के साथ-साथ पत्तों के डिज़ाइन की जटिल नक्काशी की गई है।
- पहियों की तीलियों में लगे पदक विभिन्न मुद्राओं में महिलाओं की आकृतियों को प्रदर्शित करते हैं, जो अक्सर कामुक प्रकृति की हैं।
- यह हिंदू पौराणिक कथाओं में ब्रह्मांडीय चक्र और समय की अवधारणा के प्रतिनिधित्व के रूप में कार्य करता है।

कोणार्क सूर्य मंदिर

- समयरेखा: इसका निर्माण 13वीं शताब्दी में किया गया था।
- ऐतिहासिक पृष्ठभूमि: मंदिर का निर्माण पूर्वी गंगा राजवंश के राजा नरसिम्हादेव प्रथम के शासनकाल के दौरान किया गया था।
- इसे 12 जोड़ी पत्थर-नक्काशीदार पहियों वाले एक विशाल रथ के आकार में डिज़ाइन किया गया है।
- वे सूर्य देव के रथ का प्रतिनिधित्व करते हैं। (मोढेरा सूर्य मंदिर)
- इस मंदिर का निर्माण खोंडालाइट चट्टानों का उपयोग करके किया गया है।
- इसे विभिन्न पौराणिक और धार्मिक विषयों को चित्रित करने के लिए उकेरा गया है।
- कोणार्क सूर्य मंदिर को 1984 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था।

अवश्य पढ़ें: पुरी जगन्नाथ मंदिर

SOURCE: THE INDIAN EXPRESS

फणीगिरी कलाकृतियाँ

संदर्भ: 200 ईसा पूर्व-400 ईस्वी की फ़निगिरी कलाकृतियों को न्यूयॉर्क मेट्रोपॉलिटन म्यूज़ियम ऑफ़ आर्ट में प्रदर्शन के लिए रखा गया था।

पृष्ठभूमि:-

- फणीगिरी कलाकृतियों को ट्री एंड सर्पेंट प्रदर्शनी के कला संग्रह में प्रदर्शित किया जाएगा, जो जुलाई 2023 में न्यूयॉर्क मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट (जिसे द मेट के नाम से जाना जाता है) में शुरू हुआ था।
- इस प्रदर्शनी में 200 ईसा पूर्व और 400 ईस्वी के बीच की 125 वस्तुएं हैं।
- द मेट में प्रदर्शनी 13 नवंबर, 2023 तक चलेगी।

फणीगिरी कलाकृतियों के बारे में:-

- खोजा गया: वर्ष 1942

- पुनः खोजा गया: वर्ष 2003
- स्थान: फणीगिरी, तेलंगाना।
- हैदराबाद से लगभग 150 किमी दूर, सूर्यापेट जिले में फणीगिरी लगभग 4,000 निवासियों का एक छोटा सा गाँव है।
- फणीगिरि बौद्ध स्थल को इस सहस्राब्दी में बौद्ध प्रतिमा विज्ञान में सबसे महत्वपूर्ण खोजों में से एक माना जाता है। (बंगाल के भरतपुर में बौद्ध मठ परिसर)
- फणिगिरि का अर्थ है सांप के फन की पहाड़ी।

मुख्य निष्कर्ष और उनका महत्व:-

- फणीगिरि में खोजे गए थोराना बहुत महत्वपूर्ण हैं क्योंकि वे सांची के दक्षिण में सबसे पहले पाए गए थोराना में से हैं।
  - उसी थोराना में एक पैनल है जो महायान और हीनयान दोनों विचारधाराओं को दर्शाता है।
  - इससे पता चलता है कि दार्शनिक मतभेदों के बावजूद, फणीगिरी में दोनों संप्रदाय सह-अस्तित्व में थे।
- फणिगिरि से ऐसे साक्ष्य मिले हैं जो बुद्ध के देवत्व को दर्शाते हैं। (बौद्ध सर्किट)
- ऐतिहासिक और आध्यात्मिक पहचान से परिवर्तन और संतीकरण एवं अनुष्ठान की ओर परिवर्तन फणीगिरी में स्पष्ट है।
- इस साइट की कलाकृतियों में रोमन टोगा पहने हुए बुद्ध की चूना पत्थर की नक्काशी शामिल है।

अवश्य पढ़ें: मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में बौद्ध गुफाएं, मंदिर

SOURCE: THE HINDU

मेगालिथिक डोलमेन साइट

संदर्भ: प्राचीन टेराकोटा मूर्तियाँ हाल ही में मूडबिद्री के पास मेगालिथिक डोलमेन साइट पर पुरातात्विक अन्वेषण के दौरान पाई गईं।

पृष्ठभूमि:-

- दक्षिण कन्नड़ में मूडबिद्री के पास मुदु कोनाजे में मेगालिथिक डोलमेन साइट पर हाल ही में किए गए पुरातात्विक अन्वेषणों में हड्डी और लोहे के टुकड़ों के साथ संरक्षण की विभिन्न अवस्थाओं में अद्वितीय टेराकोटा मूर्तियाँ पाई गई हैं।

मेगालिथिक डोलमेन साइट के बारे में:-

- खोज स्थल: दक्षिण कन्नड़ (कर्नाटक) में मूडबिद्री
- अवधि: 800-700 ई.पू.
- खोज: पाई गई आठ मूर्तियों में से दो गोवंश, एक मातृ देवी, दो मोर, एक घोड़ा, एक देवी मां का हाथ और एक अज्ञात वस्तु है।
- ये मूर्तियाँ डोलमेन्स की सतह के अंदर पाई गईं, हालाँकि कुछ को ख़ज़ाने की खोज करने वालों ने इधर-उधर कर दिया था।
- मेगालिथिक संस्कृति भारत में विभिन्न प्रकार के दफ़नाने और लोहे के उपयोग के लिए जानी जाती है और डोलमेन उनमें से एक है।
- एक डोलमेन के नीचे, ऑर्थोस्टैट्स के रूप में जाने जाने वाले विशाल पत्थर के स्लैब को दक्षिणावर्त क्रम में खड़ा किया गया था, जिससे एक वर्गाकार कमरा बनाया गया था जिसे एक अन्य विशाल पत्थर के स्लैब द्वारा कैपस्टोन के रूप में बंद कर दिया गया था।
- आम तौर पर, पूर्वी स्लैब पर, एक गोल या यू-आकार का प्रवेश द्वार बनाया जाता था जिसे पोर्ट-होल के रूप में जाना जाता था।
- इसे दक्षिण भारत में कलमाने, पांडवरा माने, मोरियारा माने, मोरियारा बेट्टा आदि विभिन्न नामों से जाना जाता था।

गौवंश :-

- दो गाय में से एक बैल के सिर वाला एक ठोस हस्तनिर्मित मानव शरीर है और इसकी ऊंचाई लगभग 9 सेमी और चौड़ाई 5 सेमी है।
- इसमें एक बैल की तरह स्पष्ट थूथन है और इसकी स्त्रीत्व एप्लिक विधि द्वारा जुड़े दो स्तनों द्वारा अच्छी तरह से प्रमाणित है।
- दूसरी गाय गोजातीय एक और ठोस हस्तनिर्मित मूर्ति है जिसकी ऊंचाई लगभग 7.5 सेमी और चौड़ाई 4 सेमी है।
- इसमें एक गोजातीय थूथन और एक आदर्श हेड गियर और गर्दन के चारों ओर और पेट के नीचे पिपली अलंकरण है।
- गाय के गोवंश की उपस्थिति डोलमेंस के कालक्रम को निर्धारित करने में मदद करती है।
- केरल और मिस्र जैसे स्थानों में पाई जाने वाली अन्य महापाषाण टेराकोटा मूर्तियों में गाय देवी की समानताएं हैं।

मोर और घोड़े की मूर्तियाँ:-

- दो मोरों में से एक ठोस मोर है जिसकी ऊंचाई लगभग 11 सेमी और चौड़ाई 7 सेमी है, जो लाल गेरू में डूबा हुआ है और इसके पंख नीचे जमीन की ओर हैं।

- एक अन्य मोर का एक लम्बा सिर अलग से बनाया गया है, जिसे उथले शरीर में बनाया गया है और पंख ऊपर की ओर डिज़ाइन किए गए हैं।
- मोर और घोड़े की मूर्तियाँ उनकी मान्यताओं में जानवरों से संबंध या संभवतः उनके प्राकृतिक परिवेश का प्रतिनिधित्व करती हैं।

देवी माँ:-

- देवी माँ के धड़ का कोई सिर, हाथ या पैर नहीं है।

खोज का महत्व:-

- ये खोजें 800-700 ईसा पूर्व की समय-सीमा के दौरान तटीय कर्नाटक के लोगों की सांस्कृतिक और धार्मिक प्रथाओं में अंतर्दृष्टि प्रदान करती हैं।
- ये टेराकोटा मूर्तियाँ प्राचीन काल के दौरान तटीय कर्नाटक में भूत पंथ या दैव आराधना के अध्ययन के लिए एक ठोस आधार प्रदान करती हैं।
- महापाषाणिक अंत्येष्टि संदर्भ में इन मूर्तियों की उपस्थिति क्षेत्र की धार्मिक और सांस्कृतिक प्रथाओं के बारे में हमारी समझ को बढ़ाती है।

अवश्य पढ़ें: सिंधु घाटी सभ्यता में भाषा

SOURCE: THE HINDU

शांति निकेतन

संदर्भ: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शांतिनिकेतन को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किये जाने पर राष्ट्र को बधाई दी।

पृष्ठभूमि:-

- शांतिनिकेतन को 17 सितंबर, 2023 को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में सूचीबद्ध किया गया है।
- प्रधानमंत्री मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह सभी भारतीयों के लिए गर्व का क्षण है।
- श्री मोदी ने कहा कि शांतिनिकेतन गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर के दृष्टिकोण और भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है।

शांतिनिकेतन के बारे में:-

- स्थान: पश्चिम बंगाल में बीरभूम जिला।
- स्थापना: वर्ष 1901 में
- द्वारा स्थापित: महर्षि देवेन्द्रनाथ टैगोर
- महर्षि देवेन्द्रनाथ टैगोर नोबेल पुरस्कार विजेता रवीन्द्रनाथ टैगोर के पिता थे।
- यह पुरानी भारतीय परंपराओं और धार्मिक एवं सांस्कृतिक बाधाओं से परे मानवता की एकता की दृष्टि पर आधारित था।
- शांतिनिकेतन 1921 में विश्व भारती विश्वविद्यालय के रूप में विकसित हुआ, जिसने देश के कुछ सबसे रचनात्मक दिमागों को आकर्षित किया।
- शांतिनिकेतन में विश्वभारती विश्वविद्यालय सभी प्रकार की बाधाओं को तोड़ने की क्रांतिकारी परंपरा का प्रतीक है, चाहे वह जाति, धर्म, वर्ग, पंथ, लिंग, संस्कृति का हो, जिसका मुख्य फोकस मानविकी, कला और प्रकृति पर होता है।
- शांतिनिकेतन आज भी टैगोर के समानता के सिद्धांतों का पालन करता है।
- इसके परिसरों में 10,000 से कुछ अधिक छात्र रहते हैं जिनमें सह-शिक्षा सुविधा के अंतर्गत भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय छात्र शामिल हैं।
- परिसर के पेड़ों के नीचे गुरुकुल (खुली हवा में कक्षाएँ) का चलन अभी भी प्रचलित है।
- शांतिनिकेतन अपने कई त्योहारों के लिए भी प्रसिद्ध है। उनमें से कुछ में शामिल हैं:-
    - भव्य पौष उत्सव: विश्वविद्यालय के स्थापना दिवस पर मनाया गया।
    - बसंत उत्सव: होली पर मनाया जाता है।
    - शरद उत्सव: शरद उत्सव
    - माघ उत्सव: श्रीनिकेतन परिसर का स्थापना दिवस
    - वृक्षरोपण उत्सव: वृक्षारोपण महोत्सव

शांतिनिकेतन में महत्वपूर्ण स्थान:-

- **टैगोर आश्रम:** यह आश्रम परिसर शांतिनिकेतन का सबसे पुराना क्षेत्र है जहां महर्षि देबेंद्रनाथ टैगोर ने पहला अतिथि गृह शांतिनिकेतन

गृह बनाया था।

- **रवीन्द्र भवन संग्रहालय या टैगोर संग्रहालय:** रवीन्द्र भवन संग्रहालय की स्थापना 1942 में रवीन्द्रनाथ टैगोर की मृत्यु के ठीक बाद की गई थी।
- **विश्व भारती विश्वविद्यालय:** कला, मानविकी, भाषा, संगीत, नृत्य और लोक कलाओं का पता लगाने के प्रमुख आदर्श वाक्य और उद्देश्य के साथ स्थापित, विश्व भारती का केंद्र बिंदु विविधता में एकता पैदा करना है।
- **उत्तरायण परिसर:** शांतिनिकेतन के उत्तरी भाग में स्थित, यह रवींद्रनाथ टैगोर द्वारा अपने जीवनकाल के दौरान बनाए गए पांच घरों का एक संग्रह है।
- **उपासना गृह:** प्रार्थना कक्ष पूरे शांतिनिकेतन क्षेत्र की आश्चर्यजनक इमारतों में से एक है।
- **कला भवन:** विश्व भारती विश्वविद्यालय परिसर के भीतर सबसे खूबसूरती से डिजाइन किए गए ब्लॉकों में से एक कला भवन है।
- **चाइना भवन:** विश्व भारती विश्वविद्यालय परिसर के आसपास के शैक्षणिक ब्लॉकों का नाम वहां पढ़ाए जाने वाले उद्देश्य, संस्कृति और विषय के अनुसार रखा गया है।
- **निप्पॉन भवन:** चाइना भवन की तरह, निप्पॉन भवन जापानी संस्कृति, साहित्य, कला, भाषा और परंपरा को समर्पित है।
- **छतिमतला:** छतीमतला का स्थान पवित्र माना जाता है और शांतिनिकेतन में सभी के लिए इसका बहुत महत्व है।

अवश्य पढ़ें: रवींद्रनाथ टैगोर की गीतांजलि

SOURCE: AIR

होयसल मंदिर

संदर्भ: हाल की घोषणाओं के अनुसार, होयसला मंदिर, भारत का 42वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल होगा।

पृष्ठभूमि:-

- यह घोषणा सऊदी अरब के रियाद में एजेंसी द्वारा की गई, जहां विश्व धरोहर समिति का 45वां सत्र 25 सितंबर, 2023 तक आयोजित किया जा रहा है।
- रवीन्द्रनाथ टैगोर का शांतिनिकेतन, पश्चिम बंगाल का विश्वविद्यालय शहर, पहले भी विश्व धरोहर स्थल के रूप में शामिल था।

होयसल मंदिरों के बारे में:-

IMAGE SOURCE: INDIAN EXPRESS

- होयसलों के पवित्र समूह, जिसे यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में अंकित किया गया है, में कर्नाटक के तीन मंदिर शामिल हैं।
- तीन होयसल मंदिरों में शामिल हैं:-

चेन्नकेशव मंदिर

- **स्थान:** बेलूर (हसन जिला), कर्नाटक।
- यह पारंपरिक बस्ती के केंद्र में स्थित है जो एक मिट्टी के किले और खाई के अवशेषों से घिरा हुआ है।
- गर्भगृह टेढ़ी-मेढ़ी दीवारों के साथ तारकीय आकार का है, जिससे प्रकाश और छाया के प्रभाव के कारण दिन के हर समय भगवान विष्णु के 24 रूप अलग दिखते हैं।
- राजा विष्णुवर्धन की रानी शांतलादेवी को दर्पण सुंदरी (दर्पण वाली महिला) में दर्शाया गया है।
- छत पर मदनिकाओं (आकाशीय अप्सराओं) की मूर्ति और ब्रैकेट आकृतियाँ हैं।

- कप्पे चेन्निगरया, सौम्यनायकी, अंडाल और अन्य वैष्णव अभिव्यक्तियों के मंदिर, मुख्य मंदिर के चारों ओर हैं।
-

होयसलेश्वर मंदिर

- स्थान: हलेबिदु (हसन जिला), कर्नाटक।
- नदी: यह हलेबिदु में द्वारसमुद्र तालाब के तट पर है।
- यह एक ऐसा शहर है जिसमें कई संरक्षित और असुरक्षित मंदिर, पुरातात्विक खंडहर और टीले हैं।
- जुड़वां तीर्थ मंदिर, शायद होयसल राजाओं द्वारा निर्मित सबसे बड़ा शिव मंदिर है।
- यह एक तारे के आकार के आधार पर बनाया गया है जिसमें हाथी, शेर, घोड़े और पुष्प स्क्रॉल के साथ उकेरे गए फ्रिज़ की 8 पंक्तियाँ हैं।
- बाहरी दीवारों पर हिंदू देवताओं, ऋषियों, शैलीबद्ध जानवरों, पक्षियों और होयसल राजाओं के जीवन को दर्शाने वाली नक्काशी की गई है।
- रामायण, महाभारत और भगवद गीता जैसे महाकाव्यों की छवियां बाहरी दीवारों पर सजी हैं।
- इसमें अत्यधिक अलंकृत मंदिर के दरवाजे लगे है।
- नंदीमंतप एक सुसज्जित नंदी प्रतिमा के साथ मंदिर के ठीक सामने स्थित है।
- मंदिर के अंदरूनी हिस्सों में उत्कृष्ट नक्काशी के साथ अत्यधिक पॉलिश किए गए खराद से बने खंभे हैं।

केशव मंदिर

- स्थान: मैसूर जिला, कर्नाटक
- यह सोमनाथपुरा गांव (मैसूर जिला) के केंद्र में है।
- यह एक वैष्णव मंदिर है।
- नदी: सोमनाथपुरा में कावेरी नदी के तट पर बना है।
- इसका पवित्रीकरण 1258 ई. में सोमनाथ दंडनायक द्वारा किया गया था जो राजा नरसिम्हा तृतीय के सेनापति थे।
- यह एक महाद्वार (प्रमुख द्वार) और ऊंचे नक्काशीदार सोपस्टोन स्तंभों के साथ एक दीवार वाले आंगन से घिरा हुआ है।
    - सोपस्टोन: हरे-भूरे रंग का क्लोरिटिक शिस्ट पदार्थ जो खदान में सॉफ्ट होता है लेकिन वायु के संपर्क में आने पर कठोर हो जाता है।
- पुराने कन्नड़ में शिलालेख पत्थर हैं, जिनमें हिंदू प्रतिमा विज्ञान और केशव, जनार्दन और वेणुगोपाल की लघु राहतें हैं।

होयसला वास्तुकला के बारे में:-

- होयसला वास्तुकला का विकास 11वीं और 14वीं शताब्दी के बीच होयसला साम्राज्य के शासन में हुआ।
- यह अधिकतर दक्षिणी कर्नाटक में केंद्रित है।
- होयसल मंदिरों को कभी-कभी हाइब्रिड या वेसर भी कहा जाता है क्योंकि उनकी अनूठी शैली द्रविड़ और नागर शैलियों के बीच की लगती है।
- होयसला मंदिरों में कई मंदिर हैं जो एक केंद्रीय स्तंभ वाले हॉल के चारों ओर समूहित हैं और एक जटिल डिजाइन वाले तारे के आकार में बने हैं।
- ये सोपस्टोन से बने होते हैं जो अपेक्षाकृत सॉफ्ट पत्थर होता है।
- वे अपनी अत्यधिक मूल तारो जैसी जमीनी योजनाओं और सजावटी नक्काशी की प्रचुरता के कारण अन्य मध्ययुगीन मंदिरों से आसानी से अलग पहचाने जा सकते हैं।

भारत में विश्व धरोहर स्थलों की सूची:

सांस्कृतिक 34 धरोहर

- आगरे का किला (1983)
- अजंता गुफाएं (1983)
- नालन्दा, बिहार में नालन्दा महाविहार का पुरातात्विक स्थल (2016)

- सांची में बौद्ध स्मारक (1989)
- चंपानेर-पावागढ़ पुरातत्व पार्क (2004)
- छत्रपति शिवाजी टर्मिनस (पूर्व में विक्टोरिया टर्मिनस) (2004)
- गोवा के चर्च और कॉन्वेंट (1986)
- धोलावीरा: एक हड़प्पा शहर (2021)
- एलिफेंटा गुफाएं (1987)
- एलोरा गुफाएं (1983)
- फ़तेहपुर सीकरी (1986)
- महान जीवित चोल मंदिर (1987, 2004)
- हम्पी में स्मारकों का समूह (1986)
- महाबलीपुरम में स्मारकों का समूह (1984)
- पत्तदकल में स्मारकों का समूह (1987)
- राजस्थान के पहाड़ी किले (2013)
- अहमदाबाद का ऐतिहासिक शहर (2017)
- हुमायूं का मकबरा, दिल्ली (1993)
- जयपुर शहर, राजस्थान (2019)
- काकतीय रुद्रेश्वर (रामप्पा) मंदिर, तेलंगाना (2021)
- खजुराहो स्मारक समूह (1986)
- बोधगया में महाबोधि मंदिर परिसर (2002)
- भारत की पर्वतीय रेलवे (1999, 2005, 2008)
- कुतुब मीनार और उसके स्मारक, दिल्ली (1993)
- रानी-की-वाव (रानी की बावड़ी), पाटन, गुजरात (2014)
- लाल किला परिसर (2007)
- भीमबेटका के रॉक शेल्टर्स (2003)
- होयसलाओं की पवित्र मण्डली (2023)
- शांतिनिकेतन (2023)
- सूर्य मंदिर, कोणार्क (1984)
- ताज महल (1983)
- ले कोर्बुज़िए का वास्तुशिल्प कार्य, आधुनिक आंदोलन में एक उत्कृष्ट योगदान (2016)
- जंतर मंतर, जयपुर (2010)
- मुंबई के विक्टोरियन गोथिक और आर्ट डेको एन्सेम्बल्स (2018)

नेचुरल 7 है:

- ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क संरक्षण क्षेत्र (2014)
- काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान (1985)
- केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान (1985)
- मानस वन्यजीव अभयारण्य (1985)
- नंदा देवी और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान (1988, 2005)
- सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान (1987)
- पश्चिमी घाट (2012)

मिश्रित 1 है :

- कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान (2016)

अवश्य पढ़ें: खजुराहो के मंदिर

SOURCE: INDIAN EXPRESS

आदि शंकराचार्य की मूर्ति

संदर्भ: हाल ही में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में आदि शंकराचार्य की 108 फुट ऊंची 'स्टैच्यू ऑफ वननेस' का अनावरण किया।

परिचय:

- जन्म : 11 मई 788 ई., कलाडी, केरल में।
- समाधि: केदार तीर्थ पर
- दर्शनशास्त्र: अद्वैत (अद्वैतवाद) के सिद्धांत का प्रतिपादन किया,
- वह बौद्ध दार्शनिकों के विरोधी थे।
- सनातन धर्म के प्रचार-प्रसार के लिए भारत के चार कोनों श्रृंगेरी, पुरी, द्वारका और बद्रीनाथ में चार मठों की स्थापना की।

प्रमुख पुस्तकें:

- ब्रह्मसूत्रभाष्य (ब्रह्मसूत्र पर भाष्य), भजगोविंद स्तोत्र, निर्वाण शतकम् और प्रकरण ग्रंथ।

अद्वैत वेदांत की वकालत:

- यह कट्टरपंथी अद्वैतवाद की एक दार्शनिक स्थिति को स्पष्ट करता है, एक संशोधनवादी विश्वदृष्टि जो इसे प्राचीन उपनिषद ग्रंथों से प्राप्त होती है।
- अद्वैत वेदांतियों के अनुसार, उपनिषद 'ब्राह्मण' नामक अद्वैत के एक मौलिक सिद्धांत को प्रकट करते हैं, जो सभी चीजों की वास्तविकता है।
- अद्वैतवादी ब्राह्मण को व्यक्तित्व और अनुभवजन्य बहुलता से परे समझते हैं।
    - वे यह स्थापित करना चाहते हैं कि किसी व्यक्ति का मूल (आत्मान) ब्रह्म है।
- अद्वैत वेदांत का मूल बल यह है कि आत्मा शुद्ध गैर-इरादतन चेतना है।
- यह बिना किसी द्वितीय, अद्वैत, अनंत अस्तित्व वाला और संख्यात्मक रूप से ब्रह्म के समान है।

Source: Indian Express

मेवाड़ शैली की चित्रकारी

संदर्भ: हाल ही में, राजस्थान के उदयपुर में एक मुस्लिम द्वारा चित्रित मेवाड़ शैली की महाभारत की खोज की गई थी।

पृष्ठभूमि:-

- उदयपुर के सिटी पैलेस के एक गंदे कमरे में ट्रंक में 1680 और 1698 के बीच अल्लाह बख्श द्वारा चित्रित महाभारत के हजारों लघु चित्र रखे हुए थे।
- बख्श द्वारा लिखित महाभारत में, वे इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि कैसे साहित्य सदियों और सहस्राब्दियों के दौरान निरंतर पुनर्व्याख्या से गुजरता है।
- 300 साल पुराना ग्रंथ, इस बख्श के चित्रण में संस्कृत महाभारत नहीं बल्कि राजस्थानी महाभारत है।
- इसे किसी मुस्लिम द्वारा नहीं बल्कि मेवाड़ी विचारधारा के एक समर्थक द्वारा इस तरह चित्रित किया गया है कि जब कोई इन चित्रों को देखता है, तो उसे संपूर्ण मेवाड़ी संस्कृति की कल्पना हो जाती है।

मेवाड़ शैली की चित्रकला के बारे में:-

- समयरेखा: 17वीं और 18वीं शताब्दी
- मेवाड़ चित्रकला भारतीय लघु चित्रकला की सबसे महत्वपूर्ण शाखाओं में से एक है।
- यह राजस्थानी शैली का विद्यालय है।
- इसका विकास मेवाड़ (उदयपुर) की हिंदू रियासत में हुआ।

मुख्य विशेषताएं:-

- यह सरल चमकीले रंग और प्रत्यक्ष भावनात्मक अपील की विशेषता है।
- राजपूत चित्रकला के मेवाड़ स्कूल से जुड़ी सबसे पुरानी दिनांकित पांडुलिपि चावंड रागमाला श्रृंखला (1605) है, जिसे कलाकार नसीरुद्दीन द्वारा चित्रित किया गया था।
- इस श्रृंखला की अधिकांश पेंटिंग श्री गोपी कृष्ण कनोरिया के संग्रह में हैं।
- अभिव्यंजक और सशक्त शैली इस क्षेत्र में 1680 तक कुछ बदलावों के साथ जारी रही, जिसके बाद मुगल प्रभाव अधिक स्पष्ट हो गया।
- चित्रों की बढ़ती संख्या चित्रांकन और शासक के जीवन से संबंधित थी, हालांकि धार्मिक विषय लोकप्रिय थे।
- लघु चित्रकला का मेवाड़ स्कूल, एक ही फ्रेम के भीतर जीवंत रंगों और जटिल कथाओं के लिए प्रसिद्ध है।
- ये पेंटिंग ऐतिहासिक अंतर्दृष्टि प्रदान करती हैं, जिसमें तलवार संग्रह, टर्बन स्टाइल और चित्रित समय के दौरान मनाए गए अवसरों जैसे विवरण शामिल हैं। (भित्ति कला)

मेवाड़ी चित्रकला शैली के प्रसिद्ध कलाकार:-

- **अल्लाह बख्श:** महाराणा जय सिंह के शासनकाल (1653-98) के दौरान एक उल्लेखनीय मेवाड़ी चित्रकार, अल्लाह बख्श, संपूर्ण महाभारत और गीता के प्रत्येक श्लोक सहित व्यापक चित्रण बनाने के लिए प्रसिद्ध हैं।
- **साहिबदीन:** सत्रहवीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, राज सिंह और जय सिंह के शासनकाल के दौरान, मेवाड़ में चित्रांकन को प्रमुखता मिली।

अवश्य पढ़ें: प्राचीन शैल चित्र

SOURCE: THE PRINT

हाइफा का युद्ध

संदर्भ: भारत और इज़राइल ने हाल ही में हाइफ़ा की लड़ाई का जश्न मनाया।

पृष्ठभूमि:-

- हर साल 23 सितंबर को, इज़राइल में भारतीय दूतावास के राजनयिक और उत्तरी बंदरगाह शहर हाइफ़ा की नगर पालिका का प्रतिनिधित्व करने वाले इज़राइली सरकारी अधिकारी विदेशी धरती पर युद्ध में मारे गए और घायल हुए भारतीय सैनिकों को सम्मान देने के लिए हाइफ़ा युद्ध कब्रिस्तान में इकट्ठा होते हैं।

हाइफ़ा की लड़ाई के बारे में:-

- 23 सितंबर को 'हाइफ़ा दिवस' के रूप में नामित किया गया है।
- यह प्रथम विश्व युद्ध के दौरान 15वीं इंपीरियल सर्विस कैवेलरी ब्रिगेड की साहसी घुड़सवार कार्रवाई के बाद शहर पर कब्ज़ा करने की याद दिलाता है।

- हाइफ़ा दिवस स्मरणोत्सव वर्ष 2010 में शुरू किया गया था।
- हाइफ़ा युद्ध की शताब्दी के सम्मान में भारत में तीन मूर्ति चौक का नाम बदलकर तीन मूर्ति हाइफ़ा चौक कर दिया गया।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि:-

- हाइफ़ा की लड़ाई प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सिनाई और फिलिस्तीन अभियानों के एक भाग के रूप में लड़ी गई थी। (भारत, इज़राइल और फिलिस्तीन)
- 13वीं, 14वीं और 15वीं कैवलरी ब्रिगेड वाली 5वीं कैवलरी डिवीजन को हाइफ़ा पर कब्ज़ा करने का काम सौंपा गया था।
- 15 कैवेलरी ब्रिगेड में जोधपुर लांसर्स और मैसूर एवं हैदराबाद लांसर्स शामिल थे।
- ब्रिटिश साम्राज्य, इटली साम्राज्य और फ्रांसीसी तृतीय गणराज्य ने अरब विद्रोह के साथ-साथ ओटोमन साम्राज्य, ऑस्ट्रो-हंगेरियन साम्राज्य और जर्मन साम्राज्य के विरोध में लड़ाई लड़ी।
- भारतीय घुड़सवार सेना ब्रिगेड ने एक निर्णायक भूमिका निभाई, जिससे ओटोमन साम्राज्य से हाइफ़ा और एकर पर कब्ज़ा हो गया।

महत्व:-

- हाइफ़ा का युद्ध वैश्विक संघर्षों में सिखों और राजपूतों सहित भारतीय सैनिकों की वीरता का एक प्रमाण है।
- यह प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत के योगदान पर प्रकाश डालता है।
- यह भारत-इज़राइल संबंधों को मजबूत करने में एक ऐतिहासिक महत्व जोड़ता है। (15वां भारत-इज़राइल संयुक्त कार्य समूह)

अवश्य पढ़ें: भारत और इज़राइल

SOURCE: THE INDIAN EXPRESS

सरकारी पहल, योजनाएँ और नीतियाँ

पोषण (समग्र पोषण के लिए प्रधान मंत्री की व्यापक योजना) योजना

संदर्भ: हालिया रिपोर्टों के अनुसार, सरकार सितंबर में छठा राष्ट्रीय पोषण माह 2023 मनाएगी।

राष्ट्रीय पोषण माह 2023:-

- उद्देश्य: जीवन-चक्र दृष्टिकोण के द्वारा कुपोषण से व्यापक रूप से निपटना।
- पोषण माह 2023 का केंद्र बिंदु गर्भावस्था, शैशवावस्था, बचपन और किशोरावस्था सहित महत्वपूर्ण मानव जीवन चरणों के बारे में व्यापक जागरूकता पैदा करना है।
- इस उत्सव का उद्देश्य देशभर में पोषण संबंधी समझ को बढ़ावा देना है।
- **थीम:** "सुपोषित भारत, साक्षर भारत, सशक्त भारत" (पोषण-समृद्ध भारत, शिक्षित भारत, सशक्त भारत)।

परिचय:-

- लॉन्च: वर्ष 2018 में
- मंत्रालय: महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
- दृष्टिकोण: वर्ष 2022 तक कुपोषण मुक्त भारत की प्राप्ति सुनिश्चित करना।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि:-

- सरकार ने 08 मार्च, 2018 को पोषण अभियान शुरू किया, जिसे पहले राष्ट्रीय पोषण मिशन के नाम से जाना जाता था।
- उद्देश्य: देश में कुपोषण की समस्या का समाधान करना।

पोषण की मुख्य विशेषताएं:-

- पोषण अभियान बच्चों, किशोर लड़कियों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए पोषण संबंधी परिणामों में सुधार करने के लिए भारत सरकार का प्रमुख कार्यक्रम है।
- अभियान का लक्ष्य निम्न को कम करना है:-
    - स्टंटिंग में प्रति वर्ष 2% की वृद्धि

- प्रति वर्ष 2% अल्पपोषण
- एनीमिया (छोटे बच्चों, महिलाओं और किशोर लड़कियों में) प्रति वर्ष 3%
- जन्म के समय वजन में प्रति वर्ष 2% की कमी

- यह एक बहु-मंत्रालयी अभिसरण मिशन है।
- इसका लक्ष्य जीवन चक्र दृष्टिकोण के द्वारा चरणबद्ध तरीके से देश में कुपोषण को कम करना है।
- पोषण अभियान के तहत, पोषण और स्वस्थ भोजन के बारे में जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से प्रत्येक वर्ष सितंबर में 'राष्ट्रीय पोषण माह' मनाया जाता है। (पोषण माह)

मिशन पोषण 2.0:-

- मिशन पोषण 2.0, एक एकीकृत पोषण सहायता कार्यक्रम, में पूरक पोषण कार्यक्रम और पोषण अभियान को शामिल किया गया है।
- सभी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के लिए केंद्रीय बजट 2021-2022 में इसकी घोषणा की गई थी।
- उद्देश्य: स्वास्थ्य, कल्याण और रोग एवं कुपोषण के प्रति प्रतिरक्षा को बढ़ावा देने वाली प्रथाओं को विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करते हुए पोषण संबंधी सामग्री, वितरण, आउटरीच और परिणामों को मजबूत करना। (पीएम पोषण शक्ति निर्माण योजना)

पोषण 2.0 का लक्ष्य:-

- छह महीने से छह वर्ष की आयु के बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं (पीडब्ल्यूएलएम), और 14 से 18 वर्ष की आयु वर्ग की किशोरियों के लिए पूरक पोषण कार्यक्रम (एसएनपी) के माध्यम से पोषण के लिए पोषण सहायता करना।

जिले और उत्तर पूर्वी क्षेत्र (एनईआर)

- प्रारंभिक बाल्यावस्था की देखभाल और शिक्षा [3-6 वर्ष] और प्रारंभिक उत्तेजना (0-3 वर्ष)।
- आधुनिक, उन्नत सक्षम आंगनवाड़ी पोषण अभियान सहित आंगनवाड़ी अवसंरचना।
- पोषण 2.0 मातृ पोषण, शिशु और छोटे बच्चे के आहार मानदंड, गंभीर रूप से तीव्र कुपोषित (एसएएम) / मध्यम रूप से तीव्र कुपोषित (एमएएम) के लिए उपचार प्रोटोकॉल और आयुष प्रथाओं के माध्यम से स्टंटिंग और एनीमिया के अलावा वेस्टिंग तथा कम वजन के प्रसार को कम करने के लिए कल्याण पर भी ध्यान केंद्रित करता है।

अवश्य पढ़ें: वर्षांत समीक्षा-2022: महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

SOURCE: AIR

मेरा बिल मेरा अधिकार योजना

संदर्भ: चालान प्रोत्साहन योजना मेरा बिल मेरा अधिकार योजना हाल ही में शुरू हुई।

मेरा बिल मेरा अधिकार के बारे में:-

- लॉन्च: 1 सितंबर, 2023।
- मंत्रालय: वित्त मंत्रालय।
- उद्देश्य: आम जनता में 'बिल मांगो' को उनके अधिकार और अधिकार के रूप में सांस्कृतिक और व्यवहारिक परिवर्तन लाना।
- अवधि: यह पायलट योजना 12 महीने की अवधि तक चलेगी।

मुख्य विशेषताएं:-

- यह योजना एक वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) चालान प्रोत्साहन कार्यक्रम है जो चालान अपलोड करने के लिए नकद प्रोत्साहन प्रदान करता है।
  o चालान: एक वाणिज्यिक दस्तावेज़ जो विक्रेता और खरीदार के बीच लेनदेन को सूचीबद्ध और रिकॉर्ड करता है।
- इसे शुरुआत में असम, गुजरात और हरियाणा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों पुडुचेरी, दादरा नगर हवेली और दमन एवं दीव में पायलट के रूप में लॉन्च किया जाएगा।
- लॉट का मासिक और त्रैमासिक ड्रा निकाला जाएगा, और विजेता 10,000 रुपये से लेकर 1 करोड़ रुपये तक के नकद पुरस्कार के पात्र होंगे।

पात्रता: -

o भारत के सभी निवासी अपने राज्य/केंद्रशासित प्रदेश की परवाह किए बिना इस योजना में भाग लेने के पात्र होंगे।
o ऐप पर अपलोड किए गए इनवॉइस में विक्रेता का GSTIN, इनवॉइस नंबर, भुगतान की गई राशि और कर राशि होनी चाहिए। (जीएसटी परिषद)

- चालान का न्यूनतम मूल्य: लकी ड्रा के लिए विचार किया जाने वाला 200 रुपए है।
- चालान के लिए अधिकतम मूल्य: लकी ड्रा के लिए विचार किए जाने के लिए एक व्यक्ति द्वारा एक महीने में अधिकतम 25 चालान ऐप/वेब पोर्टल पर अपलोड किए जा सकते हैं।
- मोबाइल एप्लिकेशन: चालान मोबाइल एप्लिकेशन 'मेरा बिल मेरा अधिकार' पर अपलोड किए जा सकते हैं।
  o यह IOS और Android के साथ-साथ वेब पोर्टल 'web.merabill.gst.gov.in' पर भी उपलब्ध है।
- पावती संदर्भ संख्या (एआरएन): प्रत्येक अपलोड किए गए चालान के लिए उत्पन्न की जाएगी, जिसका उपयोग पुरस्कार निकालने के लिए किया जाएगा।

पुरस्कार:-

- इस योजना में सरकार हर महीने 800 लोगों का चयन करेगी, जिन्हें दस हजार रुपये का इनाम मिलेगा।
- त्रैमासिक आयोजित होने वाले बंपर ड्रा में दो लोगों को एक करोड़ रुपये का इनाम मिलेगा।
- विजेता का चयन: विजेता चालान को नियमित अंतराल (मासिक/त्रैमासिक) पर यादृच्छिक ड्रा (random draw) की विधि द्वारा चुना जाएगा।

मेरा बिल मेरा अधिकार के लाभ:-

- इससे देश की कर प्रणाली को सरल बनाने और इंस्पेक्टर राज को समाप्त करने में मदद मिलेगी।
- इससे नागरिकों पर कर का बोझ कम होगा।

अवश्य पढ़ें:जीएसटी मुआवजा

पर्सनलाइज्ड एडेप्टिव लर्निंग (PAL)

संदर्भ: नेशनल ई-गवर्नेंस डिवीजन (NeGD) ने हाल ही में पर्सनलाइज्ड एडेप्टिव लर्निंग (PAL) को अपने मौजूदा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग (DIKSHA) प्लेटफॉर्म में एकीकृत करने की योजना की घोषणा की है।

पृष्ठभूमि:-

- PAL का सॉफ़्टवेयर-आधारित दृष्टिकोण प्रत्येक छात्र को उनकी अद्वितीय आवश्यकताओं और क्षमताओं के आधार पर पाठ्यक्रम के दौरान व्यक्तिगत सीखने का अनुभव प्राप्त करने की अनुमति देगा।
- शिक्षा मंत्रालय कक्षा 9 से 12 के लिए रसायन विज्ञान, गणित और भौतिकी जैसे चुनौतीपूर्ण विषयों के लिए पीएएल कार्यान्वयन शुरू करने का उद्देश्य रखता है।
- इन विषयों पर ध्यान केंद्रित करके, इस पहल का उद्देश्य कक्षा 10 के बाद स्कूल छोड़ने की समस्या का समाधान करते हुए सीखने के

परिणामों और स्कूल में रुकने की दर में सुधार करना है।

इसके बारे में:-

- यह एक शैक्षिक दृष्टिकोण है जो व्यक्तिगत छात्रों के लिए सीखने के अनुभव को अनुकूलित करने के लिए प्रौद्योगिकी, विशेष रूप से कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) का उपयोग करता है। (एआई नैतिकता के लिए एक नया वैश्विक मानक)
- यह व्यक्तिगत छात्र की विशिष्ट आवश्यकताओं, क्षमताओं और प्रगति को पूरा करने पर आधारित है।
- यह छात्रों की प्रगति की निगरानी करने और कठिनाई वाले क्षेत्रों की पहचान करने के लिए एआई का उपयोग करता है।
- उदाहरण के लिए, यदि कोई छात्र गणना में गलती करता है, तो सिस्टम इसका पता लगाता है और छात्र को प्रासंगिक मूलभूत सामग्री पर पुनर्निर्देशित करता है, जिससे अवधारणा की बेहतर समझ सुनिश्चित होती है।
- PAL प्रत्येक छात्र के सामने आने वाली अद्वितीय प्रगति और चुनौतियों को अपनाता है, और अधिक प्रभावी और आकर्षक सीखने का अनुभव प्रदान करता है।

लाभ:-

- वैयक्तिकृत अध्ययन योजनाएँ।
- विशेष आवश्यकताओं के लिए सहायता।
- सीखने में लचीलापन

चुनौतियाँ:-

- असम और हरियाणा जैसे राज्यों को PAL लागू करते समय बजट की कमी का सामना करना पड़ा है।
- जबकि असम ने फंडिंग संबंधी दिक्कतों के कारण इस परियोजना को बंद कर दिया।
- हरियाणा ने पाया कि सामग्री की स्ट्रीमिंग लागत बेहद अधिक है, जिससे अडॉप्ट करने की प्रक्रिया में रुकावट आ गई है।

दीक्षा के बारे में:-

- लॉन्च: वर्ष 2017 में
- मंत्रालय: शिक्षा मंत्रालय
- दीक्षा राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में स्कूली शिक्षा के लिए गुणवत्तापूर्ण ई-सामग्री और सभी ग्रेडों के लिए क्यूआर-कोडित ऊर्जावान पाठ्यपुस्तकें प्रदान करने का मंच है।
- यह शिक्षकों को स्वयं सीखने और प्रशिक्षित करने में सहायता करता है जिसके लिए मूल्यांकन संसाधन उपलब्ध होंगे।
- इसमें डिजिटलीकृत राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) की पाठ्यपुस्तकें, शिक्षण वीडियो और अभ्यास प्रश्न हैं।
- इसमें विकलांग शिक्षार्थियों के लिए सहायक प्रौद्योगिकियां भी हैं, लेकिन यह एक स्थिर सामग्री भंडार है।

अवश्य पढ़ें:आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को विनियमित करना

SOURCE: THE HINDU

ग्रामोद्योग विकास योजना

संदर्भ: दिल्ली के उपराज्यपाल श्री विनय कुमार सक्सेना ने हाल ही में 'ग्रामोद्योग विकास योजना' के तहत हनी बी-बॉक्स और टूलकिट वितरित किए।

ग्रामोद्योग विकास योजना के बारे में:-

- लॉन्च: मार्च 2020
- मंत्रालय: सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई)
- उद्देश्य: अगरबत्ती उद्योग और उसके कारीगरों की सहायता करना और उनका विकास करना।
- कार्यक्रम का लक्ष्य देश में 'अगरबत्ती' का उत्पादन बढ़ाना है।
- इसका उद्देश्य पारंपरिक कारीगरों को नियमित रोजगार प्रदान करके और उनकी मजदूरी में वृद्धि करके स्थायी रोजगार पैदा करना है।

योजना के घटक:-

- अनुसंधान एवं विकास और उत्पाद नवाचार: अनुसंधान एवं विकास सहायता उन संस्थानों को दी जाएगी जो उत्पाद विकास, नए

नवाचार, डिजाइन विकास, उत्पाद विविधीकरण प्रक्रियाएं आदि करने का इरादा रखते हैं।

- क्षमता निर्माण: मौजूदा बहु-विषयक प्रशिक्षण केंद्रों (एमडीटीसी) और उत्कृष्ट संस्थानों के माध्यम से कर्मचारियों, साथ ही कारीगरों की विशिष्ट क्षमता निर्माण को पर्याप्त रूप से संबोधित किया जाएगा।
- विपणन और प्रचार: संस्थानों को बाजार सहायता प्रदान की जाएगी। (भारत की ग्रामीण आबादी पर वैश्वीकरण का प्रभाव)

खादी और ग्रामोद्योग आयोग (KVIC) के बारे में:-

- स्थापना: वर्ष 1957 में
- मंत्रालय: सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय
- यह 1956 के खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय है।

केवीआईसी के उद्देश्य:-

- देश में रोजगार को बढ़ावा देना। (प्रोजेक्ट री-हैब)
- खादी वस्तुओं के प्रचार-प्रसार एवं बिक्री को बढ़ावा देना।

कार्य :-

- इस पर ग्रामीण क्षेत्रों में खादी और अन्य ग्रामोद्योगों के विकास के लिए कार्यक्रमों की योजना, प्रचार, संगठन और कार्यान्वयन की जिम्मेदारी है।
- यह जहां भी आवश्यक हो, ग्रामीण विकास में लगी अन्य एजेंसियों के साथ समन्वय करता है।

अवश्य पढ़ें:ग्रामीण विनिर्माण

SOURCE: PIB

हेरिटेज 2.0 कार्यक्रम अपनाना

संदर्भ: भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) ने हाल ही में संशोधित 'एडॉप्ट ए हेरिटेज 2.0' कार्यक्रम लॉन्च किया।

पृष्ठभूमि:-

- कार्यक्रम के अलावा एक भारतीय हेरिटेज ऐप भी लॉन्च किया गया।
- ऐप, एएसआई के दायरे में आने वाले स्मारकों के लिए एक व्यापक गाइड प्रदान करता है।
- इसमें तस्वीरों के साथ ऐतिहासिक संरचनाएं, साइट पर उपलब्ध सार्वजनिक सुविधाएं और जियो-टैग किए गए स्थान सूचीबद्ध हैं।

हेरिटेज 2.0 कार्यक्रम को अपनाने के बारे में:-

- लॉन्च: वर्ष 2023 में
- मंत्रालय: संस्कृति मंत्रालय
- कार्यान्वयन एजेंसी: भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण

मुख्य विशेषताएं:-

- इस कार्यक्रम के तहत, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) अपने सीएसआर फंड का उपयोग करके स्मारकों पर सुविधाएं बढ़ाने के लिए कॉर्पोरेट हितधारकों को आमंत्रित करता है।
- यह कार्यक्रम 2017 में शुरू की गई पिछली योजना का एक नया संस्करण है।
- यह प्राचीन स्मारक और पुरातात्विक स्थल और अवशेष अधिनियम या AMASR अधिनियम 1958 के अनुसार विभिन्न स्मारकों के लिए मांगी गई सुविधाओं को स्पष्ट रूप से परिभाषित करता है।
- हितधारक किसी स्मारक या विशिष्ट सुविधा/सुविधाओं को अपनाने के लिए एक यूआरएल www. Indianheritage.gov.in के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।
- पोर्टल में अंतराल विश्लेषण और सुविधाओं के वित्तीय अनुमान के साथ समर्पित वेब पोर्टल को गोद लेने के लिए मांगे गए स्मारकों का विवरण शामिल है।

चयन:-

- चयन की प्रक्रिया उचित परिश्रम और विभिन्न हितधारकों के साथ चर्चा और प्रत्येक स्मारक पर आर्थिक और विकासात्मक अवसरों का आकलन करने के बाद की जाएगी।

- चयनित हितधारक स्वच्छता, पहुंच, सुरक्षा और ज्ञान श्रेणियों में सुविधाएं विकसित, प्रदान और/या बनाए रखेंगे। (भारतीय विरासत संस्थान)

महत्व:-

- कार्यक्रम का उद्देश्य कॉर्पोरेट हितधारकों के साथ सहयोग को बढ़ावा देना है जिसके माध्यम से वे इन स्मारकों को संरक्षित करने में योगदान दे सकते हैं।

अवश्य पढ़ें: विश्व धरोहर स्थल खतरे में होना

SOURCE: THE INDIAN EXPRESS

मालवीय मिशन - शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम

संदर्भ: हाल ही में मालवीय मिशन - शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया।

इसके बारे में:-

- आयोजित: सितंबर, 2023
- आयोजक: विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और शिक्षा मंत्रालय।
- अवधि: 2 सप्ताह (निपुण भारत मिशन)
- उद्देश्य: शिक्षकों के लिए अनुरूप प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान करना।
- यह कार्यक्रम उच्च शिक्षण संस्थानों में संकाय सदस्यों की क्षमता निर्माण के लिए काम करेगा।
- यह शिक्षकों के प्रशिक्षण की गुणवत्ता में सुधार करेगा, शिक्षकों में नेतृत्व कौशल का निर्माण करेगा और एनईपी के लक्ष्यों को साकार करने में मदद करेगा। (एनईपी सुधार का एक वर्ष: नई पहल)
- विषय-वस्तु: उच्च शिक्षण संस्थानों में संकाय सदस्यों की क्षमता निर्माण के लिए पाठ्यक्रम/सामग्री के लिए 8 विषयों की पहचान की गई है।
- इनमें समग्र और बहुविषयक शिक्षा, भारतीय ज्ञान प्रणाली (आईकेएस), अकादमिक नेतृत्व, शासन और प्रबंधन, उच्च शिक्षा और समाज, अनुसंधान और विकास, कौशल विकास, छात्र विविधता और समावेशी शिक्षा और सूचना और संचार प्रौद्योगिकी शामिल हैं।
- ऑनलाइन पोर्टल: इस परिवर्तनकारी यात्रा को सुविधाजनक बनाने के लिए, यूजीसी ने क्षमता निर्माण कार्यक्रमों के लिए पंजीकरण करने के लिए संकाय सदस्यों के लिए एक समर्पित पोर्टल भी स्थापित किया है।

महत्व:-

- यह कार्यक्रम निरंतर व्यावसायिक विकास सुनिश्चित करेगा।
- यह पूरे भारत में 111 मालवीय मिशन केंद्रों के माध्यम से समयबद्ध तरीके से HEI के 15 लाख शिक्षकों की क्षमता निर्माण में मदद करेगा।
- यह शिक्षकों को भारतीय मूल्यों की गहरी समझ के साथ भविष्य के लिए तैयार करने में मदद करेगा।

अवश्य पढ़ें:सावित्रीबाई फुले: भारत की पहली महिला शिक्षिका

SOURCE: PIB

बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली

संदर्भ: सरकार ने हाल ही में देश में 4,000 मेगावाट की बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली स्थापित करने के लिए कुल पूंजी लागत के 40% तक व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण के लिए ₹3,760 करोड़ की मंजूरी दी है।

पृष्ठभूमि:-

- संपूर्ण 3,760 करोड़ रुपए की व्यवहार्यता अंतर निधि (वीजीएफ) केंद्र सरकार द्वारा वहन की जाएगी।
- VGF 2030-31 तक पांच किश्तों में जारी किया जाएगा।
  o व्यवहार्यता अंतर वित्त: इसका मतलब उन परियोजनाओं का समर्थन करने के लिए अनुदान है जो आर्थिक रूप से उचित हैं लेकिन वित्तीय रूप से व्यवहार्य नहीं हैं।
- इसका लक्ष्य भंडारण की स्तरीकृत लागत (एलसीओएस) को घटाकर ₹5.50-6.60 प्रति किलोवाट-घंटा (केडब्ल्यूएच) करना है, जिससे अधिकतम बिजली की मांग को प्रबंधित करने के लिए भंडारण एक व्यवहार्य विकल्प बन जाएगा।
- इससे देश भर में 4,000 MWh स्टोरेज बनाने में मदद मिलेगी।

- VGF अनुदान के लिए BESS डेवलपर्स का चयन एक पारदर्शी प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के माध्यम से किया जाएगा, जो सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों की संस्थाओं के लिए एक समान अवसर को बढ़ावा देगा।

बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणालियों के बारे में:-

- बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली एक प्रकार की ऊर्जा भंडारण प्रणाली है जो ऊर्जा को बिजली के रूप में संग्रहीत और वितरित करने के लिए बैटरी का उपयोग करती है।
- इनका उपयोग अक्सर सौर और पवन जैसे नवीकरणीय स्रोतों से ऊर्जा को संग्रहीत और जारी करने में सक्षम बनाने के लिए किया जाता है।

बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणालियों के प्रकार:-

- आवासीय BESS: घरों के लिए
- वाणिज्यिक BESS: व्यवसायों के लिए
- उपयोगिता-पैमाने पर BESS: बड़े पैमाने पर ऊर्जा भंडारण के लिए

लाभ :-

- BESS ग्रिड में नवीकरणीय ऊर्जा एकीकरण को बढ़ाएगा। (स्थायी ऊर्जा)
- यह बर्बादी को कम करेगा, और बुनियादी ढांचे के उन्नयन की लागत को कम करेगा।
- इससे चरम मांग और संबंधित लागत में कमी आएगी।

चुनौतियाँ:-

- इसकी प्रारंभिक लागत अधिक है। (1000 मेगावाट घंटा परियोजना के लिए बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली (बीईएसएस))
- बैटरी संबंधी समस्याओं का पुनर्चक्रण और निपटान।
- विनियामक और ग्रिड एकीकरण मुद्दे।

अवश्य पढ़ें:भारत में सौर ऊर्जा

SOURCE: THE HINDU

स्किल इंडिया डिजिटल ऐप

संदर्भ: हाल ही में, केंद्र ने स्किल इंडिया डिजिटल ऐप लॉन्च किया।

पृष्ठभूमि:-

- स्किल इंडिया डिजिटल ऐप, अपस्किलिंग पाठ्यक्रमों और जॉब लिस्टिंग के लिए लिस्टिंग को एक साथ लाता है।
- इस ऐप को अप्रैल 2023 में सॉफ्ट लॉन्च किया गया था, और संसद के बजट सत्र के दौरान केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा इसकी घोषणा की गई थी।

स्किल इंडिया डिजिटल ऐप के बारे में:-

- इसे वर्ष 2023 में लॉन्च किया गया।
- द्वारा विकसित: राष्ट्रीय कौशल विकास निगम
- मंत्रालय: कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय
- स्किल इंडिया डिजिटल ऐप, अपस्किलिंग पाठ्यक्रमों और जॉब लिस्टिंग के लिए लिस्टिंग को एक साथ लाता है।
- पाठ्यक्रम पूरा होने के सत्यापन योग्य प्रमाण पत्र जारी करने के लिए ऐप को डिजीलॉकर और आधार से जोड़ा जाएगा।
- यह नौकरी आवेदकों और पाठ्यक्रम लेने वाले लोगों के लिए डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित सीवी उत्पन्न करेगा।
- ऐप कौशल पर पाठ्यक्रम वितरित करने में मदद करेगा।
- यह संभावित नियोक्ताओं और कर्मचारियों को एक साथ लाने के लिए डिजिटल मैचमेकिंग का उपयोग करेगा।

स्किल इंडिया डिजिटल:-

- लॉन्च: सितंबर, 2023
- मंत्रालय: कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय। (कौशल विकास से संबंधित योजनाएँ)
- स्किल इंडिया डिजिटल सभी कौशल पहलों को एक साथ लाने के लिए एक अत्याधुनिक प्लेटफॉर्म है।
- यह कौशल, रोजगार और शिक्षा के लिए डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा है।

- यह शिक्षार्थियों, केंद्रीय और राज्य मंत्रालयों, नियोक्ताओं, सामग्री प्रदाताओं, ज्ञान भागीदारों, सेक्टर कौशल परिषदों, मूल्यांकन निकायों और मीडिया को संलग्न और उनकी पूर्ति करता है।
- यह सभी सरकारी कौशल और उद्यमिता पहलों के लिए एक व्यापक सूचना प्रवेश द्वार भी है।
- यह कैरियर में उन्नति और आजीवन सीखने की चाह रखने वाले नागरिकों के लिए एक पसंदीदा केंद्र है।
- यह सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के पंजीकरण के लिए उद्यम पोर्टल से जुड़ा हुआ है।
- यह "बाज़ार, वह मंच है जहां रुचि रखने वाले सभी लोग - वाणिज्यिक या गैर-व्यावसायिक हितधारक - एक साथ आ सकते हैं, जुड़ सकते हैं, कौशल प्रदान कर सकते हैं, कौशल हासिल कर सकते हैं, रोजगार की तलाश कर सकते हैं और रोजगार की पेशकश कर सकते हैं।
- इसका लक्ष्य डिजिटल प्रौद्योगिकी और उद्योग 4.0 कौशल पर ध्यान केंद्रित करते हुए कौशल विकास को अधिक नवीन, सुलभ और अपने रूप में वैयक्तिकृत बनाना है। (भारत में कौशल विकास)
- यह कुशल प्रतिभाओं की नियुक्ति में तेजी लाने और आजीवन सीखने तथा करियर में उन्नति की सुविधा प्रदान करने में एक बड़ी सफलता होगी।

अवश्य पढ़ें: राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन

SOURCE: THE HINDU

NeVA परियोजना

संदर्भ: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में गुजरात विधानसभा की राष्ट्रीय ई-विधान एप्लिकेशन (NeVA) परियोजना शुरू की।

राष्ट्रीय ई-विधान एप्लिकेशन (NeVA) परियोजना के बारे में:-

- राष्ट्रीय ई-विधान एप्लीकेशन (NeVA) एक ऑनलाइन एप्लीकेशन है।
- यह एक मिशन मोड प्रोजेक्ट (एमएमपी) है जो डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत आता है।
- उद्देश्य: सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) की मदद से सभी विधायिकाओं को डिजिटल बनाना।
- मंत्रालय: संसदीय कार्य मंत्रालय (एमओपीए)।
  o यह विधानमंडल वाले सभी 31 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में इसके कार्यान्वयन के लिए 'नोडल मंत्रालय' है।
- फंडिंग: यह MoPA द्वारा प्रदान किया जाता है।
  o NeVA की फंडिंग केंद्रीय प्रायोजित योजना यानी 60:40 के माध्यम से होती है; और उत्तर पूर्व और पहाड़ी राज्यों के लिए 90:10 और केंद्रशासित प्रदेशों के लिए 100%।
- इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमआईईटीवाई) द्वारा तकनीकी सहायता।
- अब तक, 21 राज्य विधानसभाओं ने NeVA को लागू करने के लिए समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं, और उनमें से 17 के लिए धन आवंटित किया गया है।
- नौ विधायिकाएं पूरी तरह से डिजिटल सदनों में परिवर्तित हो गई हैं और सक्रिय रूप से NeVA प्लेटफॉर्म पर काम करती हैं।
- हिमाचल प्रदेश देश की पहली डिजिटल विधानसभा थी।

महत्व:-

- NeVA क्लाउड-फर्स्ट और मोबाइल-फर्स्ट दृष्टिकोण को प्राथमिकता देने के मिशन के साथ 'वन नेशन, वन एप्लिकेशन' की अवधारणा का प्रतीक है।
- इसका उद्देश्य विधान सभाओं के सदस्यों को अधिक प्रभावी ढंग से सेवा प्रदान करना है।
- यह संपूर्ण कानून बनाने की प्रक्रिया के स्वचालन, निर्णयों और दस्तावेजों पर नज़र रखने और जानकारी साझा करने में सक्षम बनाता है।
- क्लाउड टेक्नोलॉजी (मेघराज) के माध्यम से, तैनात किए गए डेटा को किसी भी समय कहीं भी एक्सेस किया जा सकता है।
- इस एप्लिकेशन पर लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी की लाइव वेबकास्टिंग भी उपलब्ध है।

अवश्य पढ़ें: वैश्विक डिजिटल प्रशासन

SOURCE: THE HINDU

श्रेयस योजना

संदर्भ: हालिया अनुमान के अनुसार, श्रेयस योजना के तहत 2014 से छात्रों की शिक्षा के लिए 2300 करोड़ रुपये से अधिक आवंटित किए गए हैं।

पृष्ठभूमि:-

- श्रेयस नेशनल फेलोशिप योजना से 21,000 से अधिक अनुसूचित जाति के छात्रों को उच्च शिक्षा का लाभ मिलता है।

श्रेयस योजना के बारे में:-

- लॉन्च: वर्ष 2014 में
- मंत्रालय: सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
- श्रेयस का मतलब है, युवा अचीवर्स के लिए उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति योजना।
- यह एक व्यापक योजना है जिसमें 4 केंद्रीय क्षेत्र की उप-योजनाएँ शामिल हैं।
- चूँकि ये सभी उप-योजनाएँ केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएँ हैं, इसलिए इन योजनाओं के लिए राज्य-वार डेटा नहीं रखा जाता है।

उद्देश्य:-

- आर्थिक रूप से वंचित एससी और ओबीसी उम्मीदवारों को उच्च गुणवत्ता वाली कोचिंग प्रदान करना।
- उन्हें सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की नौकरियों के लिए प्रतियोगी और प्रवेश परीक्षाओं के लिए तैयार कराना।
- प्रतिष्ठित तकनीकी और व्यावसायिक उच्च शिक्षा संस्थानों में प्रवेश की सुविधा प्रदान करना।

मुख्य विशेषताएं:-

- श्रेयस का मतलब है, युवा अचीवर्स के लिए उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति योजना।
- इसके अंतर्गत 4 केंद्रीय क्षेत्र उप-योजनाओं में शामिल हैं:-
  - o अनुसूचित जाति के लिए शीर्ष श्रेणी की शिक्षा
  - o अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए निःशुल्क कोचिंग योजना
  - o अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय प्रवासी योजना
  - o अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय फैलोशिप

अनुसूचित जाति के लिए शीर्ष श्रेणी की शिक्षा:-

उद्देश्य:-

- आर्थिक रूप से वंचित अनुसूचित जाति (एससी) और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के उम्मीदवारों के लिए अच्छी गुणवत्ता की कोचिंग प्रदान करना।
- उन्हें सार्वजनिक/निजी क्षेत्र में उचित नौकरियां प्राप्त करने के साथ-साथ प्रतिष्ठित तकनीकी और व्यावसायिक उच्च शिक्षा संस्थानों में प्रवेश पाने के लिए प्रतिस्पर्धी और प्रवेश परीक्षाओं में शामिल होने में सक्षम बनाना।
- इस योजना के तहत कुल पारिवारिक आय की सीमा 8 लाख प्रति वर्ष है।
- एससी: ओबीसी छात्रों का अनुपात 70:30 है।
- प्रत्येक श्रेणी में महिलाओं के लिए 30% स्लॉट आरक्षित हैं।
- एससी वर्ग में पर्याप्त संख्या में उम्मीदवारों की अनुपलब्धता की स्थिति में, मंत्रालय इस अनुपात में छूट दे सकता है।
- हालाँकि, किसी भी स्थिति में, 50% से कम एससी छात्र को अनुमति नहीं दी जाएगी।

अनुसूचित जाति के लिए सर्वोत्तम शिक्षा:-

- **उद्देश्य:** पूर्ण वित्तीय सहायता प्रदान करके अनुसूचित जाति के छात्रों के बीच गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को पहचानना और बढ़ावा देना।
- यह योजना 12वीं कक्षा से आगे की पढ़ाई करने वाले अनुसूचित जाति के छात्रों को कवर करेगी।
- एक बार प्रदान की जाने वाली छात्रवृत्ति, छात्र के संतोषजनक प्रदर्शन के अधीन, पाठ्यक्रम पूरा होने तक जारी रहेगी।
- योजना के तहत कुल पारिवारिक आय की सीमा 8 लाख प्रति वर्ष है।
- योजना के तहत, पूर्ण ट्यूशन फीस, गैर-वापसी योग्य शुल्क (non-refundable charges) और शैक्षणिक भत्ता खर्च प्रदान किया जाता है।

अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय प्रवासी योजना:-

- इस योजना के तहत, अनुसूचित जाति, गैर-अधिसूचित, घुमंतू (Nomadic) और अर्ध-घुमंतू (Semi-Nomadic) जनजातियों, भूमिहीन कृषि मजदूरों और पारंपरिक कारीगर श्रेणियों के चयनित छात्रों को विदेश में मास्टर और पीएचडी स्तर के पाठ्यक्रम करने के लिए वित्तीय

सहायता प्रदान की जाती है।

- ऐसे छात्र इस योजना के तहत लाभ उठा सकते हैं जिनकी उम्मीदवार सहित कुल पारिवारिक आय 8 लाख प्रति वर्ष से कम है, जिनके पास योग्यता परीक्षा में 60% से अधिक अंक हैं, जिनकी आयु 35 वर्ष से कम है, और जिन्होंने 500 क्यूएस रैंकिंग विदेशी संस्थान/विश्वविद्यालय से शीर्ष स्थान पर प्रवेश प्राप्त किया है।
- योजना के तहत, पुरस्कार विजेताओं को कुल ट्यूशन फीस, रखरखाव और आकस्मिकता भत्ता, और वीजा शुल्क, आने-जाने का हवाई मार्ग प्रदान किया जाता है। (शिक्षा एवं राष्ट्र निर्माण)

अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए राष्ट्रीय फैलोशिप:-

- योजना के तहत, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों/संस्थानों/कॉलेजों में विज्ञान, मानविकी और सामाजिक विज्ञान में एम फिल/पीएचडी डिग्री के लिए उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए अनुसूचित जाति के छात्रों को फेलोशिप प्रदान की जाती है।
- यह योजना प्रति वर्ष 2000 नए स्लॉट प्रदान करती है, जिन्होंने यूजीसी की राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा जूनियर रिसर्च फेलोशिप (एनईटी-जेआरएफ) और साइंस स्ट्रीम के लिए जूनियर रिसर्च फेलो को यूजीसी-काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च (यूजीसी-सीएसआईआर) संयुक्त परीक्षा उत्तीर्ण की है।

अवश्य पढ़ें: शिक्षा में लैंगिक अंतर

SOURCE: PIB

किसान ऋण पोर्टल

संदर्भ: हाल ही में, भारत सरकार ने मौसम पोर्टल WIND के साथ किसान ऋण पोर्टल लॉन्च किया।

WIND पोर्टल:-

- लॉन्च: जुलाई 2023
- उद्देश्य: उन्नत मौसम डेटा विश्लेषण का लाभ उठाना और कृषि पर मौसम संबंधी निर्णय लेने के लिए हितधारकों को कार्रवाई योग्य जानकारी देना।
- पोर्टल हितधारकों को पोर्टल की कार्यक्षमताओं, डेटा व्याख्याओं और प्रभावी उपयोग की गहन समझ के लिए एक व्यापक मैनुअल भी प्रदान करता है, जो किसानों, नीति निर्माताओं और विभिन्न कृषि संस्थाओं को अच्छी तरह से सूचित निर्णय लेने के लिए सशक्त बनाता है।

किसान ऋण पोर्टल के बारे में:-

- लॉन्च: सितंबर, 2023
- उद्देश्य: विशेष रूप से किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) योजना के तहत ऋण सेवाओं तक पहुंच में क्रांतिकारी बदलाव लाना।
  - o किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) योजना भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा अगस्त 1998 में शुरू की गई एक क्रेडिट योजना है।
- कार्यान्वयन: कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय (MoA&FW), वित्त मंत्रालय, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI), और राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (NABARD)।

मुख्य विशेषताएं:-

- किसान ऋण पोर्टल एक एकीकृत केंद्र के रूप में कार्य करता है।
- यह किसान डेटा का एक व्यापक दृश्य प्रस्तुत करता है।
- यह योजना के उपयोग में प्रगति को भी दिखाएगा।
- यह किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) योजना के तहत सब्सिडी वाले ऋण तक आसान पहुंच प्रदान करेगा। (प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि)
- किसान ऋण डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रस्तुत करता है:-
  - o किसान डेटा का एक व्यापक दृश्य
  - o योजना उपयोग की प्रगति
  - o ऋण संवितरण विवरण (कृषि अवसंरचना निधि (एआईएफ))
  - o ब्याज छूट के दावे

- यह संशोधित ब्याज सहायता योजना (एमआईएसएस) के माध्यम से किसानों को सब्सिडी वाले कृषि ऋण प्राप्त करने में सुविधा प्रदान करेगा।

लाभ :-

- बैंकों के साथ निर्बाध एकीकरण को बढ़ावा देकर, यह अग्रणी पोर्टल अधिक केंद्रित और कुशल कृषि ऋण तथा ब्याज छूट के इष्टतम उपयोग के लिए सक्रिय नीति हस्तक्षेप, रणनीतिक मार्गदर्शन और अनुकूली संवर्द्धन को सक्षम बनाता है।
- यह अधिक प्रभावी और कुशल कृषि ऋण के लिए बैंकों के साथ निर्बाध एकीकरण को बढ़ाएगा।

अवश्य पढ़ें: डिजिटल प्लेटफार्म किसान सारथी

SOURCE: BUSINESS LINE

जीसीईएस वेब पोर्टल और मोबाइल एप्लिकेशन

संदर्भ: इनोवेटिव जीसीईएस वेब पोर्टल और मोबाइल एप्लिकेशन हाल ही में लॉन्च किया गया था।

जीसीईएस वेब पोर्टल और मोबाइल एप्लिकेशन के बारे में:-

- लॉन्च: सितंबर, 2023
- मंत्रालय: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
- उद्देश्य: इस पोर्टल और मोबाइल एप्लिकेशन को पूरे देश में कृषि पद्धतियों को बदलने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

मुख्य विशेषताएं:-

व्यापक जानकारी:-

- पोर्टल और ऐप गांव-वार जीसीईएस योजना सहित उपज अनुमान का एक व्यापक स्टॉक प्रदान करते हैं।
- प्लॉट का विवरण जहां फसल काटने के प्रयोग किए जाते हैं, कटाई के बाद फसल का वजन और फसल का जल निकासी वजन भी प्रदान किया जाता है। (फसल बीमा)

भू-संदर्भ:-

- यह मोबाइल एप्लिकेशन की प्रमुख विशेषताओं में से एक है।
- यह प्राथमिक कार्यकर्ता को प्रायोगिक भूखंड की सीमा खींचने और इसके माध्यम से भूखंड के साथ-साथ फसलों की तस्वीरें अपलोड करने में सक्षम बनाता है।
- यह सुविधा डेटा की पारदर्शिता और सटीकता भी सुनिश्चित करता है।

चुनौतियाँ:-

- रिपोर्टिंग में देरी: आज तक, डेटा संग्रह, संकलन और उपज अनुमान पूरी तरह से मैन्युअल प्रक्रिया है जो राज्यों द्वारा रिपोर्टिंग में देरी का कारण बनती है।
  o नई प्रक्रिया में, जीपीएस-सक्षम मोबाइल एप्लिकेशन का उपयोग करके फ़ील्ड डेटा एकत्र किया जाएगा।
  o सर्वर में डेटा संग्रहीत करने से फसल आंकड़ों की समय पर रिपोर्टिंग सुनिश्चित होगी।
- पारदर्शिता: जीपीएस-सक्षम डिवाइस डेटा संग्रह बिंदुओं के लिए सटीक अक्षांश और देशांतर निर्देशांक प्रदान करते हैं।
  o यह जानकारी सुनिश्चित करती है कि डेटा विशिष्ट भौगोलिक स्थानों से जुड़ा हुआ है, जिससे डेटा को जहां एकत्र किया गया था, उसके संबंध में अस्पष्टता या हेरफेर के लिए कोई जगह नहीं बचती है।

महत्व:-

- यह कृषि में वास्तविक समय अनुमान और प्रौद्योगिकी प्रदान करता है।
- यह सामाजिक लाभ के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकी को अधिकतम करने की दिशा में प्रधान मंत्री के दृष्टिकोण के अनुरूप है।

सामान्य फसल अनुमान सर्वेक्षण (जीसीईएस) के बारे में:-

- संचालन: आईसीएआर-भारतीय कृषि सांख्यिकी अनुसंधान संस्थान (आईएएसआरआई)।
- मंत्रालय: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।
- फसल उत्पादन का अनुमान फसल के अंतर्गत क्षेत्रफल और उपज दर को गुणा करके प्राप्त किया जाता है।
- उपज दर का अनुमान सामान्य फसल अनुमान सर्वेक्षण (जीसीईएस) के तहत किए गए वैज्ञानिक रूप से डिजाइन किए गए फसल-काटने के प्रयोगों पर आधारित है।

- जीसीईएस 22 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों में लगभग 68 फसलों (52 खाद्य और 16 गैर-खाद्य) को कवर करता है।
- राज्य के राजस्व और विभागों के प्राथमिक क्षेत्र के कर्मचारियों की तुलना में उच्च रैंक के कृषि कर्मचारियों की मदद से हर साल लगभग 5,00,000 प्रयोग किए जाते हैं।
- फसल काटने के प्रयोगों के संचालन में फील्ड स्टाफ को समय-समय पर प्रशिक्षित किया जाता है।

अवश्य पढ़ें:प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना

SOURCE: PIB

प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई)

संदर्भ: मत्स्य पालन विभाग प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) के 'एकीकृत आधुनिक तटीय मत्स्य पालन गांवों' के तहत एक उप-गतिविधि के रूप में तटीय राज्यों के लिए कृत्रिम रीफ इकाइयां स्थापित कर रहा है।

कृत्रिम रीफ के बारे में:

- कृत्रिम रीफ एक मानव निर्मित पानी के नीचे की संरचना है जो समुद्री जीवन के लिए आवास बनाने के लिए एक प्राकृतिक चट्टान के रूप में प्रतिस्थापित होती है।
- समुद्री आबादी को आकर्षित करने के लिए उन्हें उन क्षेत्रों में रखा जाता है जहां निचली स्थलाकृति कम होती है या मूंगा चट्टानों के पास होती है।
- ये प्रवाल भित्तियों को मानव-प्रेरित क्षति से बचाने के साथ-साथ जैव विविधता और स्वस्थ पारिस्थितिकी तंत्र का समर्थन करने का काम करते हैं।

प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) के बारे में:

- यह मत्स्य पालन क्षेत्र के केंद्रित और सतत विकास के लिए एक प्रमुख योजना है जिसे 2020-21 से 2024-25 तक लागू किया जाएगा।
- मंत्रालय: मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी
- उद्देश्य:
  - o भारत में मत्स्य पालन क्षेत्र के सतत और जिम्मेदार विकास के माध्यम से नीली क्रांति लाना।
  - o मछुआरों और मछली किसानों की आय को दोगुना करना, फसल कटाई के बाद के नुकसान को 20-25% से घटाकर लगभग 10% करना और क्षेत्र में रोजगार के अवसर पैदा करना।
- कार्यान्वयन: इसे दो अलग-अलग घटकों केंद्रीय क्षेत्र योजना और केंद्र प्रायोजित योजना के साथ एक छत्र योजना के रूप में कार्यान्वित किया गया है।
  - o उत्तर पूर्वी और हिमालयी राज्य: 90% केंद्र हिस्सेदारी और 10% राज्य हिस्सेदारी।
  - o अन्य राज्य: 60% केंद्रीय हिस्सा और 40% राज्य का हिस्सा।
- उपलब्धियाँ:
  - o वर्ष 2023 तक, PMMSY के तहत 2020-21 से 2022-23 तक 14,654.67 करोड़ रुपये की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है।
- वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान मछली उत्पादन 16.25 MMT के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया, जिसमें समुद्री निर्यात 57,586 करोड़ रुपये तक पहुंच गया।

Source: PIB

विविध

रेमन मैग्सेसे पुरस्कार

संदर्भ: हाल ही में, असम स्थित एक ऑन्कोलॉजिस्ट रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 के विजेताओं में से थे।

पृष्ठभूमि:-

- भारत के चौथे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म श्री के प्राप्तकर्ता और असम के कछार कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र (सीसीएचआरसी) के निदेशक ऑन्कोलॉजिस्ट रवि कन्नन को 2023 रेमन मैग्सेसे पुरस्कार के चार विजेताओं में से एक नामित किया गया है।
- उनके अग्रणी प्रयासों ने जन-केंद्रित और गरीब-समर्थक स्वास्थ्य देखभाल समाधानों को प्राथमिकता देकर असम में कैंसर के इलाज में क्रांति ला दी है।

परिचय :-

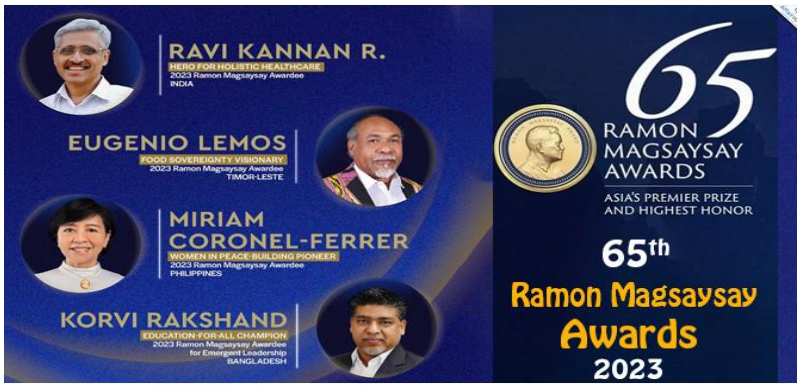

- स्थापित: वर्ष 1957 में
- नामकरण: इसका नाम रेमन मैग्सेसे के नाम पर रखा गया है।
  - रेमन मैग्सेसे: फिलीपींस गणराज्य के तीसरे राष्ट्रपति।
- यह वंश, पंथ, लिंग या राष्ट्रीयता की परवाह किए बिना एशिया में व्यक्तियों और संगठनों को मान्यता देता है और उनका सम्मान करता है, जिन्होंने विशिष्टता हासिल की है और सार्वजनिक मान्यता के लक्ष्य के बिना उदारतापूर्वक दूसरों की मदद की है।
- यह एशिया के नोबेल पुरस्कार के समकक्ष है।

पुरस्कार श्रेणियाँ:-

- वर्ष 2009 तक: पुरस्कार पारंपरिक रूप से पाँच श्रेणियों में दिए जाते थे:-
  - इनमें सरकारी सेवा; सार्वजनिक सेवा; सामुदायिक नेतृत्व; पत्रकारिता, साहित्य और रचनात्मक संचार कला; और शांति एवं अंतर्राष्ट्रीय समझ शामिल है।
- वर्ष 2009 के बाद: रेमन मैग्सेसे अवार्ड फाउंडेशन प्रतिवर्ष उभरते नेतृत्व के क्षेत्र के लिए पुरस्कार विजेताओं का चयन करता है।

पुरस्कार अलंकरण:-

- पुरस्कार विजेताओं को एक प्रमाण पत्र, रेमन मैग्सेसे की उभरी हुई छवि वाला एक पदक और नकद पुरस्कार प्रदान किया जाता है।

Awardee	Country	Contribution
Ravi Kannan	India	For his combination of skill, commitment, and compassion in pushing the boundaries of people-centered, pro-poor health care and cancer care
Korvi Rakshand	Bangladesh	For his work towards developing inclusive education for the underprivileged children in Bangladesh
Eugenio Lemos	Timor-Leste	For his efforts in ensuring adequate food for people and promoting the importance of conserving the environment and social equality.
Miriam Coronel-Ferrer	Philippines	For her unwavering confidence in the transforming power of nonviolent peacebuilding techniques.

महत्वपूर्ण भारतीय पुरस्कार विजेता:-

- अब तक, भारत को कुल 59 पुरस्कार मिले हैं, जबकि फिलीपींस को 65 पुरस्कार मिले हैं, जो इसे सभी देशों में सर्वोच्च बनाता है।
    - विनोबा भावे (1958)
    - मदर टेरेसा (1962)
    - वर्गीस कुरियन (1963)
    - जयप्रकाश नारायण (1965)
    - कमलादेवी चट्टोपाध्याय (1966)
    - सत्यजीत रे (1967)
    - एम.एस. सुब्बालक्ष्मी (1974)
    - अरुण शौरी (1982)
    - किरण बेदी (1994)
    - महाश्वेता देवी (1997)
    - अरुणा रॉय (2000)
    - राजेंद्र सिंह (2001)
    - अरविंद केजरीवाल (2006)
    - गूंज के अंशू गुप्ता (2015)
    - बेजवाड़ा विल्सन, मानवाधिकार कार्यकर्ता (2016)
    - रवीश कुमार, पत्रकार (2019)

अवश्य पढ़ें: गांधी मंडेला पुरस्कार

SOURCE: HINDUSTAN TIMES

पुरुष हॉकी 5एस एशिया कप 2023

संदर्भ: प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने पुरुष हॉकी 5एस एशिया कप जीतने पर भारतीय पुरुष हॉकी टीम को बधाई दी।

इसके बारे में :-

- दिनांक: 29 अगस्त से 2 सितंबर 2023
- स्थान: सलालाह, ओमान
- मेजबान देश: ओमान
- यह पहला पुरुष हॉकी 5एस एशिया कप 2023 था। (ग्रैंड स्लैम)
- यह फील्ड हॉकी की दुनिया में एक ऐतिहासिक घटना थी। (खेल संहिता)
- विशिष्ट समूह: इसमें भारत, मलेशिया, पाकिस्तान, जापान, ओमान और बांग्लादेश ने प्रतिस्पर्धा की।
- चैलेंजर समूह: हांगकांग चीन, इंडोनेशिया, अफगानिस्तान, कजाकिस्तान और ईरान।

- महत्व: यह टूर्नामेंट FIH हॉकी 5s विश्व कप 2024 के लिए क्वालीफायर था।
    - तीन टीमों को वैश्विक मंच पर अपना टिकट हासिल करने का मौका मिला।

अवश्य पढ़ें: खेलों से सामाजिक परिवर्तन

SOURCE: AIR

MQ-9B ड्रोन

संदर्भ: भारत ने हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका से 31 MQ-9B ड्रोन खरीदने की प्रक्रिया शुरू की है।

MQ-9B ड्रोन के बारे में:-

- द्वारा विकसित: जनरल एटॉमिक्स एयरोनॉटिकल सिस्टम्स (जीए-एएसआई)।
- MQ-9B ड्रोन MQ-9 "रीपर" का एक प्रकार है।
    - MQ-9 रीपर: एक मानवरहित हवाई वाहन (यूएवी) जो दूर से नियंत्रित या स्वायत्त उड़ान संचालन में सक्षम है।
- ये उच्च ऊंचाई वाले लंबे समय तक सहन करने वाले ड्रोन हैं।
- ये खुफिया, निगरानी और टोही मिशनों के लिए डिज़ाइन किए गए हैं और हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइलों और स्मार्ट बमों से सुसज्जित हैं।
- ये मारक मिसाइलों से लैस हैं जो उच्च सटीकता के साथ दुश्मन के लक्ष्यों को भेद सकती हैं।
- MQ-9B के दो वेरिएंट हैं: स्काईगार्डियन और सीगार्डियन।
- भारतीय नौसेना 2020 से MQ-9B सी गार्डियन का संचालन कर रही है। (ड्रोन बीमा पॉलिसी)

MQ-9बी सीगार्जियन की विशेषताएं:-

- पेलोड: यह 5,670 किलोग्राम तक वजन ले जा सकता है।
- ऊंचाई: 40,000 फीट
- सहनशक्ति का समय: 40 घंटे
- यह इसे लंबे समय तक निगरानी के लिए उपयोगी बनाता है।
- यह भूमि, समुद्री निगरानी, पनडुब्बी रोधी युद्ध, सतह रोधी युद्ध, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध और अभियान संबंधी भूमिकाओं का समर्थन कर सकता है।
- यह स्वचालित टेक-ऑफ और लैंडिंग में सक्षम है।
- यह नागरिक हवाई क्षेत्र में सुरक्षित रूप से एकीकृत हो सकता है।
- यह संयुक्त बलों और नागरिक अधिकारियों को समुद्री क्षेत्र में कहीं भी - दिन हो या रात, वास्तविक समय पर स्थितिजन्य जागरूकता प्रदान करने में सक्षम बनाता है।

अवश्य पढ़ें: भारत ने ड्रोन आयात पर प्रतिबंध लगाया

SOURCE: HIDUSTAN TIMES

ट्राइफेड (भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास महासंघ)

संदर्भ: हाल ही में, G20 शिखर सम्मेलन में भारत की समृद्ध जनजातीय विरासत और शिल्प कौशल का एक उल्लेखनीय प्रदर्शन देखा गया, जिसे TRIFED (ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया) द्वारा क्यूरेट और प्रस्तुत किया गया।

आयोजन की मुख्य बातें:-

- भारत के विभिन्न क्षेत्रों के आदिवासी कारीगरों द्वारा हस्तनिर्मित कई उत्कृष्ट उत्पादों ने दुनिया भर के प्रतिनिधियों का ध्यान और प्रशंसा आकर्षित की। इनमें शामिल हैं:-

लोंगपी मिट्टी के बर्तन:-

- स्थान: मणिपुर में लोंगपी गांव।
- जनजाति: तांगखुल नागा जनजाति।
- अधिकांश मिट्टी के बर्तनों के विपरीत, लोंगपी कुम्हार के चाक द्वारा नहीं बनाया जाता है।

छत्तीसगढ़ पवन बांसुरी:-

- स्थान: छत्तीसगढ़ में बस्तर।
- जनजाति: गोंड जनजाति।
- पारंपरिक बांसुरी के विपरीत, यह एक हाथ से घूमकर धुन उत्पन्न करता है।
- शिल्प कौशल में सावधानीपूर्वक बांस का चयन, छेद ड्रिलिंग और मछली के प्रतीक, ज्यामितीय रेखाओं और त्रिकोणों के साथ सतह की नक्काशी शामिल है।

गोंड पेंटिंग:-

- जनजाति:गोंड जनजाति।
- कलात्मक प्रतिभा उनके जटिल चित्रों के माध्यम से चमकती है, जो प्रकृति और परंपरा से उनके गहरे संबंध को दर्शाती है।

गुजरात हैंगिंग्स:-

- स्थान: दाहोद, गुजरात।
- जनजाति: भील और पटेलिया जनजाति।
- यह एक प्राचीन गुजरात कला रूप और मूल रूप से गुड़िया और पालने वाले पक्षियों से उपजा है, जिसमें सूती कपड़े और पुनर्नवीनीकरण सामग्री शामिल है।

भेड़ ऊन के स्टोल:-

- स्थान: हिमाचल प्रदेश/जम्मू और कश्मीर।
- जनजाति: बोध, भूटिया और गुज्जर बकरवाल जनजातियाँ।
- ये शुद्ध भेड़ के ऊन से अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हैं, जैकेट से लेकर शॉल और स्टोल तक विभिन्न प्रकार के परिधान तैयार करते हैं।

अराकू वैली कॉफ़ी:

- स्थान: आंध्र प्रदेश में अरकू घाटी।
- यह कॉफी अपने अनूठे स्वाद और टिकाऊ खेती पद्धतियों के लिए प्रसिद्ध है।
- ग्लास मोज़ेक मिट्टी के बर्तन:-
- यह मोज़ेक कला शैली को दर्शाता है, जिसे सावधानीपूर्वक लैंपशेड और मोमबत्ती धारकों में तैयार किया गया है।
- प्रकाशित होने पर, ये रंगों का बहुरूपदर्शक प्रकट करते हैं, जिससे किसी भी स्थान में जीवंतता जुड़ जाती है।

मीनाकारी:-

- स्थान: राजस्थान
- यह धातु की सतहों को जीवंत खनिज पदार्थों से सजाने की कला है, जो मुगलों द्वारा शुरू की गई एक तकनीक है।

धातु अंबाबारी शिल्प:-

- स्थान: राजस्थान
- जनजाति:मीना जनजाति

- यह एक सावधानीपूर्वक प्रक्रिया है जो धातु की सजावट को उन्नत बनाती है।
- आज, यह सोने से आगे बढ़कर चांदी और तांबे जैसी धातुओं तक फैल गया है।

ट्राइफेड के बारे में:-

- स्थापना: वर्ष 1987 में
- मंत्रालय: जनजातीय कार्य मंत्रालय
- उद्देश्य: लघु वन उपज (एमएफपी) और उनके द्वारा एकत्र/खेती की गई अधिशेष कृषि उपज (एसएपी) के व्यापार को संस्थागत बनाकर देश के आदिवासियों का सामाजिक-आर्थिक विकास करना।
- ट्राइफेड की स्थापना अगस्त 1987 में भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्तर की सहकारी संस्था के रूप में बहु-राज्य सहकारी समिति अधिनियम, 1984 के तहत की गई थी। (वनधन क्रॉनिकल)

कार्य:-

- यह एक बाजार डेवलपर और एक सेवा प्रदाता दोनों की दोहरी भूमिका निभाता है, आदिवासियों को व्यवस्थित, वैज्ञानिक तरीके से उनके संचालन को बेहतर बनाने के लिए ज्ञान और उपकरणों के साथ सशक्त बनाता है और उनके विपणन दृष्टिकोण को विकसित करने में भी उनकी सहायता करता है।
- यह संवेदीकरण और स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के गठन के माध्यम से जनजातीय लोगों की क्षमता निर्माण में सक्रिय रूप से शामिल है।
- यह उन्हें स्थायी आधार पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में विकसित उत्पादों के विपणन के अवसर तलाशने और बनाने में भी सहायता करता है।

MUST READ:Tech for Tribal

SOURCE: PIB

बोरलॉग पुरस्कार

संदर्भ: भारतीय कृषि वैज्ञानिक स्वाति नायक ने हाल ही में बोरलॉग पुरस्कार जीता।

पृष्ठभूमि:-

- ओडिशा में स्थानीय समुदायों द्वारा प्यार से "बिहाना दीदी" (सीड लेडी) कहलाने वाली भारतीय कृषि वैज्ञानिक स्वाति नायक 2023 के लिए प्रतिष्ठित नॉर्मन ई. बोरलॉग पुरस्कार जीतने वाली तीसरी भारतीय कृषि वैज्ञानिक बन गईं।
- डॉ. स्वाति नायक ने ओडिशा में सूखा-सहिष्णु शाहभागी धान चावल की किस्म पेश की।

स्वाति नायक के कार्य का योगदान:-

- वह नई दिल्ली में आईआरआरआई में बीज प्रणाली और उत्पाद प्रबंधन की दक्षिण एशिया प्रमुख हैं।
- उनका काम "प्रौद्योगिकी स्केलिंग" या किसानों के बीच वैज्ञानिक ज्ञान और इसके व्यावहारिक अनुप्रयोग के बीच अंतर को कम करने पर रहा है।
- उन्हें 20 से अधिक जलवायु-लचीला और जैव-फोर्टिफाइड चावल किस्मों के सफल प्रसार और अपनाने का श्रेय दिया जाता है।
- इनमें 'सहभागी धन', पहाड़ी उपरी इलाकों के लिए उपयुक्त सूखा-सहिष्णु किस्म और 'बीना धान-11', जो बाढ़-सहिष्णु है, शामिल हैं।
    - उन्होंने महिला किसानों की मदद से ओडिशा के मयूरभंज जिले के आदिवासी इलाके में 'सहभागी धन' की शुरुआत की। पूरे ओडिशा में 'सहभागी धन' काफी मांग वाली किस्म बन गई है।
- 'बीना-धन-11', जिसमें ओडिशा की एक स्वदेशी भूमि प्रजाति से पहचाना गया एक जलमग्न-सहिष्णु Sub1 जीन शामिल है, एक समान सफलता थी।
- Sub1 जीन को कई मौजूदा लोकप्रिय उच्च उपज देने वाली किस्मों जैसे 'सांबा महसूरी', 'स्वर्णा' और 'रंजीत' में शामिल किया गया है।

बोरलॉग पुरस्कार के बारे में:-

- अवधि: यह प्रत्येक वर्ष अक्टूबर में प्रस्तुत किया जाता है।
- स्थान: डेस मोइनेस, आयोवा, यूएसए।
- प्रस्तुतकर्ता: विश्व खाद्य पुरस्कार फाउंडेशन।
- यह रॉकफेलर फाउंडेशन द्वारा समर्थित है।

- यह पुरस्कार खाद्य और पोषण सुरक्षा एवं भूख उन्मूलन के क्षेत्र में काम करने वाले 40 वर्ष से कम आयु के असाधारण वैज्ञानिकों को दिया जाता है।
- यह नोबेल पुरस्कार विजेता और हरित क्रांति के मुख्य वास्तुकार डॉ. नॉर्मन बोरलॉग की स्मृति में दिया जाता है।
- नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग: एक अमेरिकी कृषिविज्ञानी जिन्होंने दुनिया भर में इस पहल का नेतृत्व किया जिसने कृषि उत्पादन में व्यापक वृद्धि में योगदान दिया जिसे हरित क्रांति कहा गया।
- बोरलॉग को अक्सर "हरित क्रांति का जनक" कहा जाता था।

डेकोरेशन :-

- पुरस्कार डिप्लोमा में मेक्सिको के क्षेत्रों में काम करते हुए डॉ. बोरलॉग की छवि शामिल है।
- $10,000 का नकद पुरस्कार।

अन्य भारतीय प्राप्तकर्ता:-

- अदिति मुखर्जी (2012) और
- महालिंगम गोविंदराज (2022)

अवश्य पढ़ें: गांधी मंडेला पुरस्कार

SOURCE: BUSINESSLINE

काउंटर टेररिज्म फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज (FTX) 2023

संदर्भ: हाल ही में, भारतीय सेना की टुकड़ी काउंटर टेररिज्म फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज (एफटीएक्स) 2023 पर आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक (एडीएमएम) प्लस एक्सपर्ट वर्किंग ग्रुप (ईडब्ल्यूजी) के लिए रवाना हुई।

इसके बारे में :-

- दिनांक: 25 से 30 सितंबर 2023
- स्थान: रूस
- यह एक बहुराष्ट्रीय संयुक्त सैन्य अभ्यास है जिसकी मेजबानी म्यांमार के साथ ईडब्ल्यूजी के सह-अध्यक्ष के रूप में रूस द्वारा की जा रही है। (व्यायाम IBSAMAR)
- इससे पहले 2 से 4 अगस्त 2023 तक म्यांमार के नेय पई ताव में आतंकवाद-निरोध पर एडीएमएम प्लस ईडब्ल्यूजी का टेबल टॉप अभ्यास आयोजित किया गया था।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि:-

- वर्ष 2017 से, दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संगठन (आसियान) और प्लस देशों के बीच बातचीत और सहयोग की अनुमति देने के लिए एडीएमएम प्लस की सालाना बैठक होती है।
- एडीएमएम प्लस का उद्घाटन 12 अक्टूबर 2010 को हा नोई, वियतनाम में आयोजित किया गया था।
- इस वर्ष आसियान सदस्य देश प्लस ग्रुप के साथ अभ्यास में भाग लेंगे।
- अभ्यास का उद्देश्य: आतंकवाद-निरोध के क्षेत्र में क्षेत्रीय सहयोग को मजबूत करना और बढ़ावा देना।
- इस अभ्यास में गढ़वाले क्षेत्र में आतंकवादी समूहों को नष्ट करने सहित कई आतंकवाद विरोधी अभ्यास शामिल होंगे।
- आतंकवाद-रोधी 2023 पर एडीएमएम प्लस ईडब्ल्यूजी भारतीय सेना को आतंकवाद-रोधी अभियानों में अपनी विशेषज्ञता और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने के लिए एक मंच प्रदान करेगा।
- इससे अन्य 12 भाग लेने वाले देशों के बीच सहयोग बढ़ेगा। (सैन्य अभ्यास)
- भारतीय सेना अभ्यास से एक समृद्ध पेशेवर अनुभव की आशा करती है।

अवश्य पढ़ें: 26वाँ अभ्यास मालाबार

SOURCE: PIB

दादा साहब फाल्के लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार

संदर्भ: वहीदा रहमान को वर्ष 2023 के 53वें दादा साहब फाल्के लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

इसके बारे में :-

- स्थापना: वर्ष 1969 में

- राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में प्रस्तुत किया गया।
- प्रस्तुतकर्ता: भारत के राष्ट्रपति।
- प्रथम पुरस्कार विजेता: देविका रानी।
- नामकरण: यह पुरस्कार दादा साहब फाल्के की स्मृति में दिया जाता है।
- दादा साहब फाल्के 1913 में भारत की पहली पूर्ण लंबाई वाली भारतीय फीचर फिल्म, "राजा हरिश्चंद्र" के निर्देशक थे।
    - उन्हें "भारतीय सिनेमा के पितामह" के रूप में जाना जाता है।
- दादा साहब फाल्के लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार भारत का सर्वोच्च सिनेमा सम्मान है।
- यह फिल्म महोत्सव निदेशालय द्वारा प्रतिवर्ष राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में प्रस्तुत किया जाता है।
- यह पुरस्कार भारत के राष्ट्रपति द्वारा केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री, जूरी के अध्यक्षों, फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रतिनिधियों और अखिल भारतीय सिने कर्मचारी परिसंघ के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में प्रदान किया जाता है।
- यह भारतीय सिनेमा की वृद्धि और विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान किया जाता है।
- वर्ष 2020 के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रसिद्ध अभिनेत्री सुश्री आशा पारेख को दिया गया।

बनावट :-

- पुरस्कार में शामिल हैं:-
    - स्वर्ण कमल (गोल्डन लोटस) पदक
    - एक शॉल
    - 10 लाख का नकद पुरस्कार

अवश्य पढ़ें: गोल्डन ग्लोब्स पुरस्कार

SOURCE: PIB

एमएस स्वामीनाथन

संदर्भ: हाल ही में एमएस स्वामीनाथन का निधन हो गया।

पृष्ठभूमि:-

- भारत की हरित क्रांति के जनक कहे जाने वाले कृषि वैज्ञानिक डॉ. एमएस स्वामीनाथन का चेन्नई में निधन हो गया।
- वह 98 वर्ष के थे।

परिचय :-

- जन्मतिथि: 7 अगस्त, 1925
- जन्म स्थान: कुंभकोणम, तमिलनाडु में।
- स्वामीनाथन ने 1960 के दशक में भारत को अकाल जैसी परिस्थितियों से बचाने के लिए अपनी नीतियों के माध्यम से एक सामाजिक क्रांति लाई।
- उन्हें 'भारतीय हरित क्रांति का जनक' कहा जाता था।

प्रारंभिक जीवन और शिक्षा:-

- प्रारंभ में, भारत छोड़ो आंदोलन और 1942-43 के बंगाल अकाल से प्रेरित होकर, उन्होंने अपने जुनून के कारण सिविल सेवाओं में करियर बनाने का लक्ष्य रखते हुए कृषि की ओर रुख किया।
- कृषि में अपनी रुचि को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने कोयंबटूर के कृषि कॉलेज में दाखिला लिया।
- स्वामीनाथन ने भारत और विदेश दोनों में कृषि से संबंधित विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया।

हरित क्रांति में योगदान:-

- वर्ष 1960 और 70 के दशक में कृषि में स्वामीनाथन के योगदान ने भारत के कृषि परिदृश्य को बदल दिया, जिससे खाद्य सुरक्षा के युग की शुरुआत हुई।
- उन्होंने फसल की किस्मों, विशेषकर चावल और गेहूं को बढ़ाने पर काम किया।
- उन्होंने पैदावार बढ़ाने के लिए अर्ध-बौनी गेहूं किस्मों के विकास का बीड़ा उठाया।

- नॉर्मन बोरलॉग के सहयोग से गेहूं की किस्मों में बौने जीन की शुरूआत हुई।
- स्वामीनाथन ने छोटे पैमाने के किसानों को यह सिखाने के लिए 1965 में देश के उत्तरी हिस्से में सैकड़ों प्रदर्शनियों का आयोजन किया कि कैसे आनुवंशिक रूप से इंजीनियर किए गए अनाज उन्हें उसी भूमि में उच्च उपज उगाने में सक्षम बना सकते हैं।
- ये प्रदर्शन गेम-चेंजिंग थे क्योंकि हरित क्रांति युग के पहले वर्ष में फसल का उत्पादन स्तर तीन गुना हो गया था।
- स्वामीनाथन ने निरक्षरता की बाधा पर काबू पाने के लिए किसानों को इन नए तरीकों का उपयोग करने के लिए प्रशिक्षित किया।
- उनके प्रयासों के कारण, केवल चार फसल मौसमों में औसत कृषि उत्पादन 12 मिलियन टन से बढ़कर 23 मिलियन टन हो गया।

भूमिकाएँ:-

- उनकी भूमिकाओं में खाद्य और कृषि संगठन परिषद के स्वतंत्र अध्यक्ष (1981-85) शामिल थे।
- प्रकृति और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ के अध्यक्ष (1984-90)।
- 1989-96 तक वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर (भारत) के अध्यक्ष।
- उन्होंने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) के महानिदेशक के रूप में भी कार्य किया।
- उन्होंने एमएस स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना की।
- उन्होंने गेहूं की उच्च उपज देने वाली किस्म के बीज विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे भारत में हरित क्रांति आई।

पुरस्कार:-

- वर्ष 1986 में अल्बर्ट आइंस्टीन विश्व विज्ञान पुरस्कार।
- उन्होंने 1987 में पहला विश्व खाद्य पुरस्कार जीता।
- वर्ष 1991 में पर्यावरण उपलब्धि के लिए टायलर पुरस्कार।
- वर्ष 2000 में अंतर्राष्ट्रीय भौगोलिक संघ का ग्रह और मानवता पदक।
- उन्हें पद्म श्री (1967), पद्म भूषण (1972), और पद्म विभूषण (1989) से सम्मानित किया गया था।

अवश्य पढ़ें: महात्मा गांधी

SOURCE: AIR

विश्व विश्वविद्यालय रैंकिंग 2024

संदर्भ: सबसे पहले, हाल ही में जारी टाइम्स हायर एजुकेशन की वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में भारतीय विश्वविद्यालयों की रिकॉर्ड-तोड़ संख्या है।

रिपोर्ट की मुख्य बातें:-

- ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय लगातार आठवें वर्ष रैंकिंग में शीर्ष पर है।
- 169 संस्थानों के साथ अमेरिका कुल मिलाकर सबसे अधिक प्रतिनिधित्व वाला देश है, और शीर्ष 200 (56) में भी सबसे अधिक प्रतिनिधित्व वाला देश है।
- 91 संस्थानों के साथ, भारत अब चीन (86) को पछाड़कर चौथा सबसे अधिक प्रतिनिधित्व वाला देश है।
- भारत का शीर्ष विश्वविद्यालय, भारतीय विज्ञान संस्थान, बैंगलोर है।
- भारत में अगले सर्वोच्च रैंक वाले विश्वविद्यालय अन्ना विश्वविद्यालय, जामिया मिलिया इस्लामिया, महात्मा गांधी विश्वविद्यालय और शूलिनी यूनिवर्सिटी ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट साइंसेज हैं, जो सभी 501-600 बैंड में हैं।
- भारतीय विश्वविद्यालयों ने इस वर्ष महत्वपूर्ण लाभ कमाया, जिसमें देश के पांच शीर्ष विश्वविद्यालय भी शामिल हैं।
- IISc पिछले साल 251-300 बैंड से बढ़कर 201-250 हो गया।
- अन्ना विश्वविद्यालय पिछले वर्ष 801-1000 बैंड से बढ़कर 501-600 हो गया।
- अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय पिछले वर्ष 801-1000 बैंड से बढ़कर 601-80 हो गया।
- भारथिअर विश्वविद्यालय पिछले साल 801-1000 बैंड से बढ़कर 601-800 हो गया।
- मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने 601-800 बैंड में पहली बार रैंकिंग में प्रवेश किया।
- दो आईआईटी - भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, गुवाहाटी और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (इंडियन स्कूल ऑफ माइन्स) धनबाद - दुनिया

के शीर्ष 800 विश्वविद्यालयों में शामिल होने के लिए 1001-1200 से 601-800 तक पहुंच गए।

विश्व विश्वविद्यालय रैंकिंग 2024 के बारे में:-

- वर्ष 2004 में स्थापित किये गए।
- प्रकाशित: टाइम्स हायर एजुकेशन
- टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में 108 देशों और क्षेत्रों के 1,904 विश्वविद्यालय शामिल हैं।
- ये रैंकिंग सबसे व्यापक, दृढ़ और संतुलित वैश्विक रैंकिंग है। (क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021)
- इसमें शिक्षण, अनुसंधान, ज्ञान हस्तांतरण और अंतर्राष्ट्रीयकरण के उनके मुख्य मिशन शामिल हैं।
- यह 18 सावधानीपूर्वक कैलिब्रेटेड प्रदर्शन संकेतकों में अनुसंधान-गहन विश्वविद्यालयों का आकलन करता है जो पांच क्षेत्रों शिक्षण, अनुसंधान वातावरण, अनुसंधान गुणवत्ता, उद्योग और अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण में एक संस्थान के प्रदर्शन को मापते हैं।
- इस पर दुनिया भर में छात्रों, शिक्षकों, सरकारों और उद्योग विशेषज्ञों द्वारा भरोसा किया जाता है।

अवश्य पढ़ें: शिक्षा एवं राष्ट्र निर्माण

SOURCE: **THE INDIAN EXPRESS**

ONLINE

IAS BABA

Integrated Learning Program (S-ILP) - 2024

Crack UPSC 2024 - The Best Strategy for Next 365 Days (Prelims & Mains)

High Quality Subjectwise Class Videos

Daily Targets & Micro Tests

Personal Mentorship

67 Prelims & 59 Mains Tests

Start's from 5th December

ADMISSION OPEN

Most Trusted

www.iasbaba.com support@iasbaba.com 91691 91888

MAINS

Paper I

जाति-आधारित पृथक निर्वाचन क्षेत्रों पर गांधी-अंबेडकर बहस

Syllabus

- **Mains – GS 1 (History)**

संदर्भ: सितंबर 1932 के महीने में, पुणे की यरवदा सेंट्रल जेल में, गांधी ने हरिजनों को अलग निर्वाचन क्षेत्र देने के खिलाफ आमरण अनशन शुरू कर दिया।

1932 के पूना समझौते के बारे में:

- वर्ष 1932 में, गांधी ने जाति के आधार पर अलग निर्वाचन क्षेत्र बनाने के ब्रिटिश फैसले के खिलाफ यरवदा जेल में आमरण अनशन शुरू किया।
- गांधी जी के दबाव में अम्बेडकर ने 1932 में ऐतिहासिक पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किये।
    - इस संधि के अनुसार, हिंदू संयुक्त निर्वाचन मंडल को बरकरार रखा गया और दलित वर्गों को आरक्षित सीटें दी गईं।
- इस पर दलित वर्गों की ओर से अम्बेडकर और उच्च जाति के हिंदुओं की ओर से मदन मोहन मालवीय ने हस्ताक्षर किये थे।

समझौते के तहत निचली जातियों के लिए आरक्षण:

- **गांधीजी की कार्रवाई:** जाति के आधार पर अलग निर्वाचन क्षेत्र बनाने के ब्रिटिश फैसले के खिलाफ गांधी ने आमरण अनशन शुरू कर दिया।
- **अम्बेडकर की दुविधा:** अंबेडकर गांधी की राजनीतिक आपत्तियों से असहमत थे और वह जानते थे कि गांधी देश के सबसे प्रिय राजनीतिक नेता थे, और अगर उन्हें कुछ हुआ, तो नवोदित दलित आंदोलन को भारी परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं।
- पूना संधि पर हस्ताक्षर: भारी मन से, अंबेडकर गांधी के दबाव पर सहमत हुए, जिसे पूना संधि के रूप में जाना जाता है, जिसने निचली जातियों के लिए आरक्षण सुरक्षित किया।

जाति पर विकसित हो रहे विचार:

गांधी विचार:

- **पहले के रूढ़िवादी विचार:** प्रारंभ में, गांधी ने पारंपरिक जाति मानदंडों का समर्थन किया, अंतर-भोजन और अंतर्विवाह निषेध की वकालत की, जाति को हिंदू धर्म के लिए मौलिक माना।
- **राष्ट्रीय आंदोलन के बीच विकास:** गांधी के विचार तब विकसित हुए जब उन्होंने उभरते दलित आंदोलन से प्रभावित होकर भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
    - उन्होंने एकता का प्रचार करना शुरू किया और अस्पृश्यता की निंदा की, अछूतों के लिए "हरिजन" शब्द गढ़ा, भगवान के बच्चों के रूप में उनकी स्थिति पर जोर दिया।
- **अस्पृश्यता की आलोचना:** गांधीजी ने 1936 में आध्यात्मिक और राष्ट्रीय कल्याण दोनों पर इसके हानिकारक प्रभाव को पहचानते हुए, अस्पृश्यता की खुले तौर पर आलोचना की।

अम्बेडकर के विचार:

- अस्वीकृति का दृष्टिकोण: जाति व्यवस्था के खिलाफ कोई भी विद्रोह तभी संभव होगा जब उत्पीड़ितों ने स्वयं अपनी स्थिति और उत्पीड़न को दैवीय रूप से निर्धारित होने के रूप में इंकार कर दिया हो।
- शास्त्रों की अस्वीकृति: जाति व्यवस्था का अंत तभी संभव होगा जब पवित्र ग्रंथों के दैवीय अधिकार को पहले अस्वीकार कर दिया जाएगा।

पृथक निर्वाचन क्षेत्रों पर विचार:

अम्बेडकर का विश्वास:

- सकारात्मक कार्रवाई: उन्होंने निचली जातियों को सशक्त बनाने के लिए सकारात्मक कार्रवाई के रूप में अलग निर्वाचन मंडल का सुझाव दिया।
- दोहरे वोट का पक्ष: उन्होंने दोहरे वोट वाले अलग निर्वाचन क्षेत्रों का समर्थन किया, एक अनुसूचित जाति के लिए एक अनुसूचित जाति के उम्मीदवार को वोट देने हेतु और दूसरा अनुसूचित जाति के लिए सामान्य निर्वाचन क्षेत्र में वोट करने के लिए।

- संयुक्त निर्वाचन क्षेत्रों के विरुद्ध: उनके लिए, संयुक्त निर्वाचन क्षेत्रों ने बहुसंख्यकों को दलित समुदाय के प्रतिनिधियों के चुनाव को प्रभावित करने में सक्षम बनाया, और इस प्रकार उन्हें 'बहुमत के अत्याचार' के खिलाफ अपने उत्पीड़न के हितों की रक्षा करने में अक्षम कर दिया।

गांधी का विरोध:

- विश्व पर शासन करने पर प्रतिबंध: गांधी ने तर्क दिया कि केवल सीटों के इस मामूली हिस्से तक ही सीमित रहने के बजाय, निचली जातियों को "पूरे विश्व के साम्राज्य" पर शासन करने की आकांक्षा रखनी चाहिए।
- शोषणकारी कदम: गांधी ने अपने उद्देश्यों के लिए भारतीय समाज में आंतरिक विभाजन का फायदा उठाने के ब्रिटिश इरादों को सही ढंग से समझा।
    - अलग निर्वाचन क्षेत्र केवल ब्रिटिशों को 'फूट डालो और राज करो' में मदद करेंगे।
    - यह वह समय भी था जब हिंदू और मुसलमानों के बीच विरोध बढ़ रहा था।
    - यदि अलग निर्वाचन क्षेत्रों की घोषणा की गई, तो इससे भारतीयों की शक्ति काफी कम हो जाएगी।

आरक्षण की वर्तमान व्यवस्था:

- जाति-आधारित आरक्षण की व्यवस्था ऐतिहासिक रूप से सामाजिक और आर्थिक भेदभाव का अनुभव करने वाली जातियों के लोगों के लिए एक निश्चित संख्या में सीटें निर्धारित करती है।
- ये आरक्षण उच्च शिक्षा, सरकारी नौकरियों और यहां तक कि राजनीतिक कार्यालय पर भी लागू हैं।
- संसद सहित सभी विधायी निकायों में अनुसूचित जाति (एससी) और (एसटी) के लिए एक निश्चित संख्या में सीटें आरक्षित हैं।

भारत में आरक्षण को नियंत्रित करने वाले संवैधानिक प्रावधान

- भाग XVI केंद्रीय और राज्य विधानसभाओं में एससी और एसटी के आरक्षण से संबंधित है।
- संविधान के अनुच्छेद 15(4) और 16(4) ने राज्य और केंद्र सरकारों को एससी और एसटी के सदस्यों के लिए सरकारी सेवाओं में सीटें आरक्षित करने में सक्षम बनाया।
- संविधान (77वां संशोधन) अधिनियम, 1995 द्वारा संविधान में संशोधन किया गया और सरकार को पदोन्नति में आरक्षण प्रदान करने में सक्षम बनाने के लिए अनुच्छेद 16 में एक नया खंड (4ए) जोड़ा गया।
    - बाद में, आरक्षण देकर पदोन्नत एससी और एसटी उम्मीदवारों को परिणामी वरिष्ठता प्रदान करने के लिए संविधान (85वां संशोधन) अधिनियम, 2001 द्वारा खंड (4ए) को संशोधित किया गया था।
- संवैधानिक 81वें संशोधन अधिनियम, 2000 में अनुच्छेद 16 (4 बी) शामिल किया गया, जो राज्य को एक वर्ष की अधूरी रिक्तियों को भरने में सक्षम बनाता है जो अगले वर्ष में एससी/एसटी के लिए आरक्षित हैं, जिससे उस वर्ष की कुल रिक्तियों पर पचास प्रतिशत आरक्षण की सीमा समाप्त हो जाती है।
- अनुच्छेद 330 और 332 क्रमशः संसद और राज्य विधानसभाओं में एससी और एसटी के लिए सीटों के आरक्षण के माध्यम से विशिष्ट प्रतिनिधित्व प्रदान करते हैं।
- अनुच्छेद 243D प्रत्येक पंचायत में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण प्रदान करता है।
- अनुच्छेद 233T प्रत्येक नगर पालिका में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण प्रदान करता है।

Source: Indian Express

भारत में बढ़ती मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं

Syllabus

- **Mains – GS 1 (Society)**

संदर्भ: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी स्थायी समिति ने हाल ही में संसद में 'मानसिक स्वास्थ्य देखभाल और समकालीन समय में इसके प्रबंधन' पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की।

रिपोर्ट की मुख्य बातें:

- रिपोर्ट मानसिक स्वास्थ्य को कल्याण की स्थिति के रूप में परिभाषित करती है जो लोगों को जीवन के तनाव से निपटने में सक्षम बनाती है।
- इसमें इस बात पर प्रकाश डाला गया कि भारत में मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित मुद्दे बढ़ रहे हैं और देश अपर्याप्त कर्मचारियों, चिकित्सा बुनियादी ढांचे और बजटीय आवंटन के कारण पिछड़ा हुआ है।

- समिति ने कहा कि भारत में वर्तमान में प्रति लाख लोगों पर 0.75 मनोचिकित्सक हैं, जो काफी कम है।
- समिति ने कहा कि यदि भारत प्रति लाख लोगों पर तीन मनोचिकित्सकों को रखने का लक्ष्य रखता है, तो उसे 27,000 और मनोचिकित्सकों की आवश्यकता होगी।

वैश्विक परिदृश्य:

- वर्ष 2010 में, सालाना लगभग 2.5 ट्रिलियन डॉलर का वैश्विक आर्थिक नुकसान खराब मानसिक स्वास्थ्य के लिए जिम्मेदार ठहराया गया था, जो कम कल्याण और उत्पादकता से उत्पन्न हुआ था। यह 2030 तक बढ़कर 6 ट्रिलियन डॉलर हो जाएगा।
- अपर्याप्त फंडिंग: यह रिपोर्ट देखभाल और अनुसंधान के लिए अपर्याप्त फंडिंग पर प्रकाश डालती है।
    - इसके लिए न केवल बढ़ी हुई वित्तीय सहायता और विस्तारित मनोरोग रेजीडेंसी कार्यक्रमों की आवश्यकता है, बल्कि प्रशिक्षित मनोचिकित्सकों के लिए पदों की स्थापना और पर्याप्त संख्या में कार्यरत मनोवैज्ञानिकों को सुनिश्चित करना भी आवश्यक है।

मानसिक स्वास्थ्य देखभाल की स्थिति

भारत:

- अनुमान है कि भारत में 6-7% आबादी मानसिक विकारों से पीड़ित है।
- WHO का अनुमान है कि भारत में मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं का बोझ प्रति 100 00 जनसंख्या पर 2443 विकलांगता-समायोजित जीवन वर्ष (DALYs) है।
- प्रति 100,000 जनसंख्या पर आयु-समायोजित आत्महत्या दर 21.1 है।
    - वर्ष 2012-2030 के बीच मानसिक स्वास्थ्य स्थितियों के कारण 1.03 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का आर्थिक नुकसान होने का अनुमान है।

वैश्विक:

- विश्व बैंक के अनुसार, लगभग 1 अरब लोग मानसिक विकार से पीड़ित हैं और कम आय वाले देशों में रहते हैं; इस विकार से पीड़ित 75% से अधिक लोगों को उपचार नहीं मिल पाता है।
- हर 40 सेकंड में एक व्यक्ति आत्महत्या से मर जाता है।
- लगभग 50% मानसिक स्वास्थ्य विकार 14 वर्ष की आयु तक शुरू हो जाते हैं।
- WHO के अनुसार अवसाद विकलांगता के प्रमुख कारणों में से एक है और 15-29 वर्ष के लोगों में आत्महत्या मृत्यु का चौथा प्रमुख कारण है।
- मानसिक बीमारी से पीड़ित लोग विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन (सीआरपीडी) के अधीन हो सकते हैं।

मानसिक रोग के कारण:

- गरीबी, हिंसा, असमानता और पर्यावरणीय अभाव सहित प्रतिकूल सामाजिक, आर्थिक, भू-राजनीतिक और पर्यावरणीय परिस्थितियों के संपर्क में आने से भी लोगों में मानसिक स्वास्थ्य स्थितियों का अनुभव होने का खतरा बढ़ जाता है।
- पिछले दो वर्षों में, महामारी के कारण लगे लॉकडाउन और उनसे जुड़ी अनिश्चितताओं का मानसिक स्वास्थ्य पर हानिकारक **प्रभाव** पड़ा है।
- प्रारंभिक प्रतिकूल जीवन अनुभव, जैसे आघात या दुर्व्यवहार का इतिहास (उदाहरण के लिए, बाल दुर्व्यवहार, यौन उत्पीड़न, हिंसा देखना, आदि)।
- शराब या नशीली दवाओं का सेवन, अकेलेपन या अकेलेपन की भावना होना आदि।

ख़राब मानसिक स्वास्थ्य के प्रभाव:

- संबंधों पर प्रभाव: किशोरावस्था और युवा वयस्कता के दौरान मानसिक-स्वास्थ्य की स्थितियाँ साथियों, माता-पिता, शिक्षकों, सहकर्मियों और भागीदारों के साथ सुरक्षित और स्वस्थ संबंधों के विकास पर काफी नकारात्मक प्रभाव डाल सकती हैं।
- शारीरिक स्वास्थ्य पर प्रभाव: एक अध्ययन में पाया गया कि सकारात्मक मनोवैज्ञानिक कल्याण दिल के दौरे और स्ट्रोक के खतरों को कम कर सकता है।
    - दूसरी ओर, ख़राब मानसिक स्थिति ख़राब शारीरिक स्वास्थ्य या हानिकारक व्यवहार का कारण बन सकती है।
    - अवसाद को कई पुरानी बीमारियों से जोड़ा गया है।
    - इन बीमारियों में मधुमेह, अस्थमा, कैंसर, हृदय रोग और गठिया शामिल हैं।

- उत्पादकता पर प्रभाव: यह किसी व्यक्ति की ध्यान केंद्रित करने और उत्पादक गतिविधियों में संलग्न होने की क्षमता को प्रभावित करता है।

भारत सरकार की पहल:

- वर्ष 1982 में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम (एनएमएचपी): यह निकट भविष्य में सभी के लिए न्यूनतम मानसिक स्वास्थ्य देखभाल की उपलब्धता और पहुंच सुनिश्चित करता है।
- मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम, 2017: यह भारत में मानसिक बीमारी वाले व्यक्तियों के लिए मानसिक स्वास्थ्य देखभाल और सेवाएं प्रदान करता है।
- विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2017: यह अधिनियम मानसिक बीमारी को विकलांगता के रूप में स्वीकार करता है और विकलांगों के अधिकारों और हकदारियों को बढ़ाने का प्रयास करता है।
- राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम रणनीति
- राष्ट्रीय टेली-मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम: देश में गुणवत्तापूर्ण मानसिक स्वास्थ्य परामर्श और देखभाल सेवाओं तक पहुंच में सुधार करना।
- किरण हेल्पलाइन: यह आत्महत्या को रोकती है और सहायता एवं संकट प्रबंधन में मदद कर सकती है।
- विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस: दुनिया भर में मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और मानसिक स्वास्थ्य के समर्थन में प्रयास जुटाना।

Source: The Hindu

बहुविवाह विरोधी कानून

Syllabus

- **Mains – GS 1 (Society)**

संदर्भ: हाल ही में असम सरकार ने बहुविवाह विरोधी कानून का मसौदा तैयार करने के लिए तीन सदस्यीय पैनल का गठन किया।

बहुविवाह के बारे में:

- बहुविवाह दो शब्दों से बना है: "पॉली", जिसका अर्थ है "बहुत" और "गामोस", जिसका अर्थ है "विवाह।"
  - परिणामस्वरूप, बहुविवाह अनेक विवाहों से संबंधित है।
- बहुविवाह (प्रथा) ऐसी प्रथा है जिसमें कोई व्यक्ति स्त्री या पुरुष एक से अधिक व्यक्तियों से विवाह करता है।
- बहुविवाह में किसी भी महिला या पुरुष के एक ही समय में एक से अधिक वैवाहिक साथी होते हैं।
  - हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 ने इस प्रथा को गैरकानूनी घोषित कर दिया।
- विशेष विवाह अधिनियम (Special Marriage Act- SMA), 1954 व्यक्तियों को अंतर-धार्मिक विवाह करने की अनुमति देता है, लेकिन इसमें बहुविवाह की मनाही है। अधिनियम का उपयोग कई मुस्लिम महिलाओं द्वारा बहुविवाह प्रथा को रोकने में मदद हेतु किया गया है।

प्रकार:

- बहुपत्नीत्व (Polygyny): यह एक वैवाहिक संरचना है जिसमें एक पुरुष की कई पत्नियाँ होती हैं। इस रूप में बहुविवाह अधिक सामान्य अथवा व्यापक है।
- माना जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में राजाओं और सम्राटों की कई पत्नियाँ होती थीं।
- बहुपतित्व प्रथा (Polyandry): यह एक प्रकार का विवाह है जिसमें एक महिला के कई पति होते हैं। ऐसी घटनाएँ अत्यंत असामान्य हैं।
- द्विविवाह (Bigamy): जब कोई व्यक्ति पहले से ही मान्य रूप से विवाहित होते हुए भी किसी और के साथ विवाह करता है, इसे द्विविवाह के रूप में जाना जाता है और ऐसा करने वाले व्यक्ति को द्विविवाही कहा जाएगा।
  - इसे भारत सहित कई देशों में एक अपराध माना जाता है।

भारत में बहुविवाह की स्थिति:

- सरकारी आंकड़ों से पता चलता है कि देश में बहुविवाह के मामले 2019-20 में घटकर 1.4 प्रतिशत हो गए हैं, जो 2005-06 में 1.9 प्रतिशत थे।
  - पूर्वोत्तर राज्यों में यह दर अधिक रही है।

- रिपोर्ट्स के मुताबिक, मेघालय में यह 6.1 फीसदी और त्रिपुरा में 2 फीसदी है।
- असम के बराक घाटी के तीन जिलों और होजई और जमुनामुख के क्षेत्रों में बहुविवाह प्रचलित है।

- यह प्रथा बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा में भी कुछ जातियों के बीच जारी है।
- इस बीच, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ में यह प्रथा हिंदुओं की तुलना में मुसलमानों में अधिक प्रचलित है।

भारत में बहुविवाह के प्रमुख कारण:

- धर्म: कुछ धर्म अपने सिद्धांत या परंपरा के एक भाग के रूप में बहुविवाह की अनुमति देते हैं या प्रोत्साहित करते हैं।
  - उदाहरण के लिए, इस्लाम एक व्यक्ति को अधिकतम चार पत्नियाँ रखने की अनुमति देता है यदि वह उनके साथ उचित व्यवहार और पर्याप्त रूप से उनका भरण-पोषण कर सकता हो।
- संस्कृति: कुछ संस्कृतियाँ अपने सामाजिक मानदंडों या मूल्यों के एक भाग के रूप में बहुविवाह को स्वीकार करती हैं या बढ़ावा देती हैं।
  - उदाहरण के लिए, कुछ आदिवासी और ग्रामीण समुदाय अपनी आबादी बढ़ाने या अपने वंश को बनाए रखने के तरीके के रूप में बहुविवाह की प्रैक्टिस करते हैं।
- अर्थशास्त्र: कुछ लोग अपने आर्थिक हितों को सुरक्षित करने या अपनी सामाजिक स्थिति में सुधार करने के तरीके के रूप में बहुविवाह की प्रैक्टिस करते हैं।
  - उदाहरण के लिए, कुछ पुरुष बहुविवाह करते हैं क्योंकि वे अधिक बच्चे चाहते हैं जो उनके लिए काम कर सकें या कमा सकें।
  - कुछ महिलाएँ बहुविवाह करती हैं क्योंकि वे अपने पतियों से अधिक संसाधन या सुरक्षा चाहती हैं।
- राजनीति: कुछ लोग अपने राजनीतिक अधिकारों का दावा करने या राज्य प्राधिकरण को चुनौती देने के तरीके के रूप में बहुविवाह की प्रैक्टिस करते हैं।
  - उदाहरण के लिए, भारत में कुछ अलगाववादी समूह भारत सरकार के खिलाफ अपना प्रतिरोध या विद्रोह व्यक्त करने के एक तरीके के रूप में बहुविवाह की प्रैक्टिस करते हैं।
- सामाजिक दबाव: कुछ लोग बहुविवाह का कार्य करते हैं क्योंकि उन्हें अपने साथियों या बड़ों से सामाजिक दबाव या अपेक्षाओं का सामना करना पड़ता है।
- उदाहरण के लिए, कुछ पुरुष बहुविवाह का अभ्यास करते हैं क्योंकि वे अपनी मर्दानगी या पौरुष (masculinity or virility) साबित करना चाहते हैं।
- व्यक्तिगत प्राथमिकताएँ: कुछ लोग बहुविवाह का कार्य करते हैं क्योंकि वे इसे एकपत्नीत्व या ब्रह्मचर्य से अधिक पसंद करते हैं।
  - उदाहरण के लिए, कुछ पुरुष बहुविवाह का कार्य करते हैं क्योंकि वे अपने जीवन में विविधता या संतुष्टि चाहते हैं।भारत में बहुविवाह का परिणाम
- महिलाओं के लिए: बहुविवाह का मतलब अक्सर स्वायत्तता, गरिमा और सुरक्षा की कमी होती है।
  - उन्हें अपने पति का ध्यान, संसाधन और स्नेह अन्य पत्नियों के साथ साझा करना पड़ता है, जिससे ईर्ष्या, संघर्ष और हिंसा हो सकती है।
  - उन्हें घरेलू दुर्व्यवहार, यौन शोषण, प्रजनन स्वास्थ्य समस्याओं और मानसिक तनाव का भी अधिक खतरा होता है।
- बच्चों के लिए: बहुविवाह के परिणामस्वरूप उपेक्षा, अभाव और भेदभाव हो सकता है।
  - उन्हें अपने माता-पिता से पर्याप्त देखभाल, पोषण और शिक्षा नहीं मिल सकती है, खासकर यदि वे कम पसंदीदा पत्नी से संबंधित हों।
- समाज के लिए: बहुविवाह सामाजिक अस्थिरता, असमानता और असामंजस्य का कारण बन सकता है।
  - यह लैंगिक असंतुलन भी पैदा कर सकता है और एकल पुरुषों और महिलाओं के लिए विवाह योग्य भागीदारों की उपलब्धता को कम कर सकता है।
  - यह घरेलू हिंसा, बाल शोषण, तलाक, व्यभिचार और वेश्यावृत्ति जैसी सामाजिक समस्याओं को जन्म देता है।
- आर्थिक प्रभाव: बहुविवाह पति और उसके परिवार पर वित्तीय बोझ बढ़ा सकता है।
  - पति को कई घर, पत्नियों और बच्चों का भरण-पोषण करना पड़ सकता है, जिससे उसकी बचत, निवेश और जीवन स्तर प्रभावित हो सकता है।
  - पत्नियों को सीमित संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा करनी पड़ सकती है और उनके पास स्वयं की पर्याप्त आय या संपत्ति नहीं हो

सकती है।

बहुविवाह पर न्यायपालिका के विचार:

- परयांकंडियाल बनाम के. देवी और अन्य (1996): सर्वोच्च न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि एक विवाह वाले रिश्ते हिंदू समाज के मानक और विचारधारा थे, जो दूसरे विवाह की निंदा और उसका तिरस्कार करते थे।
    - धर्म के प्रभाव के कारण बहुविवाह को हिंदू संस्कृति का अंग नहीं बनने दिया गया।
- जावेद और अन्य बनाम हरियाणा राज्य एवं अन्य (2003): सर्वोच्च न्यायालय ने यह फैसला सुनाया कि स्वतंत्रता, सामाजिक सद्भाव, गरिमा और कल्याण अनुच्छेद 25 के अंतर्गत आते हैं।
    - मुस्लिम कानून चार महिलाओं से विवाह की अनुमति प्रदान करता है, लेकिन यह अनिवार्य नहीं है।
    - यह चार महिलाओं से शादी नहीं करने के लिये धार्मिक प्रथा का उल्लंघन नहीं होगा।

इन देशों में बहुविवाह वैध है:

- भारत, सिंगापुर, मलेशिया जैसे देशों में बहुविवाह विशेष रूप से केवल मुसलमानों के लिये अनुमत तथा वैध है।
- वर्तमान में अल्जीरिया, मिस्र तथा कैमरून जैसे देशों में बहुविवाह मान्यता प्राप्त और प्रचलित है। केवल ये ही विश्व के ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ बहुविवाह वैध है।

आगे की राह :

संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार समिति के अनुसार, बहुविवाह उन क्षेत्रों में समाप्त किया जाना चाहिए जहां यह मौजूद है क्योंकि यह महिलाओं की गरिमा का उल्लंघन करता है और उनकी स्वतंत्र इच्छा को प्रतिबंधित करता है। बहुविवाह, तीन तलाक और निकाह हलाला जैसे कानून न केवल पुराने हैं, बल्कि मुस्लिम महिलाओं के लिए दुर्बल करने वाले भी हैं। ऐसे कानूनों की वैधता को चुनौती दी जानी चाहिए और बाद में उन्हें खारिज कर दिया जाना चाहिए।

Source: The Hindu

Paper II

महिला आरक्षण विधेयक 2023

Syllabus

- **Mains – GS 2 (Governance)**

संदर्भ: हाल ही में महिला आरक्षण विधेयक को एक सौ अट्ठाईसवें संशोधन विधेयक 2023 के रूप में लोकसभा में पेश किया गया।

महिला आरक्षण विधेयक की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि:

- देवेगौड़ा सरकार द्वारा 81वां संवैधानिक संशोधन विधेयक: महिला आरक्षण विधेयक पहली बार 1996 में 81वें संवैधानिक संशोधन विधेयक के रूप में पेश किया गया था।
    - विधेयक को गीता मुखर्जी की अध्यक्षता वाली संसद की चयन समिति को भेजा गया था।
    - हालाँकि लोकसभा भंग होने के साथ ही विधेयक समाप्त हो गया क्योंकि ओबीसी महिलाओं के लिए आरक्षण पर कोई आम सहमति नहीं बन सकी।
- इस विधेयक को एनडीए सरकार द्वारा 1999 में 13वीं लोकसभा में फिर से पेश किया गया था और बाद में इसे वर्ष 2003 में दो बार पेश किया गया था।
    - हालाँकि बिल पारित नहीं हो सके और इसलिए वे व्यपगत हो गए।
- यूपीए सरकार ने वर्ष 2004 में आरक्षण विधेयक को अपने न्यूनतम साझा कार्यक्रम में शामिल किया और इसे फिर से समाप्त होने से बचाने के लिए इसे राज्यसभा में पेश किया।
- 108वें संवैधानिक संशोधन विधेयक 2008 के रूप में पेश किया गया महिला आरक्षण विधेयक 2010 में राज्यसभा में पारित हो गया और लोकसभा में निरस्त हो गया।
    - राजद, जद(यू) और सपा इसके सबसे मुखर विरोधी थे।
    - उन्होंने महिलाओं के लिए 33% कोटा के भीतर पिछड़े समूहों के लिए 33% आरक्षण की मांग की।

विधेयक 2023 की मुख्य विशेषताएं:

- महिलाओं के लिए आरक्षण: यह बिल लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा में महिलाओं के लिए यथासंभव एक-तिहाई सीटें आरक्षित करता है।
    - यह लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में SC और ST के लिए आरक्षित सीटों पर भी लागू होगा।

- आरक्षण की शुरूआत: इस विधेयक के प्रकाशित होने के बाद होने वाली जनगणना के बाद आरक्षण प्रभावी होगा।
    - जनगणना के आधार पर महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित करने के लिए परिसीमन किया जाएगा।
    - आरक्षण 15 वर्ष की अवधि के लिए प्रदान किया जाएगा।
    - हालाँकि, यह संसद द्वारा बनाए गए कानून द्वारा निर्धारित तिथि तक जारी रहेगा।
- **सीटों का रोटेशन:** महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों को प्रत्येक परिसीमन के बाद रोटेशन किया जाएगा, जैसा कि संसद द्वारा बनाए गए कानून द्वारा निर्धारित किया गया है।

विधेयक के पक्ष में तर्क:

- महिलाओं के राजनीतिक प्रतिनिधित्व में वृद्धि- अंतर-संसदीय संघ की संसद में महिलाओं की रिपोर्ट (2021) के अनुसार, राष्ट्रीय विधायिकाओं में सेवारत महिलाओं की संख्या के मामले में भारत 140 अन्य देशों से नीचे है।
    - इस मामले में रवांडा (61 प्रतिशत), दक्षिण अफ्रीका (43 प्रतिशत) और बांग्लादेश (21 प्रतिशत) भी भारत से आगे हैं।
- परिवर्तन लाने में महिला नेतृत्व की क्षमता: पंचायतों पर किए गए अध्ययनों से पता चला है कि महिलाओं के सशक्तिकरण और संसाधनों के आवंटन पर महिला आरक्षण का सकारात्मक प्रभाव पड़ा है।
    - हरियाणा में ढाणी मयान खान जीपी की पूर्व महिला सरपंच ने महिलाओं के लिए एक प्रशिक्षण केंद्र बनाया और यह सुनिश्चित किया कि गांव का हर बच्चा स्कूल जाए।
- राजनीति को अपराधमुक्त करने की दिशा में कदम- महिलाओं के लिए आरक्षित सीटें भारतीय राजनीति को अपराधमुक्त करने में मदद करेंगी।
    - वर्तमान लोकसभा में 159 सांसदों ने अपने खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले घोषित किए हैं जिनमें बलात्कार, हत्या, हत्या का प्रयास, अपहरण, महिलाओं के खिलाफ अपराध शामिल हैं।
    - इससे समाज में महिलाओं के खिलाफ अपराध को संबोधित करने में मदद मिलेगी।
- आर्थिक प्रदर्शन और बुनियादी ढांचे में सुधार: संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय के अनुसार, महिला विधायकों ने अपने निर्वाचन क्षेत्रों के आर्थिक प्रदर्शन में पुरुष विधायकों की तुलना में 1.8 प्रतिशत अधिक सुधार किया है।
    - प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के मूल्यांकन से पता चलता है कि महिला नेतृत्व वाले निर्वाचन क्षेत्रों में अधूरी सड़क परियोजनाओं की हिस्सेदारी 22 प्रतिशत अंक कम है।
- वोट शेयर का बढ़ना लेकिन प्रतिनिधित्व कम होना: हालांकि महिलाओं का वोट शेयर बढ़ा है, लेकिन राजनीति के पदों पर महिलाओं की संख्या उस अनुपात में नहीं बढ़ी है।
    - भारत में महिलाएं पुरुषों के बराबर मतदान करती हैं लेकिन पुरुषों की तुलना में उनका प्रतिनिधित्व बहुत कम है।
    - इस बिल से राजनीति में भी प्रतिनिधित्व बढ़ेगा।
- भारतीय राजनीति के पितृसत्तात्मक संरचना को तोड़ना- भारतीय राजनीति पितृसत्तात्मक रही है और पार्टी के शीर्ष पदों पर पुरुषों का ही स्वामित्व रहा है।
    - यह भारतीय राजनीति की इस पितृसत्तात्मक प्रकृति को नष्ट कर देगा।
- रूढ़िवादिता में बदलाव: महिला राजनेताओं में वृद्धि से महिलाओं की केवल 'गृहिणी' के रूप में बनी छवि को बदलने में मदद मिलेगी और कानून निर्माता के रूप में महिलाओं की धीरे-धीरे स्वीकार्यता बढ़ेगी।

चुनौतियाँ जो विधेयक के पारित होने में बाधा बनी हुई हैं:

- **कोई अलग ओबीसी आरक्षण न होना:** विधेयक सीटों के एक तिहाई आरक्षण के मौजूदा कोटे के भीतर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं को अलग आरक्षण प्रदान करता है।
    - हालाँकि ओबीसी महिलाएँ, जो महिला आबादी का 60% हिस्सा हैं, को कोटा के भीतर अलग से आरक्षण प्रदान नहीं किया गया है।
- **राज्यसभा और विधान परिषदों में कोई आरक्षण न होना:** विधेयक राज्यसभा और विधान परिषदों में महिलाओं को आरक्षण प्रदान नहीं करता है।
- **हितों का टकराव:** कुछ राजनीतिक नेताओं को चिंता है कि बिल में महिलाओं के लिए आरक्षण कोटा लागू करने से महिला उम्मीदवारों और हाशिए पर रहने वाले समुदायों से संबंधित सीटों के लिए प्रतिस्पर्धा हो सकती है।
- **पितृसत्तात्मक मानदंड:** भारतीय समाज में गहरी जड़ें जमा चुके पितृसत्तात्मक मानदंड और लैंगिक पूर्वाग्रह राजनीति में महिलाओं की

भागीदारी में महत्वपूर्ण बाधा बने हुए हैं।

- ये मानदंड विभिन्न तरीकों से प्रकट हो सकते हैं, जिसमें यह विश्वास भी शामिल है कि महिलाएं नेतृत्व करने में कम सक्षम हैं या राजनीति एक पुरुष-प्रधान क्षेत्र है।

- **पारिवारिक और सामाजिक दबाव:** महिलाओं को अक्सर पारिवारिक और सामाजिक दबाव का सामना करना पड़ता है जो उन्हें राजनीति में करियर बनाने से हतोत्साहित करता है।
  - सुरक्षा, पारंपरिक लैंगिक भूमिकाओं और सामाजिक अपेक्षाओं के बारे में चिंताएँ महिलाओं को राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाने से हतोत्साहित कर सकती हैं।
- **हिंसा और उत्पीड़न:** भारत में राजनीतिक क्षेत्र लिंग आधारित हिंसा और उत्पीड़न से अछूता नहीं है।
  - महिला राजनेताओं और उम्मीदवारों ने धमकियों, उत्पीड़न और हिंसा की घटनाओं की जानकारी दी है, जो उनकी भागीदारी में बाधा बन सकती हैं।

आगे की राह :

इसलिए महिला आरक्षण विधेयक 2023 केवल एक विधायी प्रस्ताव नहीं है बल्कि यह भारत के राजनीतिक परिदृश्य में लैंगिक समानता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह गहराई से स्थापित संरचनात्मक मानदंडों और पूर्वाग्रहों को संबोधित करता है जो पीढ़ियों से राजनीति में महिलाओं की भागीदारी में बाधा बने हुए हैं। यह विधेयक राजनीतिक क्षेत्र में समावेशी और लिंग-संवेदनशील दृष्टिकोण को बढ़ावा देकर परिवर्तन के लिए उत्प्रेरक के रूप में काम कर सकता है।

Source: The Hindu

एक राष्ट्र एक चुनाव' प्रणाली (ONOE)

Syllabus

- **Mains – GS 2 (Governance)**

संदर्भ: सरकार द्वारा एक बार फिर 'एक राष्ट्र एक चुनाव' प्रस्ताव पर विचार किया गया।

'एक राष्ट्र एक चुनाव' प्रणाली के बारे में:

- वर्तमान प्रणाली: देश में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए पांच साल के अंतराल में अलग-अलग चुनाव होते हैं।
  o जब निचले सदन या राज्य सरकार का कार्यकाल समाप्त हो जाता है, या उनमें से कोई समय से पहले भंग हो जाता है।
- जरूरी नहीं कि राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल एक-दूसरे या लोकसभा के साथ मेल खाता हो।
  o इसके परिणामस्वरूप, चुनाव कराने का यह कार्य पूरे वर्ष चलता रहता है।
- वन नेशन वन इलेक्शन का प्रस्ताव है कि पांच साल के अंतराल में सभी राज्यों और लोकसभा में एक साथ चुनाव कराए जाएं।
- इसका मतलब यह होगा कि मतदाता लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के सदस्यों को चुनने के लिए एक ही दिन, एक ही समय पर (या चरणबद्ध तरीके से, जैसा भी मामला हो) अपना वोट डालेंगे।

ONOE की पृष्ठभूमि:

- भारत में इससे पहले 1952, 1957, 1962 और 1967 में एक साथ चुनाव कराए जा चुके हैं।
- इसके तुरंत बाद, 1968 -69 के बीच कुछ विधान सभाओं के विघटन के बाद इस मानदंड को बंद कर दिया गया।
- तब से, भारतीय चुनाव प्रणाली केंद्र और राज्यों के लिए अलग-अलग चुनाव कराती है।

ONOE संचालित करने के लिए संशोधित किए जाने वाले महत्वपूर्ण लेख:

- अनुच्छेद 172 और अनुच्छेद 83 संसद के सदनों की अवधि से संबंधित हैं, और निर्वाचित लोकसभा और राज्य विधानसभाओं दोनों के लिए पांच साल के कार्यकाल की गारंटी देते हैं, जब तक कि वे जल्दी भंग नहीं हो जाती।
- भारतीय संविधान का अनुच्छेद 85 छह महीने से अधिक के अंतराल पर संसदीय सत्र बुलाने की राष्ट्रपति की शक्तियों से संबंधित है।
  o राष्ट्रपति के पास संसद के किसी भी सदन को स्थगित करने और लोकसभा को भंग करने की शक्ति भी है।
- भारतीय संविधान का अनुच्छेद 356, किसी राज्य में शासन और संवैधानिक विफलता की स्थिति में लागू होता है और राष्ट्रपति शासन से संबंधित है।
- लोकसभा और राज्य विधानसभाओं दोनों में संगठित आचरण और स्थिरता के लिए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (आरपीए अधिनियम 1951) और दलबदल विरोधी कानून में संशोधन किया जाना चाहिए।

ONOE के पक्ष में तर्क:

- राज्य के राजकोष पर वित्तीय बोझ में कमी: लगातार चुनाव चक्र राज्य के खजाने पर वित्तीय बोझ होता हैं।
  o यह ईसीआई द्वारा राजनीतिक प्रक्रिया पर होने वाले समग्र व्यय को कम करता है।
- 'चुनाव मोड' में रहने के बजाय शासन पर ध्यान देना: एक राष्ट्र एक चुनाव" केंद्र और राज्य सरकारों की नीतियों और कार्यक्रमों की निरंतरता सुनिश्चित करेगा।
  o इससे सामान्य सार्वजनिक जीवन में व्यवधान कम होगा क्योंकि राजनीतिक रैलियां न्यूनतम रखी जाएंगी।
  o इससे जनता तक आवश्यक सेवाओं की डिलीवरी में सुधार होगा।
- राजनीतिक दलों द्वारा वित्तीय संसाधनों का बेहतर उपयोग: एक साथ चुनाव कराने से राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के प्रचार खर्च में कमी आएगी।
  o इससे छोटे क्षेत्रीय दलों को वित्तीय संसाधनों के बेहतर प्रबंधन में मदद मिलेगी।
- आदर्श आचार संहिता की अवधि में कमी: चुनाव के दौरान बार-बार आदर्श आचार संहिता (एमसीसी) लगाए जाने से कई महीनों तक सभी विकास कार्य रुक जाते हैं।
  o यह चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता लागू होने के परिणामस्वरूप होने वाली 'नीतिगत पंगुता (policy paralysis)' को कम करेगा।
- प्रशासनिक दक्षता में वृद्धि: चुनावों के दौरान राज्य स्वतंत्र मशीनरी और निष्पक्ष चुनावी प्रक्रिया आयोजित करने पर ध्यान केंद्रित करता है जिसका प्रभाव रोजमर्रा के प्रशासन पर पड़ता है क्योंकि अधिकारी मतदान कार्यों में लगे होते हैं।
  o ONOE से प्रशासनिक व्यवस्था की दक्षता बढ़ती है।
- मतदाता मतदान में वृद्धि-: विधि आयोग के अनुसार, ONOE से मतदान प्रतिशत में वृद्धि होगी क्योंकि लोगों के लिए एक साथ कई वोट डालना आसान हो जाएगा।
- काले धन का कम उपयोग: चुनावों में संभावित उम्मीदवारों द्वारा काफी खर्च किया जाता है जिसमें से अधिकांश काला धन होता है।
  o ONOE से अर्थव्यवस्था में काले धन का प्रचलन कम हो जाएगा।
- सामाजिक सद्भाव में सुधार: बार-बार होने वाले चुनावों से देश भर में जाति, धर्म और सांप्रदायिक मुद्दे कायम रहते हैं क्योंकि ये चुनाव ध्रुवीकरण की घटनाएं हैं जिन्होंने जातिवाद, सांप्रदायिकता और भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया है।
  o ONOE कई चुनावों के कारण समुदायों के बीच बनी दरार को कम करेगा।

ONOE के विरुद्ध तर्क:

- केवल राज्य ही लड़ रहे हैं चुनाव: 'भारत' में हर साल चुनाव नहीं होता है, भारत के किसी एक राज्य में चुनाव होता है।
  o इसलिए, जब कुछ राज्यों में चुनाव होते हैं, तो 'भारत' चुनावी मोड में नहीं होता है; भारत के कुछ राज्य हैं।
  o भारत के सभी प्रमुख राजनीतिक दल चुनावी मोड में नहीं हैं, केवल कुछ ही हैं।
- भारत के संघवाद के ख़िलाफ़: भारत के प्रत्येक राज्य में अलग-अलग राजनीतिक संस्कृतियाँ और पार्टियाँ हैं।
  o किसी राज्य के निर्वाचित मुख्यमंत्री के पास अपने राज्य विधानसभाओं को भंग करने और शीघ्र चुनाव कराने की सिफारिश करने की शक्तियां होती हैं।
  o 'एक चुनाव' ढांचे के तहत, राज्य पार्टियों को ऐसा करने का अधिकार नहीं होगा।
  o ये शक्तियां राज्यों से छीन ली जाएंगी और केवल केंद्र सरकार के पास प्रत्येक राज्य के लिए चुनाव कार्यक्रम तय करने की शक्तियां होंगी।
- लागत में वृद्धि: अल्पावधि में, एक साथ चुनाव से कहीं अधिक संख्या में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों और नियंत्रण इकाइयों को तैनात करने की लागत में वृद्धि होगी।
  o राजनीतिक दल और उम्मीदवार चुनावों पर सरकार की तुलना में बहुत अधिक पैसा खर्च कर सकते हैं लेकिन यह करदाताओं का पैसा नहीं है।
  o इसके विपरीत, ऐसे आर्थिक शोध हैं जो सुझाव देते हैं कि पार्टियों और उम्मीदवारों द्वारा इस तरह का चुनावी खर्च वास्तव में निजी खपत को बढ़ावा देने और प्रोत्साहन के रूप में कार्य करके अर्थव्यवस्था और सरकार के कर राजस्व को लाभ पहुंचाता है।
- राष्ट्रपति प्रणाली के लिए कार्य करना: राष्ट्रपति प्रणाली में एक एकल चुनाव कैलेंडर काम कर सकता है जहां कार्यपालिका का अस्तित्व विधायी बहुमत पर निर्भर नहीं होता है।
- अव्यवहारिक और अव्यवहार्य: 'एक राष्ट्र एक चुनाव' राजनीतिक रूप से अव्यवहार्य, प्रशासनिक रूप से अव्यवहारिक और संवैधानिक रूप से अव्यवहार्य प्रस्ताव है।

आगे की राह:

'एक भारत, एक चुनाव' की अवधारणा एक सकारात्मक बदलाव का वादा करती है, बशर्ते इसे नीतियों और विनियमों पर सावधानीपूर्वक ध्यान देकर क्रियान्वित किया जाए। कुशल प्रशासनिक कर्मचारियों की बढ़ती मांग और कड़ी सुरक्षा को संबोधित करना महत्वपूर्ण है। कार्यान्वयन के जटिल विवरणों पर काम करने के लिए संवैधानिक विशेषज्ञों, थिंक टैंक, सरकारी अधिकारियों और राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों का एक समर्पित समूह बनाना आवश्यक है।

Source: Indian Express

बिहार सरकार का जाति आधारित सर्वे

Syllabus

- **Mains – GS 2 (Governance)**

संदर्भ: हाल ही में बिहार सरकार के जाति-आधारित सर्वेक्षण पर सुप्रीम कोर्ट को अपने जवाब में केंद्र सरकार ने कहा कि केवल केंद्र ही जनगणना कराने का हकदार है।

जाति जनगणना के बारे में:

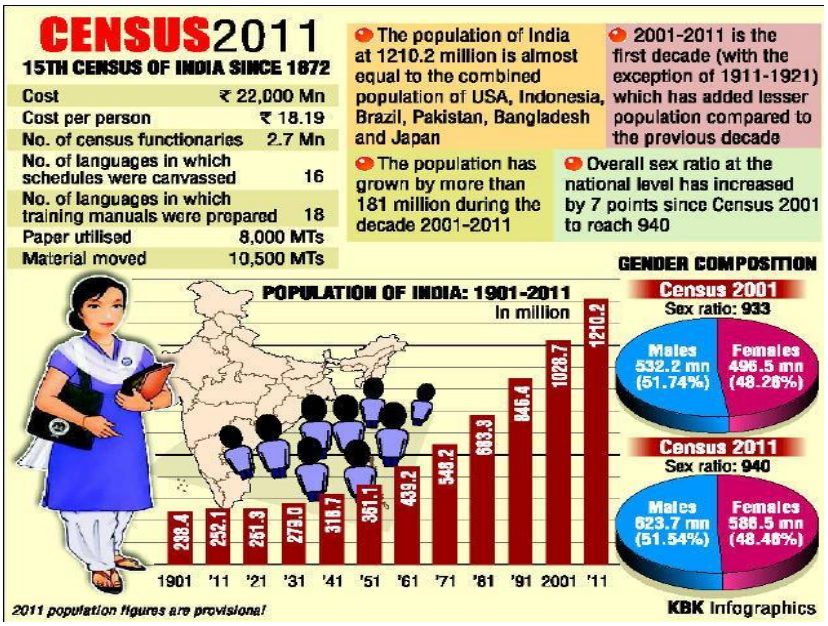

- भारत की 2011 की जनगणना के लिए सामाजिक-आर्थिक और जाति जनगणना 2011 (SECC) आयोजित की गई थी।
- SECC 2011 भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आयोजित किया गया था।
- SECC 2011 भारत की पहली कागज रहित जनगणना थी जो सरकार द्वारा 640 जिलों में हैंड-हेल्ड इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर आयोजित की गई थी।
- SECC 2011 भारत की 1931 की जनगणना के बाद पहली जाति-आधारित जनगणना थी।
- SECC 2011 को भारत की जनगणना अधिनियम 1948 के तहत आयोजित नहीं किया गया था, जिसने नागरिकों के लिए सूचना प्रकटीकरण को स्वैच्छिक बना दिया था, यह अनिवार्य प्रकटीकरण नहीं बनाया था।
- जाति जनगणना गृह मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में है: जिसमें भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त शामिल है।

भारत में जनगणना के बारे में:

- भारत में जनगणना 1872 में ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड मेयो के अधीन शुरू की गई थी।
  o हालाँकि, पहली पूर्ण जनगणना 1881 में लॉर्ड रिपन के तहत की गई थी।
- 1881 से हर 10 साल में जनगणना की जाती रही है।
- इसका संचालन गृह मंत्रालय के तहत भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त द्वारा किया जाता है।
- 1951 के बाद से सभी जनगणनाएँ 1948 के भारतीय जनगणना अधिनियम के तहत आयोजित की गईं।

जाति जनगणना का महत्व:

- समानता की ओर कदम: इससे उन जातियों को इंगित करने में मदद मिलेगी जिनका इस देश के संस्थानों में प्रतिनिधित्व नहीं है ताकि समानता की ओर कदम स्थापित किए जा सकें।

o यह विभिन्न समुदायों के लिए आरक्षण के विस्तार को उचित ठहराएगा।

- पिछली जनगणना के आंकड़ों का उपयोग: आखिरी जाति जनगणना 1931 में हुई थी और सरकार अभी भी जनसांख्यिकी और विभिन्न जाति समूहों का अनुमान लगाने के लिए इसे आधार के रूप में उपयोग करती है।
  o इस देश की जनसांख्यिकी में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं।
- डेटा अनुपलब्धता: रोहिणी आयोग को भी ओबीसी के तहत वर्गीकृत विभिन्न समुदायों पर डेटा की अनुपलब्धता के कारण कठिनाइयों का सामना करना पड़ा।
  o आयोग की स्थापना ओबीसी के उप-वर्गीकरण के मुद्दे की जांच के लिए की गई थी।
- प्रभावी सेवा वितरण: लक्षित कल्याण की अधिक प्रभावी वितरण सुनिश्चित करने के लिए जनसंख्या का एक नया अनुमान आवश्यक है।
- जाति डेटा संग्रह पर राज्य की कार्रवाई: कर्नाटक, ओडिशा और तेलंगाना ने "सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण" के नाम पर इसी तरह की गणना की थी।
- लोकप्रिय मांग: बिहार के साथ-साथ झारखंड और ओडिशा जैसे अन्य राज्य भी जाति जनगणना के लिए अपना समर्थन दोहरा रहे हैं।

इससे जुड़ी आलोचनाएँ:

- जाति विभाजन का मार्ग : 21वीं सदी के भारत को उन आधारों पर भारत को और अधिक विभाजित करने के बजाय 'आओ जाति को खत्म करें' पर चर्चा करनी चाहिए।
  o यह "लोगों के बीच विभाजनकारी भावनाओं को फिर से भड़का सकता है।"
- औपनिवेशिक प्रथा: 1931 तक प्रत्येक जनगणना में जाति पर डेटा होता था। तो यह फूट डालो और राज करो की औपनिवेशिक प्रथा थी जिसने उन्हें इस तरह के डेटा एकत्र करने के लिए प्रेरित किया।
  o 1951 से 2011 तक स्वतंत्र भारत में प्रत्येक जनगणना में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति पर डेटा प्रकाशित किया गया है, लेकिन अन्य जातियों पर नहीं।
- आरक्षण की मांग: 10 वर्षों के लिए लागू किया गया आरक्षण 75 वर्षों तक जारी है और जाति-आधारित जनगणना से और अधिक की मांग हुई।
- संवैधानिक अधिदेश: एससी और एसटी के मामले के विपरीत, ओबीसी और बीसीसी की जनगणना के आंकड़े प्रदान करने के लिए भारत के रजिस्ट्रार-जनरल और जनगणना आयुक्त के लिए कोई संवैधानिक अधिदेश नहीं है।
- गिनती की व्यवहार्यता (Feasibility of the count):केंद्र सरकार ने तर्क दिया कि ऐसी कवायद संभव नहीं है, क्योंकि प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में बहुत सारी जातियां और उपजातियां हैं, जिससे उन्हें वर्गीकृत करना मुश्किल हो जाता है।
  o लोग अपने कुल/गोत्र, उपजाति और जाति के नामों का परस्पर इस्तेमाल करते हैं।
  o सरकार ने कई प्रशासनिक, परिचालन और तार्किक कारणों का विवरण दिया है।
  o जनगणना डेटा गणनाकार 6-7 दिनों के प्रशिक्षण के साथ अंशकालिक हैं और "अन्वेषक या सत्यापनकर्ता नहीं हैं"।
  o ऐसी आशंका है कि इस तरह की गिनती से जनगणना प्रक्रिया ही खतरे में पड़ सकती है।
- राजनीतिक एजेंडा: गहरे स्तर पर इस मामले में राजनीति शामिल है।
  o बिहार की राजनीति में संख्यात्मक रूप से शक्तिशाली सामाजिक समूह अन्य पिछड़ी जातियों (ओबीसी) का वर्चस्व रहा है।

आगे की राह :

जाति जनगणना की आवश्यकता को देश में व्यापक आय असमानता में देखा जा सकता है। उदाहरण के लिए 2020 ऑक्सफैम रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत की शीर्ष 10% आबादी के पास कुल संपत्ति का 74.3% हिस्सा है; साथ ही मध्य 40% के पास 22.9% है; और निचले 50% के पास चौंकाने वाली 2.8% हिस्सेदारी है। यह इंगित करता है कि धन का असमान वितरण भारतीय समाज की बेहतर समझ की मांग करता है।
एसईसीसी 'कार्यक्रम-विशिष्ट हकदारियों के लिए कार्यक्रम-विशिष्ट संकेतक (program-specific indicators)' के सिद्धांत की ओर बढ़ने में मदद करेगा। गरीबी के कई आयामों को पहचानना और स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वच्छता और मध्याह्न भोजन जैसे कई क्षेत्रों में विभिन्न कार्यक्रमों के साथ उनसे निपटना सार्वभौमिक हो सकता है; इसमें किफायती आवास और विकलांगता जैसे अन्य लोगों को लक्षित किया जा सकता है।

Source: Indian Express

पुराने बहुपक्षवाद का अंत - और एक नई व्यवस्था की शुरुआत

Syllabus

Mains – GS 2 (International Relations)

संदर्भ: शीत युद्ध के बाद, वैश्विक और क्षेत्रीय दोनों स्तरों पर बहुपक्षवाद अपने चरम पर है।

- हाल ही में जकार्ता में पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन और दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन पुरानी बहुपक्षीय व्यवस्था में गहरे और यकीनन अपरिवर्तनीय संकटों को प्रकाश डालता है।

बहुपक्षवाद के बारे में:

- राज्यों के तीन या अधिक समूहों के बीच संबंध को बहुपक्षवाद के रूप में जाना जाता है।
  o इसमें कुछ गुणात्मक सिद्धांत शामिल होते हैं जो किसी संस्था या व्यवस्था के चरित्र का निर्माण करते हैं।
- सिद्धांत पारस्परिकता के प्रसार, हित पर प्रतिभागियों के बीच अविभाज्यता और विवादों को निपटाने की एक प्रणाली के प्रति प्रतिबद्धता हैं।
- नई बहुपक्षीय विश्व व्यवस्था एक वाक्य है जो 21वीं सदी में विभिन्न देशों और क्षेत्रों के बीच सहयोग और संवाद के नए रूपों के उद्भव को संदर्भित करता है।
  o यह वैश्वीकरण, जलवायु परिवर्तन, महामारी, आतंकवाद और अन्य मुद्दों से उत्पन्न चुनौतियों और अवसरों की प्रतिक्रिया है जिनके लिए सामूहिक कार्रवाई और साझा समाधान की आवश्यकता होती है।

शीत युद्ध के बाद बहुपक्षवाद:

- 1990 के दशक के अंत में शीत युद्ध की समाप्ति ने बहुपक्षवाद के गहन चरण के लिए अनुकूल परिस्थितियों का निर्माण किया।
- यूरोपीय संघ के बैनर तले यूरोप तेजी से क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण और विस्तार की ओर बढ़ा है।
- एशिया में, दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संगठन (आसियान) ने क्षेत्रीय आर्थिक और राजनीतिक सहयोग को तीव्र करने के लिए रूपरेखा प्रदान की।
- दोनों महाद्वीपों में महान शक्ति प्रतिद्वंद्विता के अंत से यूरोप और एशिया में क्षेत्रवाद को बढ़ावा मिला।
- रूस को पश्चिमी देशों के नेतृत्व वाले समूह सात (जी7) में शामिल कर लिया गया, जिससे यह G8 बन गया।
  o मास्को नाटो के साथ परामर्श में भी लगा हुआ था।
- एशिया में, चीन आर्थिक और राजनीतिक मोर्चों पर अमेरिका का करीबी भागीदार बन गया।
- बदले में, इसने सामूहिक विनाश के हथियारों के प्रसार, जलवायु परिवर्तन और महामारी जैसे वैश्विक मुद्दों पर प्रमुख शक्तियों के बीच सहयोग की नई संभावनाओं में दोहराया।

मौजूदा बहुपक्षवाद के पतन के पीछे कारण:

- बहुपक्षीय प्रणाली के भीतर विरोधाभास: बहुपक्षीय प्रणाली को स्वयं आंतरिक विरोधाभासों और चुनौतियों का सामना करना पड़ा है।
  o सदस्य देशों के बीच इन आंतरिक असहमतियों और परस्पर विरोधी हितों ने बहुपक्षीय संगठनों की प्रभावशीलता को कमजोर कर दिया है और सर्वसम्मति निर्माण में बाधा उत्पन्न की है।
- वैकल्पिक सुरक्षा मंचों का उदय: चीन के विस्तारवाद के जवाब में, क्वाड, AUKUS और त्रिपक्षीय कॉम्पैक्ट जैसे वैकल्पिक सुरक्षा मंच उभरे हैं।
  o ये मंच पारंपरिक बहुपक्षीय संस्थानों से हटकर बदलाव को दर्शाते हैं, जिससे आसियान जैसे मौजूदा क्षेत्रीय संगठनों की निरंतर प्रासंगिकता और केंद्रीयता पर सवाल उठते हैं।
- प्रमुख खिलाड़ियों के बदलते दृष्टिकोण: भारत जैसे प्रमुख खिलाड़ियों के बदलते दृष्टिकोण ने भी मौजूदा बहुपक्षवाद के पतन में योगदान दिया है।
  o अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के बारे में भारत के विकसित होते दृष्टिकोण, चीन के प्रभुत्व वाले "एकध्रुवीय एशिया" के बारे में चिंताओं से हटकर संयुक्त राज्य अमेरिका और उसके सहयोगियों के साथ अधिक सक्रिय जुड़ाव ने, भारत-प्रशांत क्षेत्र में बहुपक्षवाद की गतिशीलता को बदल दिया है।
- चीन का उदय और उसका विस्तारवाद: मौजूदा बहुपक्षवाद के पतन के पीछे प्राथमिक कारणों में से एक वैश्विक आर्थिक और सैन्य शक्ति के रूप में चीन का उदय है।
  o एशिया और विश्व स्तर पर चीन की विस्तारवादी नीतियां मौजूदा बहुपक्षीय व्यवस्था को चुनौती दे रही हैं।
  o पड़ोसियों के साथ सीमाओं को बदलने के इसके एकतरफा प्रयासों और इसके मुखर क्षेत्रीय विस्तारवाद ने तनाव पैदा किया है और क्षेत्रीय एवं वैश्विक संस्थानों को अस्थिर कर दिया है।
- रूसी कार्रवाइयों के प्रभाव: वर्ष 2014 में यूक्रेन के क्रीमिया पर रूसी कब्ज़ा और कब्ज़ा (और चल रहा युद्ध) शीत युद्ध के बाद की सुरक्षा व्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती है, यह खासकर यूरोप में हुआ।

o इस घटना ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में दरार और संघर्ष पैदा करके बहुपक्षवाद को बाधित कर दिया।

भारत के नए बहुपक्षीय दृष्टिकोण की मुख्य विशेषताएं?

- क्वाड सहयोग: जकार्ता शिखर सम्मेलन में, भारत के प्रधान मंत्री ने इस बात पर बल दिया कि क्वाड आसियान के प्रयासों का पूरक है और क्षेत्रीय स्थिरता को बढ़ावा देता है।
- विकासशील दुनिया और ग्लोबल साउथ से अधिक आवाजों और दृष्टिकोणों को शामिल करने के लिए संयुक्त राष्ट्र, आईएमएफ और विश्व बैंक जैसे मौजूदा बहुपक्षीय संस्थानों का विस्तार और विविधीकरण हुआ।
- पुनः वैश्वीकरण पर ध्यान: विदेश मंत्री एस जयशंकर चीन-केंद्रित उत्पादन मॉडल से हटकर एक विविध, लोकतांत्रिक वैश्वीकरण की वकालत करते हैं।
- सामूहिक जिम्मेदारी: बहुपक्षवाद में चुनौतियों के बावजूद, भारत वैश्विक कर व्यवस्था के आधुनिकीकरण जैसे विविध मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करते हुए सामूहिक समाधान तलाश जारी रखा हुआ है।
- ग्लोबल साउथ की चिंताएँ: भारत जी-20 एजेंडे में ग्लोबल साउथ की चिंताओं को प्राथमिकता देता है, जिसका लक्ष्य पुराने टकराव की राजनीति को पुनर्जीवित करने के बजाय विकसित और विकासशील देशों के बीच सहयोग बढ़ाना है।

भारत की भूमिका:

- केंद्रीय खिलाड़ी के रूप में कार्य करना: भारत क्षेत्रीय और वैश्विक गतिशीलता दोनों को आकार देने में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति के रूप में उभर रहा है, जो इंडो-पैसिफिक क्वाड्रिलैटरल फोरम जैसे मंचों में इसकी सक्रिय भागीदारी से उजागर होता है।
- G20 समूह का विकास: भारत वैश्विक दक्षिण की चिंताओं को दूर करने के लिए G20 पर बल दे रहा है, जो वैश्विक आर्थिक चर्चाओं में अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की अपनी इच्छा का संकेत देता है।
- बदलता गठबंधन: बहुध्रुवीय दुनिया के लिए ऐतिहासिक रूप से मास्को और बीजिंग के साथ गठबंधन, भारत का ध्यान चीन की बढ़ती मुखरता के कारण स्थानांतरित हो गया है, जिससे यह ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका जैसे देशों के करीब आ गया है।
- इंडो-पैसिफिक को अपनाना: भारत ने इंडो-पैसिफिक अवधारणा को अपनाया है और क्षेत्र में चीन के प्रभाव को संतुलित करने के लिए क्वाड गठबंधन को फिर से जीवंत किया है।

आगे की राह :

- G20 की अध्यक्षता के लिए एक मेजबान देश के रूप में, भारत G20 शिखर सम्मेलन का उपयोग एक वैश्विक नेता के रूप में अपनी दृष्टि और उपलब्धियों को प्रदर्शित करने के साथ-साथ जलवायु परिवर्तन, सतत विकास, स्वास्थ्य सुरक्षा और डिजिटल परिवर्तन जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर आम सहमति बनाने के अवसर के रूप में कर सकता है।
- यह भारत के लिए भागीदार देशों को मूलभूत विचारों से प्रेरित करने और एक नई विश्व व्यवस्था की शुरुआत का मार्ग प्रशस्त करने के लिए एक आदर्श मंच प्रदान करता है।

Source: Indian Express

भारत-अमेरिका संबंध

संदर्भ: हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति जी-20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए नई दिल्ली पहुंचे और द्विपक्षीय बैठक के लिए प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की।

द्विपक्षीय बैठक की मुख्य बातें:

- **INDUS -X:** दोनों नेताओं ने साझा सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए अमेरिकी और भारतीय रक्षा क्षेत्रों के नवोन्वेषी कार्यों का उपयोग करने के लिए एक मजबूत सहयोग एजेंडा स्थापित करने के लिए भारत-अमेरिका रक्षा त्वरण पारिस्थितिकी तंत्र (इंडस-एक्स) टीम की सराहना की।
- **संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद सीट:** अमेरिका ने भारत के स्थायी सदस्य के रूप में संशोधित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के लिए समर्थन की पुष्टि की।
- **महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकी (iCET) पर पहल:** संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत, सितंबर 2023 में आईसीईटी की मध्यावधि समीक्षा करने के इच्छुक हैं। ताकि 2024 की शुरुआत में दोनों देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों के सह-नेतृत्व में अगली वार्षिक आईसीईटी समीक्षा की दिशा में गति बरकरार रह सके।
- भारत-यू.एस. वैश्विक चुनौतियां संस्थान:दोनों नेताओं ने भारत-अमेरिका वैश्विक चुनौतियां संस्थान की स्थापना के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान परिषद (आईआईटी काउंसिल) और अमेरिकी विश्वविद्यालय संघ (एएयू) के प्रतिनिधित्व वाले भारतीय

विश्वविद्यालयों के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने का स्वागत किया।

- **प्रौद्योगिकी हस्तांतरण:** दोनों नेताओं ने भारत में GE F-414 जेट इंजन के निर्माण के लिए GE एयरोस्पेस और हिंदुस्तान एयरोनॉटिकल लिमिटेड (HAL) के बीच एक वाणिज्यिक समझौते के लिए बातचीत शुरू की।

भारत-अमेरिका संबंधो

ऐतिहासिक:

- शीत युद्ध के दौरान, भारत ने गुटनिरपेक्ष विदेश नीति अपनाई और अमेरिका और सोवियत संघ दोनों से दूरी बनाए रखी।
- वर्ष 1990 के दशक की शुरुआत में, भारत ने अमेरिका सहित विदेशी निवेश के लिए अपने बाज़ार खोलने शुरू कर दिए और महत्वपूर्ण आर्थिक सुधार किए।
  o इससे दोनों देशों के बीच संबंधों में धीरे-धीरे सुधार हुआ।
- दोनों देशों ने अपने रक्षा संबंधों को भी बढ़ाया है, साथ ही रूस के बाद अमेरिका भारत का दूसरा सबसे बड़ा हथियार आपूर्तिकर्ता बन गया है।
  o हाल के दशकों में, चीन के प्रतिकार के रूप में भारत के बढ़ते रणनीतिक महत्व ने अमेरिका के साथ विशेष रूप से सुरक्षा और रक्षा क्षेत्र में घनिष्ठ संबंधों को जन्म दिया है।

राजनीतिक:

- भारत अमेरिका के नेतृत्व वाले इंडो-पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी (आईपीईएफ) में शामिल हो गया है।
- भारत-यू.एस. 2+2 मंत्रिस्तरीय संवाद: इसका नेतृत्व भारत और अमेरिका के विदेश और रक्षा मंत्रालयों के प्रमुख करते हैं।
  o इस वार्ता के अब तक दो सफल दौर आयोजित हो चुके हैं।
- भारत-यू.एस. वाणिज्यिक वार्ता: भारत-अमेरिका वाणिज्यिक वार्ता का नेतृत्व वाणिज्य और उद्योग मंत्री (सीआईएम) और अमेरिकी वाणिज्य सचिव करते हैं।
- भारत-अमेरिका आर्थिक और वित्तीय साझेदारी: भारत-अमेरिका आर्थिक और वित्तीय साझेदारी का नेतृत्व वित्त मंत्री (एफएम) और अमेरिकी ट्रेजरी सचिव द्वारा किया जाता है।

व्यापार एवं वाणिज्य:

- दोनों देशों के बीच बढ़ते आर्थिक संबंधों के कारण 2022-23 में अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बनकर उभरा है।
  o द्विपक्षीय व्यापार 2022-23 में 7.65% बढ़कर 128.55 अमेरिकी डॉलर हो गया है, जबकि 2021-22 में यह 119.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर था।
- अमेरिका को निर्यात 2022-23 में 2.81% बढ़कर 78.31 बिलियन अमरीकी डॉलर हो गया, जबकि 2021-22 में यह 76.18 बिलियन अमरीकी डॉलर था, जबकि आयात लगभग 16% बढ़कर 50.24 बिलियन अमरीकी डॉलर हो गया।
- वर्ष 2021-22 में भारत का अमेरिका के साथ 32.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर का व्यापार अधिशेष रहा।
- भारत के व्यापारिक निर्यात के लिए अमेरिका सबसे बड़ा गंतव्य है, जबकि यह चीन और यूरोपीय संघ के बाद भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक आयात आपूर्तिकर्ता है।

रक्षा सहयोग:

- दोनों के बीच मजबूत रक्षा सहयोग है, जो "भारत अमेरिका रक्षा सहयोग के लिए नए ढांचे" पर आधारित है जिसे 2015 में दस वर्षों की अवधि के लिए नवीनीकृत किया गया था।
- कई रक्षा समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जैसे 2016 में लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, 2018 में संचार संगतता और सुरक्षा समझौता, 2019 में औद्योगिक सुरक्षा समझौता और 2020 में बेसिक एक्सचेंज और सहयोग समझौता आदि।
- दोनों देश युद्ध अभ्यास और वज्र प्रहरी जैसे कई द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास आयोजित करते हैं, और अपने सैन्य-से-सैन्य सहयोग को मजबूत करने के लिए रक्षा आदान-प्रदान में भी भाग लेते हैं।
- वर्ष 2019 में, दोनों देशों ने टाइगर ट्रायम्फ नामक त्रि-सेवा अभ्यास आयोजित किया।
- मध्य पूर्व में एक और समूह - I2U2 जिसमें भारत, इज़राइल, यूएई और अमेरिका शामिल हैं, को मौजूदा क्वाडग्रुपिंग के साथ नया क्वाड कहा जा रहा है।

शिक्षा साझेदारी:

- यह भारत-अमेरिका संबंधों का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है और दोनों देश उच्च शिक्षा सहयोग के मजबूत संबंध और इतिहास साझा करते हैं।
- 2 फरवरी 1950 को भारत और अमेरिका के बीच शिक्षा आदान-प्रदान पर एक द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए जाने के बाद यूनाइटेड स्टेट्स एजुकेशनल फाउंडेशन इन इंडिया (USEFI) की स्थापना की गई थी।

प्रवासी भारतीयों में वृद्धि:

- अमेरिका में भारतीयों और भारतीय अमेरिकियों की संख्या लगभग 4 मिलियन होने का अनुमान है, जो कुल अमेरिकी आबादी का लगभग 1% है।
- पिछले कुछ वर्षों में अमेरिका में भारतीय प्रवासियों की संख्या में वृद्धि हुई है। इसने ज्ञान-आधारित रोजगार के माध्यम से संयुक्त राज्य अमेरिका में आय सृजन और प्रेषण के माध्यम से भारतीय आर्थिक विकास में भी योगदान दिया है।
- समृद्ध एशियाई भारतीय प्रवासियों का बढ़ता वित्तीय और राजनीतिक दबदबा उल्लेखनीय है।

संबंधों से जुड़ी चुनौतियाँ:

- व्यापार: हाल ही में भारत और अमेरिका टैरिफ और संरक्षणवादी नीतियों को लेकर एक-दूसरे से भिड़ गए।
  o अमेरिका ने लगातार भारत पर उच्च टैरिफ का आरोप लगाया है और भारत ने अमेरिका पर अमेरिकी बाजारों पर प्रतिबंध लगाने और भारतीय उत्पादों पर उच्च टैरिफ का आरोप लगाया है।
- बौद्धिक संपदा अधिकार: अमेरिका ने आईपीआर नीतियों के लिए लगातार भारत की आलोचना की है। इसने भारत पर जेनेरिक दवाओं की तुलना में प्रमुख कंपनियों विशेषकर फार्मास्युटिकल कंपनियों के बौद्धिक गुणों के खिलाफ काम करने का आरोप लगाया है।
- पाकिस्तान को लगातार समर्थन: हालाँकि अमेरिका ने पाकिस्तान को समर्थन कम कर दिया है, फिर भी उसने पाकिस्तान को मौद्रिक सहायता प्रदान की है।
  o फरवरी 2016 में, संयुक्त राज्य अमेरिका ने पाकिस्तान को आठ परमाणु-सक्षम F-16 लड़ाकू विमान और मिश्रित सैन्य सामान प्रदान करने का प्रतिबद्धता जताई थी।
- रूस के साथ संबंध: भारत रूस का सदाबहार मित्र है जबकि अमेरिका उसका सर्वकालिक प्रतिद्वंद्विता है।
  o वर्ष 2018 में, भारत ने अमेरिका के CAATSA अधिनियम की अनदेखी करते हुए चार S-400 सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल रक्षा प्रणाली की खरीद के लिए रूस के साथ ऐतिहासिक समझौता किया।
  o उसके साथ अमेरिका ने भारत के फैसले पर प्रतिबंध लगाने की धमकी दी।
- ईरान के साथ संबंध: ईरान पर अमेरिकी प्रतिबंधों के बावजूद भारत ने लगातार ईरान से तेल खरीदा है।
  o भारत के ईरान से तेल खरीदने के फैसले पर संयुक्त राज्य अमेरिका ने भारत को प्रतिबंध लगाने की धमकी दी।
  o लेकिन हाल ही में इसने भारत को उन प्रतिबंधों से छूट दे दी जिससे भारत को ईरान से तेल खरीदने की अनुमति मिल गई।

आगे की राह :

इसलिए, यह भारत और अमेरिका दोनों के लिए आपसी हित में है कि वे मतभेदों से ऊपर बढ़े और एक शांतिपूर्ण, प्रगतिशील और बहुपक्षीय दुनिया की स्थापना के लिए निरंतर सहयोग सुनिश्चित करें। भारत और अमेरिका के बीच साझेदारी दुनिया में सबसे अधिक परिणामी साझेदारी में से एक है।

Source: The Hindu

भारत-सऊदी अरब संबंध

संदर्भ: हाल ही में, भारत और सऊदी अरब ने ऊर्जा, व्यापार और संस्कृति जैसे विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग किया है।

भारत-सऊदी अरब संबंध

राजनीतिक संबंध:

- वर्ष 1947 में राजनयिक संबंधों की स्थापना के बाद दोनों पक्षों की ओर से उच्च स्तरीय यात्राएं हुईं।
- वर्ष 2006 में किंग अब्दुल्ला की भारत की ऐतिहासिक यात्रा एक महत्वपूर्ण क्षण था जिसके परिणामस्वरूप 'दिल्ली घोषणा' पर हस्ताक्षर किए गए, जिससे द्विपक्षीय संबंधों को एक नई गति मिली।
- सऊदी अरब और भारत ने सुरक्षा, आर्थिक, रक्षा, प्रौद्योगिकी और राजनीतिक क्षेत्रों तथा आतंकवाद के संयुक्त मुकाबले को कवर करने वाली रणनीतिक साझेदारी को बढ़ाने के लिए रियाद घोषणा पर हस्ताक्षर किए।

आर्थिक सहयोग, व्यापार और निवेश:

- भारत सऊदी अरब का दूसरा सबसे बड़ा व्यापार भागीदार है, जबकि सऊदी अरब भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापार भागीदार है।
- सऊदी अरब वर्तमान में भारत का कच्चे तेल का दूसरा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता है (इराक भारत का शीर्ष आपूर्तिकर्ता रहा है)।

- भारत अपनी कच्चे तेल की आवश्यकता का लगभग 18% और तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) की आवश्यकता का लगभग 22% सऊदी अरब से आयात करता है।
- सऊदी अरब से भारत का आयात 34.01 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया और सऊदी अरब को निर्यात 8.76 बिलियन अमेरिकी डॉलर का था।

रक्षा एवं सुरक्षा सहयोग:

- AL - मोहम्मद AL - हिंदी भारत और सऊदी अरब के बीच पहला द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है।
- रियाद ने बड़े पैमाने पर भारत की आतंकवाद संबंधी चिंताओं के बारे में समझ दिखाई है, और वैश्विक खतरे का मुकाबला करने के लिए भारत के साथ काम करने पर सहमति व्यक्त की है।

सांस्कृतिक संबंध

- भारत ने वर्ष 2018 में प्रतिष्ठित सऊदी नेशनल फेस्टिवल ऑफ हेरिटेज एंड कल्चर के 32वें संस्करण में 'गेस्ट ऑफ ऑनर' के रूप में सफलतापूर्वक भाग लिया।
- सऊदी अरब में योग को 'खेल गतिविधि' घोषित किया गया।
- हज यात्रा द्विपक्षीय संबंधों का एक और महत्वपूर्ण घटक है।

भारतीय प्रवासी:

- लगभग 2.7 मिलियन मजबूत भारतीय समुदाय किंगडम में सबसे बड़ा प्रवासी समुदाय है।
- वे भारत में सालाना 11 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक का प्रेषण (remittances) भेजते हैं।

चुनौतियाँ:

- मध्य पूर्व की राजनीति जटिल और बहुआयामी है इसलिए सामूहिक और एकजुट प्रयास की आवश्यकता है।
- सऊदी अरब-तुर्की प्रतिद्वंद्विता भारत के लिए समस्याएँ खड़ी कर सकती है।
- सऊदी अरब-ईरान प्रतिद्वंद्विता: भारत के सऊदी अरब और ईरान दोनों के साथ घनिष्ठ संबंध हैं।
  o हालाँकि, भारत को एक ओर ईरान और दूसरी ओर सऊदी अरब तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ अपने संबंधों को संतुलित करने का उपाय निकालना बाकी है।
- करों में वृद्धि: सऊदी अरब में 'प्रवासी आश्रित शुल्क' या पारिवारिक कर में भारी वृद्धि, राज्य में काम करने वाले हजारों भारतीयों को अपने परिवारों को घर वापस भेजने के लिए मजबूर कर रही है।
- कफाला प्रणाली: कफाला प्रणाली के लिए सभी प्रवासी श्रमिकों को उस देश में एक प्रायोजक की आवश्यकता होती है जहां उन्हें काम करना है ताकि वैध वीजा और निवास परमिट जारी किया जा सके।
  o यह व्यावहारिक रूप से प्रवासी श्रमिक को उसके नियोक्ता की दया पर निर्भर करता है, जिससे उसका शोषण होता है।

आगे की राह:

- आर्थिक सुधार: सऊदी अरब में आर्थिक सुधार कार्यक्रम (विज़न 2030) चल रहे हैं, जिसके लिए उसे भारत की आर्थिक के साथ-साथ तकनीकी सहायता की भी आवश्यकता है।
  o सऊदी अरब भारत की ऊर्जा सुरक्षा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है जबकि भारत सऊदी अरब की खाद्य सुरक्षा में एक महत्वपूर्ण भागीदार है।
- निवेश: ऊर्जा, रिफाइनिंग, पेट्रोकेमिकल और बुनियादी ढांचे से लेकर कृषि, खनिज और खनन तक के क्षेत्रों में लगभग 100 बिलियन डॉलर का सऊदी निवेश पाइपलाइन में है।
  o यह दुनिया में हाइड्रोकार्बन के सबसे बड़े उपभोक्ताओं में से एक है और यह भारत को दुनिया के लिए एक आकर्षक निवेश गंतव्य बनाता है।
- मिलिशिया का मुकाबला करना: ऐसा प्रतीत होता है कि सऊदी अरब के पास हौथी मिलिशिया जैसे समूहों के खतरों का मुकाबला करने का सीमित अनुभव है।
  o यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण कार्यक्रमों को बढ़ाकर, ऐसे खतरों से लड़ने में भारत की विशेषज्ञता सऊदी पक्ष को प्रदान की जा सकती है।

Source: The Hindu

भारत-ब्राजील संबंध

Syllabus

- **Mains – GS 2 (International Relations)**

संदर्भ: संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) में सुधार के उद्देश्य से, भारत और ब्राजील हाल ही में नियमित द्विपक्षीय बैठकें आयोजित करने पर सहमत हुए हैं।

भारत-ब्राजील संबंध:

ऐतिहासिक संबंध:

- वास्को डी गामा के भारत में उतरने के दो साल बाद 1500 में पुर्तगाली खोजकर्ता पेड्रो अल्वारेस कैब्रल ब्राजील के पूर्वी तट पर पहुंचें।
- 16वीं और 18वीं शताब्दी के बीच, ब्राज़ील और गोवा, दोनों पुर्तगाली साम्राज्यवादी साम्राज्य की चौकी थे, में द्विपक्षीय आदान-प्रदान होता था जो खाद्य-पदार्थ और पहनावे के साथ-साथ स्थानीय परंपराओं में भी परिलक्षित होता था।
- आंध्र प्रदेश के 'ओंगोल' प्रभेद से ज़ेबू किस्म का उत्पादन हुआ, जिसे ब्राज़ील में 'नेलोर' के नाम से जाना जाता है।

राजनीतिक:

- ब्राजील और भारत के बीच 2006 में स्थापित रणनीतिक साझेदारी गहरी हो गई है, दोनों देश ब्रिक्स, आईबीएसए, G4, G20 और संयुक्त राष्ट्र के व्यापक बहुपक्षीय संदर्भ में निकटता से सहयोग कर रहे हैं।
- जर्मनी और जापान के साथ ब्राजील और भारत ने संयुक्त रूप से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सीटों की आकांक्षाओं को आगे बढ़ाया और एक बहुध्रुवीय दुनिया की दिशा में काम किया जहां बड़े विकासशील देश वैश्विक नियम बना सकते हैं और अंतरराष्ट्रीय संस्थानों का लोकतंत्रीकरण कर सकते हैं।
- दोनों देशों ने वैश्विक दक्षिण या दक्षिण-दक्षिण सहयोग के नेताओं के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
- पारस्परिक बहुपक्षवाद की ब्राजीलियाई विदेश नीति भारत की रणनीतिक स्वायत्तता की नीति के अनुरूप है।

भारत-ब्राजील व्यापार संबंध:

- वर्ष 2021 में ब्राजील और भारत के बीच व्यापार बढ़कर 7.02 बिलियन डॉलर हो गया, जिसमें ब्राजील का निर्यात 4.8 बिलियन डॉलर और भारत से आयात 6.7 बिलियन डॉलर था।
- वर्ष 2021 में, भारत दुनिया में ब्राज़ील का 5वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार (एशिया में दूसरा), और ब्राज़ीलियाई आयात का 5वां सबसे बड़ा स्रोत और ब्राज़ीलियाई निर्यात का 13वां सबसे बड़ा गंतव्य बन गया।
- ब्राजील को प्रमुख भारतीय निर्यात में प्रसंस्कृत पेट्रोलियम उत्पाद, कृषि-रसायन (कीटनाशक, कवकनाशी), रसायन, फार्मास्युटिकल, टेक्सचर्ड फिलामेंट यार्न और अनरॉट एल्युमीनियम शामिल हैं।
- भारत को ब्राजील के निर्यात में कच्चा तेल, सोया तेल, सोना (गैर-मौद्रिक), गन्ना चीनी, कपास, गोंद, लकड़ी और तारपीन तेल, रसायन (कार्बोक्जिलिक एसिड) और लौह अयस्क और सांद्र शामिल हैं।
- ब्राजील ने भारत-मर्कोसुर तरजीही व्यापार समझौते (पीटीए) में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो बड़े दक्षिण अमेरिकी बाजार तक भारत की पहुंच में सुधार करता है।

रक्षा एवं सुरक्षा सहयोग:

- भारत और ब्राज़ील ने 2003 में रक्षा क्षेत्र में सहयोग के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किये।
- संयुक्त रक्षा समिति (जेडीसी) की बैठकें रक्षा सहयोग के लिए एक संस्थागत तंत्र के रूप में आयोजित की जाती हैं।
- ब्राजील की आग्नेयास्त्र कंपनी टॉरस अरमास एसए ने भारत में छोटे हथियारों के उत्पादन और बिक्री के लिए जिंदल डिफेंस (ओ पी जिंदल समूह का हिस्सा) के साथ एक संयुक्त उद्यम पर हस्ताक्षर किए।
- जनवरी 2020 में राष्ट्रपति बोल्सोनारो की राजकीय यात्रा के दौरान CERT-In और इसकी समकक्ष एजेंसी के बीच साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

सांस्कृतिक सहयोग

- ब्राजील में योग और आयुर्वेद चिकित्सकों का एक मजबूत समुदाय है।
  o ब्राज़ीलियन एसोसिएशन ऑफ आयुर्वेद (ABRA) एक गैर-लाभकारी संघ है, जिसके कार्यालय ब्राज़ील के 9 राज्यों में हैं और पूरे ब्राज़ील में इसके सदस्य हैं।

- ब्राजील में महात्मा गांधी को बहुत माना जाता है और सरकार तथा गैर सरकारी संगठन छात्रों, युवाओं और पुलिस के बीच अहिंसा के दर्शन को विकसित करने की कोशिश कर रहे हैं।
- जनवरी 2020 में राष्ट्रपति बोल्सोनारो की भारत की राजकीय यात्रा के दौरान वर्ष 2020-2024 के लिए एक सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम (सीईपी) पर हस्ताक्षर किए गए।

भारत और ब्राज़ील के बीच द्विपक्षीय संबंधों में चुनौतियाँ:

- व्यापार प्रतिस्पर्धा: भारत और ब्राजील दोनों चीनी और मांस जैसे कृषि उत्पादों के प्रमुख निर्यातक हैं, जो दोनों देशों के बीच प्रतिस्पर्धा और व्यापार रुकावट पैदा कर सकते हैं।
- चीन का व्यापार प्रभुत्व: इसके अलावा, चिंताएं भी हैं क्योंकि चीन, जो ब्राजील का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है, भारत और ब्राजील के बीच संबंधों पर प्रभाव डाल सकता है।
- गन्ना सब्सिडी: गन्ना किसानों को भारत की सब्सिडी के बारे में ब्राजील की विश्व व्यापार संगठन से शिकायत है।
  o इससे भारत की कृषि नीतियों पर ब्राजील की चिंताओं के कारण दोनों देशों के बीच तनाव पैदा हो गया है जो उसके आर्थिक हितों पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है।
- सीमित लोगों से लोगों के बीच संपर्क: भारत और ब्राजील में व्यापार, सांस्कृतिक और शैक्षिक आदान-प्रदान सहित लोगों से लोगों के बीच सीमित संख्या में संपर्क हैं।
- रणनीतिक प्राथमिकताओं में अंतर: भारत और ब्राजील दोनों उभरती हुई शक्तियां हैं जो अपने वैश्विक प्रभाव को बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर उनके दृष्टिकोण भिन्न हो सकते हैं।

आगे की राह :

भारत और ब्राजील के बीच एक दशक लंबी द्विपक्षीय रणनीतिक साझेदारी एक समान वैश्विक दृष्टिकोण, साझा लोकतांत्रिक मूल्यों और दोनों देशों के लोगों के कल्याण के लिए सामाजिक समावेशन के साथ आर्थिक विकास को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता पर आधारित है। विभिन्न बहुपक्षीय और बहुपक्षीय मंचों पर अपने एकजुट रुख के साथ, दोनों देशों को नई विश्व व्यवस्था के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है।

Source: The Hindu

भारत-कनाडा संबंध

Syllabus

- **Mains – GS 2 (International Relations)**

संदर्भ: हाल ही में खालिस्तान समर्थक गतिविधियों पर निलंबन और चिंताओं के कारण भारत के साथ कनाडाई व्यापार वार्ता अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई है।

भारत-कनाडा संबंध:

राजनीतिक:

- भारत ने वर्ष 1947 में कनाडा के साथ राजनयिक संबंध स्थापित किये।
- अप्रैल 2015 में भारत के प्रधान मंत्री की कनाडा यात्रा ने द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ा दिया।
- भारत और कनाडा संसदीय संरचना और प्रक्रियाओं में समानताएं साझा करते हैं।
  o अक्टूबर 2019 में आम चुनाव के बाद, हाउस ऑफ कॉमन के सांसद श्री राज सैनी को कनाडा-भारत संसदीय संघ के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है।
- भारत में, कनाडा का प्रतिनिधित्व नई दिल्ली में कनाडा के उच्चायोग द्वारा किया जाता है।
- कनाडा में भारत का प्रतिनिधित्व ओटावा में एक उच्चायोग और टोरंटो तथा वैंकूवर में वाणिज्य दूतावासों द्वारा किया जाता है।

वाणिज्यिक संबंध:

- व्यापार और आर्थिक संबंधों की समीक्षा के लिए एक वार्षिक व्यापार मंत्री संवाद को संस्थागत बनाया गया है।
- दोनों पक्ष वस्तुओं, सेवाओं, निवेश, व्यापार सुविधा आदि में व्यापार सहित एक व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते (सीईपीए) के लिए तकनीकी वार्ता में लगे हुए हैं।
- भारत कनाडा का 9वां सबसे बड़ा निर्यात बाजार है।
- भारत के निर्यात में रत्न, आभूषण और कीमती पत्थर, फार्मास्युटिकल उत्पाद, रेडीमेड परिधान, हल्के इंजीनियरिंग सामान, लोहा और इस्पात लेख आदि शामिल हैं।

- कनाडा से भारत के आयात में दालें, अखबारी कागज, लकड़ी का गूदा, एस्बेस्टस, पोटाश, लौह स्क्रैप, तांबा, खनिज और औद्योगिक रसायन आदि शामिल हैं।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी:

- इसरो और सीएसए (कनाडाई अंतरिक्ष एजेंसी) ने बाहरी अंतरिक्ष की खोज और उपयोग के क्षेत्र में सहयोग के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं और विशेष रूप से उपग्रह ट्रैकिंग और अंतरिक्ष खगोल विज्ञान को संबोधित करने वाली दो कार्यान्वयन व्यवस्थाओं पर भी हस्ताक्षर किए गए हैं।
- इसरो की वाणिज्यिक शाखा एंट्रिक्स ने कई कनाडाई उपग्रह लॉन्च किए हैं।
- आईसी-इम्पैक्ट्स कार्यक्रम के तहत जैव प्रौद्योगिकी विभाग स्वास्थ्य देखभाल, कृषि-बायोटेक और अपशिष्ट प्रबंधन में संयुक्त अनुसंधान परियोजनाओं को लागू करता है।
- पृथ्वी विज्ञान विभाग और ध्रुवीय कनाडा ने शीत जलवायु (आर्कटिक) अध्ययन पर ज्ञान के आदान-प्रदान और वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए एक कार्यक्रम शुरू किया है।

सुरक्षा और रक्षा:

- भारत और कनाडा ने 1994 में पारस्परिक कानूनी सहायता संधि (1998 में क्रियान्वित) और 1987 में प्रत्यर्पण संधि पर हस्ताक्षर किए हैं।
- आतंकवाद-रोधी मुद्दों पर विशेष रूप से आतंकवाद-रोधी JWG के ढांचे के माध्यम से मजबूत सहयोग है।
- भारत और कनाडा अंतरराष्ट्रीय मंचों, विशेष रूप से संयुक्त राष्ट्र, राष्ट्रमंडल राष्ट्र और जी-20 के माध्यम से निकटता से सहयोग करते हैं।

भारतीय प्रवासी:

- कनाडा दुनिया के सबसे बड़े भारतीय प्रवासियों में से एक की मेजबानी करता है, जिनकी संख्या 1.6 मिलियन (पीआईओ और एनआरआई) है, जो इसकी कुल आबादी का 4% से अधिक है।
  o प्रवासी भारतीयों ने कनाडा में हर क्षेत्र में सराहनीय प्रदर्शन किया है।
- राजनीति के क्षेत्र में, विशेष रूप से, वर्तमान हाउस ऑफ कॉमन्स (कुल संख्या 338) में भारतीय मूल के 22 संसद सदस्य हैं।

संबंधों से जुड़ी चुनौतियाँ:

- सिख उग्रवाद: सिख भारतीय प्रवासियों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं; वे कनाडा की कुल जनसंख्या का एक प्रतिशत से भी कम (500,000 से थोड़ा अधिक) हैं।
  o कनाडा में सक्रिय सिख अलगाववादी समूहों का मुद्दा भारत और कनाडा के बीच तनाव का एक बढ़ता स्रोत बन गया है।
  o ओंटारियो प्रांतीय संसद ने 1984 के सिख विरोधी दंगों को 'नरसंहार' करार देते हुए एक प्रस्ताव अपनाया और कई अन्य कनाडाई नेता भी आज भी इसका समर्थन करते हैं।
- भारत की संरचनात्मक बाधाएँ: भारत को अभी भी जटिल श्रम कानून, बाज़ार संरक्षणवाद और नौकरशाही नियमों जैसी संरचनात्मक बाधाओं से पार पाना है।
- अपर्याप्त व्यापार: भारत-कनाडा आर्थिक संबंधों में कुछ प्रगति हुई है; जबकि कनाडा भारत के लिए एक महत्वहीन व्यापारिक भागीदार बना हुआ है।

आगे की राह :

- भारत और कनाडा दोनों के लिए सहयोग को बढ़ावा देने और अपने संबंधों को अगले स्तर पर ले जाने की पर्याप्त संभावनाएं हैं। लेकिन इसके लिए अपने भारतीय दृष्टिकोण को व्यापक बनाकर कनाडाई प्रयास की आवश्यकता है।
- ऐसा तभी हो सकता है जब भारत बातचीत को राजनीतिक रूप से विवादास्पद मुद्दों से भटका दे। भारतीय मीडिया, सरकार और यहां तक कि पंजाब के राजनेताओं को यह महसूस करने की जरूरत है कि कनाडा, ब्रिटेन और अमेरिका में रहने वाले सिखों के राजनीतिक विचार अलग-अलग हो सकते हैं।
- इसी प्रकार, किसी उद्देश्य के लिए अहिंसक समर्थन को उग्रवादी गतिविधि के रूप में लेबल नहीं किया जा सकता है।

Source: The Hindu

पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन (ईएएस) और इसका महत्व

Syllabus

- **Mains – GS 2 (International Relations)**

संदर्भ: हाल ही में प्रधान मंत्री ने जकार्ता में आयोजित 18वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन (ईएएस) में भाग लिया।

इसकी मुख्य विशेषताएं:

- आसियान पर नेताओं की घोषणा: 18वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन (ईएएस) में, विकास के केंद्र के रूप में आसियान पर नेताओं की घोषणा को अपनाया गया।
  o ऊर्जा सुरक्षा और खाद्य सुरक्षा को बढ़ाने, वित्तीय स्थिरता बनाए रखने और क्षेत्रीय स्वास्थ्य वास्तुकला को मजबूत करने पर सहयोग के माध्यम से उभरती चुनौतियों और भविष्य के झटकों के खिलाफ लचीलापन बनाने पर चर्चा की गई।
- कार्य योजना (पीओए): अगले पांच वर्षों के लिए कार्य योजना (पीओए) प्राथमिकताओं को रेखांकित करती है जिसमें इंडो-पैसिफिक (एओआईपी) पर आसियान आउटलुक को मुख्यधारा में लाने और कार्यान्वयन के प्रयास शामिल हैं।
  o यह अंतर-क्षेत्रीय सहयोग के माध्यम से साझेदारी को मजबूत करने पर जोर देता है जिसमें सतत विकास के लिए 2030 एजेंडा के कार्यान्वयन को आगे बढ़ाने के प्रयास शामिल हैं।
- आसियान और गैर-आसियान देशों की बैठक: इस बैठक ने आसियान सदस्य देशों और आठ गैर-आसियान देशों को क्षेत्र और दुनिया भर से संबंधित मुद्दों पर विचारों का आदान-प्रदान करने का अवसर प्रदान किया।

पूर्वी एशिया का महत्व:

- क्षेत्रीय सुरक्षा: कोरियाई प्रायद्वीप, दक्षिण चीन और ताइवान जलडमरूमध्य पर तनाव को ध्यान में रखते हुए, जापान, चीन और दक्षिण कोरिया के लिए एक समान रुख बनाए रखना और पूर्वी एशियाई क्षेत्र में सुरक्षा के लिए एक समान चिंता साझा करना महत्वपूर्ण है।
- आर्थिक लाभ: यह वैश्विक व्यापार के 20 प्रतिशत के साथ दुनिया की लगभग 50 प्रतिशत आबादी का प्रतिनिधित्व करता है, और इसमें 16 देश शामिल हैं जो आर्थिक विकास के गतिशील पथ पर हैं।
- वैश्विक निहितार्थ: पूर्वी एशिया समुदाय एशियाई देशों में जिम्मेदारी की भावना पैदा करने और वैश्विक मुद्दों के समाधान में योगदान देने में संयुक्त रूप से उनका नेतृत्व करने में एक बड़ी भूमिका निभाएगा।

क्षेत्र में चुनौतियाँ:

- क्षेत्रीय चुनौतियाँ: ईएएस में भाग लेने वाले देश इंडो-पैसिफिक में शांति और सुरक्षा प्राप्त करने के उद्देश्य से एक सामान्य दृष्टिकोण साझा करते हैं, जबकि चीन जैसे अन्य देशों के साथ चल रहे विवाद मूल रूप से परिकल्पित सहकारी और सहयोगात्मक ढांचे को सीमित करते हैं।
- जटिल भू-राजनीतिक मुद्दे: सामान्य हित और चिंता के रणनीतिक, राजनीतिक और आर्थिक मामलों के व्यापक स्पेक्ट्रम पर बातचीत और सहयोग के लिए एक मंच के रूप में ईएएस को मजबूत करना जटिल बना हुआ है।
  o यह उपस्थिति और लगातार विकसित हो रहे बहुआयामी खतरों और चुनौतियों से उत्पन्न होता है जो क्षेत्र में देखी जा रही गहन भू-राजनीतिक और भू-आर्थिक चर्चा के कारण और भी जटिल हो जाते हैं।
- प्रासंगिकता पर चिंताएं: प्रासंगिकता पर चिंताएँ: वर्तमान समय में देखा जा रहा गहराता हुआ भू-राजनीतिक विभाजन, कोविड-19 और चल रहे यूक्रेन-रूस युद्ध से सामाजिक-आर्थिक नतीजों के परिणामस्वरूप मानव सुरक्षा चुनौतियों के मुद्दों को संबोधित करने में ईएएस की प्रासंगिकता पर चिंता पैदा करता है।
- प्रभावकारिता और प्रभावशीलता में बाधा: ईएएस में भाग लेने वाले देशों के बीच संबंधों की प्रकृति, जो टकराव और प्रतिस्पर्धा से चिह्नित है, ने इसकी प्रभावकारिता और प्रभावशीलता पर प्रभाव डाला है।

आगे की राह :

- यह 18वें ईएएस में विभाजन और टकराव के बिना सहयोग पर आधारित एक अंतरराष्ट्रीय समुदाय पर जोर देकर संस्था की प्रभावकारिता और प्रभावशीलता को मजबूत करने का एक प्रयास था। ईएएस क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय कानून और नियम-आधारित आदेश के पालन को बढ़ावा देता है जिसमें समुद्री अधिकारों और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करना और शांतिपूर्ण संघर्ष समाधान की दिशा में काम करना शामिल है।

Source: The Hindu

Paper III

जेंडर रिस्पॉन्सिव बजटिंग

Syllabus

- **Mains – GS 2 (Governance) and GS 3 (Economy)**

संदर्भ: हाल ही में यूनिसेफ की भारत प्रतिनिधि सिंथिया मैककैफ्रे ने कहा है कि देश को चाइल्ड और लिंग-उत्तरदायी बजटिंग में अग्रणी के रूप में

देखा जा रहा है, यह विशेषकर दक्षिण एशिया में हो रहा है।

जेंडर रिस्पॉन्सिव बजटिंग (जीआरबी) के बारे में:

- जेंडर बजटिंग सार्वजनिक संसाधनों को एकत्र करने और खर्च करने के तरीके पर ध्यान केंद्रित करके महिलाओं और पुरुषों के बीच समानता हासिल करने की एक राजकोषीय रणनीति है।
- यह पहल लैंगिक अंतर को कम करने में मदद कर सकती है, साथ ही यह सुनिश्चित करते हुए कि सार्वजनिक धन जुटाया जाए और अधिक प्रभावी ढंग से खर्च किया जाए।

भारत की जेंडर रिस्पॉन्सिव बजटिंग:

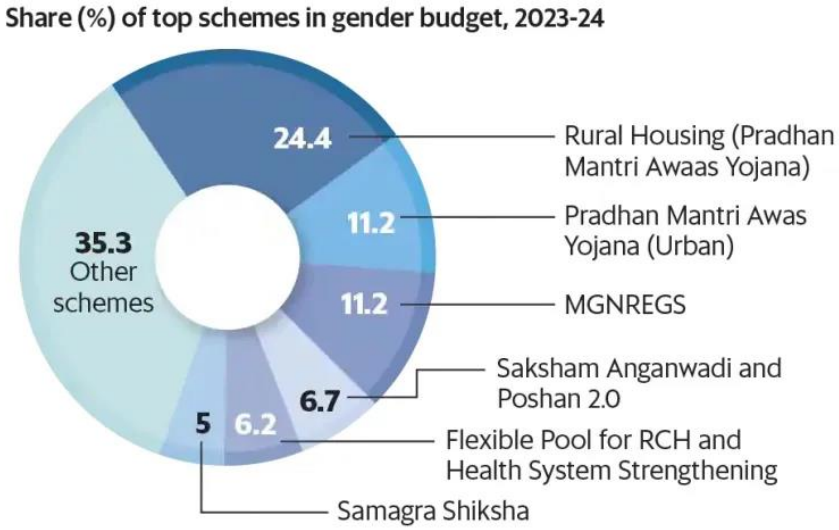

- यह भारत में 2005-2006 में एक वित्तीय नवाचार के रूप में शुरू हुआ, तब से हर साल वित्त मंत्रालय केंद्रीय बजट के साथ "जेंडर बजट विवरण" प्रकाशित करता रहा है।
- वर्ष 2010 में, योजना आयोग ने स्पष्ट किया कि महिला घटक योजना के स्थान पर, वित्त मंत्रालय और MoWCD को केवल जेंडर रिस्पॉन्सिव बजटिंग या जेंडर बजटिंग को अपनाना चाहिए।
- महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा जारी 'जेंडर बजटिंग हैंडबुक, 2015' में कहा गया है कि जेंडर बजटिंग जेंडर को मुख्यधारा में लाने का एक उपकरण है।
- वर्ष 2023-24 के केंद्रीय बजट में, वित्त मंत्री ने 'नारी-शक्ति' (महिला शक्ति) पर जोर दिया और महिलाओं के विकास से महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास पर ध्यान केंद्रित किया।

जेंडर रिस्पॉन्सिव बजटिंग का महत्व:

- उपलब्धि लैंगिक साझेदारी और समानता: भारत का संविधान न केवल महिलाओं को समानता प्रदान करता है, बल्कि राज्य को महिलाओं के पक्ष में सकारात्मक भेदभाव के उपाय अपनाने का अधिकार भी देता है।
- साक्षरता में सुधार: सरकार महिला साक्षरता पर ध्यान केंद्रित करते हुए विद्या शक्ति कार्यक्रम सफलतापूर्वक चला रही है।
- नीतिगत लक्ष्यों की उपलब्धि की निगरानी: यह राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण नीति 2001 के लक्ष्यों और अन्य नीतिगत लक्ष्यों की उपलब्धि की निगरानी करने का एक उपकरण है।
- आर्थिक विकास: महिलाओं और लड़कियों की विशिष्ट आवश्यकताओं और चुनौतियों का समाधान करने के लिए संसाधनों का आवंटन सुनिश्चित करता है।
  o भारत में बैंकिंग उद्योग में अपनी तरह का पहला भारतीय महिला बैंक लिमिटेड और प्रधानमंत्री जन धन योजना वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के अलावा लैंगिक न्याय और समानता के लिए उत्प्रेरक के रूप में उभर रहे हैं।

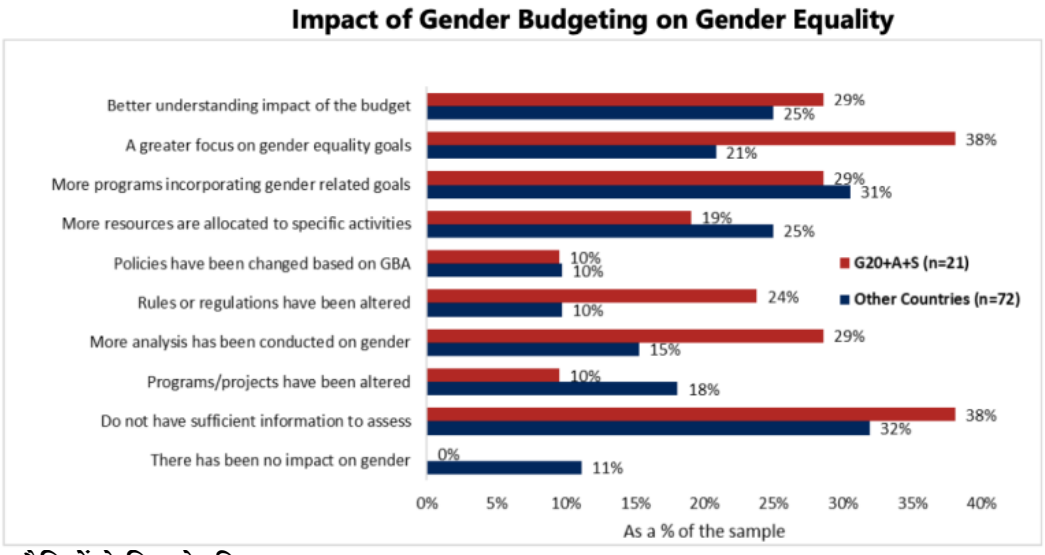

चुनौतियों से निपटने की आवश्यकता :

- राजनीतिक प्रतिनिधित्व: 17वीं लोकसभा के 545 सदस्यों में से केवल 14.44% महिलाएं हैं।
- शिक्षा: विश्व बैंक भारत की रिपोर्ट के अनुसार, देश में पुरुष साक्षरता दर जहां 84.7 प्रतिशत है, वहीं महिलाओं के लिए यह 77 प्रतिशत है।
- आर्थिक अवसर: आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार, 2021-2022 में 15-29 वर्ष के बीच की केवल 32.8 प्रतिशत महिलाएं भारत की श्रम शक्ति का हिस्सा थीं, जबकि पुरुष 77.2 प्रतिशत थे।
- कम बजटीय आवंटन: लगभग दो दशकों से लागू होने के बावजूद, इस पर बजटीय व्यय केंद्रीय बजट 2023-24 में कुल आवंटन का मात्र 4-5 प्रतिशत है।
- विषम कार्यान्वयन: जेंडर मेनस्ट्रीमिंग (जून 2022) पर नीति आयोग के पेपर में कहा गया है कि 119 केंद्र प्रायोजित योजनाओं में से केवल 62 ही जेंडर रिस्पॉन्सिव बजटिंग का अभ्यास कर रही हैं।
  o पेपर के अनुसार पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन, शहरी परिवर्तन, कौशल आदि से जुड़े मंत्रियों का रिकॉर्ड खराब रहा है।
- गुणवत्ता लैंगिक पृथक्कृत डेटा: सरकारी एजेंसियां जो अपनी योजनाओं और कार्यक्रमों से लैंगिक पृथक्कृत जानकारी एकत्र नहीं करती हैं, वे महिलाओं और लड़कियों के सशक्तिकरण के लिए लक्षित व्यय का आकलन करने में सक्षम नहीं हो सकती हैं।

जेंडर रिस्पॉन्सिव बजटिंग की दिशा में सरकार की पहल:

- सुरक्षित शहर परियोजना: यह सार्वजनिक संसाधनों को मजबूत करके महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करती है।
- समर्थ योजना: मौजूदा महिला सशक्तिकरण कार्यक्रमों जैसे कि प्रधान मंत्री वंदना योजना और स्वाधार गृह आदि को मिलाकर शुरू की गई।
- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा)
- प्रधानमंत्री आवास योजना
- सक्षम आंगनवाड़ी योजना और पोषण 2.0
- स्वच्छ भारत मिशन
- बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ
- प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई)

आगे की राह :

- भारत में जेंडर रिस्पॉन्सिव बजटिंग (जीआरबी) ने सरकारी पहल और बजट आवंटन के माध्यम से लैंगिक समानता को बढ़ावा देने में वृद्धि की है। हालाँकि, शिक्षा में असमानता, आर्थिक अवसर और राजनीतिक प्रतिनिधित्व जैसी चुनौतियों को सर्वोच्च प्राथमिकता के रूप में संबोधित करने की आवश्यकता है। ऐसा करके, भारत बीजिंग घोषणा के सिद्धांतों को प्राप्त कर सकता है और राजकोषीय उपायों से परे गहरे सामाजिक-आर्थिक मुद्दों का समाधान कर सकता है।

Source: Business Standard

स्टेम सेल थेरेपी

Syllabus

- **Mains – GS 3 (Science and Technology)**

संदर्भ: दिल्ली उच्च न्यायालय ने हाल ही में ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर (एएसडी) से पीड़ित दो बच्चों को स्टेम सेल थेरेपी कराने की अनुमति दी है।

स्टेम सेल थेरेपी के बारे में:

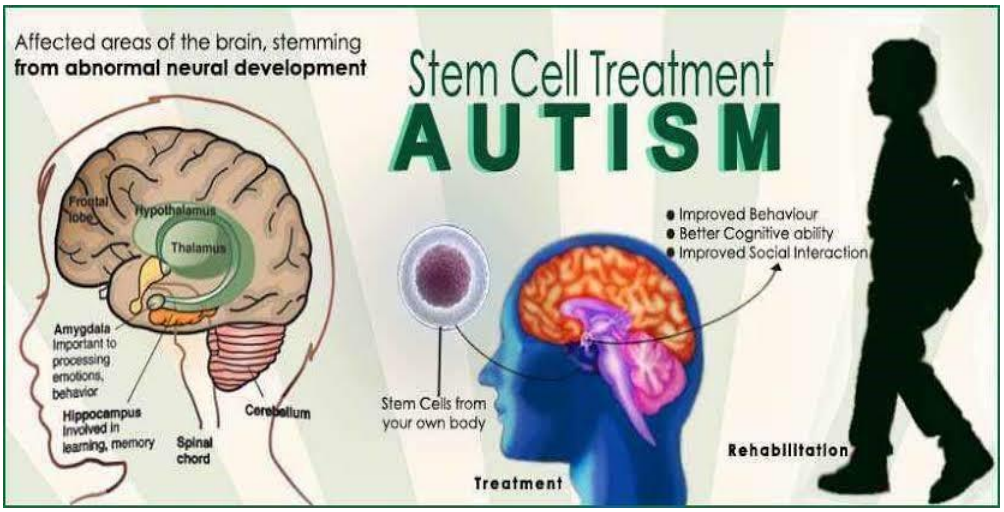

- स्टेम कोशिकाएँ अविभाजित जैविक कोशिकाएँ हैं जो विशिष्ट कोशिकाओं में विभेदित हो सकती हैं और अधिक स्टेम कोशिकाएँ बनाने के लिए विभाजित हो सकती हैं।
- किसी भी बीमारी को रोकने या उसका इलाज करने के लिए उपचार या थेरेपी में स्टेम सेल का उपयोग किया जाता है, जिसे स्टेम सेल थेरेपी के रूप में जाना जाता है।
- स्टेम कोशिकाओं को प्रयोगशालाओं में विकसित किया जाता है, इन स्टेम कोशिकाओं को विशिष्ट प्रकार की कोशिकाओं, जैसे हृदय की मांसपेशियों की कोशिकाओं, रक्त कोशिकाओं या तंत्रिका कोशिकाओं आदि में विशेषज्ञ बनाने के लिए हेरफेर किया जाता है।
- स्टेम सेल थेरेपी रोगग्रस्त, मृत या घायल ऊतकों के पुनर्योजी उपचार को बढ़ावा देती है।

स्टेम सेल थेरेपी के संभावित अनुप्रयोग: थेरेपी का उपयोग इलाज के लिए किया जा सकता है:

- आर्थोपेडिक चोटें और मस्कुलोस्केलेटल समस्याएं
- रीढ़ के हड्डी की चोट, मस्तिष्क आघात और स्पाइनल स्टेनोसिस
- उच्च रक्तचाप, कोरोनरी हृदय रोग, स्ट्रोक और कंजेस्टिव हृदय विफलता सहित हृदय संबंधी रोग
- बालों का झड़ना और दृष्टि हानि
- मधुमेह और अन्य अग्न्याशय संबंधी विकार
- पार्किंसंस, मल्टीपल स्केलेरोसिस और अल्जाइमर जैसी न्यूरोडीजेनेरेटिव बीमारियाँ

स्टेम सेल थेरेपी का महत्व:

- चिकित्सीय लाभ: यह चिकित्सीय क्लोनिंग और पुनर्योजी चिकित्सा में बहुत सारे चिकित्सीय लाभ प्रदान करता है।
  o यह पार्किंसंस रोग, रीढ़ की हड्डी की चोट, अल्जाइमर रोग, सिज़ोफ्रेनिया, कैंसर, मधुमेह और कई अन्य स्थितियों जैसी कई स्थितियों के उपचार में काफी संभावनाएं दिखाता है।
- मानव विकास का बेहतर ज्ञान: यह शोधकर्ताओं को मानव कोशिकाओं की वृद्धि और उनके विकास के बारे में अधिक जानने में मदद करता है।
  o स्टेम सेल अनुसंधान वैज्ञानिकों को जानवरों और मनुष्यों पर कोई परीक्षण किए बिना कई संभावित दवाओं और इनका परीक्षण करने की अनुमति देता है। इन दवा का परीक्षण सीधे कोशिकाओं की सख्यां पर किया जाता है।
- प्रारंभिक देखभाल और उपचार: स्टेम सेल थेरेपी शोधकर्ताओं को विकास के चरणों का अध्ययन करने की भी अनुमति देती है जिसे सीधे मानव भ्रूण के माध्यम से नहीं जाना जा सकता है और इसका उपयोग कई जन्म दोषों, बांझपन समस्याओं और गर्भावस्था के नुकसान के उपचार में भी किया जा सकता है।

- एक उच्च समझ मानव शरीर में असामान्य विकास के उपचार की अनुमति देती है।

- अस्वीकृति का जोखिम कम: स्टेम सेल थेरेपी रोगी के स्वयं के शरीर की कोशिकाओं का उपयोग करती है और इसलिए अस्वीकृति का जोखिम कम किया जा सकता है क्योंकि कोशिकाएं एक ही मानव शरीर की होती हैं।

नुकसान:

- ब्लास्टोसिस्ट की हानि: शोध के लिए स्टेम कोशिकाओं के उपयोग में ब्लास्टोसिस्ट का विनाश शामिल है जो मानव अंडे के प्रयोगशाला निषेचन से बनते हैं।
- अज्ञात दुष्प्रभाव: किसी भी अन्य नई तकनीक की तरह, यह पूरी तरह से अज्ञात है कि प्रकृति के साथ इस तरह के हस्तक्षेप के दीर्घकालिक प्रभाव क्या हो सकते हैं।
- वयस्क कोशिकाओं की सीमाएँ: वयस्क स्टेम कोशिकाओं का नुकसान यह है कि एक विशेष मूल की कोशिकाएं केवल उसी प्रकार की कोशिकाएं उत्पन्न करती हैं, जैसे मस्तिष्क कोशिकाएं केवल मस्तिष्क कोशिकाएं उत्पन्न करती हैं इत्यादि।
- संभावित अस्वीकृति: यदि चिकित्सा में उपयोग की जाने वाली कोशिकाएं भ्रूणीय हैं, तो कोशिकाएं उसी मानव शरीर से नहीं होंगी और अस्वीकृति की संभावना होगी।
- नकारात्मक गतिविधियों में संभावित उपयोग: इसका उपयोग जैव-हथियार या सामूहिक विनाश के हथियार बनाने के लिए किया जा सकता है।

आगे की राह :

विभिन्न प्रकार की चिकित्सीय स्थितियों के इलाज के लिए स्टेम सेल थेरेपी भारत में लोकप्रियता हासिल कर रही है। इस तथ्य पर विचार करते हुए कि थेरेपी को अक्सर और दुनिया भर में एक सार्वभौमिक मानव उपचार के रूप में पेश किया जाता है, अध्ययन को संभावित प्रो-ट्यूमरजेनिक और थेरेपी के अन्य हानिकारक प्रभावों को निर्धारित करने के लिए पशु अनुसंधान मॉडल की निरंतर निगरानी और दीर्घकालिक अनुवर्ती पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए।

Source: Indian Express

राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (NMCG)

Syllabus

- **Mains – GS 2 (Governance) and GS 3 (Environment)**

संदर्भ: सात वर्षों में, जब से सरकार ने अपने महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (NMCG) का अनावरण किया है, उसने उपचार संयंत्र स्थापित किए हैं जो केवल 20% सीवेज का उपचार करने में सक्षम हैं।

- ये संयंत्र नदी के किनारे स्थित पांच प्रमुख राज्यों- उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में उत्पन्न होने वाले 20% सीवेज का उपचार करने में सक्षम हैं।
    - 2024 तक इसके लगभग 33% तक बढ़ने की उम्मीद है और अनुमान है कि उपचार संयंत्र दिसंबर 2026 तक 60% सीवेज का उपचार करने में सक्षम होंगे।

राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (एनएमसीजी) के बारे में

- इसे सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत 2011 में एक सोसायटी के रूप में पंजीकृत किया गया था।
- इसने राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण (एनजीआरबीए) की कार्यान्वयन शाखा के रूप में कार्य किया, जिसे पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम (ईपीए), 1986 के प्रावधानों के तहत गठित किया गया था।

- गंगा नदी के कायाकल्प, संरक्षण और प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय परिषद के गठन के परिणामस्वरूप 2016 से एनजीआरबीए को भंग कर दिया गया है, जिसे राष्ट्रीय गंगा परिषद के रूप में जाना जाता है।

- भारत के प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में राष्ट्रीय गंगा परिषद।
- राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (एनएमसीजी) में दो स्तरीय प्रबंधन संरचना है और इसमें शामिल हैं:
  o गवर्निंग काउंसिल
  o कार्यकारी समिति
- दोनों का नेतृत्व एनएमसीजी के महानिदेशक द्वारा किया जाता है।

नमामि गंगे कार्यक्रम का महत्व:

- सीवेज उपचार क्षमता का निर्माण: 48 सीवेज प्रबंधन परियोजनाएं कार्यान्वयन के अधीन हैं और बेसिन राज्यों में 98 सीवेज परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं।
- जैव विविधता संरक्षण: गंगा कायाकल्प के लिए एनएमसीजी के दीर्घकालिक दृष्टिकोण में से एक नदी की सभी स्थानिक और लुप्तप्राय जैव विविधता की व्यवहार्य आबादी को बहाल करना है, ताकि वे अपनी पूरी ऐतिहासिक सीमा पर कब्जा कर सकें और गंगा नदी पारिस्थितिकी तंत्र की अखंडता को बनाए रखने में अपनी भूमिका निभा सकें।
- नदी तट विकास का निर्माण: 267 घाटों/श्मशान घाटों और कुंडों/तालाबों के निर्माण, आधुनिकीकरण और नवीकरण के लिए 68 घाट/श्मशान परियोजनाएं शुरू की गई हैं।
- नदी की सतह की सफाई: घाटों और नदी की सतह से तैरते ठोस कचरे के संग्रह और उसके निपटान के लिए नदी की सतह की सफाई का काम चल रहा है और 11 स्थानों पर सेवा शुरू की गई है।
- वनरोपण: इस प्रक्रिया में मुख्य जल क्षेत्रों और नदी तथा उसकी सहायक नदियों के किनारे वनों की उत्पादकता और विविधता को बढ़ाना शामिल है।
- गंगा ग्राम: पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय ने 5 राज्यों (उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल) में गंगा नदी के किनारे स्थित 1674 ग्राम पंचायतों की पहचान की।

मिशन की चुनौतियाँ:

- कीचड़ नियंत्रण (Sludge control): जबकि गंगा ग्राम में शौचालय के निर्माण के माध्यम से स्वच्छ भारत मिशन (एसबीएम) द्वारा मानव अपशिष्ट की रोकथाम काफी हद तक हासिल की गई है, लेकिन इसका सुरक्षित निपटान अभी भी एक बड़ी चुनौती है।
  o मल कीचड़ सीवरेज से भी बड़ा प्रदूषक है।
- सीवेज उपचार: इस पहल के बावजूद, भूमि अधिग्रहण और अन्य प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं, सीवेज उपचार संयंत्रों (एसटीपी) के खराब प्रदर्शन और शहरों में सीवरेज नेटवर्क की कमी के कारण नई परियोजनाओं में देरी जैसी चुनौतियां हैं।
  o उद्योगों को अपने पूरे कचरे को आम नाले में निपटाना आसान लगता है जो घरेलू और औद्योगिक दोनों तरह के कचरे को नदी में बहा देता है।
- प्रवाह को बहाल करना: पर्याप्त प्रवाह के साथ, एक नदी स्व-शुद्धिकरण प्रणाली के रूप में कार्य करती है। हालाँकि, मानसून को छोड़कर गंगा इस बुनियादी परीक्षण में विफल रही है।
  o प्रतिबंध और प्रवाह में कमी के कारण पानी का वेग कम हो जाता है और गाद बढ़ जाती है और स्व-शोधन क्षमता कम हो जाती है।
- लागत में वृद्धि: कई परियोजनाओं में देरी और अप्रभावी वित्तीय प्रबंधन के परिणामस्वरूप कार्यक्रम की लागत में वृद्धि हुई है।
- शासन के मुद्दे: गंगा कार्य योजनाओं में विभिन्न मंत्रालयों के समन्वय का अभाव था।
  o समन्वय की कमी के परिणामस्वरूप दोषपूर्ण निष्पादन, देरी और लागत में वृद्धि होती है।

आगे की राह:इसलिए, कीचड़ और उपचारित पानी का मुद्रीकरण 'अर्थ गंगा' के बैनर तले नमामि गंगे कार्यक्रम के फोकस क्षेत्रों में से एक है, जिसका अर्थ है 'अर्थशास्त्र के पुल' के माध्यम से लोगों को गंगा से जोड़ना। वांछित परिवर्तन लाने के लिए सूचना का लक्षित प्रसार किया जाना चाहिए। "स्वच्छता के प्रति जागरूक पीढ़ी" बनाने की आवश्यकता है और बाकी सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा।

Source: The Hindu

क्वांटम कंप्यूटिंग में वैश्विक पहल: अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की भूमिका

Syllabus

- **Mains – GS 3 (Science and Technology)**

संदर्भ: क्वांटम कंप्यूटिंग तेजी से एक परिवर्तनकारी तकनीक के रूप में उभर रही है, जो दुनिया भर में सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों का ध्यान आकर्षित कर रही है।

- इसकी उल्लेखनीय क्षमता शास्त्रीय कंप्यूटरों की तुलना में अभूतपूर्व कंप्यूटिंग गति प्रदान करने की क्षमता और साइबर सुरक्षा में क्रांति लाने की क्षमता में निहित है।

क्वांटम प्रौद्योगिकी के बारे में:

- क्वांटम कंप्यूटिंग परमाणुओं और प्राथमिक कणों के पैमाने पर प्रकृति का वर्णन करने के लिए 20 वीं शताब्दी की शुरुआत में विकसित क्वांटम यांत्रिकी के सिद्धांतों पर आधारित है।
- यह गणना के लिए एक क्रांतिकारी दृष्टिकोण है जो जानकारी को संसाधित करने के लिए क्वांटम यांत्रिकी के सिद्धांतों का लाभ उठाता है।
    - यह क्लासिकल कंप्यूटिंग से काफी भिन्न है, जो शास्त्रीय भौतिकी पर आधारित है और डेटा को 0 या 1 के रूप में दर्शाने के लिए बिट्स का उपयोग करता है।

वैश्विक क्वांटम कंप्यूटिंग परिदृश्य

- 2022 तक, क्वांटम कंप्यूटिंग क्षेत्र ने पर्याप्त निवेश आकर्षित किया है, जो वैश्विक स्तर पर लगभग 35.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है।
- इस वृद्धि का श्रेय क्वांटम कंप्यूटरों द्वारा दी गई कंप्यूटिंग क्षमताओं में आशाजनक उछाल और उनके द्वारा साइबर सुरक्षा में लाए गए बदलाव को दिया जा सकता है।

अंतर-सरकारी क्वांटम प्रौद्योगिकी पहल:

- यूरोपीय संघ: क्वांटम टेक्नोलॉजीज फ्लैगशिप की स्थापना यूरोपीय संघ (ईयू) द्वारा 2018 में लगभग 1 बिलियन यूरो के बजट के साथ की गई थी, जिसका उद्देश्य क्वांटम प्रौद्योगिकियों में यूरोपीय नेतृत्व को मजबूत करना है।
  o यह सहयोग को बढ़ावा देने के लिए अनुसंधान संस्थानों, निजी कंपनियों और सार्वजनिक संस्थाओं को एक साथ लाता है।
- AUKUS: ऑकस 2021 में ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम (यूके) और संयुक्त राज्य अमेरिका (यूएस) के बीच गठित एक त्रिपक्षीय सुरक्षा व्यवस्था है।
  o वर्ष 2022 में शुरू की गई AUKUS क्वांटम व्यवस्था का उद्देश्य, विशेष रूप से चीन के साथ प्रतिस्पर्धा में, क्वांटम कंप्यूटिंग और क्रिप्टोग्राफी में रणनीतिक लाभ बनाए रखने पर ध्यान देने के साथ, क्वांटम क्षमताओं में निवेश में तेजी लाना है।
- चतुर्भुज सुरक्षा वार्ता: जिसे क्वाड के नाम से भी जाना जाता है, ने 2021 में एक महत्वपूर्ण और उभरती हुई प्रौद्योगिकी कार्य समूह की स्थापना की।
  o इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि क्वांटम कंप्यूटिंग सहित प्रमुख प्रौद्योगिकियों के लिए मानक और ढांचे साझा हितों और मूल्यों द्वारा शासित हों।
  o मई 2023 में, क्वाड इन्वेस्टर्स नेटवर्क (QUIN) लॉन्च किया गया, जो नवीन प्रौद्योगिकियों में रुचि रखने वाले निवेशकों को जोड़ता है।
- CERN क्वांटम प्रौद्योगिकी पहल: यूरोपीय परमाणु अनुसंधान परिषद (CERN) ने 2020 में क्वांटम प्रौद्योगिकी पहल शुरू की।
  o यह क्वांटम सिस्टम और सूचना प्रसंस्करण के ज्ञान को आगे बढ़ाते हुए नई कंप्यूटिंग, डिटेक्टर और संचार प्रणाली विकसित करने पर केंद्रित है।

निजी पहल:

- आईबीएम: आईबीएम, एक तकनीकी नवाचार लीडर, जो टोक्यो विश्वविद्यालय और शिकागो विश्वविद्यालय के साथ सहयोग कर रहा है, का लक्ष्य अगले दशक में 100,000-क्यूबिट क्वांटम कंप्यूटर विकसित करना है।
  o वर्ष 2022 में, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मद्रास, भारत में क्वांटम कंप्यूटिंग अनुसंधान और कौशल विकास को आगे बढ़ाते हुए, आईबीएम क्वांटम नेटवर्क में शामिल हो गया।
- Google: Google ने 2019 में "क्वांटम सर्वोच्चता" हासिल की और क्वांटम कंप्यूटिंग में एक प्रमुख खिलाड़ी बन गया है।
  o यह विभिन्न क्वांटम कंप्यूटिंग स्टार्टअप्स के साथ सहयोग करता है, जिनमें IonQ, QSimulator और Pasqal शामिल हैं।
  o वर्ष 2021 में, Google ने डिजिटल फ्यूचर इनिशिएटिव लॉन्च किया, जो ऑस्ट्रेलियाई बुनियादी ढांचे, अनुसंधान और साझेदारी में पांच वर्षों में 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश है।
- D-वेव: डी-वेव, जिसका मुख्यालय कनाडा में है, यह एनीलिंग और गेट-मॉडल क्वांटम कंप्यूटर दोनों में माहिर है और इसने क्वांटम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैब्स स्थापित करने के लिए नासा और Google के साथ मिलकर काम किया है।
- इंफोसिस: भारत में, इंफोसिस ने साइबर सुरक्षा क्षमताओं को बढ़ाने के लिए क्लासिकल एन्क्रिप्शन सिस्टम के साथ संगत क्वांटम

यादृच्छिक संख्या जनरेटर बनाने के लिए ऑस्ट्रेलियाई क्वांटम साइबर सुरक्षा फर्म क्विंटेसेंसलैब्स के साथ साझेदारी की है।

क्वांटम कंप्यूटिंग के संभावित अनुप्रयोग:

- नई दवाएं: क्वांटम कंप्यूटिंग जटिल आणविक इंटरैक्शन को अनुकरण करने में मदद कर सकती है, जिससे शोधकर्ताओं को नई दवाओं की खोज करने और मौजूदा दवाओं को अनुकूलित करने की अनुमति मिलती है।
- बेहतर जलवायु पूर्वानुमान: क्वांटम कंप्यूटर बड़ी मात्रा में डेटा संसाधित कर सकते हैं, जिससे अधिक सटीक जलवायु मॉडल और पर्यावरण संरक्षण के लिए बेहतर जानकारी वाली नीतियां बन सकती हैं।
- सुरक्षित संचार: क्वांटम कंप्यूटर क्वांटम एन्क्रिप्शन का उपयोग करके अल्ट्रासिक्योर संचार को सक्षम कर सकते हैं, जिससे हैकर्स के लिए संवेदनशील जानकारी को रोकना लगभग असंभव हो जाता है।
- उन्नत एआई मॉडल: क्वांटम कंप्यूटिंग मशीन लर्निंग एल्गोरिदम में नाटकीय रूप से सुधार कर सकती है, जिससे विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए अधिक कुशल और सटीक एआई मॉडल सक्षम हो सकते हैं।
- लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन: क्वांटम कंप्यूटिंग लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन में दक्षता में सुधार करने के लिए रूटिंग और शेड्यूलिंग जैसी जटिल अनुकूलन समस्याओं के लिए इष्टतम समाधान ढूंढ सकती है।
- बेहतर निवेश रणनीतियाँ: क्वांटम कंप्यूटिंग जटिल वित्तीय डेटा का विश्लेषण कर सकती है, जिससे वित्तीय क्षेत्र में बेहतर जोखिम मूल्यांकन और निवेश रणनीतियों की अनुमति मिलती है।
- जलवायु परिवर्तन: क्वांटम कंप्यूटिंग जलवायु मॉडलिंग और विश्लेषण को बढ़ा सकती है, जिससे प्रभावी जलवायु परिवर्तन शमन रणनीतियों के विकास में सहायता मिलती है।

क्वांटम कंप्यूटिंग तकनीक विकसित करने में चुनौतियाँ:

- बड़े क्वांटम प्रोसेसर की इंजीनियरिंग: एक व्यावहारिक QC के लिए कम से कम 1,000 क्यूबिट की आवश्यकता होती है। वर्तमान में, सबसे बड़े क्वांटम प्रोसेसर में 433 क्यूबिट हैं।
  o बड़े प्रोसेसर बनाने के लिए इंजीनियरिंग बाधाओं को दूर करने की आवश्यकता है।
- विशिष्ट परिस्थितियों को बनाए रखना: क्यूबिट्स को अपनी सुपरपोजिशन स्थिति को बनाए रखने के लिए बेहद कम तापमान, विकिरण परिरक्षण और फिजिकल शॉक से सुरक्षा की आवश्यकता होती है।
- त्रुटि-सुधार: नो क्लोनिंग थ्योरम के कारण क्वांटम त्रुटि-सुधार मुश्किल है, जो बताता है कि एक क्वबिट की स्थिति को पूरी तरह से क्लोन नहीं किया जा सकता है।
  o त्रुटि-सुधार के लिए प्रत्येक क्वबिट को हजारों भौतिक क्वबिट के साथ उलझाने की आवश्यकता होती है।
- त्रुटि प्रवर्धन: शोधकर्ताओं को ऐसे क्यूसी विकसित करने चाहिए जो अधिक क्यूबिट जोड़े जाने पर त्रुटियों को न बढ़ाएं।
  o त्रुटि दर को एक निश्चित सीमा से नीचे रखना महत्वपूर्ण है, क्योंकि अधिक क्यूबिट अतिरिक्त सूचनात्मक हलचल बढ़ा सकती हैं।

आगे की राह:

- तेजी से बढ़ते आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बाजार की तरह, एक अन्य तकनीक के रूप में क्वांटम कंप्यूटिंग ने विश्व स्तर पर देशों और कंपनियों के बीच दौड़ में शामिल होने और नेतृत्व की स्थिति हासिल करने की लहर पैदा कर दी है।
- इसलिए समय की मांग है कि पर्याप्त क्वांटम कम्प्यूटेशनल क्षमता का निर्माण किया जाए, व्यावहारिक आकार और किफायती लागत वाले क्वांटम कंप्यूटर के निर्माण और संचालन में कौशल विकसित किया जाए, विभिन्न व्यावहारिक अनुप्रयोगों को साकार करने के लिए अनुसंधान जारी रखा जाए।

Source: ORF

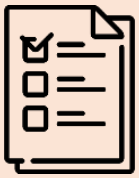

Practice Questions

Q1) निम्नलिखित जोड़ों पर विचार कीजिए:

आयोग	मंत्रालय
1. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड	वित्त मंत्रालय
2. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भारत	रक्षा मंत्रालय
3. राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग	शिक्षा मंत्रालय

उपरोक्त में से कितने जोड़े सही सुमेलित हैं?
(A) केवल एक
(B) केवल दो
(C) सभी तीन
(D) कोई नहीं

Q2) निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
कथन-I:
वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) के अध्यक्ष चार साल तक या 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक इस पद पर बने रहते है।
कथन-II:
वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के पास दंडात्मक शक्तियां हैं।
उपरोक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है?
(A) कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं और कथन-II कथन-I की सही व्याख्या है
(B) कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं और कथन-II, कथन-I की सही व्याख्या नहीं है
(C) कथन-I सही है लेकिन कथन II ग़लत है
(D) कथन-I गलत है लेकिन कथन II सही है

Q3) दादा साहब फाल्के लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. इसकी स्थापना 1969 में हुई थी।
2. यह भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रस्तुत किया जाता है।
3. यह सबसे पहले देविका रानी को प्रदान किया गया था।
ऊपर दिए गए कथनों में से कितने सही हैं/हैं?
(A) केवल 1
(B) केवल 1, 2 और 3
(C) केवल 2 और 3
(D) केवल 3

Q4) निम्नलिखित जोड़ों पर विचार कीजिए:

संस्थान	मुख्यालय
SEBI	पुणे
LIC	मुंबई
RBI	नई दिल्ली

उपरोक्त में से कितने जोड़े सही सुमेलित हैं?
(A) केवल एक
(B) केवल दो
(C) सभी तीन
(D) कोई नहीं

Q5) निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
कथन-I:
गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (एसएफआईओ) कंपनी मामलों के विभाग से प्राप्त धोखाधड़ी के गंभीर मामलों की जांच करता है।
कथन-II:
इसका एक क्षेत्रीय कार्यालय मुंबई में है।
उपरोक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है?
(A) कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं और कथन-II कथन-I की सही व्याख्या है
(B) कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं और कथन-II, कथन-I की सही व्याख्या नहीं है
(C) कथन-I सही है लेकिन कथन II ग़लत है
(D) कथन-I गलत है लेकिन कथन II सही है

Q6) CSIR PRIMA ET11 के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. देखा गया है कि महिलाएं केवल एक ही साथी के साथ मैट (mate) करती हैं।
2. IUCN स्थिति असुरक्षित है।
3. यह छोटे अकशेरुकी जीवों को उत्तेजित करने के लिए पानी पर तेजी से घूमने के लिए जाना जाता है।
ऊपर दिए गए कथनों में से कितने सही हैं?
(A) केवल 1 और 2
(B) केवल 1, 2 और 4
(C) केवल 3 और 4
(D) केवल 3

Q7) निम्नलिखित जोड़ों पर विचार कीजिए:

अभ्यास	देश
JIMEX	जापान-भारत
सम्प्रीति	भारत और श्रीलंका
युद्ध अभ्यास	भारत और इंडोनेशिया

उपरोक्त में से कितने जोड़े सही सुमेलित हैं?
(A) केवल एक
(B) केवल दो
(C) सभी तीन
(D) कोई नहीं

Q8) निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
कथन-I:
इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक (आईपीपीबी) पैसा उधार नहीं दे सकता।
कथन-II:
यह क्रेडिट कार्ड जारी कर सकता है।
उपरोक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है?
(A) कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं और कथन-II कथन-I की सही व्याख्या है
(B) कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं और कथन-II, कथन-I की सही व्याख्या नहीं है
(C) कथन-I सही है लेकिन कथन II ग़लत है
(D) कथन-I गलत है लेकिन कथन II सही है

Q9) नीलगिरि तहर के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. इसे IUCN लाल सूची के तहत लुप्तप्राय के रूप में सूचीबद्ध किया गया है।
2. यह कर्नाटक का राज्य पशु है।
3. यह हिमालय के लिए स्थानिक है।
ऊपर दिए गए कथनों में से कितने सही हैं/हैं?
(A) केवल 2
(B) केवल 1, 2 और 3
(C) केवल 2 और 3
(D) केवल 1

Q10) निम्नलिखित जोड़ों पर विचार कीजिए:

राष्ट्रीय उद्यान	स्थान
एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान	तमिलनाडु
सिमिलिपाल राष्ट्रीय उद्यान	मध्य प्रदेश
साइलेंट वैली नेशनल पार्क	कर्नाटक

उपरोक्त में से कितने जोड़े सही सुमेलित हैं?
(A) केवल एक
(B) केवल दो
(C) सभी तीन
(D) कोई नहीं

Q11) निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए
कथन-I:
जहाजों की न्यायिक बिक्री के अंतर्राष्ट्रीय प्रभावों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन वर्ष 2022 में अपनाया गया था।
कथन-II:
इस सम्मेलन को जहाजों की न्यायिक बिक्री पर बीजिंग कन्वेंशन के रूप में भी जाना जाता है।
उपरोक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है?
(A) कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं और कथन-II कथन-I की सही व्याख्या है
(B) कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं और कथन-II, कथन-I की सही व्याख्या नहीं है
(C) कथन-I सही है लेकिन कथन II ग़लत है
(D) कथन-I गलत है लेकिन कथन II सही है

Q12) सेगुर हाथी गलियारे के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. यह पश्चिमी और पूर्वी घाट को जोड़ता है।
2. इसके उत्तरपूर्वी हिस्से में नीलगिरि पहाड़ियाँ हैं।
3. मोयार नदी घाटी इसके दक्षिण-पश्चिमी किनारे पर है।
ऊपर दिए गए कथनों में से कितने सही हैं?
(A) केवल 1
(B) केवल 1, 2 और 3
(C) केवल 2 और 3
(D) केवल 1 और 3

Q13) निम्नलिखित जोड़ों पर विचार कीजिए :

अंतरिक्ष मिशन	एजेंसी
DISCOVERY	NASA
Aditya-L1	ISRO
MOM	JAXA

उपरोक्त में से कितने जोड़े सही सुमेलित हैं?
(A) केवल एक
(B) केवल दो
(C) सभी तीन
(D) कोई नहीं

Q14) निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
कथन-I:
UNCTAD न्यूनतम विकसित देशों की रिपोर्ट वर्ष में दो बार प्रकाशित करता है।
कथन-II:
दूसरा UNCTAD सम्मेलन 1968 में नई दिल्ली, भारत में हुआ।
उपरोक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है?
(A) कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं और कथन-II कथन-I की सही व्याख्या है

(B) कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं और कथन-II, कथन-I की सही व्याख्या नहीं है
(C) कथन-I सही है लेकिन कथन II ग़लत है
(D) कथन-I गलत है लेकिन कथन II सही है

Q15) CALIPSO मिशन के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. यह बेहतर वायु गुणवत्ता आकलन और मौसम पूर्वानुमान में योगदान देता है।
2. यह NASA-ESA का संयुक्त मिशन है।
3. यह उच्च परिशुद्धता के साथ बादलों और एरोसोल की ऊंचाई और गुणों को मापने के लिए लेजर पल्स का उपयोग करता है।
ऊपर दिए गए कथनों में से कितने सही हैं/हैं?
(A) केवल 2
(B) केवल 1, 2 और 3
(C) केवल 1 और 3
(D) केवल 3

Q16) निम्नलिखित जोड़ों पर विचार कीजिए :

मंदिर	स्थान
सम्मेद शिखरजी जैन मंदिर	झारखंड
मोढेरा सूर्य मंदिर	गुजरात
श्रीशैलम मंदिर	केरल

उपरोक्त में से कितने जोड़े सही सुमेलित हैं?
(A) केवल एक
(B) केवल दो
(C) सभी तीन
(D) कोई नहीं

Q17) निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
कथन-I:
लचीलेपन के लिए आपदा न्यूनीकरण में निवेश सेंडाई फ्रेमवर्क की कार्रवाई की चार प्राथमिकताओं में से एक है।
कथन-II:
यह ह्योगो फ्रेमवर्क फॉर एक्शन (एचएफए) का पूर्ववर्ती है।
उपरोक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है?
(A) कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं और कथन-II कथन-I की सही व्याख्या है
(B) कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं और कथन-II, कथन-I की सही व्याख्या नहीं है
(C) कथन-I सही है लेकिन कथन II ग़लत है
(D) कथन-I गलत है लेकिन कथन II सही है

Q18) भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक (CAG) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. इनकी पेंशन भारत की संचित निधि से आती है और मतदान के अधीन है।
2. वह भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग के प्रमुख होता हैं।
3. उसका कार्यकाल 5 वर्ष या 60 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो, होता है।
ऊपर दिए गए कथनों में से कितने सही हैं?
(A) केवल 2
(B) केवल 1, 2 और 3
(C) और केवल 3
(D) केवल

Q19) निम्नलिखित जोड़ों पर विचार कीजिए:

टाइगर रिजर्व	स्थान
मेलघाट	महाराष्ट्र
संजय धुबरी	छत्तीसगढ़
रानीपुर टाइगर रिजर्व	उत्तर प्रदेश

उपरोक्त में से कितने जोड़े सही सुमेलित हैं?
(A) केवल एक
(B) केवल दो
(C) सभी तीन
(D) कोई नहीं

Q20) निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
कथन-I:
'सहभागी धान' चावल की सूखा-सहिष्णु किस्म है।
.कथन-II:
'बीना धान-11', जो बाढ़-सहिष्णु है।
उपरोक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है?
(A) कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं और कथन-II कथन-I की सही व्याख्या है
(B) कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं और कथन-II, कथन-I की सही व्याख्या नहीं है
(C) कथन-I सही है लेकिन कथन II ग़लत है
(D) कथन-I गलत है लेकिन कथन II सही है

Q21) भारतीय एक सींग वाले गैंडे के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. IUCN रेड लिस्ट में इसकी स्थिति सबसे कम चिंता जनक है।
2. यह गैंडे की सभी प्रजातियों में सबसे छोटी है।
3. यह CITES के परिशिष्ट II में है।
ऊपर दिए गए कथनों में से कितने सही हैं?
(A) केवल एक
(B) केवल दो
(C) सभी तीन
(D) कोई नहीं

Q22) निम्नलिखित जोड़ों पर विचार कीजिए :

पशु	IUCN स्थिति
गौर	संवेदनशील
इंडियन फ़्लाइंग फ़ॉक्स	सबसे कम चिंता जनक
भारतीय गिद्ध	अति संकटग्रस्त

उपरोक्त में से कितने जोड़े सही सुमेलित हैं?

(A) केवल एक

(B) केवल दो

(C) सभी तीन

(D) कोई नहीं

Q23) निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

कथन-I:

हाल ही में बंगाल में खोजी गई टेरीगोट्रिग्ला इंटरमेडिका, टेरीगोट्रिग्ला जीनस की अब तक भारत में रिपोर्ट की गई चौथी प्रजाति है।

कथन-II:

गर्नार्ड मांसाहारी होते हैं।

उपरोक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है?

(A) कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं और कथन-II कथन-I की सही व्याख्या है

(B) कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं और कथन-II, कथन-I की सही व्याख्या नहीं है

(C) कथन-I सही है लेकिन कथन II ग़लत है

(D) कथन-I गलत है लेकिन कथन II सही है

Q24) GCES वेब पोर्टल और मोबाइल एप्लिकेशन के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. इसे वर्ष 2017 में लॉन्च किया गया था।
2. यह कृषि में वास्तविक समय अनुमान और प्रौद्योगिकी प्रदान करता है।
3. यह प्राथमिक कार्यकर्ता को इसके माध्यम से भूखंड के साथ-साथ फसलों की तस्वीरें अपलोड करने में सक्षम बनाता है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कितने सही हैं/हैं?

(A) केवल 1

(B) केवल 1, 2 और 3

(C) केवल 2 और 3

(D) केवल 3

Q25) निम्नलिखित जोड़ों पर विचार कीजिए:

रोग	रोगज़नक़
सामान्य सर्दी	राइनो वायरस
खसरा	रूबेला वायरस
चेचक	वेरियोला वायरस

उपरोक्त में से कितने जोड़े सही सुमेलित हैं?

(A) केवल एक

(B) केवल दो

(C) सभी तीन

(D) कोई नहीं

Q26) निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

कथन-I:

ई-कोर्ट मिशन इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा चलाया जाता है।

कथन-II:

इसे भारत की ई-कमेटी सुप्रीम कोर्ट और न्याय विभाग के सहयोग से कार्यान्वित किया जा रहा है।

उपरोक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है?

(A) कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं और कथन-II कथन-I की सही व्याख्या है

(B) कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं और कथन-II, कथन-I की सही व्याख्या नहीं है

(C) कथन-I सही है लेकिन कथन II ग़लत है

(D) कथन-I गलत है लेकिन कथन II सही है

Q27) मलेरिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह अधिकतर उष्णकटिबंधीय देशों में पाया जाता है।
2. यह रोकथाम और इलाज योग्य नहीं है।
3. संक्रमण संक्रामक है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कितने सही हैं?

(A) केवल एक

(B) केवल दो

(C) सभी तीन

(D) कोई नहीं

Q28) निम्नलिखित जोड़ों पर विचार कीजिए:

द्विध्रुवी विकार के प्रकार	सेटअप
द्विध्रुवी II	कम से कम एक उन्मत्त प्रकरण जो हाइपोमेनिक या प्रमुख अवसादग्रस्तता प्रकरण से पहले या बाद में होता है।
साइक्लोथैमिक विकार	कम से कम दो वर्ष या एक वर्ष के बच्चों और किशोरों में हाइपोमेनिया के लक्षणों की कई अवधियों और अवसादग्रस्तता
द्विध्रुवी I	द्विध्रुवी I में कम से कम एक प्रमुख अवसादग्रस्तता प्रकरण और कम से कम एक हाइपोमेनिक प्रकरण, लेकिन कभी भी उन्मत्त प्रकरण नहीं।

उपरोक्त में से कितने जोड़े सही सुमेलित हैं?

(A) केवल एक

(B) केवल दो

(C) सभी तीन

(D) कोई नहीं

Q29) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

कथन-I:

रेड सैंड बोआ भारत की स्थानिक प्रजाति है।

कथन-II:

यह डिंबवाहिनी होता है।

उपरोक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है?
(A) कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं और कथन-II कथन-I की सही व्याख्या है
(B) कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं और कथन-II, कथन-I की सही व्याख्या नहीं है
(C) कथन-I सही है लेकिन कथन II ग़लत है
(D) कथन-I गलत है लेकिन कथन II सही है

Q30) निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
कथन-I:
मेरा बिल मेरा अधिकार योजना 1 सितंबर 2023 को लॉन्च की गई।
कथन-II:
यह फिलहाल केवल एंड्रॉइड पर उपलब्ध है।
उपरोक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है?
(A) कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं और कथन-II कथन-I की सही व्याख्या है
(B) कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं और कथन-II, कथन-I की सही व्याख्या नहीं है
(C) कथन-I सही है लेकिन कथन II ग़लत है
(D) कथन-I गलत है लेकिन कथन II सही है

Q31) निम्नलिखित जोड़ियों पर विचार कीजिए :

रोग	रोगज़नक़
एंथ्रेक्स	बैसिलस एन्थ्रेसीस
काली खांसी	क्लोस्ट्रीडियम टेटानी
टेटनस	बोर्डेटेला पर्टुसिस

उपरोक्त में से कितने जोड़े सही सुमेलित हैं?
(A) केवल एक
(B) केवल दो
(C) सभी तीन
(D) कोई नहीं

Q32) निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
कथन-I:
राष्ट्रीय ई-विधान एप्लिकेशन (NeVA) विधान सभाओं के सदस्यों को अधिक प्रभावी ढंग से सेवा प्रदान करने के लिए है।
कथन-II:
तेलंगाना देश का पहला डिजिटल विधानमंडल था।
उपरोक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है?
(A) कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं और कथन-II कथन-I की सही व्याख्या है
(B) कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं और कथन-II, कथन-I की सही व्याख्या नहीं है
(C) कथन-I सही है लेकिन कथन II ग़लत है
(D) कथन-I गलत है लेकिन कथन II सही है

Q33) प्रोबायोटिक्स के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. बटरमिल्क एक प्रोबायोटिक युक्त भोजन है।
2. प्रोबायोटिक्स विटामिन बनाते हैं।
3. प्रोबायोटिक्स में कभी भी यीस्ट नहीं होता है।
ऊपर दिए गए कथनों में से कितने सही हैं?
(A) केवल एक
(B) केवल दो
(C) सभी तीन
(D) कोई नहीं

Q34) निम्नलिखित जोड़ों पर विचार कीजिए:

प्राचीन संस्कृत साहित्य	द्वारा लिखित
अभिज्ञानशाकुन्तलम्	कालिदास
मृच्छकटिक	शूद्रक
रघुवंश	तुलसीदास

उपरोक्त में से कितने जोड़े सही सुमेलित हैं?
(A) केवल एक
(B) केवल दो
(C) सभी तीन
(D) कोई नहीं

Q35) निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
कथन-I:
भोरमदेव वन्यजीव अभयारण्य (बीडब्ल्यूएस) की विशेषता इसके हरे-भरे जंगल, घुमावदार पहाड़ियाँ और सतपुड़ा पहाड़ियों की मैकल श्रृंखला है।
कथन-II:
यह झारखंड के कवर्धा जिले में स्थित है।
उपरोक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है?
(A) कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं और कथन-II कथन-I की सही व्याख्या है
(B) कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं और कथन-II, कथन-I की सही व्याख्या नहीं है
(C) कथन-I सही है लेकिन कथन II ग़लत है
(D) कथन-I गलत है लेकिन कथन II सही है

Q36) निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. स्मॉग में वायुजनित कण शामिल हो सकते हैं, जिनमें अधिकतर पीएम 2.5 और पीएम 10 होते हैं।
2. पार्टिकुलेट पीएम 10 के संपर्क में आने से अस्थमा और क्रॉनिक ऑब्सट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज (सीओपीडी) जैसी श्वसन संबंधी बीमारियों की स्थिति बिगड़ सकती है।
3. गैसोलीन, तेल, डीजल ईंधन या लकड़ी के दहन से अधिकांशतः PM 2.5 उत्पन्न होता है।
उपरोक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
(A) 1 और 3
(B) केवल 2
(C) केवल 1
(D) 1,2, और 3

Q37) निम्नलिखित जोड़ों पर विचार कीजिए:

संगठन	मुख्यालय
भारतीय रिज़र्व बैंक	नई दिल्ली

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो	मुंबई
प्रवर्तन निदेशालय	कोलकाता

उपरोक्त में से कितने जोड़े सही सुमेलित हैं?
(A) केवल एक
(B) केवल दो
(C) सभी तीन
(D) कोई नहीं

Q38) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें
कथन-I:
वित्तीय समावेशन के लिए G20 ग्लोबल पार्टनरशिप (GPFI) की बैठक नई दिल्ली, भारत में आयोजित की गई।
कथन-II:
बैठक में G20 इंडिया प्रेसीडेंसी के तहत वित्तीय समावेशन एजेंडा के चल रहे कार्य पर चर्चा हुई।
उपरोक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है?
(A) कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं और कथन-II कथन-I की सही व्याख्या है
(B) कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं और कथन-II, कथन-I की सही व्याख्या नहीं है
(C) कथन-I सही है लेकिन कथन II ग़लत है
(D) कथन-I गलत है लेकिन कथन II सही है

Q39) शांतिनिकेतन के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. टैगोर का आश्रम परिसर शांतिनिकेतन का सबसे नया क्षेत्र है जहां महर्षि देबेंद्रनाथ टैगोर ने पहला अतिथि गृह शांतिनिकेतन गृह बनाया था।
2. विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना विविधता में एकता पैदा करने के मुख्य आदर्श वाक्य और उद्देश्य के साथ की गई थी।
3. परिसर के पेड़ों के नीचे गुरुकुल (खुली कक्षा) का चलन आज भी है।
ऊपर दिए गए कथनों में से कितने सही हैं/हैं?
(A) केवल 1
(B) केवल 2 और 3
(C) केवल 1,2 और 3
(D) केवल 3

Q40) निम्नलिखित जोड़ों पर विचार कीजिए:

फसल उत्सव	राज्य
नुआखाई	उड़ीसा
पोंगल	केरल
बोहाग बिहू	अरुणाचल प्रदेश

उपरोक्त में से कितने जोड़े सही सुमेलित हैं?
(A) केवल एक
(B) केवल दो
(C) सभी तीन
(D) कोई नहीं

Q41) निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
कथन-I:
केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) उन वस्तुओं या निकासी सेवाओं को वापस ले सकता है जो "खतरनाक, जोखिमभरा या असुरक्षित" हैं।
कथन-II:
यह वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है।
उपरोक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है?
(A) कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं और कथन-II कथन-I की सही व्याख्या है
(B) कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं और कथन-II, कथन-I की सही व्याख्या नहीं है
(C) कथन-I सही है लेकिन कथन II ग़लत है
(D) कथन-I गलत है लेकिन कथन II सही है

Q42) 'पुलिक्कली' के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:-
1. यह ओणम उत्सव के चौथे दिन किया जाता है।
2. इसे महाराजा राम वर्मा सकथन थंपुरन द्वारा प्रस्तुत किया गया था।
3. यह कर्नाटक की एक मनोरंजक स्ट्रीट फोल्क आर्ट है।
उपरोक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है?
(A) केवल 1 और 2
(B) केवल 1
(C) 1,2 और 3
(D) केवल 2 और 3

Q43) निम्नलिखित जोड़ों पर विचार कीजिए:

रामसर वेटलैंड	स्थान
कांवर झील	बिहार
नलसरोवर	राजस्थान
यशवन्त सागर	उत्तर प्रदेश

उपरोक्त में से कितने जोड़े सही सुमेलित हैं?
(A) केवल एक
(B) केवल दो
(C) सभी तीन
(D) कोई नहीं

Q44) निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
कथन-I:
भारत में प्रतिवर्ष 10 जनवरी को "हिन्दी दिवस" मनाया जाता है।
कथन-II:
भारतीय संविधान भारत की 22 प्रमुख भाषाओं को मान्यता देता है जिसे संविधान की "8वीं अनुसूची" के रूप में जाना जाता है।
उपरोक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है?
(A) कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं और कथन-II कथन-I की सही व्याख्या है

(B) कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं और कथन-II, कथन-I की सही व्याख्या नहीं है
(C) कथन-I सही है लेकिन कथन II ग़लत है
(D) कथन-I गलत है लेकिन कथन II सही है

Q45) विश्व व्यापार रिपोर्ट 2023 के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. इसे सितंबर, 2022 में लॉन्च किया गया था।
2. इसे WTO द्वारा प्रकाशित किया गया था।
3. यह दर्शाता है कि चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया।
ऊपर दिए गए कथनों में से कितने सही हैं?
(A) केवल एक
(B) केवल दो
(C) सभी तीन
(D) कोई नहीं

Q46) निम्नलिखित जोड़ों पर विचार कीजिए:

जीआई टैग	राज्य
नवारा चावल	कर्नाटक
कानी शॉल	जम्मू और कश्मीर
पलक्कडन मट्टा चावल	केरल

उपरोक्त में से कितने जोड़े सही सुमेलित हैं?
(A) केवल एक
(B) केवल दो
(C) सभी तीन
(D) कोई नहीं

Q47) निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
कथन-I:
विद्युतीकृत फ्लेक्स ईंधन वाहन बढ़ी हुई ईंधन दक्षता प्रदान करते हैं।
कथन-II:
दुनिया का पहला बीएस-6 स्टेज-II, विद्युतीकृत फ्लेक्स ईंधन वाहन, टाटा मोटर्स द्वारा विकसित किया गया है।
उपरोक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है?
(A) कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं और कथन-II कथन-I की सही व्याख्या है
(B) कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं और कथन-II, कथन-I की सही व्याख्या नहीं है
(C) कथन-I सही है लेकिन कथन II ग़लत है
(D) कथन-I गलत है लेकिन कथन II सही है

Q48) CSIR PRIMA ET11 के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. यह 100% शुद्ध इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर है।
2. इसमें प्रिज़मैटिक सेल कन्फर्मेशन के साथ अत्याधुनिक लिथियम-आयन बैटरी है।
3. किसान पारंपरिक घरेलू चार्जिंग सॉकेट का उपयोग करके ट्रैक्टर को चार्ज कर सकते हैं।
ऊपर दिए गए कथनों में से कितने सही हैं?
(A) केवल एक
(B) केवल दो
(C) सभी तीन
(D) कोई नहीं

Q49) निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
कथन-I:
नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई) की स्थापना वर्ष 2009 में हुई थी।
कथन-II:
यह भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) और भारतीय बैंक संघ (IBA) की एक पहल है।
उपरोक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है?
(A) कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं और कथन-II कथन-I की सही व्याख्या है
(B) कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं और कथन-II, कथन-I की सही व्याख्या नहीं है
(C) कथन-I सही है लेकिन कथन II ग़लत है
(D) कथन-I गलत है लेकिन कथन II सही है

Q50) अनुच्छेद 371D के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. इसे 1974 में 22वें संशोधन अधिनियम, 1973 द्वारा संविधान में जोड़ा गया था।
2. यह रोजगार और शिक्षा के मामलों में अधिकारों की रक्षा करता है।
3. यह अरुणाचल प्रदेश राज्य के लिए विशेष प्रावधान देता है।
ऊपर दिए गए कथनों में से कितने सही हैं?
(A) केवल एक
(B) केवल दो
(C) सभी तीन
(D) कोई नहीं

ANSWERS

Ans 1	A	Ans 2	D	Ans 3	B
Ans 4	B	Ans 5	C	Ans 6	D
Ans 7	A	Ans 8	C	Ans 9	D
Ans 10	D	Ans 11	B	Ans 12	A
Ans 13	B	Ans 14	B	Ans 15	C
Ans 16	B	Ans 17	C	Ans 18	A
Ans 19	B	Ans 20	B	Ans 21	D
Ans 22	B	Ans 23	B	Ans 24	C
Ans 25	C	Ans 26	D	Ans 27	A
Ans 28	A	Ans 29	D	Ans 30	C
Ans 31	A	Ans 32	C	Ans 33	B
Ans 34	B	Ans 35	C	Ans 36	D
Ans 37	D	Ans 38	D	Ans 39	B
Ans 40	A	Ans 41	C	Ans 42	A
Ans 43	A	Ans 44	D	Ans 45	B
Ans 46	B	Ans 47	C	Ans 48	C
Ans 49	D	Ans 50	A		

IAS BABA

TLP CONNECT 2024

INTEGRATED PRELIMS CUM MAINS TEST SERIES

TLP CONNECT

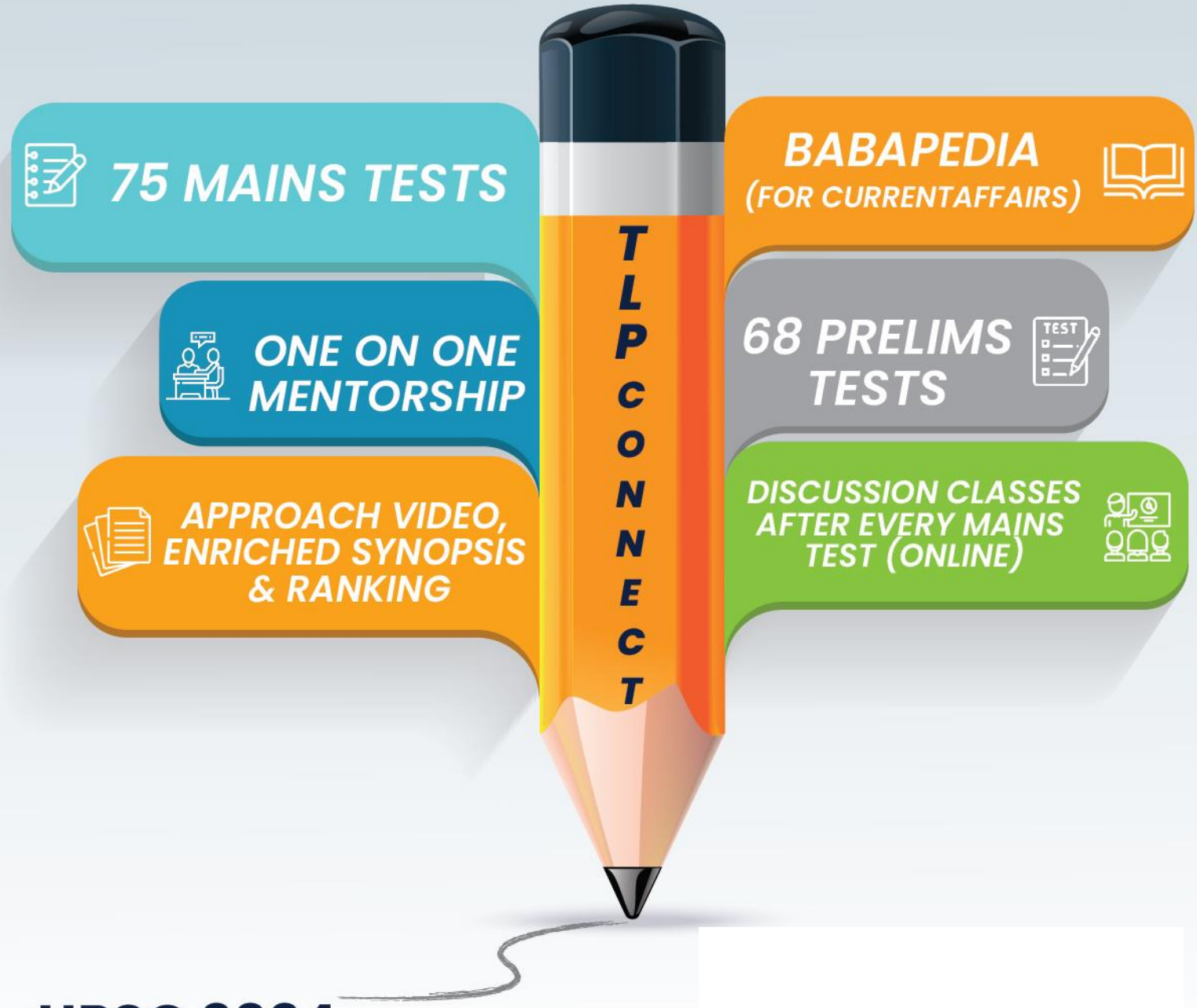

- 75 MAINS TESTS
- ONE ON ONE MENTORSHIP
- APPROACH VIDEO, ENRICHED SYNOPSIS & RANKING
- BABAPEDIA (FOR CURRENTAFFAIRS)
- 68 PRELIMS TESTS
- DISCUSSION CLASSES AFTER EVERY MAINS TEST (ONLINE)

UPSC 2024

ENROLL NOW

ONLINE & OFFLINE

www.iasbaba.com support@iasbaba.com +91 9169191888